September 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Chinook Helicopters

Karnataka Hijab Row

The G7 Countries & Russia

India - Saudi Arabia relations

Maratand Temple

CBI & it's Troubles

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

हिंदी

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

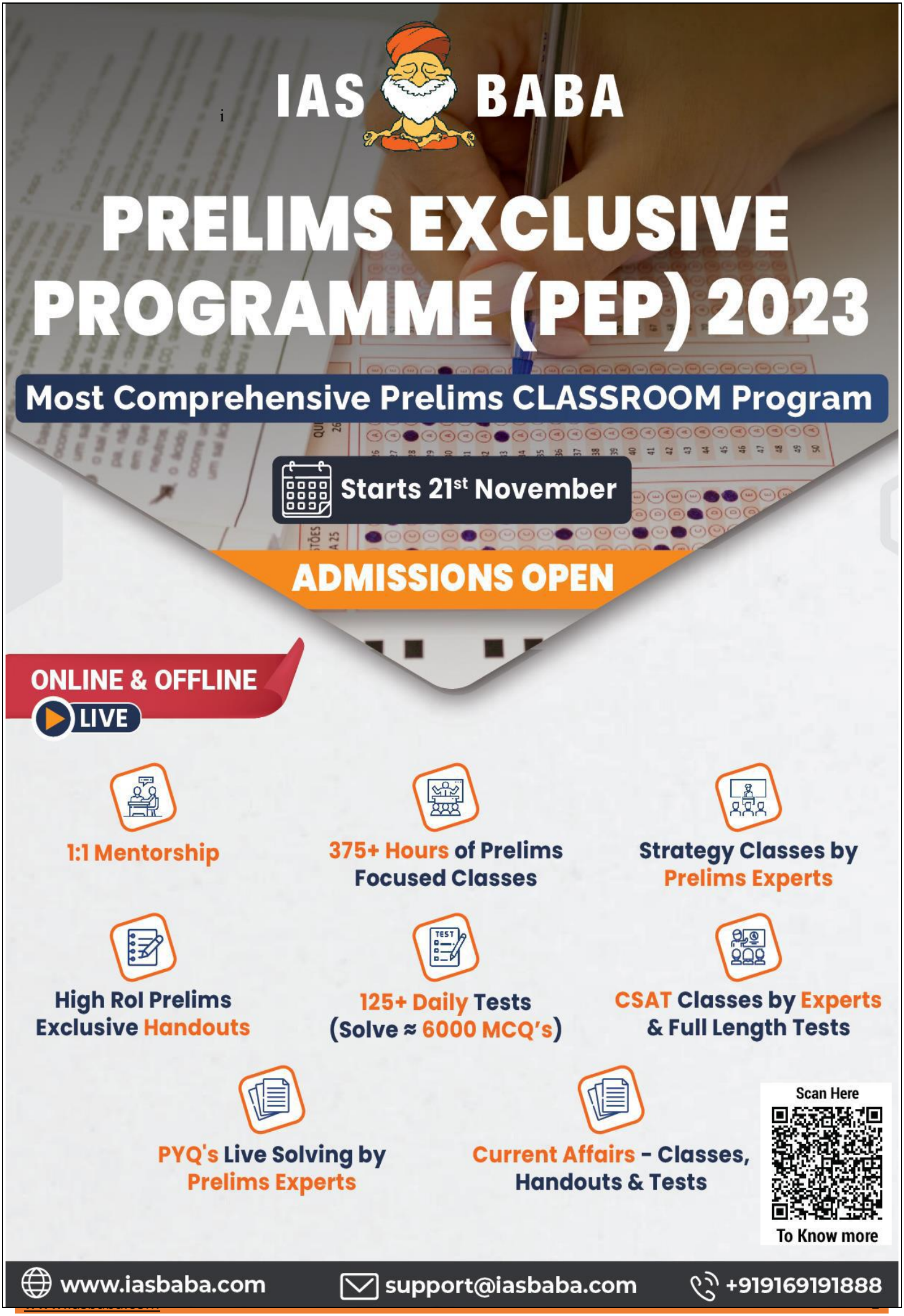

IAS BABA
PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) 2023
Most Comprehensive Prelims CLASSROOM Program
Starts 21st November
ADMISSIONS OPEN
ONLINE & OFFLINE
LIVE
1:1 Mentorship
375+ Hours of Prelims Focused Classes
Strategy Classes by Prelims Experts
High RoI Prelims Exclusive Handouts
125+ Daily Tests (Solve ≈ 6000 MCQ's)
CSAT Classes by Experts & Full Length Tests
PYQ's Live Solving by Prelims Experts
Current Affairs - Classes, Handouts & Tests
Scan Here
To Know more
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
+919169191888

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम
- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)
- पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools)
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022
- फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS)
- कुशियारा नदी जल समझौता
- अभ्यास पर्वत प्रहार
- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) व्यापार स्तंभ
- किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण संशोधन) मॉडल संशोधन नियम 2022
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- किर्गिस्तान - ताजिकिस्तान संघर्ष
- चिनूक हेलीकॉप्टर
- G7 और रूस
- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT)
- अब्राहम समझौते और I2U2
- पूर्वी आर्थिक मंच (EEF)
- कामनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स (Commonwealth of Nations)
- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

अर्थव्यवस्था

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट
- भारत के बाहरी ऋण पर स्थिति रिपोर्ट 2021-22
- मानव विकास सूचकांक
- प्राकृतिक रबर (Natural Rubber)
- श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation)
- लोरा (LoRa) (लॉन्ग रेंज रेडियो) तकनीक
- बेसल III मानदंड
- स्टार्ट-अप इंडिया इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए फंड ऑफ फंड्स
- माल्थसियन जनसंख्या ट्रैप (Malthusian trap)

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- मार्तंड मंदिर
- हैदराबाद मुक्ति दिवस
- वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई
- मोहन जोदड़ो (Mohenjo-Daro)
- रेमन मैग्सेसे पुरुस्कार
- दारा शिकोह
- होयसला मंदिर
- आचार्य विनोबा भावे
- स्वामी विवेकानंद
- अन्नाभाऊ साठे (Annabhau Sathe)
- अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर
- पेरियार ई.वी. रामासामी
- सालार जंग संग्रहालय (Salar Jung Museum)
- अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट
- सित्तनवासल जैन विरासत स्थल
- प्राचीन पौधा सिलफियोन
- शहीद भगत सिंह
- बौद्ध गुफाएं और स्तूप तथा ब्राह्मी शिलालेख
- बथुकम्मा उत्सव (Bathukamma festival)

भूगोल

- कॉफी बोर्ड
- सोलोमन द्वीप (Solomon Islands)
- प्राग (Prague)

- गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र (Gogra-Hotsprings area)
- वेम्बनाड झील
- अज़रबैजान-अर्मेनियाई सीमा विवाद (Azerbaijan-Armenian border dispute)
- मानसबल झील (Manasbal Lake)
- लौह अयस्क (Iron Ore)
- सुपर टाइफून हिन्नमनोर

पर्यावरण

- न्युकमाडोंग कम्युनिटी रिजर्व (Nyukmadong community Reserve)
- चीता पुनरुत्पादन (Cheetah Reintroduction)
- चीता और अन्य बड़ी बिल्लियाँ
- भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व
- कार्बन डेटिंग
- हाथी संरक्षण (Elephant Conservation)
- ड्रैगनफलीज़ (Dragonflies)
- ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022
- अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण

- **सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे**
- ऑपरेशन "मेघ चक्र"
- भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI)
- अनुसूचित जनजाति
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
- टी माधव राव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल
- सेमीकंडक्टर
- एंटी रेडिएशन गोलियां
- सर्ववैक (Cervavac)
- आईएनएस विक्रांत
- इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD)
- iNCOVACC
- Qimingxing-50, या मॉर्निंग स्टार-50
- सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया (QRSAM) प्रणाली
- प्रोजेक्ट 17 ए के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी'
- CRISPR जैव प्रौद्योगिकी
- नासा का डार्ट (दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण) मिशन
- एथेरियम (Ethereum)
- मलेरिया का टीका
- पारिस्थितिक निके मॉडलिंग
- उलझी हुई परमाणु घड़ियाँ
- फ्लेक्स ईंधन प्रौद्योगिकी
- भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली/NavIC
- रोहिणी आरएच-200 साउंडिंग रॉकेट

विविध

- भारतीय नौसेना ध्वज (झंडा)
- नैनो-यूरिया (Nano-Urea)
- डार्क स्काई रिजर्व
- आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2022

Mains

राजव्यवस्था और शासन

- सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता
- पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
- यूरोप का ऊर्जा संकट
- फेडरल फैब्रिक अंडर थ्रेट
- सीबीआई और उसकी परेशानियाँ (CBI and its Troubles)
- स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतंत्र
- कर्नाटक हिजाब केस

- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम
- भारत में मौत की सजा
- अपराधियों की पहचान के लिए नियम

अर्थव्यवस्था

- लोगों को खाना खिलाना, ग्रह को बचाना
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- विंडफॉल टैक्स
- पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना
- धर्मशाला घोषणा
- खाद्य सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-सऊदी अरब संबंध
- भारत-मिस्र संबंध
- G4 देश और UNSC सुधार
- भारत-रूस संबंध

इतिहास , कला और संस्कृति

- सुभाष चंद्र बोस

भूगोल

- शहरी बाढ़ (Urban Flooding)
- बंगाल की खाड़ी

पर्यावरण

- कार्बन ट्रेडिंग नीति
- जलवायु सुधार
- 'मियावाकी पद्धति' के तहत मेरा गांव, मेरा जंगल'
- संधारणीय ऊर्जा (Sustainable energy)

सामाजिक मुद्दे

- गर्भपात का अधिकार
- भारत में एलजीबीटी अधिकारों और कानूनों का एक संक्षिप्त इतिहास
- संस्कृतिकरण (Sanskritization)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- केस स्टडी

PRACTICE QUESTIONS

KEY ANSWERS

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम	**ख़बरों में क्यों :** कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में कहीं भी भांग को प्रतिबंधित ड्रग या पेय के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है। **भांग और संबंधित कानून:** • भांग कैनबिस (सन गांजा) के पौधे के मादा फूलों की एक खाद्य तैयारी है, जिसे अक्सर विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ ठंडाई और लस्सी (thandai and lassi) जैसे पेय में मिलाया जाता है। • वर्ष 1985 में अधिनियमित, एनडीपीएस अधिनियम मुख्य कानून है जो ड्रग्स और उनकी तस्करी से संबंधित है। • अधिनियम के प्रावधान चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, स्वामित्व, उपभोग, खरीद, परिवहन और उपयोग को दंडित करते हैं। **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** • **NDPS अधिनियम:** यह व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है। • प्रारंभ में 1985 में अधिनियमित, NDPS अधिनियम में अब तक तीन बार 1988, 2001 और 2014 में संशोधन किया गया है। • अधिनियम के अनुसार, मादक दवाओं में कोका पत्ता, भांग (कैनाबिज/हेंप), अफीम और खसखस शामिल हैं। • एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं। • अधिनियम के तहत, यह नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को ज़ब्त करने का भी प्रावधान करता है। • नशीली दवाओं के दोषियों द्वारा समाप्ति, छूट, और पारित वाक्यों को कम करके कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है। **जुर्माना:** अधिनियम के तहत अपराध एक साल से लेकर 20 साल तक की जेल की सजा और अपराध के आधार पर जुर्माना लगाते हैं। **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:** • एनसीबी भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए उत्तरदायी होती है। • यह केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत कार्यरत है। • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। • यह स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित किया गया था।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)	**ख़बरों में क्यों :** न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **नालसा (NALSA) :** यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित है। CJI संरक्षक-इन-चीफ हैं, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। **संवैधानिक प्रावधान:** • भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। • अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। **मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?** • महिलाएं और बच्चे

	• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य • औद्योगिक कामगार • सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार। • दिव्यांग व्यक्ति • हिरासत में उपस्थित व्यक्ति • वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है और यदि मामला 5 लाख रुपए से कम का है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। • मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग।
पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools)	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना - पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) को मंजूरी दी। **पीएम श्री योजना की मुख्य विशेषताएं:** • इसका उद्देश्य NEP 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। • इन स्कूलों को पर्यावरण की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकाथॉन और सतत जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु हरित स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। • हर क्लास के बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा। • रोजगारपरकता बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग के साथ जुड़ाव का पता लगाया जाएगा। • परिणामों को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को निर्दिष्ट करते हुए एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) विकसित किया जा रहा है। **यह कैसे लागू होगा ?** • समग्र शिक्षा, केन्द्रीय विद्यालयों (KV) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों को लागू किया जाएगा। **योजना के तहत पीएम श्री स्कूल की पहचान:** • पीएम श्री योजना आवेदन आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि राज्यों को योजना के तहत उन्नयन के लिए स्कूलों की पहचान करनी होगी। • केंद्र सरकार द्वारा तय की गई चयन पद्धति के अनुसार, योजना के तहत शामिल होने के इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले एनईपी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सहमत होना होगा। • केवल वही स्कूल योग्य होंगे जो एक निश्चित बेंचमार्क को पूरा करते हैं - योग्यता मानदंड में बिजली की उपलब्धता से लेकर शौचालय तक लगभग 60 पैरामीटर शामिल होंगे। • राज्य सरकार के अधिकारियों, केवी और जेएनवी की टीमें भौतिक निरीक्षण के माध्यम से आवेदक स्कूल द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करेंगी। "अधिकतम दो विद्यालयों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक) का चयन प्रति ब्लॉक/यूएलबी..." (शहरी स्थानीय निकाय) योजना के अनुसार किया जाएगा। अंतिम निर्णय एक विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाएगा।
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022	**संदर्भ:** आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेगा। **क्या है प्रस्तावित कानून?** • **कवरेज-** यह प्रस्ताव करता है कि कानून तीन श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होता है। ○ सभी दोषी व्यक्ति (पहले यह केवल कुछ मामलों के लिए था) ○ गिरफ्तार व्यक्ति ○ संदिग्ध अपराधी ○ किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्ति • **विवरण का प्रतिधारण:** कानून राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) को किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ स्टोर करने, संरक्षित करने, साझा करने और राष्ट्रीय स्तर पर माप के रिकॉर्ड को नष्ट करने का अधिकार देता है। अभिलेखों को 75 वर्ष की अवधि तक संग्रहीत किया जा

सकता है।

- **ब्यौरों को हटाना:** उन व्यक्तियों के मामले में रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है जो: (i) पहले दोषी नहीं ठहराए गए हैं, और (ii) सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के बाद न्यायालय द्वारा मुकदमे के बिना रिहा किए गए, आरोपमुक्त या बरी कर दिए गए हैं।
  - हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस कर्मियों को माप रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **विवरण देने का विरोध:** विधेयक के अनुसार, प्रतिरोध या विवरण देने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध माना जाएगा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की भूमिका: विधेयक के तहत NCRB के कार्यों में शामिल हैं:
  - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विधेयक के तहत शामिल व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करना
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट व्यक्तियों के बारे में विवरण संग्रहीत करना और नष्ट करना
  - प्रासंगिक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ विवरण संसाधित करना, और
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विवरण का विस्तार करना।

नया कानून 1920 के पुराने अधिनियम से किस प्रकार अलग है?

	1920 अधिनियम	2022 के बिल में बदलाव
डेटा एकत्र करने की अनुमति होती है	• फ़िंगरप्रिंट, फ़ुटप्रिंट इंप्रेशन, फ़ोटोग्राफ़ी	• **जोड़ना:** (i) जैविक नमूने, और उनका विश्लेषण, (ii) हस्ताक्षर, लिखावट सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं, और (iii) CrPC की धारा 53 और 53A के तहत परीक्षण (रक्त, वीर्य, बालों के नमूने, और स्वाब, और विश्लेषण जैसे कि DNA प्रोफाइलिंग)
वे व्यक्ति जिनका डेटा एकत्र किया जा सकता है	• एक वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए दोषी हों या गिरफ्तार किए गए हों। • व्यक्तियों ने अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया। • आपराधिक जांच में सहायता के लिए मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में किसी गिरफ्तार व्यक्ति से रिकवरी का आदेश दे सकता है।	• नया विधेयक किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों पर लागू होता है। साथ ही यह महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराध करने पर गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति से जबरन जैविक नमूने जुटाने की अनुमति देता है। इसके अलावा अगर किसी अपराध में न्यूनतम सात साल कैद की सजा है तो उसमें भी यह विधेयक लागू होगा। • किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति • मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी भी व्यक्ति (सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति) से जांच में सहायता करने के लिए
ऐसे व्यक्ति जिन्हें डेटा की आवश्यकता/प्रत्यक्ष संग्रह की आवश्यकता	• जांच अधिकारी, पुलिस थाने का	• पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, या हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का

	हो सकती है	प्रभारी अधिकारी, या उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का अधिकारी। • मजिस्ट्रेट	अधिकारी। इसके अलावा, जेल का हेड वार्डर। • मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यक्तियों के मामले में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS)

ख़बरों में क्यों : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS) शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

मुख्य निष्कर्ष:

- कक्षा III में नामांकित 37 प्रतिशत छात्रों के पास "सीमित" मूलभूत संख्यात्मक कौशल है, जैसे कि संख्याओं की पहचान करना, जबकि 11 प्रतिशत में "सबसे बुनियादी ज्ञान और कौशल की कमी है"।
- जबकि 15 प्रतिशत के पास अंग्रेजी में "बुनियादी कौशल" की कमी थी, 30 प्रतिशत के पास "सीमित कौशल" पाया गया, 21 प्रतिशत के पास पर्याप्त कौशल था, जबकि 34 प्रतिशत के पास काफी बेहतर कौशल था।
- राष्ट्रीय स्तर पर, 11 प्रतिशत के पास बुनियादी ग्रेड-स्तरीय कौशल नहीं था; 37 प्रतिशत के पास सीमित कौशल था; 42 प्रतिशत के पास पर्याप्त कौशल था; और 10 प्रतिशत के पास बेहतर कौशल था।
- अन्य भारतीय भाषाओं में, बुनियादी कौशल की कमी वाले छात्रों का अनुपात मराठी में 17 प्रतिशत, बंगाली में 20 प्रतिशत, गुजराती में 17 प्रतिशत, मलयालम में 17 प्रतिशत, तमिल में 42 प्रतिशत और 25 प्रतिशत उर्दू में था।

निष्कर्षों की उपयोगिता:

- निष्कर्ष बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र की योजना NIPUN भारत (समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल) के लिए आधार रेखा निर्धारित करेंगे।

समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुन भारत)

- प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने का लक्ष्य और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और अंकगणित में ग्रेड-स्तरीय दक्षता प्राप्त करें।
- ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं और कार्रवाई योग्य एजेंडा निर्धारित करता है।
- निपुन भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं, जिसमें बालवाटिका से शुरू होकर 9 वर्ष की आयु तक लक्ष्य या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य शामिल हैं।

कुशियारा नदी जल समझौता

खबरों में: 6 सितंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौता पर हस्ताक्षर किये। गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किये जाने के बाद इस तरह का यह पहला समझौता है।

- भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 12 साल बाद पिछले महीने नई दिल्ली में बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी।
- 'कुशियारा', बराक नदी की एक वितरिका या शाखा-नदी है जो असम से होकर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- बराक नदी मणिपुर से निकलती है और सुरमा-मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है।
- समझौते का उद्देश्य भारत में असम के दक्षिणी क्षेत्रों और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र (Sylhet region) को लाभ पहुंचाना है।
- सिलहट में 'रहीमपुर नहर परियोजना' के माध्यम से कुशियारा का जल प्रवाहित किया जाएगा।

भौगोलिक अंतर्दृष्टि:

- बांग्लादेश और भारत एक 4,096 किलोमीटर लंबी (2,545 मील) अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो सबसे लंबी भूमि सीमा है जिसे भारत अपने किसी भी पड़ोसी के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है।
- देश 50 से अधिक नदियों को साझा करते हैं जैसे कि गंगा की मुख्य शाखा जिसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।

महत्व

	• नदी की बदलती प्रकृति के प्रमुख मुद्दे को संबोधित करने में मदद करना जो मानसून के दौरान बांग्लादेश में बाढ़ लाती है और सर्दियों के दौरान सूख जाती है जब सिलहट में फसल चक्र के कारण पानी की मांग बढ़ जाती है। • सिलहट के उपखण्डों के कृषि क्षेत्रों और बागों की सिंचाई के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। • बाढ़ नियंत्रण में अधिक सहयोग। • साझा नदी के प्रदूषण से निपटने में आपसी सहयोग को मजबूत करना।
अभ्यास पर्वत प्रहार	**संदर्भ:** सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में अभ्यास 'पर्वत प्रहार' की समीक्षा के लिए लद्दाख सेक्टर का दौरा किया। **मुख्य विवरण:** • यह अभ्यास 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख पठार में आयोजित किया गया था। • इस अभ्यास में चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों और K9-वज्र हॉवित्जर द्वारा परिवहन किए गए सभी इलाके के वाहनों का इस्तेमाल किया गया। • इस अभ्यास में आर्टिलरी गन और अन्य प्रमुख हथियार प्रणालियों द्वारा परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। • इसके साथ ही पश्चिमी मोर्चे पर, अभ्यास गगन स्ट्राइक का समापन स्ट्राइक कोर द्वारा गहन अभियानों का समर्थन करने वाले हमले हेलीकाप्टरों के एक अग्नि शक्ति प्रदर्शन के साथ हुआ।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) व्यापार स्तंभ	**ख़बरों में क्यों :** भारत ने अभी के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) व्यापार स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है। **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के बारे में** • यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा जारी किए गए आईपीईएफ पर एक अंतर्दृष्टि पत्र के अनुसार, आईपीईएफ एक पारंपरिक व्यापार समझौता नहीं है। बल्कि, इसमें विभिन्न मॉड्यूल (चार स्तंभ) शामिल होंगे: ○ निष्पक्ष और लचीला व्यापार, ○ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, ○ अवसंरचना और डीकार्बोनाइजेशन, और ○ कर और भ्रष्टाचार विरोधी। **भारत और आईपीईएफ:** • भारत ने IPEF के तीन स्तंभों में शामिल होने का निर्णय लिया ○ भारत आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचे, और कर-विरोधी और भ्रष्टाचार स्तंभों में शामिल हो गया है। हालांकि, इसने ट्रेड पिलर से बाहर रहने का फैसला किया है। **भारत के व्यापार स्तंभ में शामिल न होने का कारण:** • अभी तक आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। हालांकि, व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को व्यापार स्तंभ के कुछ पहलुओं के बारे में कुछ वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं जो शायद विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से परे हैं।
किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण संशोधन) मॉडल संशोधन नियम 2022	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत सरकार ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण संशोधन) मॉडल संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल या संरक्षण) अधिनियम/जेजे अधिनियम, 2015:** • अधिनियम (महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा) पेश किया गया था और 2015 में किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदलने के लिए पारित किया गया

था।

- अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में से एक 16-18 वर्ष के आयु वर्ग में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के वयस्कों के रूप में परीक्षण की अनुमति देना है।
    - अधिनियम के तहत, किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को जघन्य (heinous) (न्यूनतम या अधिकतम 7 साल की सजा के साथ), गंभीर (3-7 साल के कारावास के साथ) और छोटे अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अधिनियम के अनुसार, जघन्य अपराधों के आरोपित और 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें वयस्क न्याय प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
- अपराध की प्रकृति और क्या किशोर पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, यह एक किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाना था।
- इस अधिनियम ने अनाथों, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लिए गोद लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और मौजूदा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एक वैधानिक निकाय बनाया गया है।
- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना कर सकती है।
- समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला और दूसरा बाल विशेषज्ञ होगा।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल या संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021:

- संशोधन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट (2018-19) पर आधारित है, जिसमें 7,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई या बच्चों के घरों) का सर्वेक्षण किया गया था।
    - रिपोर्ट में पाया गया कि 1.5% CCI जेजे अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं हैं और उनमें से 29% के प्रबंधन में बड़ी खामियां थीं।
    - यह भी पाया गया कि देश में एक भी CCI को जेजे अधिनियम के प्रावधानों का 100% अनुपालन नहीं पाया गया।

संशोधन:

- संशोधन के अनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) सहित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), अब जेजे अधिनियम के तहत गोद लेने के आदेश जारी कर सकते हैं।
    - यह तेजी से मामले के समाधान और बढ़ी हुई जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।
- नया संशोधन डीएम की मंजूरी के बिना किसी भी नए सीसीआई को खोलने पर रोक लगाता है।
    - अब, डीएम यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि उनके जिले में आने वाले सीसीआई सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।
    - डीएम सीडब्ल्यूसी सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच (शैक्षिक योग्यता सहित) भी करेंगे, जो आमतौर पर सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- अधिनियम के अनुसार, गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा सात साल से अधिक जेल और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात साल से कम है।
- मॉडल नियम में कहा गया है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।
- NCPCR (प्रियांक कानूनगो) के अध्यक्ष के अनुसार, CWC में शामिल लोगों के पास मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है और वे सरकारी अधिकारियों के समकक्ष होते हैं, जिन्हें विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया जाता है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि हितों का टकराव पैदा करने वाले किसी गैर सरकारी संगठन या संगठन में जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन में शामिल कोई भी व्यक्ति सीडब्ल्यूसी में सेवा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यह कहा जाता है कि किसी गैर सरकारी संगठन के लिए काम करने वाले "परिवार के किसी सदस्य" या "निकट संबंध" वाला कोई भी व्यक्ति सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है।

	• जिले में बचाव और पुनर्वास में शामिल कोई भी व्यक्ति, साथ ही सीसीआई चलाने वाले किसी व्यक्ति या बोर्ड के सदस्य या किसी गैर सरकारी संगठन के ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति, सीडब्ल्यूसी में सेवा करने के लिए पात्र नहीं है। • सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को भी उन व्यक्तियों की श्रेणी से हटा दिया गया है जिन पर सीडब्ल्यूसी में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)	**ख़बरों में क्यों :** NAAC ने कथित तौर पर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद रोक दिया था कि विश्वविद्यालय ने सहकर्मी समीक्षा टीम को सोने, नकद और अन्य एहसानों से प्रभावित करने की कोशिश की थी। **इसके बारे में:** उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के पोर्टल पर 1,043 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेज सूचीबद्ध हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 406 विश्वविद्यालय और 8,686 कॉलेज नैक से मान्यता प्राप्त है। • महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद कर्नाटक का स्थान है। तमिलनाडु में सबसे अधिक (43) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। **NAAC के बारे में:** • यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है। • यह भारतीय उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों (HEI) की गुणवत्ता जांच या आकलन करता है। • यह एचईआई को मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ प्रमाणित करता है। संस्थानों की रेटिंग A++ से लेकर C तक होती है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। • एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से, एक उच्च शिक्षा संस्थान यह सीखता है कि क्या वह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और अन्य मापदंडों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। **कार्यप्रणाली:** • यूजीसी (अनिवार्य मूल्यांकन और उच्च शैक्षणिक संस्थानों का प्रत्यायन) विनियम, 2012 के माध्यम से प्रत्यायन अनिवार्य कर दिया गया है। • प्रत्यायन के लिए वर्तमान दृष्टिकोण "इनपुट-आधारित" है जिसका अर्थ है मात्रात्मक और गुणात्मक मैट्रिक्स से संबंधित आवेदक संस्थानों की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट पर भारी निर्भरता है। • इसके बाद डेटा को NAAC विशेषज्ञ टीमों द्वारा मान्य और उसके बाद संस्थानों में सहकर्मी टीम का दौरा किया जाता है। • पीयर टीम (Peer Team) के दौरों की प्रक्रिया में एनएएसी और एचईआई दोनों की ओर से अधिक प्रयास शामिल हैं। • केवल उच्च शिक्षा संस्थान जो कम से कम छह साल पुराने हैं, या जहां से छात्रों के कम से कम दो बैचों ने स्नातक किया है, आवेदन कर सकते हैं। • प्रत्यायन पांच साल के लिए वैध है। • जब कोई संस्थान पहली बार प्रत्यायन प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे चक्र 1 और उसके बाद की पांच वर्षों की अवधि को चक्र 2, 3 और इसी तरह के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

किर्गिस्तान - ताजिकिस्तान संघर्ष

संदर्भ: किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।

- जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में दो गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था।
- ऐतिहासिक रूप से किर्गिज़ और ताजिक आबादी को प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार प्राप्त थे।
- फ़रगना घाटी संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोटों का स्थल बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से ताजिक, किर्गिज़ और उज़बेक शामिल हैं। इनकी ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विशिष्टताएं, आर्थिक गतिविधियां और धार्मिक प्रथाएं एक जैसी थी।
- यह "विकास परियोजना" सोवियत संघ के आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से तुलनीय है,जिसके कारण खानाबदोश आबादी का व्यापक निष्कासन हुआ और अंततः चल रहे संघर्ष के लिए "पर्यावरण चालक" के रूप में कार्य किया।

चिनूक हेलीकॉप्टर

ख़बरों में क्यों : अमेरिकी सेना ने इंजन में आग लगने का खतरा पाए जाने के बाद CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े को ग्राउंड कर दिया है। भारतीय वायु सेना (IAF) चिनूक हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा भी संचालित करती है।

चिनूक के बारे में: भारत ने 2015 में अमेरिका के साथ 15 चिनूक हैवी लिफ्ट और 22 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 3 बिलियन डॉलर का समझौता किया था।

विशेषताएँ:

- चिनूक एक बहु-भूमिका, ऊर्ध्वाधर-लिफ्ट प्लेटफार्म पर आधारित है, जिसका उपयोग सैनिकों, तोपखाने, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है।
- चिनूक को मानवीय और आपदा राहत कार्यों और राहत आपूर्ति के परिवहन और शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निकासी जैसे अभियानों के लिए तैनात किया जाएगा।
- चिनूक हेलीकॉप्टर में दो रोटर इंजन लगे हैं जो अमेरिकी सशस्त्र बलों के सबसे स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक बन गया है।
- हेलीकॉप्टर, जो लगभग 10 टन भार ले जा सकता है, ने भारतीय वायुसेना की हवाई लिफ्ट क्षमताओं को

	काफी बढ़ाया है।
G7 और रूस	**ख़बरों में क्यों :** सात देशों का समूह यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मास्को की क्षमता को सीमित करने के प्रयास में रूसी तेल की कीमत को सीमित करने के लिए काम कर रहा है। **G7 देशों के बारे में:** सात का समूह (G7) पारस्परिक रूप से घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी, पर्यावरण, सैन्य, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है। • सदस्य दुनिया की सबसे बड़ी आईएमएफ उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और उदार लोकतंत्र हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा और यूरोपीय संघ शामिल हैं। • **विशेषताएं:** बहुलवाद और प्रतिनिधि सरकार के साझा मूल्य। वर्ष 2020 तक, सामूहिक समूह का वैश्विक नेट वेल्थ का 50 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 32 से 46 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी शामिल है। • वर्ष 2022 से, जर्मनी ने यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता के बाद, G7 की घूर्णन अध्यक्षता संभाल ली है। • **उद्देश्य:** प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान पर चर्चा और समन्वय करना, विशेष रूप से व्यापार, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में। • G7 किसी संधि पर आधारित नहीं है और इसका कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय नहीं है। **G8 G7 क्यों बन गया है?** • वर्ष 1998 से रूसी संघ के शामिल होने पर G7 G8 बन गया। • हालांकि, रूसी संघ द्वारा यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के कारण यूरोपीय सदस्यों, उत्तरी अमेरिकी सदस्यों और जापान के नेताओं ने वर्ष 2014 में रूसी राष्ट्रपति पद के दौरान G8 में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। उन्होंने उसी वर्ष सात सदस्यीय प्रारूप में काम फिर से शुरू किया।
परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT)	**संदर्भ:** अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT) के 10वें समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। • एनपीटी के बारे में: एनपीटी पर 1960 के दशक के दौरान तीन प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों को समेटने के लिए चर्चा की गई थी - • P-5 देश (यू.एस., यू.एस.एस.आर., यू.के., फ्रांस और चीन) से परे परमाणु हथियारों के आगे प्रसार को नियंत्रित करना जो पहले ही परीक्षण कर चुके थे; • परमाणु शस्त्रागार को कम करने के लिए चर्चा करने हेतु प्रतिबद्ध है जिससे उनका उन्मूलन हो सके; तथा • परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के लाभों को साझा करना। **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW):** • परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW), या परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि, परमाणु हथियारों को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका अंतिम लक्ष्य उनका पूर्ण निशस्त्रीकरण है। इसे 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था, 20 सितंबर 2017 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 22 जनवरी 2021 को इसे लागू किया गया । • सभी 86 हस्ताक्षरकर्ता परमाणु संपन्न हैं और एनपीटी के पक्षकार हैं। • यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है। **व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)**

	• व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) 1996 में संपन्न हुई थी, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है क्योंकि दो प्रमुख शक्तियों, एस और चीन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। • इसका उद्देश्य हर जगह और सभी के द्वारा सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। • संधि के अनुबंध 2 में सूचीबद्ध सभी 44 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद संधि लागू हो जाएगी। जिस समय संधि पर चर्चा हुई और उसे अपनाया गया, उस समय इन राज्यों के पास परमाणु सुविधाएं थीं। • भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
अब्राहम समझौते और I2U2	**संदर्भ:** इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की दलाली वाले अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह हमारे लोगों और राष्ट्रों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि की नई आशा को बढ़ावा दिया। **प्रमुख बिंदु:** • स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, नवाचार, प्रौद्योगिकी, कृषि, जल, व्यापार, पर्यटन और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहरीन, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच नए संयुक्त उद्यम शुरू किए जा रहे हैं। • समझौते ने अधिक क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। • विस्तार के आर्थिक अवसरों का भारत तक पहुंचना जारी है। ○ हमारी सरकारों के बीच उच्च-स्तरीय आर्थिक सहयोग का एक ठोस उदाहरण I2U2 समूह का गठन है, जिसे इज़राइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया है। **I2U2 समूह के बारे में:** • I2U2 का गठन शुरू में अक्टूबर, 2021 में इज़राइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, ताकि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। • उस समय इसे 'आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच' कहा जाता था। • इसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा जाता था। • I2U2 पहल भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक नया समूह है। • समूह के नाम में, 'I2' का अर्थ भारत और इज़राइल है, जबकि 'U2' का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है।
पूर्वी आर्थिक मंच (EEF)	**ख़बरों में क्यों :** रूस ने 5 से 8 सितंबर तक सातवें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) व्लादिवोस्तोक की मेजबानी की। चार दिवसीय मंच उद्यमियों के लिए रूस के सुदूर पूर्व (आरएफई) में अपने कारोबार का विस्तार करने का एक मंच है। **RFE के बारे में:** • इस क्षेत्र में रूस का एक तिहाई क्षेत्र शामिल है और यह मछली, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, हीरे और अन्य खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। • क्षेत्र के धन और संसाधनों का रूस के सकल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत का योगदान है। लेकिन सामग्री की प्रचुरता और उपलब्धता के बावजूद, कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण उनकी खरीद और आपूर्ति एक समस्या है। **EEF के बारे में:** • पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 2015 में रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

	• वार्षिक सभा के रूप में, ईईएफ क्षेत्र में आर्थिक क्षमता, उपयुक्त व्यावसायिक परिस्थितियों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है। • वर्ष 2022 तक, बुनियादी ढांचे, परिवहन परियोजनाओं, खनिज उत्खनन, निर्माण, उद्योग और कृषि पर ध्यान देने के साथ इस क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। क्या भारत ईईएफ और आईपीईएफ के बीच संतुलन हासिल करने में सक्षम होगा! • अमेरिका के नेतृत्व वाली समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) और ईईएफ इसके भौगोलिक कवरेज और मेजबान देशों के साथ साझेदारी के आधार पर अतुलनीय हैं। भारत के दोनों मंचों में निहित स्वार्थ हैं और उसने अपनी भागीदारी को संतुलित करने की दिशा में काम किया है। ○ भारत ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद ईईएफ में काफी निवेश किया है।
कामनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स (Commonwealth of Nations)	**संदर्भ:** यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु ने 14 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया, जिसमें वह राज्य की प्रमुख थीं। **राष्ट्रमंडल क्या है और इसके क्षेत्र क्या हैं?** • राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र हैं। • राष्ट्रमंडल में गणराज्य और राज्य दोनों शामिल हैं। ब्रिटिश सम्राट राज्य का प्रमुख है, जबकि गणराज्यों पर निर्वाचित सरकारों द्वारा शासन किया जाता है, सिवाय पाँच देशों के ब्रुनेई दारुस्सलाम, इस्वातिनी, लेसोथो, मलेशिया और टोंगा, ये प्रत्येक देश स्व-शासित राजतंत्र है। • ये क्षेत्र एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सोलोमन द्वीप और तुवालु हैं। **राष्ट्रमंडल को उसके सदस्य किस रूप में देखते हैं?** • वर्ष 1997 में रानी की तीसरी और अंतिम भारत यात्रा के दौरान, कई लोगों ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी की उम्मीद की, जो तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार द्वारा किया गया था, और जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा आदेश दिया गया था। ○ फिर भी वह माफी कभी नहीं आई, और इसके बजाय रानी ने केवल एक भोज भाषण के दौरान हत्याओं का उल्लेख किया जब उसने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि हमारे अतीत में कुछ कठिन घटनाएं हुई हैं। जलियांवाला बाग एक परेशान करने वाला उदाहरण है।" • यह 1997 में भी था कि यूके ने हांगकांग का नियंत्रण पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंप दिया, जिससे 156 वर्षों के बाद वह हार गया जिसे एशिया में सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशों में से एक माना जाता था। **कौन से देश ब्रिटिश राजतंत्र से औपचारिक संबंध समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं?** • उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया सहित कुछ राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में बहस ने देश को एक गणतंत्र के रूप में स्थान देने के लिए लोकप्रिय आंदोलनों का नेतृत्व किया है। • जबकि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि उनका देश किंग चार्ल्स का समर्थन करेगा, उन्होंने कहा कि यह "समय पर" गणतंत्र बन जाएगा। • इसी तरह, बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस ने कहा है कि वह किंग चार्ल्स को आधिकारिक राज्य प्रमुख की भूमिका से हटाने के लिए एक जनमत संग्रह कराने का इरादा रखते हैं, जिससे देश, वर्ष 1973 में स्वतंत्रता प्राप्त की, एक गणतंत्र होने की ओर बढ़ रहा है। ○ पांच अन्य कैरिबियाई देशों - एंटीगुआ और बारबुडा, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका और सेंट किट्स एंड नेविस की सरकारों ने भी इसी तरह से कार्य करने के अपने इरादे का संकेत दिया है।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम	**संदर्भ:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation : IFC) से आग्रह किया है कि भारत को अगले दो वर्षों में 2 बिलियन

	डॉलर से अधिक और अगले तीन-चार वर्षों में 3-3.5 बिलियन डॉलर तक उधार दिया जाए। **विश्व बैंक क्या है?** • विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्तपोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है। **ऐतिहासिक अवलोकन:** • विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी जो तीन लक्ष्यों का अनुसरण कर रहा था: ○ पुनर्निर्माण की सुविधा, जिसके कारण IBRD (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट) का निर्माण हुआ। ○ वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना, जिसके कारण IMF का निर्माण हुआ। ○ व्यापार को पुनर्स्थापित और उसका विस्तार करना, एक ऐसा उद्देश्य जिसे हासिल करना अधिक कठिन रहा है। इसकी शुरुआत GATT से हुई थी और वर्ष 1995 में ही WTO की स्थापना हुई थी। • इस प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका आधिकारिक नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) था। वर्ष 1946 में जब इसने पहली बार परिचालन शुरू किया, तो इसमें 38 सदस्य थे। आज विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। • विश्व बैंक का विस्तार पांच सहकारी संगठनों के साथ विश्व बैंक समूह के रूप में जाना जाने लगा है, जिन्हें कभी-कभी विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। • संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, उसके बाद जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान है। शेष शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं। **विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट:** • व्यापार करने में आसानी • विश्व विकास रिपोर्ट • वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट • रसद प्रदर्शन सूचकांक • प्रेषण रिपोर्ट • ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स • भारत विकास अद्यतन • यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स • सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक **इसके बारे में: अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम** • IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। • IFC, विश्व बैंक समूह का एक सदस्य, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है और लोगों के जीवन में सुधार करता है। • IFC की स्थापना वर्ष 1956 में एक साहसिक विचार पर की गई थी: निजी क्षेत्र में विकासशील देशों को बदलने की क्षमता है। • वित्त वर्ष 2011 में 31.5 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएं: इसका उद्देश्य लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है जहां हम काम करते हैं। वे प्रभाव-रेटिंग प्रणाली, जिसे प्रत्याशित प्रभाव मापन और निगरानी ढांचा कहा जाता है, परियोजनाओं का मूल्यांकन उनके अपेक्षित विकास परिणामों के साथ-साथ बाजार निर्माण पर उनके प्रभाव के आधार पर करता है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)	**संदर्भ:** उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक, मौजूदा संघर्षों से निपटने और भविष्य के लिए नए दिशानिर्देशों का प्रयास करने पर सरकारों के लिए एक परीक्षण मामला था।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में:

- SCO एक अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अनिश्चित काल तक मौजूद रहता है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में प्रभावी हुआ था।
- SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी है। यह भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया का लगभग 60%, विश्व की आबादी का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक है।

SCO की संरचना:

- राज्य परिषद के प्रमुख - शीर्ष SCO निकाय जो आंतरिक SCO संचालन, अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ चर्चा, और अंतरराष्ट्रीय चिंताओं पर निर्णय लेता है।
- सरकारी परिषद के प्रमुख - बजट को मंजूरी देते हैं और SCO के आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विषयों पर मूल्यांकन और निर्णय लेते हैं।
- विदेश मंत्रियों की परिषद - दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है।
- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) - आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए गठित एक संगठन है।

अर्थव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट	**ख़बरों में क्यों :** श्रीलंका ने लगभग 2.9 बिलियन डॉलर के ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। **आईएमएफ ऋण कैसे मदद करता है?** • आईएमएफ ऋण देने का उद्देश्य देशों को व्यवस्थित तरीके से समायोजन नीतियों को लागू करने के लिए ब्रीथिंग (breathing) की जगह देना है, जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए स्थितियों को बहाल करेगा। • आईएमएफ वित्तपोषण एक अधिक क्रमिक और सावधानीपूर्वक सुविचारित समायोजन की सुविधा प्रदान करता है। **ऋण साधन** • आईएमएफ के विभिन्न ऋण साधन विभिन्न प्रकार के भुगतान संतुलन की आवश्यकता के साथ-साथ इसकी विविधता की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हैं। • सभी आईएमएफ सदस्य गैर-रियायती शर्तों पर सामान्य संसाधन खाते (जीआरए) में फंड के संसाधनों तक पहुंचने के पात्र हैं। • आईएमएफ गरीबी में कमी और विकास ट्रस्ट के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता (वर्तमान में जून 2021 तक शून्य ब्याज दरों पर) भी प्रदान करता है जो कम आय वाले देशों की विविधता और जरूरतों के अनुरूप बेहतर है। • ऐतिहासिक रूप से, संकट में उभरती और उन्नत बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अल्पकालिक या संभावित भुगतान संतुलन समस्याओं को दूर करने के लिए स्टैंड-बाय व्यवस्था (SBA) के माध्यम से आईएमएफ सहायता का बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया है। • स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा (एससीएफ) कम आय वाले देशों के लिए समान उद्देश्य प्रदान करती है। • कम आय वाले देशों के लिए विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) और संबंधित विस्तारित क्रेडिट सुविधा (ईसीएफ) लंबे समय से भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे देशों को मध्यम अवधि के समर्थन के लिए फंड के मुख्य साधन हैं। • संकटों को रोकने या कम करने और बढ़े हुए जोखिमों की अवधि के दौरान बाजार के विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, पहले से ही मजबूत नीतियों वाले सदस्य लचीली क्रेडिट लाइन (FCL) या एहतियाती और तरलता रेखा (PLL) का उपयोग कर सकते हैं। • कम आय वाले देशों के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) और संबंधित रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF) उन देशों को त्वरित सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें कमोडिटी की कीमतों में झटके, प्राकृतिक आपदाएं और घरेलू कमजोरियां शामिल हैं।
भारत के बाहरी ऋण पर स्थिति रिपोर्ट 2021-22	**ख़बरों में क्यों :** वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में बाहरी ऋण प्रबंधन इकाई (ईडीएमयू) ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का 28 वां संस्करण जारी किया है। • मार्च 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2% अधिक था। • इसका 2% अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित था, जबकि भारतीय रुपया मूल्यवर्ग का ऋण, अनुमानित रूप से 31.2%, दूसरा सबसे बड़ा था। • सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण मार्च 2022 के अंत में एक साल पहले के 21.2 प्रतिशत से मामूली रूप से गिरकर 19.9 प्रतिशत हो गया। • विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार एक साल पहले के 100.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 के अंत में 97.8% पर थोड़ा कम था। • वाणिज्यिक उधार (CB), NRI जमा, अल्पकालिक व्यापार ऋण और बहुपक्षीय ऋण एक साथ कुल विदेशी

	ऋण के 90% के लिए उत्तरदायी हैं। • मार्च 2022 के अंत तक, संप्रभु विदेशी ऋण (SED) की राशि 130.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो एक साल पहले के स्तर से 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह 2021-22 के दौरान आईएमएफ द्वारा एसडीआर के अतिरिक्त आवंटन को दर्शाती है। • एसडीआर मार्च 2021 के अंत में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। • दूसरी ओर, जी-सेक (G-Sec) की FPI होल्डिंग एक साल पहले के 20.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। • मार्च 2022 के अंत तक 490.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर-संप्रभु विदेशी ऋण ने एक साल पहले के स्तर की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
मानव विकास सूचकांक	**ख़बरों में क्यों :** वर्ष 2021 मानव विकास सूचकांक (HDI) पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 का हिस्सा रही है। • मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धि को मापता है जिसमें शामिल है: लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और एक सभ्य जीवन स्तर। • इसकी गणना चार संकेतकों - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का उपयोग करके की जाती है। मानव विकास सूचकांक (HDI), 2021 में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। यह तीन दशकों में पहली बार लगातार दो वर्षों में इसके स्कोर में गिरावट दर्शाता है। **प्रमुख बिंदु:** • भारत का नवीनतम HDI मान 0.633, देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में इसके 0.645 के मूल्य से कम है। • भारत के मामले में भी 2019 में एचडीआई मान 0.645 था जो 2021 में 0.633 तक आ गया, इसके लिए जीवन प्रत्याशा में गिरावट (69.7 से घटकर 67.2 वर्ष होने को) जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। • भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 9 वर्ष हैं, जो 2020 की रिपोर्ट में 12.2 वर्ष से कम है, हालांकि स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 6.5 वर्ष से बढ़कर 6.7 वर्ष हो गया है। • हालांकि भारत ने लिंग विकास सूचकांक में अपना 132वां स्थान बरकरार रखा, लेकिन 2020 की रिपोर्ट में महिला जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष से घटकर 2021 की रिपोर्ट में 68.8 वर्ष हो गई। • इसी अवधि में महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 12.6 से घटकर 11.9 वर्ष हो गए। • भारत ने बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (Multi-Dimensional Poverty Index- एमपीआई) में 27.9 प्रतिशत के हेडकाउंट अनुपात के साथ 0.123 स्कोर किया, जिसमें 8.8 प्रतिशत आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी से जूझ रही है। **एशियाई देश:** भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका (73वां), चीन (79वां), बांग्लादेश (129वां), और भूटान (127वां) भारत से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान (161वां), नेपाल (143वां) और म्यांमार (149वां) की स्थिति बदतर (worse off) है।
प्राकृतिक रबर (Natural Rubber)	**संदर्भ:** हाल ही में, रबर उत्पादकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन, रबर प्रोड्यूसर सोसाइटीज इंडिया के क्षेत्रीय संघों के राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में, केरल के कोट्टायम में रबर बोर्ड मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। • भारत वर्तमान में प्राकृतिक रबर का दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यह विश्व स्तर पर सामग्री का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है। **रबड़ बोर्ड के बारे में:** • रबर बोर्ड रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। • बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होता है और इसमें 28 सदस्य होते हैं जो प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

	• बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। • केरल में अकेले कुल उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा है। • बोर्ड रबर से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन देकर देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। • यह रबर के सांख्यिकीय आंकड़े भी रखता है, रबर के विपणन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है और श्रम कल्याण गतिविधियों को शुरू करता है। • बोर्ड की गतिविधियों का प्रयोग पांच विभागों सामान्य सेवाओं, विस्तार और सलाहकार सेवाओं, अनुसंधान सेवाओं (भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान), प्रशिक्षण (रबर प्रशिक्षण संस्थान) और वित्त के माध्यम से किया जाता है। ○ इसके 5 स्वतंत्र प्रभाग हैं, अर्थात् आंतरिक लेखा परीक्षा, योजना, बाजार संवर्धन, प्रचार और जनसंपर्क, सतर्कता।

श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation)	**श्रिंकफ्लेशन क्या है?**
	• श्रिंकफ्लेशन किसी उत्पाद के आकार को कम कर उसके अंकित मूल्य (sticker price) को बनाए रखता है।
	• श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation) मूल रूप से छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है।
	• व्यापार और अकादमिक अनुसंधान में श्रिंकफ्लेशन को पैकेज डाउनसाइज़िंग के रूप में भी जाना जाता है।
	• इस शब्द का कम आम उपयोग एक व्यापक आर्थिक स्थिति को संदर्भित कर सकता है जहां अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और साथ ही बढ़ते मूल्य स्तर का भी एहसास कर रही है।
	
	श्रिंकफ्लेशन के प्रमुख कारण क्या हैं?
	• **उच्च उत्पादन लागत:** बढ़ती उत्पादन लागत आमतौर पर श्रिंकफ्लेशन का प्रथम कारण रही है।
	  ○ सामग्री या कच्चे माल, ऊर्जा वस्तुओं, और श्रम की लागत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और बाद में उत्पादकों के लाभ मार्जिन में कमी आती है।
	  ○ समान खुदरा मूल्य टैग रखते हुए उत्पादों के वजन, मात्रा या मात्रा को कम करने से निर्माता के लाभ मार्जिन में सुधार हो सकता है।
	• **तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा:** बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा भी श्रिंकफ्लेशन का कारण बन सकती है।
	  ○ खाद्य और पेय उद्योग आम तौर पर एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी उद्योग है, क्योंकि उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं।
	  ○ इसलिए, निर्माता उन विकल्पों की तलाश करते हैं जो उन्हें अपने ग्राहकों का पक्ष रखने और एक ही समय में अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

लोरा (LoRa) (लॉन्ग रेंज रेडियो) तकनीक	**ख़बरों में क्यों :** बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (Institute for Development and Research in Banking Technology-IDRBT) ने बैंकिंग को दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए लोरा (लॉन्ग रेंज रेडियो) तकनीक नामक एक नया कम लागत वाला वित्तीय नेटवर्क विकसित किया है। वे इस नेटवर्क को विकसित करने वाले दुनिया के पहला संस्थान हैं। **यांत्रिकी:** • लोरा (LoRa) तकनीक भौतिक परत में एक वायरलेस मॉड्यूलेशन तकनीक है, जो चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम का

	उपयोग कर लंबी दूरी के संचार की अनुमति देती है। • यह तकनीक समर्पित रेडियो का उपयोग करती है, तथा अन्य उपकरणों से हस्तक्षेप को सीमित करते हैं। • वर्तमान में, बैंक एक तृतीय-पक्ष नेटवर्क का उपयोग करते हैं जो या तो उपग्रह लिंक या वायर्ड (फाइबर) पर आधारित होता है। • अब, बैंक इस तकनीक का उपयोग अपने निजी नेटवर्क के रूप में कर सकते हैं और वित्तीय लेनदेन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट भेज सकते हैं। • दूरदराज के इलाकों से संपर्क वहीं से शुरू होता है, जहां से बैंक की आखिरी शाखा दूरदराज के गांव या पहाड़ी क्षेत्र में होती है। • 30,000 रुपये की लागत से बैंक लेनदेन के लिए 30 मील की कनेक्टिविटी हासिल की जा सकती है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। **महत्व:** • **लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Last mile connectivity):** दूर-दराज के पहाड़ी और वन क्षेत्रों के लोगों के लिए बिना सैटेलाइट सिग्नल के बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच संभव होगी। • **अधिक सुरक्षित:** साइबर हमलों से बेहतर सुरक्षा। • **सस्ता:** वैकल्पिक नेटवर्क प्रौद्योगिकियों की तुलना में 20% सस्ता होने का अनुमान है। • सरल रिकवरी और उपग्रडेशन • लगभग कोई रखरखाव नहीं है और उपकरणों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। **IDRBT के बारे में:** • यह एक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान है जो विशेष रूप से बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। • यह वर्ष 1996 में आरबीआई द्वारा स्थापित, संस्था बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के चौराहे पर काम करती है। • इसकी नींव रंगराजन समिति ने रखी थी। • यह हैदराबाद, भारत में स्थित है।
बेसल III मानदंड	**ख़बरों में क्यों :** विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय बैंक अगले कुछ महीनों में बेसल III-अनुपालन और बुनियादी ढांचा बांड जारी करके अपनी धन उगाहने की होड़ जारी रख सकते हैं। **बेसल फ्रेमवर्क क्या है:** • बेसल फ्रेमवर्क बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा 2007-08 के वित्तीय संकट से उत्पन्न वित्तीय विनियमन में कमियों के जवाब में विकसित पूंजी नियम हैं। • **उद्देश्य:** वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना, वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम करना, पूंजी मानक बढ़ाना और प्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से मजबूत अंतरराष्ट्रीय मुआवजा मानकों को लागू करना। जो अत्यधिक जोखिम लेने की ओर ले जाता है। • इन्हें पहली बार 1992 में G-10 देशों में लागू किया गया था। **विकास:** **बेसल I** • वर्ष 1999 में शुरुआत। • लगभग पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम पर केंद्रित है, इसने बैंकों के लिए जोखिम भार की पूंजी और संरचना को परिभाषित किया। • न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम-भारित संपत्ति (RWA) के 8% पर तय की गई थी। **बेसल II** • वर्ष 2004 में शुरुआत। • इसने तीन प्रकार के जोखिम को परिभाषित किया - परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, पूंजी जोखिम। • इसके 3 स्तंभ इस प्रकार थे: **बेसल III मानदंडों के बारे में:** • नए मानक जनवरी 2023 से लागू होंगे।

	• जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताएं (RWA) और ब्याज दर जोखिम पहली बार पेश किए गए थे। • नए मानकों का उद्देश्य पूंजी की आवश्यकताओं को बढ़ाना है, यह तरल परिसंपत्ति होल्डिंग्स और वित्त पोषण स्थिरतापर आवश्यकताओं का परिचय देता है। • **बेसल II और बेसल III के बीच मुख्य अंतर:** बेसल III संरचना अधिक सामान्य इक्विटी, पूंजी बफर का निर्माण, लीवरेज अनुपात की शुरूआत, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण (एनएसएफआर) का परिचय देता है। • **उत्तोलन अनुपात:** इसकी गणना टियर 1 पूंजी को समेकित बैंक आस्तियों के औसत कुल से विभाजित करके की जाती है। बैंकों से बेसल III के तहत 3% से अधिक का उत्तोलन अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। • **चलनिधि कवरेज अनुपात:** चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित अत्यधिक तरल संपत्ति को दर्शाता है। बैंक के लिए बेसल III के तहत एलसीआर एक आवश्यकता है, जिसके लिए 30 दिनों में अपनी स्ट्रेस्ड नेट कैश आवश्यकताओं के 100% को कवर करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) रखना आवश्यक है। LCR की गणना इस प्रकार की जाती है: LCR = HQLAs / शुद्ध नकदी बहिर्वाह • **निवल स्थिर निधीयन (NSF):** निवल स्थिर निधियन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंक अपनी संपत्ति की संरचना और बैलेंस शीट से बाहर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधिकरण प्रोफ़ाइल बनाए रखें। **बेसल III अनुपालन बांड के बारे में:** • बांड बैंक की टियर II पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक का अंकित मूल्य रु 10 लाख है, जिसमें 6.24 प्रतिशत प्रति वर्ष की कूपन दर है जो 10 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रूप से देय है। • 5 साल बाद और उसके बाद वर्षगांठ पर कॉल का विकल्प है। • कॉल ऑप्शन का मतलब है कि बांड जारीकर्ता निवेशकों को मूल राशि का भुगतान करके परिपक्वता तिथि से पहले बांड को वापस बुला सकता है।
स्टार्ट-अप इंडिया इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए फंड ऑफ फंड्स	**ख़बरों में क्यों :** हाल ही में भारत सरकार ने 88 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के लिए स्टार्टअप इंडिया निवेश के लिए फंडों के फंड के तहत 7,385 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की, एआईएफ द्वारा 720 स्टार्टअप्स की सहायता की गई। **इसके बारे में:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत 2016 में स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) लॉन्च किया गया था। • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है। इसने ड्रॉडाउन में तेजी लाने के लिए कई सुधार किए हैं। • **निधियों का संग्रह:** FFS की 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ की गई थी, जिसे DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बजटीय समर्थन के माध्यम से बनाया जाएगा। • **कार्यप्रणाली:** FFS सेबी पंजीकृत एआईएफ का समर्थन करता है, जो बदले में स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। **महत्व:** • इसने विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करने और घरेलू एवं नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने के मामले में भी एक उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। • सृजित नवोन्मेषणों की सफलता से उत्पन्न रिटर्न भारत के भीतर ही रहेगा तथा रोजगार पैदा करने और संपदा के सृजन को सुगम बनाएगा। • एफएफएस के माध्यम से सहायता प्राप्त निष्पादनकारी स्टार्टअप्स वैल्यूएशन में 10 गुना से अधिक वृद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं और उनमें से कई यूनिकॉर्न का दर्जा (1 बिलियन डॉलर से अधिक का वैल्यूएशन) भी अर्जित कर रहे हैं। • एफएफएस के माध्यम से वित्त पोषित कुछ उल्लेखनीय स्टार्टअप्स में डुंजो, क्योरफिट, फ्रेशटूहोम, जम्बोटेल, अनएकेडैमी, यूनिफोर, वोगो, जोस्टेल, जेटवर्क आदि शमिल हैं। **वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के बारे में:** • वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) एक सार्वजनिक रूप से जमा निवेश साधन है जो जटिल/परिष्कृत निवेशकों से

	धन एकत्र करता है। वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में अनिवासी भारतीयों से धन जुटाया जा सकता है। **आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में एआईएफ के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकते हैं,** • श्रेणी I AIF: वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड सहित), एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड • श्रेणी II AIF • श्रेणी III AIF • फंड ऑफ फंड्स स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने के बजाय अन्य निवेश फंडों के पोर्टफोलियो को रखने की एक निवेश रणनीति है। AIF के संदर्भ में, फंड ऑफ फंड एक एआईएफ है जो दूसरे एआईएफ में निवेश करता है।
माल्थसियन जनसंख्या ट्रैप (Malthusian trap)	**खबरों में क्यों :** माल्थस के विचार को अक्सर आधुनिक पर्यावरणविदों और अन्य लोगों द्वारा उद्धृत किया गया है जो मानते हैं कि बढ़ती मानव आबादी पृथ्वी के संसाधनों पर निरंतर दबाव डालता है। **माल्थसियन ट्रैप के बारे में:** • माल्थसियन ट्रैप जनसंख्या का एक सिद्धांत है जो कहता है कि जैसे-जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती है, पृथ्वी के संसाधनों पर असंधारणीय दबाव होता है, जो बदले में जनसंख्या में और वृद्धि पर एक रोक के रूप में कार्य करता है। • इसका नाम अंग्रेजी अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी वर्ष 1798 की पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इस अवधारणा पर विस्तार से बताया, जिसने चार्ल्स डार्विन को भी प्रेरित किया। • जबकि किसी देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि से सामान्य आबादी के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, लाभ अस्थायी होने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि माल्थस ने तर्क दिया, भोजन की बढ़ती उपलब्धता लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी क्योंकि वे अब उन्हें खिलाने का खर्च उठा सकते हैं, इस प्रकार कुल जनसंख्या में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में गिरावट आई है। • माल्थसियन ट्रैप 1980 में साइमन-एर्लिच दांव के मूल में था। जबकि एर्लिच, माल्थस की तरह, ने तर्क दिया कि आर्थिक विकास की प्राकृतिक सीमाएं हैं; साइमन ने तर्क दिया कि एक बाजार अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अधिकार और मूल्य तंत्र ने लोगों को दुर्लभ संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और नवाचारों के साथ आने के लिए आश्चर्जनक प्रोत्साहन की पेशकश की और जनसंख्या के स्तर में वृद्धि के साथ जीवन स्तर बढ़ सकता है। **यह काम कैसे करता है:** • पूर्व-आधुनिक युग में, जब भी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, जब तक जनसंख्या का स्तर स्थिर रहा, तब तक प्रति व्यक्ति आय में कुछ समय के लिए वृद्धि हुई। • हालांकि, देश की जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में कमी आई और यह अपनी ऐतिहासिक प्रवृत्ति में वापस आ गया। • दूसरी तरफ जब भी खाद्य उत्पादन में कमी आई, तब अकाल पड़ा जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। मानव जनसंख्या में गिरावट तब तक जारी रही जब तक देश की प्रति व्यक्ति आय निर्वाह स्तर तक नहीं पहुंच गई। • किसी भी तरह से, संसाधन की कमी ने मानव आबादी पर नियंत्रण रखा।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

मार्तंड मंदिर	**खबरों में क्यों :** इस साल मई में, कुछ तीर्थयात्रियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के स्मारक मार्तंड मंदिर के अंदर पूजा-अर्चना की। • इसके तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने परिसर में 'नवग्रह अष्टमंगलम पूजा' में भाग लिया। • ASI ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समारोह के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई। **मंदिर के बारे में:** मार्तंड मंदिर का निर्माण करकोटा वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने किया था, जिन्होंने 725 ईस्वी से 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। • ललितादित्य ने परिहस्पोरा में अपनी राजधानी का निर्माण किया, जिसके खंडहर आज भी जीवित हैं। • विष्णु-सूर्य को समर्पित, मार्तंड मंदिर में तीन अलग-अलग कक्ष हैं- मंडप, गर्भगृह और अंतलय-शायद कश्मीर में एकमात्र तीन-कक्षीय मंदिर है। • यह मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से गांधार प्रभाव है। • कश्मीर के इतिहास का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत राजतरंगिणी है, जिसे कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, और कृति के विभिन्न अनुवादों में मार्तंड की भव्यता का वर्णन है। **स्थापत्य शैली का संगम** • मंदिर के खंडहरों से, यह स्पष्ट है कि परिसर में मूल रूप से एक चतुर्भुज प्रांगण के केंद्र में एक प्रमुख मंदिर था, जो उत्तर और दक्षिण की ओर दो छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ था। • ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय प्रांगण शुरू में पानी से भरा हुआ था। लिडार नदी से एक नहर द्वारा एक स्तर तक आपूर्ति की जाती है जो स्तंभों के आधार के लगभग एक फुट को डुबो देता है। • यह प्रांगण एक उपनिवेश से घिरा हुआ था, जो 84 स्तंभों से बना हुआ प्रतीत होता है। • मंदिर शास्त्रीय ग्रीको-रोमन, बौद्ध-गंधारन और उत्तर भारतीय शैलियों से प्रभावित है। • ललितादित्य को कन्नौज के राजा को अपने अधीन करने के लिए जाना जाता है, जो उत्तर भारतीय श्रमिकों द्वारा अपना मंदिर बनाने का एक कारण हो सकता है। **मार्तण्ड मंदिर का विध्वंस** • कई इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे सुल्तान सिकंदर 'बुतशिकन' (आइकोनोक्लास्ट) था, अन्य लोग भूकंप, मंदिर की चिनाई में दोष और मौसम की अधिकता वाले क्षेत्र में समय के सरल मार्ग को दोष देते हैं। • सिकंदर को जिम्मेदार ठहराने वाले मुख्य स्रोतों में से एक कवि-इतिहासकार जोनाराजा का काम है जिन्होंने 'द्वितीय', या दूसरी, राजतरंगिणी लिखी थी। • ऐसी रिपोर्टें हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि मंदिर भूकंप, उपयोग की जाने वाली सामग्री की भुरभुरी प्रकृति, ठंढ और बर्फ के कारण प्राकृतिक अपक्षय और उनके जोड़ों पर पत्थरों की अनुचित फिटिंग से नष्ट हो गया है। **हर्ष ने मंदिरों को क्यों तोड़ा:** • ललितादित्य के तीन शताब्दी बाद और सिकंदर से दो शताब्दी पहले एक हिंदू राजा था जो मंदिरों को नष्ट और अपवित्र करने के लिए जाना जाता था: प्रथम लोहार वंश के राजा हर्ष (1089 ईस्वी से 1101 ईस्वी)। • मंदिरों के विरुद्ध हर्ष के कार्यों का धर्म से कोई लेना-देना नहीं था - वह केवल एक धूर्त राजा था, जिसके पास पैसे नहीं थे और उसने खजाने के लिए और मूर्तियों की कीमती धातुओं के लिए मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया था। • हालांकि, हर्ष ने मार्तंड मंदिर को बख्शा (spared) है, जहां कुछ साल पहले उसके पिता ने अंतिम सांस ली थी।
हैदराबाद मुक्ति दिवस	**खबरों में क्यों :** केंद्र ने 17 सितंबर को हैदराबाद राज्य मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है। • तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। **इतिहास और महत्व:** • भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से भी अधिक समय बाद, 17 सितंबर, 1948 को, तत्कालीन हैदराबाद राज्य, जिसमें पूरे तेलंगाना राज्य और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिले शामिल थे, निज़ाम के

	शासन से आजाद हुआ। • ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल की त्वरित और समय पर कार्रवाई के कारण यह संभव हुआ। • उपनिवेशवाद, सामंतवाद और निरंकुशता के खिलाफ तत्कालीन हैदराबाद राज्य के लोगों का संघर्ष राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। **ऑपरेशन पोलो** • हालाँकि, स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर ने केवल एक वर्ष के लिए शांति सुनिश्चित की। • लगभग तुरन्त ही, हैदराबाद ने शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ रजाकारों की हिंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। अंतिम उपाय के रूप में, भारत ने सितंबर 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' शुरू किया और हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए पांच दिनों के भीतर विद्रोही ताकतों को पराजित कर दिया। **तेलंगाना विद्रोह:** • तेलंगाना विद्रोह किसानों के एक समूह द्वारा 1945 के अंत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया गया था, जहां कुछ अधिकारियों में राजस्व एकत्र करने और कुछ भूमि जोतों को नियंत्रित करने की शक्ति स्थापित की गई थी। • यह कॉमरेड्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध थे, विद्रोह हिंसक हो गया और कासिम रिज़वी के नेतृत्व वाले मिलिशिया रजाकारों से भिड़ गया। • वर्ष 1945 में हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने के लिए कई शर्तें रखीं - ये सभी भारतीय राज्य को अस्वीकार्य थीं। • इस बीच, कासिम रिजवी और उनके रजाकार शीघ्रता से हावी हो गए, हैदराबाद में इस उपस्थिति को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। • उसने निजाम के सभी बड़े फैसलों को प्रभावित किया और अपने चुने हुए लोगों को सरकार में स्थापित किया। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि हैदराबाद की पहले से बिगड़ते कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब न हो, भारत ने हैदराबाद के साथ स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि निज़ाम और ब्रिटिश क्राउन के बीच होने वाले सभी प्रशासनिक समझौते निज़ाम और भारत के बीच जारी रहेंगे।
वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई	**खबरों में क्यों :** प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ.चिदंबरम पिल्लै को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। **वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई के बारे में** • वल्लिनयागम ओलागनाथन चिदंबरम पिल्लई (VOC) का जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्टापिडारम में एक प्रख्यात वकील ओलागनाथन पिल्लई और परमी अम्माई के घर हुआ था। • चिदंबरम पिल्लई ने कैलडवेल कॉलेज, तूतीकोरिन से स्नातक किया। अपनी कानून की पढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने एक संक्षिप्त अवधि के लिये तालुक कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम किया। **राजनीति में प्रवेश:** • चिदंबरम पिल्लई ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया। • वर्ष 1905 के अंत में चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास का दौरा किया और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े गए। • चिदंबरम पिल्लई रामकृष्ण मिशन की ओर आकर्षित हुए और सुब्रमण्यम भारती तथा मांडयम परिवार के संपर्क में आए।

	• तूतीकोरिन (वर्तमान थूथुकुडी) में चिदंबरम पिल्लई के आने तक तिरुनेलवेली ज़िले में स्वदेशी आंदोलन ने गति प्राप्त करना शुरू नहीं किया था। **स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:** • 1906 तक चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी (एसएसएनसीओ) के नाम से एक स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन स्थापित करने के लिये तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का समर्थन हासिल किया। • उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्मसंग नेसावु सलाई, राष्ट्रीय गोदाम, मद्रास एग्रो-इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और देसबीमना संगम जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की। • चिदंबरम पिल्लई को उनके प्रयासों हेतु तिरुनेलवेली स्थित कई वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने स्वदेशी संगम या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' नामक एक संगठन का गठन किया। • तूतीकोरिन कोरल मिल्स की हड़ताल (1908) की शुरुआत के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक द्वितीयक चरित्र प्राप्त कर लिया। • गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह (1917) से पहले भी चिदंबरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मज़दूर वर्ग का मुद्दा उठाया था और इस तरह वह इस संबंध में गांधीजी के अग्रदूत रहे। • चिदंबरम पिल्लई ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर 9 मार्च, 1908 की सुबह बिपिन चंद्र पाल की जेल से रिहाई का जश्न मनाने और स्वराज का झंडा फहराने के लिये एक विशाल जुलूस निकालने का संकल्प लिया। **कृतियाँ:** मेयाराम (1914), मेयारिवु (1915), एंथोलॉजी (1915), आत्मकथा (1946), थिरुकुरल के मनकुदावर के साहित्यिक नोट्स के साथ ((1917)), टोल्कपियम के इलमपुरनार के साहित्यिक नोट्स के साथ (1928)। **मृत्यु:** चिदंबरम पिल्लई की मृत्यु 18 नवंबर, 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस कार्यालय तूतीकोरिन में उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हुई।
मोहन जोदड़ो (Mohenjo-Daro)	**खबरों में क्यों :** हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ ने मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल (archaeological site) पर भारी तबाही मचाई है। **मोहन जोदड़ो** • यह सुक्कुर शहर से लगभग 80 किमी दूर स्थित 5000 साल पुराना पुरातात्विक स्थल है । • इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष शामिल हैं। • मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है 'मृतकों का टीला', यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था। • वर्ष 1920 तक, जब पुरातत्वविद् आरडी बनर्जी ने इस स्थल का दौरा किया तो इस शहर के खंडहर लगभग 3,700 वर्षों तक बिना दस्तावेज के बने रहे। • यह सिन्धु नदी के दाएं किनारे पर है। • महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यह 612 मीटर लंबी ईंट की कृति है। • मोहनजोदड़ो काल के सबसे बड़े निर्माण की खोज की गई है: एक अन्न भंडार। इस अन्न भंडार में विभिन्न आकार और आकार के 27 कक्ष हैं। • मोहनजोदड़ो में एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना असेंबली हॉल है, जो एक चौकोर खंभों वाला हॉल है जिसकी माप 90X90 फीट है। विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यह खंभों वाला हॉल एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में कार्य करता था। **उल्लेखनीय कलाकृतियाँ:** • हाथीदांत, लैपिस, कारेलियन, और सोने के मोतियों के साथ-साथ पकी हुई-ईंट शहर की इमारतें, शहर की समृद्धि और प्रमुखता को प्रदर्शित करती हैं। • IVC की सबसे आकर्षक आकृतियों में से एक है 'देवी माँ' शीर्षक वाली मूर्ति। • पुजारी-राजा मोहनजोदड़ो, एक नष्ट कांस्य युग शहर में खोजे गए एक छोटे से आदमी की आकृति की एक स्टेटाइट मूर्ति है। • नृत्य करती हुई लड़की या डांसिंग गर्ल (Dancing girl) एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्तिकला है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता शहर मोहनजो-दड़ो में लगभग 2300-1750 ईसा पूर्व लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में बनाया गया था। • पशुपति मुहर, जिसके लिए अक्सर "तथाकथित" शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक स्टीटाइट मुहर (steatite

seal) है।

मोहनजोदड़ो का पतन:

- साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो ने न केवल निकट आने वाली सिंधु के कारण, असामान्य गहराई और अवधि की कई गंभीर बाढ़ें देखीं।
- लेकिन, मोहनजोदड़ो और समुद्र के बीच संरचनात्मक उत्थान हेतु सिंधु जल निकासी तालाब में तब्दील हो गई।

क्या स्थलों को विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है?

- **ओमान में अरेबियन ओरिक्स सैंक्चुअरी:** अवैध शिकार और आवास के क्षरण पर चिंताओं के बाद वर्ष 2007 में हटा दिया गया।
- **लिवरपूल** - मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी' (यूके) - 18वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक - अपनी अग्रणी डॉक तकनीक, परिवहन प्रणालियों और बंदरगाह प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है।
- जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे वैली को एल्बे नदी के पार वाल्डश्लोएशन रोड ब्रिज के निर्माण के बाद हटा दिया गया ।

रेमन मैग्सेसे पुरुस्कार

खबरों में क्यों : रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को 64वें मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना था। हालांकि, उन्होंने अपनी पार्टी के आदेश के बाद इसे ठुकरा दिया।

रमन मैग्सेसे पुरस्कार:

- वर्ष 1958 में शुरू किया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यापक रूप से एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
- यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है।
- लोगों की सेवा, सुशासन और व्यावहारिक आदर्शवाद की मैगसेसे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन सरकार के ट्रस्टियों द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मैग्सेसे की जयंती पर दिया जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र, रेमन मैग्सेसे की छवि के साथ एक पदक एवं नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

रेमन मैग्सेसे कौन थे?

- 'रेमन डेल फिएरो मैगसेसे सीनियर' फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1953 से 1957 में एक हवाई दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रमुखता से आए जब जापानी सेना ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया, जो लगभग चार वर्षों तक अमेरिका का एक उपनिवेश था।
- दिसंबर, 1953 में, उन्हें फिलीपींस की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी से अध्यक्ष चुना गया।

साम्यवाद और मैग्सेसे के बीच की कड़ी क्या है?

- 1946 के बाद फिलीपींस युद्ध के बाद की अराजकता में डूब गया। साथ ही, इस अवधि के दौरान, पूंजीवाद के विस्तार के साथ, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई और किसान बेहाल होते गए।
- चूंकि देश संयुक्त राज्य अमेरिका का एक करीबी सहयोगी था, कई नेताओं को साम्यवाद के प्रति प्रतिबद्धता की

	घोषणा और किसान अधिकारों की मांग पर संदेह की दृष्टि से देखा गया था। • फिलीपींस की तत्कालीन सरकार ने इन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई शुरू की। • मैग्सेसे की प्रशासनिक और सैन्य नीतियों के तहत ही साम्यवाद से खतरे को निष्प्रभावी माना गया। **सूची में भारतीय विजेता:** • पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख भारतीयों में 1958 में विनोबा भावे, 1962 में मदर टेरेसा, 1966 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय, 1967 में सत्यजीत रे, 1997 में महाश्वेता देवी शामिल हैं। • हाल के वर्षों में, अरविंद केजरीवाल (2006), गूंज के अंशु गुप्ता (2015), मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन (2016), और पत्रकार रवीश कुमार (2019) ने यह पुरस्कार जीता है।
दारा शिकोह	**खबरों में क्यों :** उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह को सामाजिक समरसता का पथप्रदर्शक बताया। **दारा शिकोह के बारे में:** • वह (1615-59) शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। • उन्हें इतिहासकारों द्वारा एक "उदार मुस्लिम" के रूप में वर्णित किया जाता है जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता खोजने की कोशिश की। • उन्हें भारत में अंतर्धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। • उन्हें प्रमुख धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म की गहरी समझ और ज्ञान था। • औरंगज़ेब की तुलना में उनका सैन्य गतिविधियों पर दर्शन और रहस्यवाद की ओर झुकाव था • 1655 में, उनके पिता ने उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया, लेकिन शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद 1657 में उनके छोटे भाई औरंगज़ेब ने उन्हें हरा दिया। • 30 अगस्त, 1659 को सिंहासन के लिए एक कटु संघर्ष (a bitter struggle) में औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जब वह 44 वर्ष के थे। **कार्य :** **हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध:** • उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं, मजमा-उल-बहरीन (दो महासागरों का मिलन) और सिर्र-ए-अकबर (महान रहस्य), हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए समर्पित हैं। **भारतीय संस्कृति का प्रचार:** • उन्होंने संस्कृत और फारसी में दक्षता हासिल की, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू धार्मिक विचारों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद मिली। • उन्होंने उपनिषदों और हिंदू धर्म एवं आध्यात्मिकता के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद किया। इन अनुवादों के माध्यम से, वह हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को यूरोप और पश्चिम में ले जाने के लिए जिम्मेदार थे।
होयसला मंदिर	**खबरों में क्यों :** एक विशेषज्ञ टीम बेलूर, हलेबिड और समनाथपुर में होयसला मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने से पहले यूनेस्को को एक रिपोर्ट सौंपने से पहले इस सप्ताह का दौरा करेगी। • इसमें बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर, हलेबिड में होयसलेश्वर मंदिर (एक साथ "होयसला के पवित्र समूह") और सोमनाथपुर में 13 वीं शताब्दी के केशव मंदिर शामिल हैं। **यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए मानदंड** नामांकित साइटें "उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य" की होनी चाहिए और निम्नलिखित दस मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना चाहिए • मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए • वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, टाउन-प्लानिंग या लैंडस्केप डिज़ाइन के विकास पर, समय-समय पर या दुनिया के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर, मानवीय मूल्यों का एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान प्रदर्शित करने के लिए। • एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता जो जीवित है या जो गायब हो गई है के लिए एक अनोखी या कम से कम असाधारण साक्ष्य को सभालने के लिए। • एक प्रकार की इमारत, वास्तुशिल्प या तकनीकी कलाओं का समूह या परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना

चाहिए जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाता है।

- एक पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि-उपयोग, या समुद्र-उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए जो एक संस्कृति (या संस्कृतियों) का प्रतिनिधि है, या पर्यावरण के साथ मानव संपर्क खासकर जब यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन के प्रभाव में असुरक्षित हो गया है।
- घटनाओं या जीवित परंपराओं, विचारों या विश्वासों, उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के साथ प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से जुड़ा हो।
- उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाओं या असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य महत्व के क्षेत्रों को समाहित करने के लिए।
- पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण होने के लिए, जिसमें जीवन का रिकॉर्ड, भू-आकृतियों के विकास में महत्वपूर्ण चल रही भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, या महत्वपूर्ण भू-आकृति या भौगोलिक विशेषताएं शामिल हैं
- स्थलीय, ताजे पानी, तटीय तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और पौधों तथा जानवरों के समुदायों के उत्थान तथा विकास में चल रहे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण के लिए।
- जैविक विविधता के यथावत संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक प्राकृतिक आवास शामिल करने के लिए, जिनमें विज्ञान या संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की खतरे वाली प्रजातियां शामिल हो।

होयसल वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं:

- द्रविड़ और नागर शैलियों के समामेलन के कारण होयसल मंदिर संकर या वेसर शैली के मंदिर हैं।
- एक केंद्रीय खंभों वाले हॉल के चारों ओर समूहित विभिन्न देवताओं के कई मंदिर।
- तारामंडल योजना जिसमें मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया जाता है।
- सॉफ्ट सोपस्टोन मुख्य निर्माण सामग्री है।
- मूर्तियों के माध्यम से मंदिर की सजावट - दोनों आंतरिक और बाहरी दीवारों, यहां तक कि देवताओं द्वारा पहने गए आभूषणों के टुकड़े भी प्रभावी रूप से उकेरे गए थे।
- उठा हुआ मंच जिसे जगती के नाम से जाना जाता है।
- मंदिर की दीवारें और सीढ़ियां टेढ़े-मेढ़े पैटर्न का अनुसरण करती हैं।

कर्नाटक के सोमनाथपुर का चेन्नाकेशव मंदिर

- यह कावेरी नदी के तट पर एक वैष्णव हिंदू मंदिर है।
- मंदिर का निर्माण 1258 ई. में होयसल राजा नरसिंह III के एक सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा किया गया था।
- अलंकृत मंदिर होयसल वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है।
- मंदिर छोटे मंदिरों (क्षतिग्रस्त) के खंभे वाले गलियारे के साथ एक आंगन में घिरा हुआ है।
- केंद्र में मुख्य मंदिर तीन सममित गर्भगृहों (गर्भगृह) के साथ एक ऊँचे तारे के आकार के मंच पर है। गर्भगृह कई स्तंभों के साथ एक सामान्य सामुदायिक हॉल (सभा-मंडप) साझा करते हैं।
- बाहरी दीवारों, भीतरी दीवारों, स्तंभों और मंदिर की छत को हिंदू धर्म की धार्मिक प्रतिमा के साथ जटिल रूप से उकेरा गया है और रामायण, महाभारत और भागवत पुराण को प्रदर्शित करता है।

स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICOMOS):

- यह एक पेशेवर संघ है जो दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करता है।
- फ्रांस के चारेनटन-ले-पोंट में मुख्यालय, ICOMOS की स्थापना 1965 में वारसॉ में 1964 के वेनिस चार्टर के परिणामस्वरूप की गई थी, और विश्व धरोहर स्थलों पर यूनेस्को को सलाह प्रदान करता है।
- उद्देश्य: "ब्लू शील्ड" के तहत ऐतिहासिक इमारतों की बहाली और युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं से खतरे में पड़ी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना; जिनमें से ICOMOS एक भागीदार और संस्थापक सदस्य है।

आचार्य विनोबा भावे

संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती (11 सितंबर) पर श्रद्धांजलि दी।

	विनोबा भावे के बारे में: • विनोबा भावे (1895-1982) एक भारतीय राष्ट्रवादी और समाज सुधार नेता थे। • भावे का सबसे उल्लेखनीय योगदान भूदान (भूमि उपहार) आंदोलन का निर्माण था। • उनका जन्म बंबई के दक्षिण में गागोडे गांव में एक उच्च पदस्थ चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। **भावे और महात्मा गांधी:** • महात्मा गांधी द्वारा विनायक भावे का नाम बदलकर स्नेही संक्षिप्त "विनोबा" रखा गया था। • वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। • वह कुछ समय के लिए गांधी के साबरमती आश्रम में एक झोपड़ी में रहे, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया, 'विनोबा कुटीर'। • वर्ष 1940 में उन्हें गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही (सामूहिक कार्रवाई के बजाय सत्य के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति) के रूप में चुना गया था। **सर्वोदय और भूदान आंदोलन:** • भावे ने एक गाँव में रहने वाले औसत भारतीय के जीवन का अवलोकन किया और उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जिनका सामना उन्होंने एक मजबूत आध्यात्मिक नींव के साथ किया। • यह उनके सर्वोदय आंदोलन का मूल बना। • इसका एक अन्य उदाहरण 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली में शुरू हुआ भूदान (भूमि उपहार) आंदोलन है। • वह देश भर में घूम-घूमकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। • उन्होंने गोहत्या पर कड़ा रुख अपनाया और इसके प्रतिबंधित होने तक उपवास करने की घोषणा की। **पुरस्कार:** • विनोबा भाबे वर्ष 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। • उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। **साहित्यिक कार्य:** • उन्होंने "कन्नड़" लिपि को "विश्व लिपियों की रानी" कहा। • • उन्होंने कई धार्मिक और दार्शनिक कार्यों का संक्षिप्त परिचय और आलोचनाएँ लिखीं, जैसे: ○ भगवद गीता, ○ आदि शंकराचार्य के कार्य, ○ बाइबिल ○ कुरान • भावे ने भगवद गीता का मराठी में अनुवाद किया था।
स्वामी विवेकानंद	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के साथ "विशेष संबंध" विनोबा भावे जयंती को याद किया, यह देखते हुए कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति ने 1893 में इस दिन शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। **स्वामी विवेकानंद के बारे में:** • उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जोर दिया, और उनका प्रसिद्ध भाषण वही है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में दिया था (विश्व धर्मों की संसद)। • वर्ष 1984 में भारत सरकार ने घोषणा की कि 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। **प्रारंभिक जीवन- योगदान:** • 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद को उनके पूर्व-मठवासी जीवन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। • उन्हें योग और वेदांत के हिंदू दर्शन को पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। • नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था। • वर्ष 1893 में, खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध करने के बाद उन्होंने

	'विवेकानंद' नाम लिया। • उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया था "एक ऐसी मशीनरी को गति देने के लिए जो सबसे गरीब और तुच्छ (meanest) लोगों के दरवाजे तक महान विचारों को लाएगी।" • 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया। • उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, पश्चिमी दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या, और भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास किया। • **मृत्यु:** वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। **उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें:** • 'राज योग', 'ज्ञान योग', 'कर्म योग' उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं।
अन्नाभाऊ साठे (Annabhau Sathe)	**संदर्भ:** महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री मॉस्को में ऑल-रूस स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर में लोक शाहिर (बैलाडर) अन्नाभाऊ साठे की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 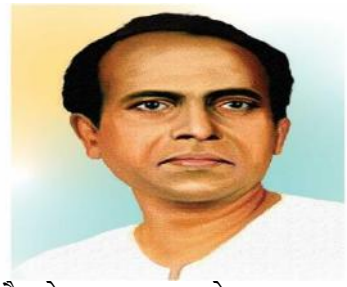 **कौन थे अन्नाभाऊ साठे?** • तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें बाद में अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाने लगा था उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वटेगांव गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। • वर्ष 1934 में, मुंबई में लाल बावटा मिल वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों की हड़ताल हुई जिसमें उन्होंने भाग लिया। • माटुंगा श्रम शिविर में अपने दिनों के दौरान, उन्होंने महाड में प्रसिद्ध 'चावदार झील' सत्याग्रह में डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर के सहयोगी आरबी मोरे को जाना और श्रम अध्ययन मंडल में शामिल हो गए। • दलित होने के कारण उन्हें उनके गांव में स्कूली शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इन अध्ययन मंडलियों के दौरान ही उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। **उन्होंने गाने, गाथागीत और किताबें लिखना कैसे शुरू किया?** • साठे ने अपनी पहली कविता श्रमिक शिविर में मच्छरों के खतरे पर लिखी थी। • उन्होंने दलित युवक संघ, एक सांस्कृतिक समूह का गठन किया और मज़दूरों के विरोध आंदोलनों पर कविताएँ लिखना शुरू की। • प्रेमचंद, फैज अहमद फैज, मंटो, इस्मत चुगताई, राहुल सांकृत्यायन, मुल्कराज आनंद जैसे सदस्यों के साथ एक ही समय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया गया था। • वर्ष 1939 में उन्होंने अपना पहला गाथागीत 'स्पेनिश पोवाड़ा' लिखा। **उनका काम कितना लोकप्रिय था?** • 'अकलेची गोष्ठा', 'स्टेलिनग्रादचा पोवाड़ा', 'माझी मैना गवावर रहीली', 'जग बादल घलूनी घाव' जैसी उनकी कई रचनाएँ राज्य भर में लोकप्रिय थीं। • बंगाल के अकाल पर उनकी 'बंगालची हक' (बंगाल की पुकार) का बंगाली में अनुवाद किया गया और बाद में लंदन के रॉयल थियेटर में प्रस्तुत किया गया। • वर्ष 1943 में, उन्होंने अमर शेख और दत्ता गावंकर के साथ मिलकर लाल बवता कला पाठक का गठन किया। समूह ने जाति अत्याचार, वर्ग संघर्ष और मज़दूरों के अधिकारों पर कार्यक्रम करने शुरू करते हुए पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया • वर्ष 1943 में, वह उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसके कारण इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) का गठन हुआ। वर्ष 1949 में वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

	उनका रूसी संबंध क्या था? • वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सदस्य थे, और भारत के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल थे जिनके कार्य का रूसी में अनुवाद किया गया था। • साठे का साहित्य तत्कालीन साम्यवादी रूसी साहित्य से निकटता से संबंधित है जो वास्तविकता और कला का मिश्रण था। • उनके छह उपन्यासों को फिल्मों में बदल दिया गया और कई का रूसी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया (चित्रा या स्टेलिनग्राद युद्ध की लड़ाई पर उनका प्रसिद्ध स्टेलिनग्राचा पोवाड़ा)। • अपने यात्रा वृतांत 'माझा रशियाचा प्रवास' (रूस की मेरी यात्रा) में, वह लिखते हैं कि कार्यकर्ता उन्हें विदा करने आए थे और वे चाहते थे कि वे कैसे रूस की झुग्गियों को देखें और उनके घर लौटने के बाद उनका वर्णन करें।
अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर	**खबरों में क्यों :** हाल ही में रिलीज़ हुई मलयालम फिल्म पथोनपथम नूट्टंडु ('उन्नीसवीं सदी') अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर के जीवन पर और 19वीं शताब्दी में केरल में सामाजिक सुधार से जुड़े नांगेली और कायमकुलम कोचुन्नी की कहानियों पर आधारित है, जिसके कारण राज्य में मौजूदा जाति पदानुक्रम और सामाजिक व्यवस्था बड़े पैमाने परध्वंस हुआ। **अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर के बारे में:** • वह केरल में एझावा समुदाय के एक समाज सुधारक थे जो 19वीं शताब्दी में रहते थे। • उनका जन्म केरल के अलाप्पुझा जिले में व्यापारियों के एक संपन्न परिवार में हुआ था। • राज्य में सुधार आंदोलन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, उन्होंने उच्च जातियों या 'सवर्णों' के वर्चस्व को चुनौती दी तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के जीवन में बदलाव लाए। **पनिकर का योगदान:** • 1852-54 में केरल के गांवों में हिंदू भगवान शिव को समर्पित दो मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति थी। • केरल के पिछड़े समुदायों की महिलाओं के अधिकारों के लिए विरोध किया। • पनिकर कलारीपयट्टू के उस्ताद थे, केरल में प्रचलित पारंपरिक मार्शल आर्ट, जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना भी माना जाता है। • नांगेली (Nangeli) एक एझावा महिला थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 19वीं शताब्दी में अलाप्पुझा में रहती थी। उसने कथित तौर पर निचली जातियों की महिलाओं पर त्रावणकोर साम्राज्य द्वारा लगाए गए 'स्तन कर' (Breast Tax) का विरोध करने के लिए अपने स्तन काट दिए। ब्रेस्ट टैक्स के अनुसार - निचली जातियों की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने की अनुमति नहीं थी और ऐसा करने पर उन पर भारी कर लगाया जाता था। • कायमकुलम कोचुन्नी, 19वीं सदी के अलाप्पुझा में रॉबिन हुड जैसी आकृति, उनके लिए समर्पित एक मंदिर और एक छोटा संग्रहालय भी है।
पेरियार ई.वी. रामासामी	**संदर्भ:** हम पेरियार ई.वी. रामासामी की जयंती (17 सितंबर) को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। **पेरियार के बारे में:** • ई.वी. रामास्वामी नायकर का जन्म 1879 में तमिलनाडु (TN) के इरोड जिले में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग भोजन के सवाल पर गांधी से झगड़ा किया। • उन्होंने वर्ष 1925 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और खुद को जस्टिस पार्टी और आत्म सम्मान आंदोलन से जोड़ा, जिसने सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया, खासकर नौकरशाही का। • वर्ष 1924 के वैकोम सत्याग्रह के दौरान पेरियार की ख्याति तमिल क्षेत्र से बाहर फैल गई, यह मांग करने के लिए एक जन आंदोलन था कि निचली जाति के लोगों को प्रसिद्ध वैकोम मंदिर के सामने एक सार्वजनिक मार्ग का उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। बाद में उन्हें वैकोम वीरार (वाइकोम का हीरो) कहा जाने लगा। • वर्ष 1940 के दशक में, पेरियार ने एक राजनीतिक दल, द्रविड़ कज़गम (डीके) की शुरुआत की, जिसने तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषियों वाले एक स्वतंत्र द्रविड़ नाडु का समर्थन किया। • • पेरियार का वर्ष 1973 में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्षों से, पेरियार को आधुनिक तमिलनाडु के पिता के रूप में थंथई पेरियार के रूप में सम्मानित किया जाता है।

	आत्म सम्मान आंदोलन के बारे में : • आत्म-सम्मान आंदोलन एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में नष्ट करना और जाति, धर्म और ईश्वर के बिना एक नया, तर्कसंगत समाज बनाना था। • इस आंदोलन की शुरुआत 1925 में तमिलनाडु में हुई थी। ○ यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं के पुनरोद्धार की विचारधाराओं का प्रचार किया। **सामाजिक न्याय और पेरियार:** • सामाजिक न्याय यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य हर किसी के लिए पहुंच और अवसर के दरवाजे खोलना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। • सामाजिक न्याय और तर्कसंगतता अधिकांश लोगों के लिए "सत्य का सर्वोत्तम संभव संस्करण" परिभाषित करती है। (कारण या तर्क के आधार पर या उसके अनुसार होने का गुण।) **तर्कवाद की नींव (Foundation of rationalism):** • पेरियार का दृष्टिकोण समावेशी विकास और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में था। उन्होंने तर्कवाद को इन पंक्तियों के साथ सोचने के लिए एक ठोस आधार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "बुद्धि सोच में निहित है। सोच का आधार तर्कवाद है। ” • पेरियार ने कहा, "कोई भी विरोध जो तर्कवाद या विज्ञान या अनुभव पर आधारित नहीं है, एक न एक दिन धोखाधड़ी, स्वार्थ, झूठ और साजिशों को उजागर करेगा।" हम इसे देश भर में और कभी-कभी विदेशों में भी हो रही अति-दक्षिणपंथी गतिविधियों के संबंध में कह सकते हैं। • उन्होंने लोगों के साथ साझा किए गए सभी सुधारों को उस समय लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उनके द्वारा की गई गंभीर चर्चाओं के कारण। ऐसा ही एक सुधार उपाय उन्होंने महसूस किया कि समाज में जाति की गतिशीलता को बदलने के लिए 'सभी जातियों के लिए प्रीस्टहुड' था।
सालार जंग संग्रहालय (Salar Jung Museum)	**खबरों में क्यों :** 14वीं सदी की औपचारिक तलवार जो 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद में एक ब्रिटिश जनरल को बेची गई थी, को भारत में वापस लाने की तैयारी की जा रही है। • साँप के आकार की तलवार में दाँतेदार किनारे और दमिश्क पैटर्न है, जिसमें हाथी-बाघ की सोने की नक्काशी हुई है। • तलवार का प्रदर्शन हैदराबाद के निज़ाम महबूब अली खान, आसफ जाह VI (वर्ष 1896-1911) द्वारा दिल्ली या इंपीरियल दरबार में वर्ष 1903 में किया गया था, जो भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राजा एडवर्ड सप्तम और रानी एलेक्जेंड्रा के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित एक औपचारिक स्वागत समारोह था। • तलवार को वर्ष 1905 में बॉम्बे कमांड के कमांडर-इन-चीफ, जनरल सर आर्चीबाल्ड हंटर द्वारा (1903-1907) महाराजा किशन प्रसाद जो हैदराबाद के बहादुर यामीन उस-सुल्तान के प्रधानमंत्री थे, से खरीदा गया था। • किशन प्रसाद को उनकी उदारता के लिये जाना जाता था, वहीँ उन्हें अपनी मोटरकार का पीछा करने वाले लोगों के लिये सिक्के लुटाने हेतु भी जाना जाता था। **सालार जंग संग्रहालय का इतिहास:** • सालार जंग संग्रहालय वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था और यह भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में मुसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। • परिवार दक्कन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक है, उनमें से पांच हैदराबाद-दक्कन के तत्कालीन निजाम शासन में प्रधान मंत्री रहे हैं। • नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें सालार जंग III के नाम से जाना जाता है, को 1912 में नवाब मीर उस्मान अली खान निजाम VII द्वारा प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। • एक संग्रहालय के रूप में संग्रह को 1951 में दीवान देवदी, स्वर्गीय सालार जंग के घर में खुला घोषित किया गया था और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जनता के लिए खोला गया था।

	• बाद में भारत सरकार ने परिवार के सदस्यों की सहमति से एक समझौता विलेख के माध्यम से संग्रहालय को औपचारिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया और संग्रहालय को वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया गया। • अंत में, 1961 में, "संसद के अधिनियम" के माध्यम से सालार जंग संग्रहालय को अपने पुस्तकालय के साथ "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया था।
अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट	**खबरों में क्यों :** हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की जिसमें डॉ. भीम राव अंबेडकर से संबंधित पाँच प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। **पांच प्रमुख स्थल - "पंचतीर्थ"** • **महू:** उनका जन्मस्थान • **नागपुर:** जहां उन्होंने पढ़ाई की • **लंदन:** जहां उन्होंने रहा और अध्ययन किया • **दिल्ली:** जहां उनका निधन हुआ • **मुंबई:** यह उनका अंतिम संस्कार का स्थान **अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों को मान्यता** • **रायगढ़ (महाराष्ट्र):** महाराष्ट्र का रायगढ़ ज़िला, जहाँ डॉ. अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, दलितों के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक ○ 20 मार्च, 1927 को ○ महाडी में अछूतों को सार्वजनिक तालाब में पानी का उपयोग करने की अनुमति देना • पुणे, महाराष्ट्र: जहां उन्होंने यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ पहली बार बातचीत की थी। ○ वर्ष 1932 में ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल पर। ○ इसी का परिणाम दलित वर्गों की ओर से डॉ अंबेडकर द्वारा और उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित पूना पैक्ट था। • **कोल्हापुर, महाराष्ट्र:** कोल्हापुर, जहाँ मार्च 1920 में एक और महान समाज सुधारक छत्रपति शाहूजी महाराज ने डॉ अंबेडकर को भारत में उत्पीड़ित वर्गों के सच्चे नेता के रूप में घोषित किया। मार्च 2020 इस आयोजन का शताब्दी वर्ष है। • श्रीलंका, जहाँ उन्होंने एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया, के बारे में कहा जाता है कि इसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिये प्रभावित किया।
सित्तनवासल जैन विरासत स्थल	**खबरों में क्यों :** तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सित्तनवासल रॉक गुफा मंदिर में तीन-चौथाई कला या तो क्षतिग्रस्त या तोड़-फोड़ हो गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षण के उपाय किए हैं और सार्वजनिक पहुंच को ट्रैक करने के लिए डिजिटल जांच भी शुरू की है। **गुफाओं के बारे में:** • सित्तनवासल गुफाएँ (Sittanavasal Caves) या अरिवर कोइल (Arivar Koil) भारत के तमिल नाडु राज्य के पुदुकोट्टई ज़िले के सित्तनवासल गाँव में स्थित एक द्वितीय शताब्दी में निर्मित एक तमिल श्रमण परिसर है। • सित्तनवासल नाम का उपयोग उस गाँव और पहाड़ी के लिए किया जाता है जिसमें अरिवार कोविल (अरिहत का मंदिर – जैन जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी), 'एझादिपट्टम' (17 पॉलिश रॉक बेड के साथ एक गुफा), मेगालिथिक दफन स्थल और नवचुनई तरन (छोटी पहाड़ी झील) एक जलमग्न मंदिर के साथ अवस्थित हैं। • तमिलनाडु में यह एकमात्र स्थान है जहां पांड्या चित्रों को देखा जा सकता है। • स्थल और कला का उल्लेख सबसे पहले स्थानीय इतिहासकार एस. राधाकृष्णन अय्यर ने अपनी 1916 की पुस्तक पुदुकोट्टई राज्य के सामान्य इतिहास में किया था। **कलाकृति के बारे में:** • गर्भगृह की छत और अरिवार कोविल के अर्ध मंडपम पर कलाकृतियां, चौथी से छठी शताब्दी के बाद के अजंता गुफा चित्रों का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जिसे फ्रेस्को-सेको तकनीक (दीवार पर गीले प्लास्टर का उपयोग) का उपयोग करके किया जाता है।

	• छत की पेंटिंग में 'भव्यास (bhavyas)' (मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं) कमल से भरे कुंड में आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। • 'अर्ध मंडपम' के खंभों पर नाचती हुई लड़कियों की बेहोश रूपरेखा। • बरामदे के स्तंभ (1900 के दशक में तत्कालीन दीवान अलेक्जेंडर टोटेनहम के कहने पर पुदुकोट्टई के महाराजा द्वारा जोड़े गए), कुडुमियानमलाई से लाए गए थे। • रंग पौधे के रंगों और खनिज तत्वों जैसे चूना, दीपक काला, और मिट्टी के रंगद्रव्य जैसे पीले रंग के लिए गेरू और भूरे-हरे रंग के रंगों के लिए टेरे वर्टे का मिश्रण होते हैं। • डिजाइन तत्व शैव तीर्थ के रूप में इसके पहले के संभावित अस्तित्व का संकेत देते हैं। • तीसरी शताब्दी ईस्वी के ब्राह्मी और 'वट्टाएजुथु' के शिलालेख यहां मौजूद हैं। जैन भिक्षु इलान-गौतमन के नौवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक तमिल शिलालेख, परिसर के अंदर हैं। • पुदुकोट्टई जिले के 20 गुफा मंदिरों में से 19 हिंदू धर्म की शैव और वैष्णव धाराओं से संबंधित हैं; मूर्तियों वाला सित्तनवासल एकमात्र जैन मंदिर है।
प्राचीन पौधा सिलफियोन	**संदर्भ:** एक रामबाण दवा (cure-all) के रूप में माना जाने वाला 'सिल्फ़ियन' (Silphion) नामक एक भूमध्यसागरीय औषधीय पौधा लगभग 2,000 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एक हालिया अध्ययन में किए गए दावे के अनुसार- यह औषधीय पौधा अभी भी आसपास मौजूद हो सकता है। **सिल्फ़ियन का प्राचीन उपयोग:** • 'सिल्फ़ियन' (Silphion) की राल का बड़े पैमाने पर मसाले, इत्र, कामोद्दीपक, गर्भनिरोधक और दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। • यह पौधा उत्तर-पूर्वी लीबिया के निकट प्राचीन ग्रीक और बाद में रोमन उपनिवेश प्राचीन साइरेन की निर्यात अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया। • सिल्फ़ियन का उपयोग गोइटर, कटिस्नायुशूल (तंत्रिका दर्द), दांत दर्द, आंतों के विकार, हार्मोनल विकार, मिर्गी, टेटनस, पॉलीप्स (ऊतकों की असामान्य वृद्धि) और घातक ट्यूमर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया गया था। • इसके डंठल को सब्जी के रूप में खाया जाता था, जबकि जड़ों को कच्चा खाया जाता था। **पर्यावरण की स्थिति:** • इन पौधों को बीज के अंकुरण के लिए ठंडी और नम स्थितियों की आवश्यकता हो सकती है। • ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्फ़ियन से संबंधित पौधों, जैसे कि फेरुला डूडीना और फेरुला हींग को भी बीजों के अंकुरण के लिए समान पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। • तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण में वृद्धि हो सकती है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
शहीद भगत सिंह	**खबरों में क्यों :** स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया और हवाई अड्डे पर अपने दावों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। **शहीद भगत सिंह के बारे में:** • भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर, 1907 को लायलपुर, पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। • वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नायक थे। • उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो आर्य समाज द्वारा संचालित था। उन्होंने तेरह साल की उम्र में शिक्षा छोड़ दी और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। उन्होंने अमृतसर में मार्क्सवादी सिद्धांतों की वकालत करने वाले पंजाबी और उर्दू भाषा के अखबारों के लिए एक लेखक और संपादक के रूप में काम किया। • 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा, जो सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने बगीचे में मारे गए भारतीयों के खून से लथपथ मिट्टी ले ली और उसे ब्रिटिश सरकार की निर्ममता की याद दिलाने के लिए अपने पास रख लिया। **राष्ट्रवादी गतिविधियाँ:** • उन्हें "इंकलाब जिंदाबाद" ("क्रांति की जय हो") के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

	• हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अन्य ने की थी। • वर्ष 1928 में, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, सॉन्डर्स को गलती से ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जेम्स स्कॉट समझ लिया। उन्होंने साइमन कमीशन के लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मौत के लिए स्कॉट को जिम्मेदार ठहराया। • 8 अप्रैल, 1929 को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में 'बधिरों को सुनने के लिए' बम फेंके। • लाहौर षड्यंत्र मामले में, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह को एक साल की सजा हुई। मार्च 1931 में जब उन्हें फांसी दी गई तब वह लाहौर जेल में थे। • **दर्शन:** वे मिखाइल बाकुनिन की शिक्षाओं के उत्साही पाठक थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा। अपने अंतिम वसीयतनामे, "युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए" में, उन्होंने अपने आदर्श को "नए, यानी मार्क्सवादी, आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण" के रूप में घोषित किया। सिंह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य करतार सिंह सराभा को अपना नायक मानते थे। • **प्रकाशन:** मैं नास्तिक क्यों हूँ, मेरे पिता को पत्र, जेल नोटबुक
बौद्ध गुफाएं और स्तूप तथा ब्राह्मी शिलालेख	**खबरों में क्यों :** मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बौद्ध गुफाओं और स्तूपों, और ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की, जो दूसरी शताब्दी की और 9 वीं -11 वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर, और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति है। **इसके बारे में:** वराह मूर्तिकला भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कई अखंड मूर्तियों में से एक है। • **खोज में शामिल :** 26 बौद्ध गुफाएं दूसरी और 5वीं शताब्दी की हैं। गुफाओं और उनके कुछ अवशेषों में महायान बौद्ध स्थलों के विशिष्ट चैत्य (गोल) दरवाजे और पत्थर के बिस्तर प्राप्त हुए हैं। • ब्राह्मी पाठ में 24 शिलालेख, सभी दूसरी-पांचवीं शताब्दी के हैं। शिलालेखों में मथुरा और कौशाम्बी, और पावता, वेजबरदा और सपतनैरिका जैसे स्थलों का उल्लेख है। वे जिन राजाओं का उल्लेख करते हैं उनमें भीमसेना, पोथासिरी और भट्टदेव शामिल हैं। • 26 मंदिर 9वीं-11वीं शताब्दी के बीच कलचुरी काल के हैं। इसके अलावा, दो शैव मठों का भी दस्तावेजीकरण किया गया है। कलचुरी राजवंश, जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला है, सबसे पुराने एलोरा और एलीफेंटा गुफा स्मारकों से भी जुड़ा है। • गुप्त काल के कुछ अवशेष, जैसे दरवाजे की चौखट और गुफाओं में नक्काशी भी मिले हैं।
बथुकम्मा उत्सव (Bathukamma festival)	**खबरों में क्यों :** बथुकम्मा उत्सव पहली बार संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में देश की राजधानी में रहने वाले तेलुगु लोगों के साथ इंडिया गेट पर मनाया जाएगा। **इसके बारे में:** • बथुकम्मा तेलंगाना में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक रंगीन, फूलों का त्योहार है। • यह मानसून के उत्तरार्ध के दौरान, सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है। यह दशहरा से दो दिन पहले पड़ता है। • इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में 'गुनुका पूलु' और 'तांगेदु पूलु' हैं। • 'शिल्पक्का पंडलू' (या 'सीताफलालु'), कस्टर्ड सेब या 'गरीबों का सेब', इस मौसम के दौरान बहुत आकर्षण होते हैं। • फूलों को एक पीतल की प्लेट (जिसे 'ताम्बलम' कहा जाता है) में गोलाकार पंक्तियों में और वैकल्पिक रंगों में पंक्ति के बाद सावधानीपूर्वक पंक्ति में व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाता है। महिलाएं उन्हें अपने सिर पर ले

	जाती हैं और एक जुलूस के रूप में गांव या कस्बे के पास एक बड़े जल निकाय की ओर बढ़ती हैं। फिर, बथुकम्मालु 'को धीरे-धीरे पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। • फिर वे 'मालीदा' (चीनी या कच्ची चीनी और मकई की रोटी से बनी मिठाई) मिठाई बांटते हैं। • महिलाएं बथुकम्मा के साथ 'बोड्डेम्मा' (गौरी की देवी 'मां दुर्गा' की मिट्टी से बनी हुई) बनाती हैं और इसे तालाब में विसर्जित करती हैं। यह तालाबों को सुदृढ़ करने में मदद करता है और अधिक पानी बनाए रखने में मदद करता है। • त्योहार में उपयोग किए जाने वाले फूलों में तालाबों और टैंकों में पानी को शुद्ध करने का एक बड़ा गुण होता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

भूगोल

कॉफी बोर्ड	**खबरों में क्यों :** यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया के वार्षिक सम्मेलन की तर्ज पर, कॉफी बोर्ड भारतीय कॉफी के लिए एक स्थिरता कोड लेकर आया है। **कॉफी बोर्ड के बारे में:** भारत सरकार ने एक संवैधानिक अधिनियम "1942 के कॉफी अधिनियम VII" के माध्यम से 'कॉफी बोर्ड' की स्थापना की। • वर्ष 1995 तक कॉफी बोर्ड एक पूलित आपूर्ति की कॉफी का विपणन करता था। बाद में, भारत में आर्थिक उदारीकरण के कारण कॉफी मार्केटिंग एक निजी क्षेत्र की गतिविधि बन गई। • यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। • इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं, जो मुख्य कार्यकारी होता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। • **कॉफी बोर्ड की भूमिका:** कॉफी बोर्ड संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले कॉफी क्षेत्र के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मुख्य गतिविधियां विशेष रूप से अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, निर्यात प्रोत्साहन और घरेलू बाजार के विकास को समर्थन देने के लिए निर्देशित हैं। • कॉफी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बंगलौर में स्थित है। • अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। **कॉफी और इसकी कृषि के बारे में:** • यह एबिसिनिया पठार (इथियोपिया) के लिए स्वदेशी है जहां से इसे 11वीं शताब्दी में अरब ले जाया गया था। अरब से, इसके बीज 17 वीं शताब्दी में बाबा बदन गिरी द्वारा भारत लाए गए थे और कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाए गए थे। • वातावरण की परिस्थितियाँ • गर्म और आर्द्र जलवायु जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता रहता है • वर्षा: 150 से 250 सेमी. • यह पाला, हिमपात, 30°C से ऊपर के उच्च तापमान और तेज धूप को सहन नहीं करता है। यह आम तौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। • जामुन के पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक है। • रुका हुआ पानी हानिकारक होता है • और समुद्र तल से 600 से 1,600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फसल उगाई जाती है। • अच्छी जल निकासी वाली दोमट दोमट, जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस और आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, कॉफी की खेती के लिए आदर्श हैं।

	• भारत में, कॉफी पारंपरिक रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेजी से बढ़ रही है। **भारत में कॉफी की किस्में:** • कॉफी की दो मुख्य किस्में, अरेबिका (क्षेत्र का 49%) और रोबस्टा (क्षेत्र का 51%) भारत में उगाई जाती हैं। अरेबिका एक हल्की कॉफी है, लेकिन बीन्स अधिक सुगंधित होने के कारण, रोबस्टा बीन्स की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक होता है। दूसरी ओर, रोबस्टा में अधिक ताकत होती है और इसलिए, विभिन्न मिश्रणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। • अरेबिका रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। • अरेबिका कीटों और रोगों जैसे सफेद तना छेदक, लीफ रस्ट (leaf rust) आदि के लिए अतिसंवेदनशील है, और रोबस्टा की तुलना में अधिक छाया की आवश्यकता होती है। • अरेबिका की फसल नवंबर से जनवरी के बीच होती है, जबकि रोबस्टा की फसल दिसंबर से फरवरी के बीच होती है।
सोलोमन द्वीप (Solomon Islands)	**खबरों में क्यों :** हाल ही में, सोलोमन द्वीप समूह ने सभी नौसैनिक यात्राओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। **मुद्दे का मुख्य विवरण:** • अपने बंदरगाहों तक पहुंच से इनकार करने के लिए देश का कदम आदर्श से हटकर है और देश तथा क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है। • इस साल की शुरुआत में, सोलोमन द्वीप समूह ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता स्थापित किया, यह कहते हुए कि उसे अपनी घरेलू सुरक्षा स्थिति में चीन की सहायता की आवश्यकता है। • घोषणा ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोगों को झकझोर कर रख दिया था। • चिंता यह थी कि समझौता संभावित रूप से द्वीप राष्ट्र पर एक चीनी सैन्य अड्डे का नेतृत्व कर सकता है, और शक्ति-प्रक्षेपण क्षमताएं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को प्राप्त होंगी।
प्राग (Prague)	**खबरों में क्यों :** बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने में उनकी सरकार की विफलता के विरोध में चेक गणराज्य के 70,000 से अधिक नागरिक देश की राजधानी प्राग के केंद्र में एकत्र हुए। **रूस-यूक्रेन युद्ध, और प्राग क्यों मायने रखता है?** • चेक गणराज्य यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। • युद्ध शुरू होने के बाद से यह यूक्रेन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक रहा है। • इसके अलावा, यह वर्तमान में यूरोपीय संघ की रोटेशन अध्यक्षता रखता है, और इसलिए युद्ध के समय में एकता को प्रोजेक्ट करने के ब्लॉक के प्रयासों में अधिक कूटनीतिक रूप से ध्यान देने योग्य है। • अगस्त के मध्य तक, लगभग 4,13,000 शरणार्थी - देश की आबादी का लगभग 4% - चेक गणराज्य में

	पंजीकृत किए गए थे। • रूसी आक्रमण का विरोध 1968 के प्राग वसंत के ऐतिहासिक संदर्भ बिंदु से भी आता है जब सोवियत टैंक तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में घुसे और लोकतंत्र में तेजी से संक्रमण की मांग को लेकर विद्रोह को कुचल दिया।
गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र (Gogra-Hotsprings area)	**खबरों में क्यों :** भारत और चीन ने घोषणा की कि उनकी सेनाओं ने मई 2020 से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स क्षेत्र में पैट्रोलिंग पॉइंट -15 से हटना शुरू कर दिया है। **पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 और 17ए:** • भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ, भारतीय सेना को कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जहां उसके सैनिकों की पहुंच उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में गश्त करने के लिए है। • इन बिंदुओं को पेट्रोलिंग पॉइंट या पीपी के रूप में जाना जाता है। • देपसांग मैदानों जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ये गश्ती बिंदु एलएसी पर हैं, और सैनिक इन बिंदुओं तक पहुंच कर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। • यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है क्योंकि भारत और चीन के बीच की सीमा का अभी तक आधिकारिक तौर पर सीमांकन नहीं किया गया है। • PP15 और PP17A एलएसी के साथ लद्दाख में 65 गश्ती बिंदुओं में से दो हैं। • ये दोनों बिंदु ऐसे क्षेत्र में हैं जहां भारत और चीन एलएसी के संरेखण पर काफी हद तक सहमत हैं। • PP15 हॉट स्प्रिंग्स नामक क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP17A गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। 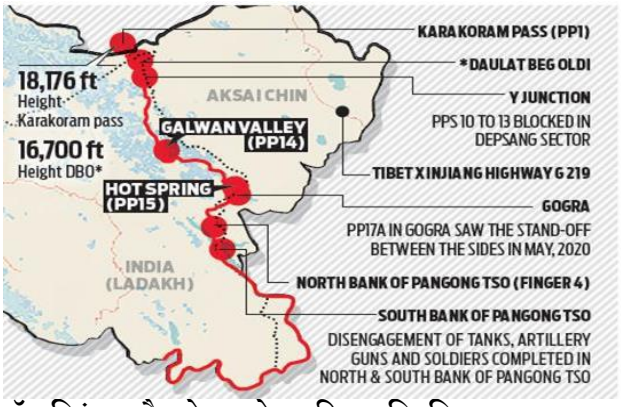 **हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट की अवस्थिति:** • हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो (Chang Chenmo) नदी के उत्तर में है और गोगरा पोस्ट इस नदी के गलवान घाटी से दक्षिण-पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ने पर बने हेयरपिन मोड़ (Hairpin Bend) के पूर्व में है। • यह क्षेत्र काराकोरम श्रेणी (Karakoram Range) के उत्तर में है जो पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण में स्थित है। **महत्त्व** • यह क्षेत्र कोंगका दर्रे (Kongka Pass) के पास है, जो मुख्य दर्रे में से एक है, जो चीन के अनुसार भारत और चीन के बीच की सीमा को चिह्नित करता है। • भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दावा पूर्व की ओर अधिक है, क्योंकि इसमें पूरा अक्साई चिन (Aksai Chin) का क्षेत्र भी शामिल है। • हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट, चीन के दो सबसे अशांत प्रांतों (शिनजियांग और तिब्बत) की सीमा के करीब हैं। **पैंगोंग त्सो झील** **गलवान घाटी** • गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है, जो गलवान नदी (Galwan River) के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। • नदी का स्रोत एलएसी के चीन की ओर अक्साई चिन में है, और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है, जहां यह एलएसी के भारत की ओर श्योक नदी (Shyok River) से मिलती है।

	• यह घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चिन के बीच स्थित है, जो वर्तमान में चीन द्वारा अपने झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में नियंत्रित है। **चांग चेनमो नदी** • चांग चेनमो नदी या चांगचेनमो नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है, जो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। • यह विवादित अक्साई चिन क्षेत्र के दक्षिणी किनारे और पैंगोंग झील बेसिन के उत्तर में है। • चांग चेनमो का स्रोत लनक दर्रे (Lanak Pass) के पास है। **कोंग्का दर्रा** • कोंग्का दर्रा या कोंग्का ला एक पहाड़ी दर्रा है, जिससे चांग चेनमो घाटी में प्रवेश किया जाता है। यह लद्दाख में विवादित भारत-चीन सीमा क्षेत्र में है। **काराकोरम श्रेणी** • काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है, जो चीन, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ फैली हुई है, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान और ताजिकिस्तान तक फैली सीमा के उत्तर पश्चिमी छोर हैं। • काराकोरम पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग गिलगित-बाल्टिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है। • सबसे ऊंची चोटी (और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची), K2, गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित है। • पश्चिम में वखान कॉरिडोर (अफगानिस्तान) से शुरू होता है, गिलगित-बाल्टिस्तान के अधिकांश हिस्से को शामिल करता है, और लद्दाख (भारत द्वारा नियंत्रित) और अक्साई चिन (चीन द्वारा नियंत्रित) तक फैला हुआ है। • भारत-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच प्लेट सीमा पर, दुनिया के सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। • हिमनदों का सर्वाधिक विकास काराकोरम श्रेणी में होता है। यह श्रेणी लगभग 16,000 वर्ग किमी या हिमालयी क्षेत्र के बर्फीले क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है।
वेम्बनाड झील	**खबरों में क्यों :** 20 साल पहले रामसर साइट घोषित होने के बावजूद वेम्बनाड झील सिकुड़ रही है और इसकी अनूठी जैव विविधता पारिस्थितिक क्षय के खतरे में है। **झील की विशेषताएं:** • यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। • वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील (कुट्टनाड में) और कोच्चि झील (कोच्चि में) के नाम से भी जाना जाता है। • यह अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम से घिरी हुई है। • यह केरल के कई जिलों में फैले और 2033.02 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र को कवर किया हुआ है। • झील का उद्गम चार नदियों मीनाचिल, अचनकोविल, पम्पा और मनीमाला में है। • यह एक संकीर्ण बाधा द्वीप द्वारा अरब सागर से अलग है और केरल में एक लोकप्रिय बैकवाटर खंड है। • वल्लम काली (यानी, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस) एक स्नेक बोट रेस है जो हर साल अगस्त के महीने में वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। • वर्ष 2002 में, इसे रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। • यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद ही भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। • भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्रभूमि की पहचान की है। • कुमारकोम पक्षी अभयारण्य (Kumarakom Bird Sanctuary) झील के पूर्वी तट पर स्थित है। • वर्ष 2019 में विलिंगडन द्वीप जो कि कोच्चि शहर में अवस्थित है, के कुछ हिस्सों को अलगकर वेम्बनाड झील का निर्माण किया गया था।
अज़रबैजान-अर्मेनियाई सीमा विवाद (Azerbaijan-	**खबरों में क्यों :** हाल ही में, नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवाद भारी संघर्षों के साथ फिर से उत्पन्न हो गया है। • आर्मेनिया और अजरबैजान ट्रांसकेशिया या दक्षिण काकेशिया का हिस्सा हैं। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी

Armenian border dispute)	एशिया की सीमा पर दक्षिणी काकेशस पर्वत के आसपास का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं। **क्या आप जानते हैं?** • नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र में 95% आबादी जातीय रूप से अर्मेनियाई है और उनके द्वारा नियंत्रित है लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मानसबल झील (Manasbal Lake)	**खबरों में क्यों :** लगभग 33 वर्षों के बाद, नौसेना ने उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है। तत्कालीन राज्य में उग्रवाद के विस्फोट के बाद तीन दशक पहले इसे बंद कर दिया गया था। • हाल ही में महिला कैडेटों सहित जम्मू-कश्मीर और बाहर के 100 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेटों ने नौकायन और बोट पुलिंग (boat pulling) जैसे अभ्यासों में भाग लिया। **मानसबल झील के बारे में:** • **स्थान:** मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सफापोरा क्षेत्र। • **विशेषताएं:** यह सुरम्य पहाड़ियों और पुराने जल के साथ मीठे पानी की झील है। नूरजहाँ द्वारा निर्मित मुगल गार्डन, जिसे जारोका बाग कहा जाता है, (जिसका अर्थ है बे विंडो) इस झील से इसका दृश्य दिखाई देता है। • **जैव विविधता:** झील पक्षियों को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। • **वनस्पति:** मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लांकटन • **जीवजंतु:** ज़ोप्लांकटन, बेंटोस और मछली • **इतिहास:** 1989 में उग्रवाद की शुरुआत के दौरान क्षेत्र में प्रशिक्षण निलंबित कर दिया गया था और इस तरह नौसेना द्वारा छोड़ दिया गया था। एनसीसी 1965 से जम्मू-कश्मीर में काम कर रही है। • **मुद्दे:** यूट्रोफिकेशन (फाइटोप्लांकटन उत्पादकता में पोषक तत्वों से प्रेरित वृद्धि) और प्रदूषण • **कश्मीर में अन्य झीलें:** डल झील, वुलर झील, तरसर-मरसर झीलें। **NCC के बारे में:** • यह एक त्रि-सेवा संगठन के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल होती हैं। • इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में हैं। • यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए ओपन है। • इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक के रूप में विकसित करना। • एनसीसी के प्रतीक में 3 रंग होते हैं- लाल, गहरा नीला और हल्का नीला। ये रंग, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं।इसमें चित्रित 17 कमल, भारत की 17 निर्देशिकाओं को दर्शाते हैं।
लौह अयस्क (Iron Ore)	**खबरों में क्यों :** सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कुछ जिलों के लिए लौह अयस्क खनन की सीमा को यह कहते हुए बढ़ा दिया कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण आर्थिक विकास की भावना के साथ-साथ होना चाहिए। **लौह अयस्क के बारे में :** • लौह अयस्क चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लोहा निकाला जा सकता है। • भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। यह विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं में होता है लेकिन प्रमुख आर्थिक निक्षेप प्रागैतिहासिक युग के तलछटी बैंडेड आयरन फॉर्मेशन (बीआईएफ) ज्वालामुखी के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। • मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लौह अयस्क है जिसमें 72 प्रतिशत तक लौह की मात्रा बहुत अधिक होती है। • इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण हैं, विशेष रूप से विद्युत उद्योग में मूल्यवान होते है।

- हेमेटाइट अयस्क उपयोग की जाने वाली मात्रा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में लोहे की मात्रा थोड़ी कम है।
- सबसे अधिक उत्पादक ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेल्लारी-चित्रदुर्ग-चिकमगलूर-तुमकुर बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हैं।

लौह अयस्क निम्नलिखित चार प्रकारों में पाया जाता है:

मैग्नेटाइट: यह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें लगभग 72% धात्विक लोहा होता है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल में पाया जाता है।

हेमेटाइट: इसमें लगभग 60-70 प्रतिशत धात्विक लोहा होता है।

- यह लाल और भूरे रंग का होता है।
- यह ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी खंड में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में इस प्रकार का अयस्क होता है।

लिमोनाइट (Limonite): इसमें लगभग 30 से 40 प्रतिशत धात्विक लोहा होता है। यह ज्यादातर पीले रंग का होता है। यह निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है।

साइडराइट (Siderite): इसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं।

- इसमें लगभग 48 प्रतिशत धात्विक लौह तत्व होता है।
- यह भूरे रंग का होता है।
- इसमें लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। यह निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है। चूने की उपस्थिति के कारण यह स्व-प्रवाहित होता है।

लौह अयस्क का भंडार और वितरण:

- लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है।
- लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का अग्रणी राज्य ओडिशा है। यह कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन करता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 17% उत्पादन होता है, इसके बाद कर्नाटक और झारखंड में क्रमशः 14% और 11% उत्पादन होता है।

भारत से लौह अयस्क का निर्यात:

- भारत विश्व में लौह अयस्क का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है।
- हमारे कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 50 से 60 प्रतिशत जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और हाल ही में खाड़ी देशों को जाता है।
- जापान भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार है जो हमारे कुल निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है।
- लौह अयस्क निर्यात को संभालने वाले प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम, पारादीप, मरमागाओ और मैंगलोर हैं।

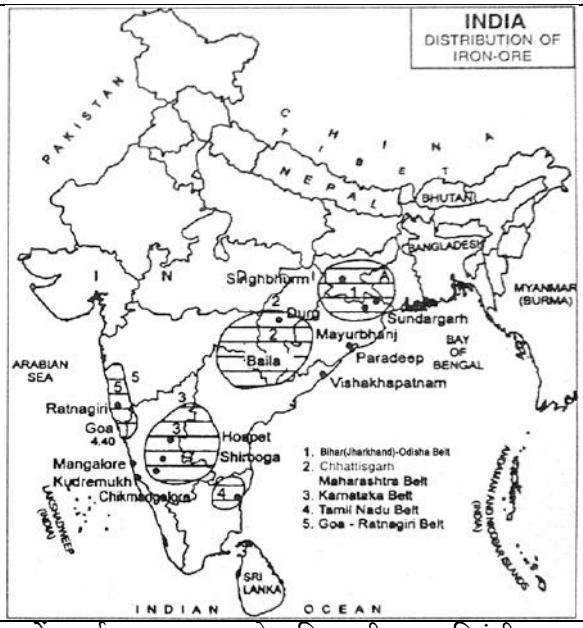

सुपर टाइफून हिन्नमनोर

खबरों में क्यों : वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे सुपर टाइफून 'हिन्नमनोर' कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में बार-बार आ रहा है।

चक्रवात के बारे में:

- चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेज़ी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।
- उत्तरी गोलार्द्ध में हवा की दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।

ऊष्णकटिबंधी चक्रवात:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' शब्द का उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिये करता है जिसमें पवनें 'गैल फोर्स' (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटे) से अधिक होती हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में बनते हैं।
- वे बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियाँ हैं जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनती हैं और सतही पवन परिसंचरण में मिलती हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:

- 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
- कोरिओलिस बल एक चक्रवाती भंवर बनाने के लिए काफी मजबूत होता है।
- ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव
- पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
- समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति:

- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों के ऊपर गर्मियों के अंत में उत्पन्न होते हैं और इनका उद्गम ऊष्मीय होता है (अगस्त से मध्य नवंबर)।
- कोरिओलिस प्रभाव के कारण, शक्तिशाली स्थानीय संवहन धाराएं इन क्षेत्रों में एक चक्कर लगाती हैं।
- ये चक्रवात तब तक बनते और चलते रहते हैं जब तक कि वे व्यापारिक पवन पेटी में कमजोर स्थान पर नहीं पहुंच जाती है।

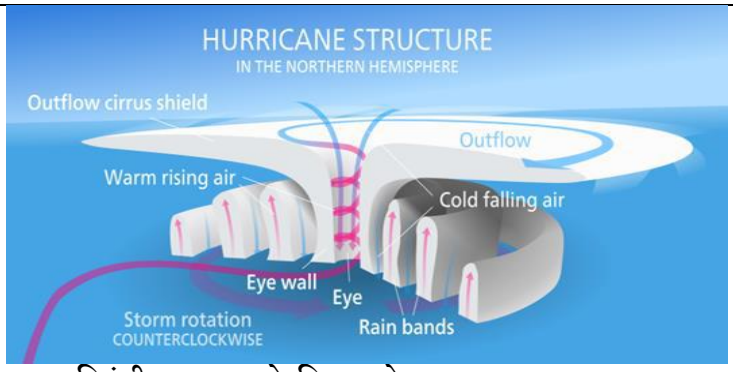

उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के चरण

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनके विकास के दौरान तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

गठन और प्रारंभिक विकास चरण

- चक्रवाती तूफान का निर्माण और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्र की सतह से वाष्पीकरण द्वारा गर्म महासागर से ऊपरी हवा में जल वाष्प एवं ऊष्मा के हस्तांतरण पर निर्भर करता है।
- यह समुद्र की सतह से ऊपर उठने वाली हवा के संघनन के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर मेघपुंज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

परिपक्व अवस्था

- जब उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होता है, तो वायु ज़ोरदार गरज के साथ उठती है और क्षोभमंडल स्तर पर क्षैतिज रूप से फैलने लगती है।
- एक बार जब हवा फैलती है, तो उच्च स्तर पर सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जो संवहन के कारण हवा की नीचे की ओर गति को तेज़ करता है।
- अवतलन के उत्प्रेरण के साथ वायु संपीडन द्वारा गर्म होती है और गर्म 'नेत्र' (निम्न दाब केंद्र) उत्पन्न होता है।
- हिंद महासागर में एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता के रूप में अत्यधिक अशांत बड़े क्यूम्यलस थंडरक्लाउड बैंड का एक संकेंद्रित पैटर्न होता है।

संशोधन और क्षय

- एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने केंद्रीय निम्न दबाव, आंतरिक ऊष्मा और अत्यधिक उच्च गति के संदर्भ में कमज़ोर (जैसे ही गर्म नम हवा का स्रोत कम होना शुरू हो जाता है या अचानक कट जाता है) होना शुरू हो जाता है।
- यह जमीन पर पहुंचने या ठंडे पानी के पार जाने के बाद होता है।

स्थानीय नाम

- उत्तरी अटलांटिक (कैरिबियन और मैक्सिको की खाड़ी सहित): हरिकेन (Hurricanes)
- पूर्वी और मध्य उत्तर प्रशांत: हरिकेन (Hurricanes)
- पश्चिमी उत्तरी प्रशांत: टाइफून (Typhoons)
- अरब सागर/उत्तरी हिंद महासागर: उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)
- दक्षिण हिंद महासागर: दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात/विली-विली
- प्रवाल सागर/दक्षिण प्रशांत: उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone)

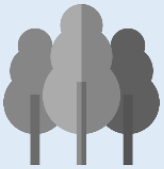

पर्यावरण

न्युकमाडोंग कम्युनिटी रिजर्व (Nyukmadong community Reserve)	**प्रसंग:** न्युकमाडोंग गांव के निवासियों ने कहा कि सीमा सड़क संगठन ने बिना परामर्श या मुआवजे के 36 वर्ग किमी के जंगल के 80% से अधिक को नष्ट कर दिया। **पृष्ठभूमि:** भारतीय सेना के सैनिकों और चीनी आक्रमणकारियों के बीच भीषण लड़ाई में से एक में संपार्श्विक क्षति बनने के लगभग 60 साल बाद, अरुणाचल प्रदेश का एक गाँव 1962 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक परियोजना से एक पवित्र जंगल की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। **जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन और वनस्पतियों और जीवों की हानि:** • यह स्थान बौद्ध शैली के युद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है, जो 1.5 एकड़ के भूखंड पर 18 नवंबर, 1962 को एक युद्ध स्थल को देखता है। • कोलकाता स्थित साउथ एशियन फोरम फॉर एनवायरनमेंट के अनुसार, सड़क परियोजना एक स्थानीय आदिवासी समुदाय के भूमि और वन पारिस्थितिकी तंत्र के अधिकारों के अतिक्रमण और अनदेखी का एक उदाहरण है, जिस पर वे निर्भर हैं। • WWF (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) ने अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण पैच को सामुदायिक आरक्षित वन के रूप में घोषित किया। रेड लिस्टेड भारतीय लाल पांडा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। • समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वनों की कटाई (सड़क के लिए) ने उनके पारंपरिक पवित्र स्थलों को प्रभावित किया, जिन्हें स्थानीय रूप से फु (phu) कहा जाता है। • यह नए वन नियम 2022 के लिए पहला परीक्षण मामला हो सकता है जो स्वदेशी लोगों के वन संसाधनों के अधिकार को लूटने का प्रयास करता है। • स्थानीय हितधारकों ने कहा कि पवित्र वन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। "जैव विविधता को हुए नुकसान की कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस उखड़े पैच को फिर से हरा-भरा करने के लिए भूस्वामियों के रूप में समुदाय को भुगतान किया जाना चाहिए। • अन्य प्रभावित क्षेत्रों में ग्यांद्रब्रांगसा, हलफतांगमु, पेनपेयटंग, चेंधुफू, यांगफू और चांगफुनकफू हैं। **सीमा सड़क संगठन (BRO):** • सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है और अब इसका एक हिस्सा है। • BRO भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। • BRO में रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क विंग और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) शामिल हैं। अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।
चीता पुनरुत्पादन (Cheetah Reintroduction)	**खबरों में क्यों :** 16 सितंबर को, एक विशेष विमान B-747 जंबो जेट नामीबिया से जयपुर के लिए आठ नामीबिया के जंगली चीतों, पांच मादा और तीन नर को ले जाने के लिए उड़ान भरेगा, जो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक नई आबादी का संस्थापक हैं। **कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के बारे में:** • श्योपुर और मुरैना जिलों में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। • वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का हिस्सा है। • इसका क्षेत्रफल 344.686 वर्ग किमी है। • **पशुवर्ग :** इस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय तेंदुआ , जंगली बिल्ली , सुस्त भालू , ढोल , भारतीय भेड़िया , सुनहरा सियार , धारीदार लकड़बग्घा और बंगाल लोमड़ी, चीतल, सांभर हिरण , नीलगाय , चार सींग वाले मृग , चिंकारा , काला हिरण और जंगली सूअर और बहुत सी जानवरो की प्रजातियां संरक्षित की गई है।
चीता और अन्य बड़ी	**संदर्भ:** चीता, जिसे अफ्रीका से भारत में फिर से लाया जा रहा है, को तेंदुआ के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिसमें

बिल्लियाँ

भी धब्बे होते हैं जो कुछ हद तक समान दिखते हैं।निम्नलिखित 'बिल्ली' जीनस पैंथेरा, प्यूमा और एसिनोनिक्स के सदस्यों की सूची दी गई है।

टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस)

- **आकार/वजन:** ये 75-300 किग्रा तक होते है | **IUCN स्थिति:** लुप्तप्राय (Endangered)
- यह भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु है।
- यह मुख्य रूप से एक वन प्राणी है; वे साइबेरियाई टैगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक पाए जाते हैं।
- बाघ सबसे बड़ी जीवित बिल्ली प्रजाति है और जीनस पैंथेरा का सदस्य है।
- दिसंबर 2021 में जारी जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की आबादी 2,967 है, जो विश्व के बाघों के लगभग दो-तिहाई वैश्विक सीमा के एक-चौथाई से भी कम हैं।
- MoEF और CC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी (526), उसके बाद कर्नाटक (524) है।

शेर (पेंथेरा लियो)

- **आकार/वजन:** ये 100-250 किग्रा तक होते है | **IUCN स्थिति:** अफ्रीकी शेर: कमजोर (Vulnerable), एशियाई शेर: लुप्तप्राय (Endangered)
- अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी, शेर सबसे अधिक सामाजिक बिल्लियां होते है, और समूह में रहता है जिसे प्राइड कहा जाता है।
- वे स्क्रबलैंड जैसे खुले जंगलों को पसंद करते हैं, और वयस्क नर के पास एक प्रमुख अयाल होता है
- पश्चिमी भारत के गिर वन में लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं, जो उनका अंतिम प्राकृतिक आवास है।
- शेर यकीनन मानव संस्कृति में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पशु प्रतीक है, चाहे वह सारनाथ में अशोक स्तंभ हो, बकिंघम पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार हो, या 20वीं सेंचुरी फॉक्स और एमजीएम लोगो (MGM logo) हो।

जगुआर (पैंथेरा ओंका)

- **आकार/वजन :** ये 50-110 किलो तक होते है | IUCN स्थिति: निकट संकटग्रस्त (Almost Threatened)
- अमेरिका में सबसे बड़ी बिल्ली जगुआर में सभी जंगली बिल्लियों की सबसे मजबूत काटने की शक्ति होती है, जो इसे अपने शिकार की खोपड़ी से सीधे काटने में सक्षम बनाती है।
- मेलानिस्टिक (काला) जगुआर आम हैं और इन्हें अक्सर ब्लैक पैंथर कहा जाता है।मय (Mayan) और एज़्टेक सभ्यताओं (Aztec civilisations) में जगुआर एक शक्तिशाली आदर्श था।

तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस)

- **आकार/वजन :** ये 30-90 किग्रा तक होते है | **IUCN स्थिति:** संवेदनशील (Vulnerable)
- एक रोसेट पैटर्न वाले कोट के साथ जगुआर के समान, तेंदुए को जिम कॉर्बेट द्वारा "सभी जानवरों में सबसे सुंदर" के रूप में वर्णित किया गया था, जो "आंदोलन की सुंदरता और रंग की सुंदरता" के लिए था।
- सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक अनुकूलनीय, वे अफ्रीका और एशिया में सभी ऊंचाई पर विविध आवासों में रहती हैं। काले जगुआर की तरह, मेलेनिस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पैंथर कहा जाता है।
- कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में, तेंदुओं को शेरों से बेहतर शिकारी माना जाता है।

हिम तेंदुआ (पैंथेरा अनकिया)

- **आकार/वजन :** ये 25-55 किग्रा तक होते हुई | IUCN स्थिति: संवेदनशील (Vulnerable)
- पहाड़ों का भूत, यह स्मोकी-ग्रे बिल्ली मध्य और दक्षिण एशिया में बर्फ की रेखा के ऊपरी हिस्सों में रहती है।
- सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे मायावी, यह दहाड़ नहीं सकती है, और उन सभी की सबसे लंबी पूंछ होती है जो चट्टानों के साथ शिकार करते समय संतुलन के काम आती है, और शरीर के चारों ओर लपेटे जाने पर गर्मी भी देती है।
- हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है।

प्यूमा घरेलू बिल्ली से निकटता से संबंधित है, इस जीनस में केवल एक मौजूदा प्रजाति है, कौगर। कौगर (प्यूमा कॉनकोलर)

- **आकार/वजन :** 40-100 किग्रा | **IUCN स्थिति:** कम से कम चिंता (Least Concern)
- कौगर अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। (जगुआर सबसे बड़ा है।)
- कौगर को कनाडा के युकोन से लेकर दक्षिणी एंडीज तक की सीमा में 'माउंटेन लायन' और 'पैंथर' भी कहा जाता है। कॉनकलर "एकसमान रंग का" के लिए लैटिन है। इंकास ने कुस्को शहर को एक कौगर के आकार में डिजाइन किया।

एसिनोनीक्स (Acinonyx): यह बिल्ली परिवार के भीतर एक अद्वितीय प्रजाति है, जिसमें केवल एक जीवित सदस्य, चीता है।

चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस)

- **आकार:** 20-70 किलो | IUCN स्थिति: संवेदनशील (Vulnerable)

	• चीता दुनिया का सबसे तेज़, भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। • यह एसीनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है, जो कि अपने पंजों की बनावट के रूपांतरण के कारण पहचाने जाते हैं। • इसी कारण, यह इकलौता विडाल वंशी है जिसके पंजे बंद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से इसकी पकड़ कमज़ोर रहती है। • ज़मीन पर रहने वाला ये सबसे तेज़ जानवर है जो एक छोटी सी छलांग में 120 कि॰मी॰ प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर लेता है और 460 मी. तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र तीन सेकेंड के अंदर ये अपनी रफ्तार में 103 किमी प्रति घंटे का इज़ाफ़ा कर लेता है, जो अधिकांश सुपरकार की रफ्तार से भी तेज़ है। • चीते इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, और उन्हें सुमेरियन युग से ही पालतू बनाया गया है।
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व	**खबरों में क्यों :** हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिये भारत के पहले संरक्षण रिज़र्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। • यह भारत को डुगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप-क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। 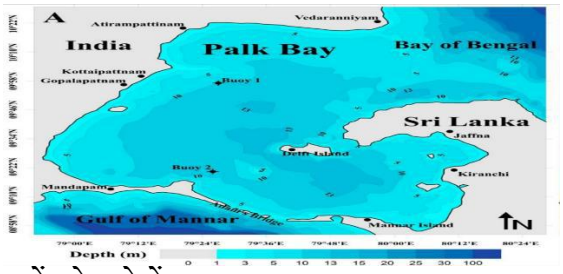 **डुगोंग के बारे में:** • डुगोंग (Dugong dugon) जिसे 'सी काउ (Sea Cow)' भी कहा जाता है, सिरेनिया (Sirenia) श्रेणी की चार जीवित प्रजातियों में से एक है तथा यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती हैं। • डुगोंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी आबादी में कमी का प्रभाव खाद्य शृंखला पर पड़ेगा। • वितरण और पर्यावास: वे 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में देखे जा सकते हैं। • **IUCN की रेड लिस्ट:** संवेदनशील (Vulnerable) • **वन्य (जीवन) संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I • **CITES:** परिशिष्ट I **संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** • फरवरी 2020 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (सीएमएस) पर कन्वेंशन के पार्टियों (सीओपी) के 13वें सम्मेलन की मेजबानी की। • भारत सरकार वर्ष 1983 से CMS का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। • भारत ने साइबेरियन क्रेन (वर्ष 1998), मरीन टर्टल (वर्ष 2007), डुगोंग (वर्ष 2008) और रैप्टर (वर्ष 2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर CMS के साथ गैर- बाध्यकारी कानूनी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में 'यूएनईपी/सीएमएस डुगोंग एमओयू' के कार्यान्वयन और डगोंग संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर गौर करने हेतु 'डुगोंग के संरक्षण के लिये कार्य बल' का गठन किया।
कार्बन डेटिंग	**खबरों में क्यों :** वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर पाए जाने वाले विवादित ढांचे की कार्बन-डेटिंग के संबंध में नोटिस जारी किया है।

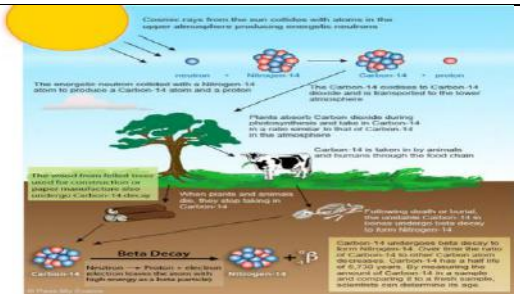

कार्बन डेटिंग क्या है?

- कार्बन डेटिंग, जिसे रेडियोकार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, आयु निर्धारण की विधि है जो रेडियोकार्बन (कार्बन-14) के नाइट्रोजन के क्षय पर निर्भर करती है।
- इस पद्धति का विकास अमेरिकी भौतिक विज्ञानी विलार्ड एफ. लिब्बी ने 1946 के आसपास किया था।
- पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन-14 के साथ न्यूट्रॉनों की परस्पर क्रिया से प्रकृति में कार्बन-14 लगातार बनता है।
- इस प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन कॉस्मिक रे (cosmic rays) द्वारा वातावरण के साथ परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं।

यह कार्य कैसे करता है?

- वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में मौजूद रेडियोकार्बन जैविक कार्बन चक्र में प्रवेश करता है: यह हरे पौधों द्वारा हवा से अवशोषित होता है और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जानवरों को प्रदान किया जाता है।
- रेडियोकार्बन एक जीवित जीव में धीरे-धीरे क्षय होता है, और क्षयित राशि को लगातार तब तक लिए जाता है जब तक जीव हवा या भोजन ग्रहण करता है।
- एक बार जब जीव मर जाता है, तो यह कार्बन-14 को अवशोषित करना बंद कर देता है, एवं इसके ऊतकों में रेडियोकार्बन की मात्रा लगातार कम हो जाती है।

अर्ध-आयु की अवधारणाएं:

- कार्बन-14 की अर्ध-आयु 5,730 ± 40 वर्ष है—अर्थात, किसी भी समय मौजूद रेडियोआइसोटोप की आधी मात्रा लगातार 5,730 वर्षों के दौरान सहज विघटन से गुजरेगी।
- क्योंकि इस स्थिर दर पर कार्बन-14 क्षय जिस तारीख को एक जीव की मृत्यु हो गई उसका एक अनुमान उसके अवशिष्ट रेडियोकार्बन की मात्रा को मापकर बनाया जा सकता है।
- उपयोग: यह 500 से 50,000 साल पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है। इस पद्धति का व्यापक रूप से भूवैज्ञानिकों, मानवविज्ञानी, पुरातत्वविदों और संबंधित क्षेत्रों में जांचकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।

हाथी संरक्षण (Elephant Conservation)

संदर्भ: तमिलनाडु के वन अधिकारी काल्फ रेस्क्यू मिशन (calf rescue missions) की बदौलत 'हाथियों की भाषा' सीखते हैं। पिछले एक साल में, विभाग ने तीन हाथी के बच्चों को सफलतापूर्वक फिर से जोड़ा है जो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में अपने झुंड से अलग हो गए थे।

अफ्रीकी हाथियों के बारे में:

- अफ्रीकी सवाना (या झाड़ी) हाथी
  - IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय

	• अफ्रीकी वन हाथी
	  ○ IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
	• **नोट:** पहले, IUCN ने दोनों अफ्रीकी हाथियों को "असुरक्षित" के रूप में सूचीबद्ध किया था। लेकिन अब उसने उन्हें अलग से सूचीबद्ध करने का विकल्प चुना है। आनुवंशिक प्रमाण के बाद यह साबित हो गया है कि दोनों अलग-अलग प्रजातियां हैं।
	• **पर्यावास:** अफ्रीकी हाथियों का वितरण उप-सहारा अफ्रीका के सवाना और मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावनों में है।
	• **अफ्रीकी सवाना (या झाड़ी) हाथी:** ये बड़े जानवर होते हैं जो उप-सहारा अफ्रीका के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं।
	• **अफ्रीकी वन हाथी:** ये अफ्रीकी सवाना से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं।
	विशेषताएं:
	• अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि जानवर हैं। ये एशियाई हाथियों से थोड़े बड़े होते हैं और इन्हें इनके बड़े कानों से पहचाना जा सकता है। (एशियाई हाथियों के छोटे, गोल कान होते हैं)
	• हाथी मातृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात् समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है। मातृसत्ता आमतौर पर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी होती है।
	• **कीस्टोन प्रजातियां:** अफ्रीकी हाथी एक कीस्टोन प्रजाति (keystone Species) है, जिसका अर्थ है कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसे "पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर" (Ecosystem Engineers) के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे कई तरह से अपने आवास को आकार देते हैं।
	एशियाई हाथियों के बारे में:
	यह एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। इनका निवास स्थान भारत सहित दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में हैं।
	  ○ IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय,
	  ○ CITES: परिशिष्ट I
	  ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
	भारत में हाथी रिजर्व:
	• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में हाथियों की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद केरल का स्थान आता है।
	• **हाथी परियोजना:** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
	• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाथी परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ड्रैगनफलीज़ (Dragonflies)	**संदर्भ:** दिल्ली के जैव विविधता पार्कों में ड्रैगनफ़्लाइज़ (dragonflies) और डैमफ़्लाइज़ (damselflies) के एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि इस साल कम वर्षा ने उनके जीवन चक्र और संख्या को प्रभावित किया होगा।

- हर साल 18 अगस्त को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया) और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रैगनफ्लाई दिवस मनाते हैं।

ड्रैगनफलीज़ क्या हैं?

- यह एक हवाई परभक्षी कीट है जो आमतौर पर पूरे विश्व में मीठे पानी के आवासों के पास पाया जाता है।
- ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 'जैव संकेतक' (Bioindicators) के रूप में कार्य करते हैं।
- **प्राकृतिक वास:**
  - ड्रैगनफलीज़ की अधिकांश प्रजातियाँ उष्ण कटिबंध में और विशेष रूप से वर्षावनों में रहती हैं।
- **महत्व:**
  - ड्रैगनफलीज़ अपने वातावरण के लिए परभक्षी (विशेषकर मच्छरों) और पक्षियों और मछलियों के शिकार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन कीड़ों को स्थिर ऑक्सीजन स्तर और स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के विश्वसनीय जैव संकेतक मानते हैं।
  - ड्रैगनफलीज़ एक क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के आवश्यक जैव-संकेतक हैं। क्योंकि वे मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी जानलेवा बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं।
- **खतरा :**
  - इनके आवास का तेजी से नष्ट होना इनके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बन गया है जिससे उनका संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- कमला नेहरू रिज पर अधिकतम 25 प्रजातियां दर्ज की गई।
- यमुना जैव विविधता पार्क में 23 प्रजातियां दर्ज की गईं, जो वर्ष 2018 में दर्ज 25 प्रजातियों से थोड़ा कम हैं।
- दर्ज किए गए प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में, कालिंदी जैव विविधता पार्क में सबसे अधिक संख्या 3,348 दर्ज की गई, इसके बाद अरावली जैव विविधता पार्क में 555 प्रजातियों की गणना की गई।
- नीला हौज जैव विविधता पार्क ने भी वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष केवल छह प्रजातियों की कम संख्या दर्ज की, जब नौ प्रजातियों की गणना की गई थी।
- जिन प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया उनमें स्कारलेट स्किमर, पिक्चर विंग ड्रैगनफ्लाई और ग्रेनाइट घोस्ट के साथ नीचे वर्णित ड्रेगन शामिल हैं। (चित्रों में)

ड्रैगनफलीज़ की हाल की अन्य खोजें:

- हाल ही में, ड्रैगनफ्लाई के प्रति उत्साही ने "स्पाइनी हॉर्नटेल" नामक एक दुर्लभ ड्रैगनफ़्लू प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है जो अब तक केरल में नहीं देखी गई थी।
  - पश्चिमी घाट इस प्रजाति का घर है, जिसे इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में खोजा गया था।

गोल्डन डार्टलेट

डिच ज्वेल

	पिएड पैडी स्किम्मर (Pied paddy skimmer) **स्पाइनी हॉर्नटेल**
ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022	**खबरों में क्यों :** पहली वार्षिक ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट, सरकारों द्वारा ऐतिहासिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों पर एक प्रगति रिपोर्ट है। • रिपोर्ट में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम और अमेरिका के पिट्सबर्ग में आयोजित होने वाली 13वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में चर्चा के लिए नेताओं के लिए 25 सिफारिशें सामने रखी गई हैं। **रिपोर्ट के बारे में:** • निर्णायक एजेंडा रिपोर्ट 2022 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च-स्तरीय चैंपियंस की एक नई रिपोर्ट है। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षा को बढ़ाने, प्रगति में तेजी लाने और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना है। यह पाँच प्रमुख क्षेत्रों - विद्युत , हाइड्रोजन, सड़क परिवहन, इस्पात और कृषि में उत्सर्जन को कम करने की प्रगति का आकलन करता है। • रिपोर्ट में विश्लेषण किये गए पाँच क्षेत्रों में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 60% हिस्सा है, और वर्ष 2030 तक आवश्यक उत्सर्जन में कमी कर सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप तक सीमित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। • हाल के वर्षों में व्यावहारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के साथ ही आवश्यक प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में प्रगति हुई है, जिसमें वर्ष 2022 में वैश्विक नवीकरणीय क्षमता में 8% की वृद्धि का पूर्वानुमान शामिल है जो पहली बार 300GW के साथ लगभग 225 मिलियन घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के बराबर है। **IEA के बारे में:** • वर्ष 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र इसे वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे में स्थापित किया गया था। • IEA एक स्वायत्त अंतरसरकारी संगठन है। • इसका मिशन फोकस के चार मुख्य क्षेत्रों द्वारा निर्देशित है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता, और दुनिया भर में जुड़ाव। • **मुख्यालय:** पेरिस (फ्रांस) में हैं। • **संरचना:** वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। आईईए परिवार में आठ संघ देश भी शामिल हैं। एक उम्मीदवार देश ओईसीडी का सदस्य देश होना चाहिए। लेकिन सभी ओईसीडी सदस्य आईईए सदस्य नहीं हो सकते हैं। • तीन देश पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं: चिली, इज़राइल और लिथुआनिया। **IEA द्वारा रिपोर्ट:** • वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट • विश्व ऊर्जा आउटलुक • विश्व ऊर्जा सांख्यिकी • विश्व ऊर्जा संतुलन • ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य
अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण	**संदर्भ:** हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की पूर्व शर्त को पूरा किए बिना 3000 मेगावाट की दिबांग पनबिजली परियोजना के लिए वन मंजूरी देने पर स्वतः संज्ञान लेने वाले मामले को खारिज कर दिया है।

राज्य में वन्यजीव संरक्षण:

पक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve)

- पीटीआर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसे पखुई टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है।
- यह चार निवासी हॉर्नबिल प्रजातियों के अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है।
- ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और यह IUCN रेड लिस्ट के तहत 'सुभेद्य' श्रेणी में है।

नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व:

- नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप-क्षेत्र में मिश्मी पहाड़ियों की पटकाई और दाफा बम (Dapha bum) श्रेणियों के बीच स्थित है।
- नमदाफा उग्र नोआ-दिहिंग नदी के किनारे भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
- यह दुनिया में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बड़ी बिल्लियों की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमे (1) बाघ (Tiger) (2) तेंदुआ (Leopard) (3) हिम तेंदुआ (Snow Leopard) और (4) धूमिल तेंदुए (Clouded Leopard) शामिल हैं।

मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान:

- मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के ऊपरी सियांग जिले (पश्चिम सियांग और पूर्वी सियांग जिलों के कुछ हिस्से) में स्थित है।
- मोलिंग नाम स्थानीय आस्था और विश्वास के अनुसार मोलिंगनाम की सबसे ऊंची चोटी से लिया गया है।
- सिओम नदी पार्क की पश्चिमी सीमाओं के साथ बहती है, जबकि कई छोटी नदियाँ भी पार्क से होकर गुजरती हैं, जैसे कि सेमोंग, क्रोबोंग, सुबोंग और सीरिंग, ये सभी सियांग नदी में बहती हैं, जो पूर्वी सीमा पर है।

ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य:

- ईगलनेस्ट या ईगल्स नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम कामेंग जिले, अरुणाचल प्रदेश की हिमालय की तलहटी में भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है।
- यह उत्तर-पूर्व में सेसा आर्किड अभयारण्य और पूर्व में कामेंग नदी के पार पाखुई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। यह कामेंग एलीफेंट रिजर्व का भी एक हिस्सा है।
- इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय सेना के रेड ईगल डिवीजन से लिया गया है जो वर्ष 1950 के दशक में इस क्षेत्र में तैनात था।
- ईगलनेस्ट वह स्थान है जहां बुगुन लियोसिचला (पैसेरिन पक्षी प्रजाति) पहली बार वर्ष 1995 में खोजा गया था और वर्ष 2006 में फिर से देखा और वर्णित किया गया था।

सेसा आर्किड अभयारण्य:

- सेसा आर्किड अभयारण्य पश्चिम कामेंग जिले, अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग वन प्रभाग में हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- यह ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य को दक्षिण-पश्चिम में जोड़ता है।
- यह कामेंग संरक्षित क्षेत्र परिसर (केपीएसी) का एक हिस्सा है, जो एक हाथी रिजर्व है। सेसा 5 नई और स्थानिक प्रजातियों के साथ 200 से अधिक आर्किड प्रजातियों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है।
- सैप्रोट्रोफिक ऑर्किड की 7 स्थानिक प्रजातियों के मामले में यह अभयारण्य अद्वितीय है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में:

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई है।
- यह बहु-अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है।
- न्यायाधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

	• पर्यावरणीय मामलों में ट्रिब्यूनल का समर्पित अधिकार क्षेत्र त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करेगा। • ट्रिब्यूनल के आवेदनों या अपीलों को दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से सुलझाने का प्रयास करना अनिवार्य है। • नई दिल्ली ट्रिब्यूनल की बैठक का मुख्य स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थान होंगे।

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

ऑपरेशन "मेघ चक्र"	**संदर्भ:** केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान के तहत तलाशी ली। ऑपरेशन का कोड नाम "मेघ चक्र" रखा गया था। **ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में:** • ऑपरेशन मेघ चक्र अंतरराष्ट्रीय लिंकेज और संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों में तेजी से प्रतिक्रिया के लिए हाल के दिनों में सीबीआई के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियानों में से एक है। • इसका उद्देश्य बाल यौन शोषण सामग्री प्रसारित करने और नाबालिगों को ब्लैकमेल करने वाले व्यक्तियों और गिरोहों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। • ऑपरेशन को क्लाउड स्टोरेज पर लक्षित किया गया है- इसलिए कोडनेम 'मेघा चक्र'- जिसका उपयोग पेडलर्स द्वारा नाबालिगों के साथ अवैध यौन गतिविधियों पर ऑडियो-विजुअल सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जाता है। • यह "ऑपरेशन भारत में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से सूचनाओं का मिलान करेगा, वैश्विक स्तर पर एजेंसियों के साथ जुड़ेगा और ऑनलाइन बाल यौन शोषण और इस तरह की संगठित साइबर आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए इंटरपोल चैनलों के माध्यम से निकटता से समन्वय करेगा।"
भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI)	**संदर्भ:** हाल ही में भारत ने अपने 'इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (आईएचसीआई)' के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का पुरस्कार जीता, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बड़े पैमाने पर उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए की गई पहल है, जिसमें 3.4 मिलियन उच्च रक्तचाप वाले लोगों की पहचान की गई और उन्हें विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज के लिए रखा गया। **आईएचसीआई के बारे में:** • भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (आईएचसीआई) उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए रक्तचाप नियंत्रण में सुधार के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, डब्ल्यूएचओ-भारत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक बहु-भागीदार पहल है। • वर्ष 2018 में 26 जिलों में शुरू की गई परियोजना का वर्ष 2022 तक 100 से अधिक जिलों में विस्तार किया गया है। • बीस लाख से अधिक रोगियों का इलाज शुरू किया गया और यह देखने के लिए उन पर नज़र रखी गई कि क्या उन्होंने बीपी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। **वर्ष 2022 के बारे में संयुक्त राष्ट्र इंटर-एजेंसी टास्कफोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कारों पर डब्ल्यूएचओ का विशेष कार्यक्रम:** • पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए: (i) स्वास्थ्य मंत्रालय (या स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत सरकारी एजेंसी); (ii) स्वास्थ्य से परे मंत्रालय (या सरकारी एजेंसियां); और (iii) गैर-राज्य अभिनेता (गैर-सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और परोपकार (philanthropy))। • एनसीडी, मानसिक स्वास्थ्य या अन्य एनसीडी से संबंधित एसडीजी की रोकथाम और नियंत्रण में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई के लिए प्रदर्शनकारी प्रतिबद्धता के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया। • बच्चों और युवा समूहों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों के साथ काम करने वाले संगठनों के लिए नामांकन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। • 2022 पहला साल है जब पुरस्कारों को PHC के साथ साझेदारी में चलाया गया था, हालांकि, 5वां साल जब टास्क फोर्स ने पुरस्कार चलाए हैं। स्व-नामांकन की अनुमति नहीं है।
अनुसूचित जनजाति	**संदर्भ:** कैबिनेट ने हिमाचल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में चार जनजातियों को एसटी सूची में जोड़ने को मंजूरी दी। **अनुसूचित जनजातियों की सूची में किन जनजातियों को जोड़ा गया है?** • हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति।

	• तमिलनाडु की नारिकोरावन और कुरीविक्करन (Narikoravan and Kurivikkaran) पहाड़ी जनजातियाँ। • बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। • कर्नाटक के कडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। • छत्तीसगढ़ में, मंत्रिमंडल ने भारिया (जोड़े गए विविधताओं में भूमिया और भुइयां शामिल हैं), गढ़वा (गढ़वा), धनवार (धनवार, धनुवर), नगेसिया (नागसिया, किसान), और पोंध जैसी जनजातियों के लिए समानार्थक शब्द को मंजूरी दी। **जनजातियों को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:** • यह संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ शुरू होगा, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और उन्हें भारत के महापंजीयक को अनुमोदन के लिए भेजता है। ○ अंतिम निर्णय के लिए सूची को कैबिनेट को भेजने से पहले इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी मिलती है। **नोट:** कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें गोंड समुदाय की पांच उपश्रेणियां (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड) शामिल हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा	**संदर्भ:** हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा क्या है?** • 10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। • संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया गया। • यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है। • यह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। • यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। **अतिरिक्त जानकारी: आरक्षण की न्यायिक जांच:** • मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोरैराजन (1951) मामला आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला था। इस मामले में संविधान में पहला संशोधन हुआ। ○ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य के तहत रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ○ इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में संसद ने अनुच्छेद 15 में खंड (4) सम्मिलित करके संशोधन किया। • इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में अदालत ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे और सीमा की जांच की। ○ न्यायालय ने कहा है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए; और कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ○ संसद ने 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करके प्रतिक्रिया दी जिसने अनुच्छेद 16(4ए) को प्रस्तुत किया। • एम. नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4ए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए ऐसी कोई भी आरक्षण नीति निम्नलिखित तीन संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी:

	• वर्ष 2018 के जरनैल सिंह (Jarnail Singh) बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। • मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उस कानून को बरकरार रखा, जिसके तहत एससी और एसटी को पदोन्नति में वरिष्ठता के साथ आरक्षण दिया जाता है।
टी माधव राव	**टी माधव राव के बारे में:** • राजा सर तंजौर माधव राव, जिन्हें सर माधव राव तंजावुरकर या बस माधवराव तंजौरकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनेता, सिविल सेवक , प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1873 से 1875 तक इंदौर और 1875 से 1882 तक बड़ौदा में दीवान के रूप में कार्य किया। • माधव राव का जन्म 20 नवंबर 1828 को तमिलनाडु के एक प्रमुख तंजावुर में हुआ था। वह त्रावणकोर के पूर्व दीवान टी वेंकट राव के भतीजे और रंगा राव के पुत्र थे। • ब्रिटिश उदारवादी राजनेता हेनरी फॉसेट ने उन्हें "भारत का तुर्गोट (Turgot)" कहा। वर्ष 1866 में, उन्हें नाइट कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ इंडिया बनाया गया था। • वह शहर में भाप इंजन, वाहन, बांस से बनी दूरबीन और बच्चों को शिक्षित करने में शुरुआती प्रोजेक्टर (मैजिक लैंटर्न्स) को उपयोग में लाये। • उन्होंने अपनी बेटी को नए शुरू किए गए जनाना मिशन स्कूल (Zenana Mission schoo) में भेजकर शहर में लड़कियों की शिक्षा शुरू की। • वे मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालयों के सीनेट सदस्य थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। • वह समाजशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार हर्बर्ट स्पेंसर के एक महान अनुयायी थे। • दीवान माधव राव द्वारा लिखित मूल बच्चों के प्रशिक्षण पर लघु संकेत और संकेत और सखा राम रायर लक्ष्मण रायर और कुलथु अय्यर की जीवनी उनके व्यक्तित्व के कुछ दुर्लभ पहलुओं को प्रकाश में लाते हैं। **प्रशासनिक सुधार:** • उनके प्रशासनिक सुधारों में 1860 में श्री ग्रीनवे को सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त करके लोक निर्माण विभाग को मजबूत करना शामिल है। • टेलीग्राफ कार्यालय शुरू किया गया और अंचल (डाक) विभाग, जो अब तक केवल आधिकारिक पत्र ले जा रहा था, को आम जनता के लिए खोल दिया गया। • निदेशक के रूप में सनकरा सुब्बा अय्यर की नियुक्ति के साथ शिक्षा विभाग को औपचारिक रूप दिया गया। • अपनी अंतिम प्रशासनिक रिपोर्ट में, उन्होंने "यात्रा के कुछ घंटों के भीतर हर विषय को प्रदान करने के लिए, एक डॉक्टर, एक स्कूल मास्टर, एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक पंजीकरण अधिकारी और एक पोस्टमास्टर के लाभ" के रूप में विकास के अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। **शीर्षक और पुरस्कार:** • मद्रास विश्वविद्यालय के फेलो- 1862 • भारत के स्टार के नाइट कमांडर- 1866 • राजा का शीर्षक- 1868

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल

संदर्भ: हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपये के एक करार पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत 38 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए करार किया गया है। इनमें से 35 कॉम्बेट मिसाइल और 3 अभ्यास के लिए हैं। इन्हें प्रोजेक्ट-15बी के तहत निर्मित दो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर तैनात किया जायेगा।

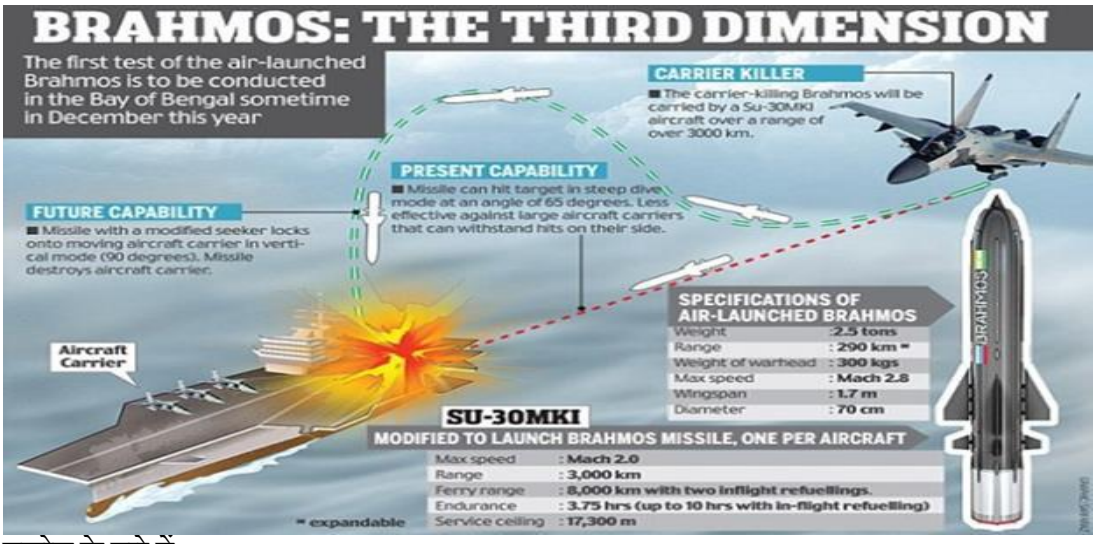

ब्रह्मोस के बारे में:

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए DRDO (भारत) और NPO Mashinostroyeniya (रूस) के बीच एक संयुक्त उद्यम है और मिसाइल का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा की नदियों से लिया गया है।

पृष्ठभूमि और विकास:

- वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत से, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग सहित मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित करना शुरू कर दिया।
- वर्ष 1998 में मास्को में रूस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन हुआ, जो डीआरडीओ और एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया (एनपीओएम) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारतीय पक्ष 50.5% और रूसियों का 49.5% हिस्सा है।

सामरिक महत्व:

- ब्रह्मोस एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ दो चरणों वाली मिसाइल है।
- इसका पहला चरण मिसाइल को सुपरसोनिक गति में लाता है और फिर अलग हो जाता है।
- यह ' फायर एंड फॉरगेट' प्रकार की मिसाइल है जो लक्ष्य को हिट करने के लिए 15 किमी की परिभ्रमण ऊंचाई और 10 मीटर की टर्मिनल ऊंचाई हासिल कर सकती है।
- ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें , जिन्हें "स्टैंडऑफ रेंज हथियार" कहा जाता है, हमलावर को रक्षात्मक काउंटर-फायर से बचने की अनुमति देने के लिए काफी दूर से दागी जाती हैं।
- सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस में तीन गुना गति, 2.5 गुना उड़ान रेंज और उच्च रेंज है।

तीनों सशस्त्र बलों में तैनात संस्करणों का अभी भी नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है:

भूमि आधारित:

- भूमि आधारित ब्रह्मोस परिसर में चार से छह मोबाइल स्वायत्त लांचर हैं, जिनमें से प्रत्येक में तीन मिसाइलें हैं जिन्हें लगभग एक साथ दागा जा सकता है।

	• 2.8 मैक पर परिभ्रमण की क्षमता के साथ यह 400 किमी तक की सीमा तक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकता है। **जहाज आधारित:** • नौसेना ने 2005 से अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों में ब्रह्मोस को शामिल करना शुरू किया। • ये राडार क्षितिज से परे समुद्र-आधारित लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता रखते हैं। • नौसेना संस्करण समुद्र से समुद्र और समुद्र से भूमि मोड में सफल रहा है। • ब्रह्मोस को एकल इकाई के रूप में या 2.5 सेकंड के अंतराल से अलग करके आठ मिसाइलों के एक सैल्वो में लॉन्च किया जा सकता है। **एयर-लॉन्च किया गया:** • 22 नवंबर, 2017 को, बंगाल की खाड़ी में समुद्र-आधारित लक्ष्य के खिलाफ सुखोई -30 एमकेआई से पहली बार ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। • ब्रह्मोस से लैस सुखोई -30, जिनकी सीमा हवा में बिना ईंधन भरने के 1500 किमी की दूरी पर है, भूमि सीमाओं के साथ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में विरोधियों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक निवारक माना जाता है। **सबमरीन-लॉन्च किया गया** • इस संस्करण को पानी की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे से लॉन्च किया जा सकता है। • पनडुब्बी के दबाव पतवार से लंबवत रूप से लॉन्च किया जाता है, और पानी के नीचे और पानी के बाहर उड़ान के लिए अलग-अलग सेटिंग्स का उपयोग किया जाता है। • इस संस्करण का पहली बार मार्च 2013 में विशाखापत्तनम के तट पर एक जलमग्न मंच से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
सेमीकंडक्टर	**संदर्भ:** भारत को अपनी जैविक मांग को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, देश को अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर देश ताइवान पर निर्भरता को कम करते हैं। **इस संदर्भ में अर्धचालकों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं:** **सेमीकंडक्टर क्या है?** • यह आमतौर पर सिलिकॉन से बना एक भौतिक उत्पाद है, जो कांच जैसे इन्सुलेटर से अधिक बिजली का संचालन करता है, लेकिन तांबे या एल्यूमीनियम जैसे शुद्ध कंडक्टर से कम होता है। • सेमीकंडक्टर्स उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी घटक हैं जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लिकेशन, 5 जी संचार, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी उपभोज्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऑटोमोबाइल से लेकर रणनीतिक संचालन के क्षेत्रों तक के अनुप्रयोगों के व्यापक कवरेज के साथ। **भारत के लिए अवसर:** • भारत में अर्धचालकों की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। • भारत में असाधारण सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टैलेंट पूल है, जो विश्व के सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंजीनियरों के 20% तक का योगदान करता है। • वर्तमान दशक भारत के लिए एक अनूठा अवसर पेश करता है। कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और चीन में अपने ठिकानों के विकल्प तलाश रही हैं। • अर्धचालकों के लिए मूल्य श्रृंखला की स्थापना से पूरी अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव सुनिश्चित होगा।

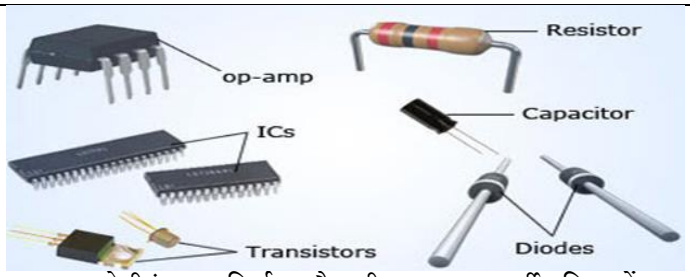

- सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण आधार पूर्वी एशिया में बहुत अधिक केंद्रित हैं, एक्ट ईस्ट नीति (Act East policy) क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के साथ संबंधों को जोड़ने और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष चुनौतियां:

- निवेश की भारी आवश्यकता
  - फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत होती है।
  - रॉ पानी को अल्ट्राहाई शुद्धता वाले पानी में बदलना इस प्रकार सभी सेमीकंडक्टर फैब के लिए एक महत्वपूर्ण और महंगी गतिविधि है।
- **पानी और बिजली की आपूर्ति**
  - सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण कूलिंग से लेकर वेफर सतह की सफाई तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में पानी की खपत करता है।
- तकनीकी प्रतिस्पर्धा
  - सेमीकंडक्टर चिप बनाने में कुछ तकनीकी कौशल शामिल होता है।
- अपर्याप्त रसद और उचित अपशिष्ट का अभाव
  - अपर्याप्त रसद और उचित अपशिष्ट निपटान के अभाव ने इसके उत्पादन की खराब स्थिति को और बढ़ा दिया है।
- निर्बाध गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति।
- कोविड-19
  - दुनिया भर में कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सहित देशों में महत्वपूर्ण चिप बनाने वाली सुविधाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया।
  - कोविड-19 के कारण चिप की कमी ने वाहन निर्माताओं को वर्ष 2021 में 110 अरब डॉलर के राजस्व नुकसान के साथ प्रभावित किया है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष
  - रूस-यूक्रेन संघर्ष और अर्धचालक मूल्य श्रृंखला के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए इसके निहितार्थ ने भी चिप निर्माताओं को अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है।

भारत द्वारा की गई पहल:

- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
  - यह $10 बिलियन की वित्तीय सहायता और अन्य गैर-वित्तीय उपाय प्रदान करता है
  - सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य उन कंपनियों/संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी) और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी हुई हैं।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन:
  - इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें अर्धचालक विकसित करने और विनिर्माण सुविधाओं और अर्धचालक डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने और चलाने

	के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है। • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ○ सरकार ने हाल ही में देश में अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में प्रमुख कदमों के रूप में पीएलआई और डीएलआई (PLI and DLI) योजनाओं की भी घोषणा की। • सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए छह साल की अवधि में फैले 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी हाथ में एक शॉट होने की उम्मीद है। ○ यह भारत में 1.7 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित करने का दावा करेगा।
एंटी रेडिएशन गोलियां	**खबरों में क्यों :** यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़िया पावर प्लांट में परमाणु आपदा की आशंका के साथ, यूरोपीय संघ ने आसपास के निवासियों के बीच वितरित 5.5 मिलियन एंटी-रेडिएशन गोलियों की आपूर्ति करने का फैसला किया है। **क्या होती है रेडिएशन इमरजेंसी?** • विकिरण आपातकाल अनियोजित या आकस्मिक घटनाएं हैं, जो मनुष्यों और पर्यावरण के लिए रेडियो-परमाणु खतरा पैदा करती हैं। • ऐसी स्थितियों में रेडियोधर्मी स्रोत से रेडिएशन का निकलना शुरू हो जाता है, जो इंसानों की जान ले लेती हैं और इस खतरे को कम करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। • ऐसी आपात स्थिति से निपटने में विकिरण रोधी गोलियों का उपयोग भी शामिल है। **एंटी रेडिएशन गोलियां क्या हैं?** • एंटी रेडिएशन गोलियां, पोटेशियम आयोडाइड (KI) की गोलियां होती हैं, जो रेडिएशन की स्थिति में कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। • इनमें गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन होता है और थायरॉइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण, और बाद में एकाग्रता को अवरुद्ध करने में मदद कर सकता है। **एंटी रेडिएशन गोलियां कैसे करती हैं काम?** • रेडियोएक्टिव विकिरण के रिसाव के बाद रेडियोधर्मी आयोडीन हवा में तैरता है और फिर भोजन, पानी और मिट्टी को दूषित कर देता है। • जबकि, बाहरी एक्सपोजर के दौरान जमा रेडियोधर्मी आयोडीन को गर्म पानी और साबुन का उपयोग करके हटाया जा सकता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर ये इंसानी शरीर के अंदर चला जाए, तो इंसानों की मौत हो सकती है। • आंतरिक जोखिम, या विकिरण, तब होता है जब रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में प्रवेश करता है और थायरॉयड ग्रंथि में जमा हो जाता है। • थायरॉयड ग्रंथि, जो शरीर के मेटाबोलिज्म को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है, उसके पास गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन से रेडियोधर्मी बनाने का कोई तरीका नहीं है। • पोटैशियम आयोडाइड (KI) की गोलियां 'थायरॉयड ब्लॉकिंग' हासिल करने के लिए इसी पर निर्भर करती हैं। • विकिरण के संपर्क में आने से कुछ घंटे पहले या उसके तुरंत बाद ली गई KI गोलियां यह सुनिश्चित करती हैं कि दवा में मौजूद गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड को "पूर्ण" बनाने के लिए जल्दी से अवशोषित हो जाए। • क्योंकि KI में बहुत अधिक गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन होता है, इसलिए थायरॉयड भर जाता है और अगले 24 घंटों के लिए - स्थिर या रेडियोधर्मी - किसी भी अधिक आयोडीन को अवशोषित नहीं कर सकता है। • लेकिन KI गोलियां केवल उपचार हैं और विकिरण द्वारा थायरॉयड ग्रंथि को हुए किसी भी नुकसान को उलट नहीं सकती हैं। • एक बार जब थायरॉयड ग्रंथि रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित कर लेती है, तो इसके संपर्क में आने वालों में थायराइड कैंसर विकसित होने का उच्च जोखिम होता है। **क्या ये तरीका पूर्ण सुरक्षा है?** • विकिरण रोधी गोलियां 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। • KI की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में कितना प्रवेश करता है और शरीर में कितनी जल्दी अवशोषित हो जाता है।

	• साथ ही, गोलियां हर किसी के लिए नहीं होती हैं। उन्हें 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। • हालांकि यह रेडियोधर्मी आयोडीन से थायरॉयड की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह अन्य अंगों को विकिरण संदूषण से नहीं बचा सकता है।
सर्ववैक (Cervavac)	**संदर्भ:** सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस (क्यूएचपीवी) वैक्सीन सर्ववैक लांच हुआ। **नए टीके के बारे में** • Cervavac को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के समन्वय में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। • एचपीवी टीके दो खुराक में दिए जाते हैं और दोनों के बाद विकसित होने वाले एंटीबॉडी छह या सात साल तक चल सकते हैं। • कोविड टीकों के विपरीत, सर्वाइकल कैंसर के टीके के लिए बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता नहीं हो सकती है। • अब तक, भारत में उपलब्ध एचपीवी टीकों का उत्पादन विदेशी निर्माताओं द्वारा प्रति खुराक 2,000 रुपये से 3,500 रुपये की अनुमानित लागत पर किया जाता था। • Cervavac के काफी सस्ते होने की संभावना है, जिसकी कीमत लगभग 200 से 400 रुपये होगी। • इसने एक मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का भी प्रदर्शन किया है जो सभी लक्षित एचपीवी प्रकारों और सभी खुराक और आयु समूहों के आधार पर लगभग 1,000 गुना अधिक है। **भारत में सर्वाइकल कैंसर कितना आम है?** • व्यापक रूप से रोके जाने योग्य होने के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। • वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि हर साल लगभग 25 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है, और भारत में इस बीमारी से 75 हजार से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, और 83% आक्रामक सर्वाइकल कैंसर भारत में एचपीवी 16 या 18 और दुनिया भर में 70% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। • भारत में सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग पांचवां हिस्सा है, जिसमें 1.23 लाख मामले और प्रति वर्ष लगभग 67,000 मौतें होती हैं। • लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर के मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कुछ उपभेदों से जुड़े होते हैं, जो एक सामान्य वायरस है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। • जबकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर दो साल के भीतर स्वाभाविक रूप से एचपीवी संक्रमण से छुटकारा पाती है, कुछ प्रतिशत लोगों में वायरस समय के साथ बना रह सकता है और कुछ सामान्य कोशिकाओं को असामान्य कोशिकाओं और फिर कैंसर में बदल सकता है।
आईएनएस विक्रांत	**खबरों में क्यों :** देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक (IAC-1) हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। • आईएनएस विक्रांत - 44,000 टन का स्वदेशी विमानवाहक पोत (आईएसी) - भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला विमान है। • इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। • **विशेषताएं:** विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, जो दो फुटबॉल मैदानों से अधिक है और 62 मीटर चौड़ा है। करीब 20 विमान हैंगर में पार्क किए जा सकते हैं। • इसकी शीर्ष गति लगभग 28 समुद्री मील (50 किमी प्रति घंटे से अधिक) और लगभग 7,500 समुद्री मील की सहनशक्ति के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति है। • वाहक पर 76 प्रतिशत से अधिक सामग्री और उपकरण स्वदेशी हैं, जिसमें 21,500 टन विशेष ग्रेड स्टील शामिल है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और पहली बार भारतीय नौसेना के जहाजों में उपयोग किया गया है। **यह अपने साथ ले जाएगा:** • रूस निर्मित मिग-29के लड़ाकू विमान, • कामोव-31 पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टर,

	• स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और • MH-60R बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर अमेरिकी रक्षा प्रमुख लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है।
इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD)	**खबरों में क्यों:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अभी घोषणा की है कि उसने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD) के साथ नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। **आईएडी क्या है?** • इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर या संक्षेप में आईएडी एक वायुमंडलीय प्रवेश पेलोड के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। • एक इन्फ्लेटेबल इन्वेलोप और एक इन्फ्लेटेंट (ऐसी कोई भी चीज जो इन्वेलोप को फुलाती है, जैसे हवा या हीलियम) आईएडी बनाती है। • वायुमंडल में प्रवेश करते समय, यह गुब्बारे की तरह फुलाता है और लैंडर को धीमा कर देता है। • वायु पूरित (इन्फ्लैटेंट) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह स्फीतिशील आवरण को एक ऐसी स्थिति में भर दे कि यह किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के लिए पेलोड को आवरित कर ले तथा वायुगतिकीय बल इसे मंद कर देते हैं। • सरल शब्दों में, IAD को पृथ्वी, मंगल या चंद्रमा जैसे किसी भी ग्रह पिंड के वातावरण में प्रवेश करने पर ड्रैग बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इसका आकार एक बंद, गैस-दबाव वाले निकाय द्वारा बनाए रखा जाता है एवं आंतरिक रूप से स्फीतिशील गैस भी उत्पन्न होती है। कुछ संस्करण भी पलित वायु या दोनों का उपयोग करते हैं। • नासा सहित कुछ अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले ही पराध्वनिक (सुपरसोनिक) एवं अतिध्वनिक (हाइपरसोनिक) प्रकारांतरों सहित प्रौद्योगिकी के उन्नत संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। • हालांकि, इसरो के निकट भविष्य के मिशनों के लिए, इसका परीक्षण किया गया वर्तमान संस्करण आदर्श है। **ISRO इसका उपयोग कहां करना चाहता है?** • आईएडी इसरो को अनेक अंतरिक्ष कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने में सहायता करेगा जिसमें रॉकेट के प्रयुक्त किए गए चरणों की पुनर्प्राप्ति, अन्य ग्रह निकायों के मिशन पर नीतभार अवतरण (पेलोड लैंडिंग) के लिए शामिल है।
iNCOVACC	**खबरों में क्यों :** राष्ट्रीय दवा नियामक, DGCI, ने वयस्कों में आपातकालीन उपयोग के लिए देश के पहले इंट्रा-नाक कोविड वैक्सीन - iNCOVACC को हरी झंडी दे दी है। • भारत बायोटेक द्वारा निर्मित, कोवैक्सिन के पीछे की कंपनी, वाशिंगटन विश्वविद्यालय-सेंट लुइस के साथ साझेदारी में, और आंशिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कोविड सुरक्षा कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित है। • नए टीके को प्राथमिक टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी गई है - इसे केवल अप्रतिरक्षित लोगों को ही दिया जा सकता है। • जो लोग पहले ही अन्य टीकों की पहली और दूसरी खुराक प्राप्त कर चुके हैं, वे "एहतियाती" तीसरी खुराक के रूप में iNCOVACC प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। • इसे नासिका मार्ग से पहुंचाया जाएगा। • यह संभावित रूप से म्यूकोसल झिल्ली में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा। • इसे न केवल संक्रमण से बचाने के लिए बल्कि वायरस के संचरण को कम करने के लिए भी डिजाइन किया

	गया है। • ऊपरी श्वसन पथ में स्थानीय एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकता है, जो संक्रमण और संचरण को कम करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। • टीका एक संशोधित चिंपैंजी एडेनोवायरस का उपयोग करता है, जो शरीर में प्रतिकृति नहीं बना सकता है, ताकि प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के लिए कोविड स्पाइक प्रोटीन ले जाया जा सके। **इंट्रानैसल वैक्सीन के लाभ:** • यह अधिक प्रभावी होने का वादा करता है, क्योंकि इससे संक्रमण के स्थान पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की उम्मीद है (श्वसन श्लेष्मा) • गैर-आक्रामक, सुई मुक्त। • प्रशासन में आसानी - प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। • सुई से जुड़े जोखिमों (चोटों और संक्रमणों) का उन्मूलन। • उच्च अनुपालन (बच्चों और वयस्कों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त)। • स्केलेबल विनिर्माण - वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम। यह एक महीने में 100 मिलियन खुराक का उत्पादन कर सकता है। **भारत के औषधि महानियंत्रक के बारे में:** • भारत के औषधि महानियंत्रक भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं। • भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके, और सीरा जैसी विशिष्ट श्रेणियों की दवाओं के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। • DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है। • यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। • DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक और गुणवत्ता निर्धारित करता है। • दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना शामिल है। • राष्ट्रीय संदर्भ मानक की तैयारी और रखरखाव। • औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिए। • DCGI चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के दायरे में आने वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) के रूप में भी कार्य करता है।
Qimingxing-50, या मॉर्निंग स्टार-50	**खबरों में क्यों :** चीन ने अपने पहले पूरी तरह से सौर-संचालित मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) / ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम 'किमिंगक्सिंग -50' या मॉर्निंग स्टार -50 है जो महीनों तक निर्बाध रूप से उड़ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उपग्रह के रूप में भी कार्य कर सकता है। **यांत्रिकी:** • 164-फीट के पंखों के साथ, ड्रोन एक बड़ी मशीन है जो पूरी तरह से सौर पैनलों द्वारा संचालित होती है। • उच्च-तुंगता, अधिक- स्थिरता (HALE) के साथ UAV लंबी अवधि तक हवा में रह सकती है। • यह ड्रोन 20 किमी की ऊँचाई से ऊपर उड़ता है जहाँ बिना बादलों के स्थिर वायु प्रवाह होता है। • यह पंख, इन ड्रोनों को विस्तारित अवधि के लिए क्रियाशील रहने के लिए, सौर उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करते हैं। • वास्तव में, ड्रोन महीनों, यहां तक कि वर्षों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। **ड्रोन और सैटेलाइट के बीच क्रॉस:** • ड्रोन, निकट-अंतरिक्ष में – पृथ्वी की सतह से 20 किमी से 100 किमी ऊपर कार्य कर सकते हैं – जिससे ये ड्रोन, उपग्रह की भांति कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। • इन ड्रोनों को 'उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफार्म स्टेशन' या छद्म उपग्रह भी कहा जाता है। • चीन के पास पहले से ही यह क्षमता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार-50 की अधिक- स्थिरता इसकी क्षमता को लंबी अवधि तक उपलब्ध कराने हेतु एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।
सतह से हवा में मार	**खबरों में क्यों :** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली

करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया (QRSAM) प्रणाली	त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली (QRSAM) प्रणाली के छह उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। **इसके बारे में** • यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है। • इसे DRDO द्वारा मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद कतार को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। • QRSAM एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से बनाए गए डिब्बों से संग्रहीत और संचालित किया जाता है। • यह चलते-फिरते लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है और छोटे पड़ावों के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। • क्यूआरएसएएम हथियार प्रणाली की विशिष्टता यह है कि यह खोज और ट्रैक क्षमता और शॉर्ट हॉल्ट पर आग के साथ चलते-फिरते काम कर सकती है। • संपूर्ण हथियार प्रणाली को मोबाइल पर कॉन्फ़िगर किया गया है और यह चलते-फिरते वायु रक्षा प्रदान करने में सक्षम है। • इसकी सीमा 25 से 30 किमी तक है। • इसमें एक लॉन्चर के साथ दो रडार - एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार - भी शामिल हैं। • दोनों राडार में "सर्च ऑन मूव" और "ट्रैक ऑन मूव" क्षमताओं के साथ 360-डिग्री कवरेज है। • यह प्रणाली कॉम्पैक्ट है, जो एकल चरण ठोस चालित मिसाइल का उपयोग करती है तथा इसमें डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दो-तरफा डेटा लिंक और टर्मिनल सक्रिय साधक के साथ एक मध्य-पाठ्यक्रम जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है।
प्रोजेक्ट 17 ए के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी'	**खबरों में क्यों :** प्रोजेक्ट 17ए तारागिरी का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹25,700 करोड़ है। **विशेषताएँ:** • स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए तारागिरी में अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, सूचना प्रणाली, एक एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, विश्व स्तरीय मॉड्यूलर रहने की जगह, एक परिष्कृत बिजली वितरण प्रणाली और कई अन्य उन्नत सुविधाएं होंगी। • यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस होगा और जहाज की वायु रक्षा क्षमता को दुश्मन के विमान और जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • 'तारागिरी (Taragiri)' पोत को 3510 टन के अनुमानित भार के साथ लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के इन-हाउस डिजाइन संगठन, ब्यूरो ऑफ नवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। • 149.02 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा जहाज, दो गैस टर्बाइनों और दो मुख्य डीजल इंजनों के एक CODOG संयोजन द्वारा संचालित है, जिन्हें लगभग 6,670 टन के विस्थापन पर 28 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **संरचना:** • इस जहाज को एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हल ब्लॉक निर्माण और एमडीएल में स्लिपवे पर एकीकरण और निर्माण शामिल है। • तारागिरी की कील (समर्थन और स्थिरता बढ़ाने के लिए जहाज के आधार के साथ लकड़ी या स्टील की संरचना) 10 सितंबर, 2020 को रखी गई थी, और जहाज की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। • P17A फ्रिगेट के हल निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला स्टील स्वदेशी रूप से विकसित DMR 249A है जो सेल द्वारा निर्मित एक कम कार्बन माइक्रो मिश्र धातु ग्रेड स्टील है। **पृष्ठभूमि** • P17A श्रेणी के उदयगिरि का दूसरा जहाज इस साल 17 मई को लॉन्च किया गया था और वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के दौरान समुद्री परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। चौथे और अंतिम जहाज की कील 28 जून को

	रखी गई थी।
CRISPR जैव प्रौद्योगिकी	**खबरों में क्यों :** भारत ने सिकल सेल एनीमिया (यह मुख्य रूप से आदिवासी आबादी को प्रभावित करता है) को ठीक करने के लिए CRISPR पद्धति विकसित करने के लिए 5 साल की एक परियोजना को मंजूरी दी है क्योंकि इस तकनीक ने नैदानिक परीक्षणों में त्रुटिहीन परिणाम दिए हैं। **CRISPR के बारे में:** • यह एक जीन-संपादन तकनीक है जो विशिष्ट प्रोटीन और आरएनए अणुओं जैसे जैव रासायनिक उपकरणों का उपयोग करके जीवित जीवों के आनुवंशिक कोड का 'संपादन' करती है; इसमें आमतौर पर एक नए जीन का परिचय, या एक मौजूदा जीन का दमन शामिल होता है, जिसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। • CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स के लिए छोटा है, जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डीएनए के क्लस्टर्ड और रिपीटिटिव सीक्वेंस का एक संदर्भ है, जिसके कुछ वायरल रोगों से लड़ने के लिए प्राकृतिक तंत्र को इस जीन-एडिटिंग टूल में दोहराया जाता है। • यह रोगों को ठीक करने, शारीरिक विकृतियों को रोकने या यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए आनुवंशिक जानकारी को 'सुधार' करने की संभावना को ओपन करता है। • जेनिफर डौडना और इमैनुएल चारपेंटियर ने CRISPR के संबंध में 2020 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। 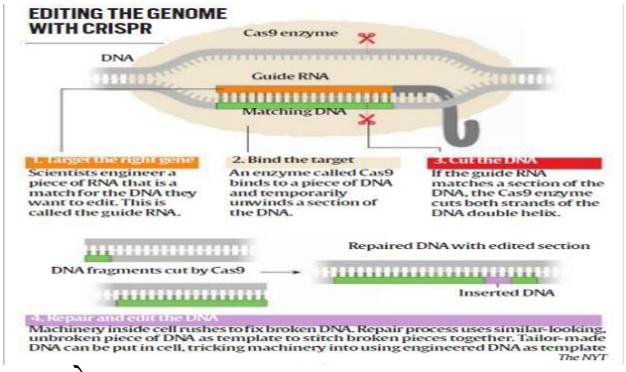 **अनुप्रयोग:** • सिकल सेल एनीमिया जैसे जीन में अवांछित परिवर्तन या उत्परिवर्तन के कारण आनुवंशिक रोग जैसे कई रोगों का स्थायी इलाज, कलर ब्लाइंडनेस सहित नेत्र रोग, कई प्रकार के कैंसर, मधुमेह, एचआईवी, और यकृत और हृदय रोग या वंशानुगत शामिल है। • **विकृतियों का इलाज:** यह जीन अनुक्रमों में असामान्यताओं से उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए भी सही है, जैसे कि रुका हुआ या धीमा विकास, भाषण विकार, या खड़े होने या चलने में असमर्थता। • **उपचारात्मक समाधान:** सीआरआईएसपीआर-आधारित चिकित्सीय समाधान गोली या दवा के रूप में नहीं हैं। इसके बजाय, प्रत्येक रोगी की कुछ कोशिकाओं को निकाला जाता है, जीन को प्रयोगशाला में संपादित किया जाता है, और ठीक किए गए जीन को फिर से रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है। • **कृषि:** विशिष्ट वांछनीय लक्षणों के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित रूपों को विकसित करने में मदद करना।
नासा का डार्ट (दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण) मिशन	**खबरों में क्यों :** नासा का DART (दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण) मिशन पृथ्वी को क्षुद्रग्रहों से बचाने के लिए मानवता का पहला ग्रह रक्षा प्रणाली परीक्षण (यानी, एक नागरिक मिशन में रक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना) होगा जो भविष्य में इसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। **डार्ट मिशन के बारे में:** इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रहों के आकार और संरचना को उसकी कक्षा में परिवर्तन और निकाले गए पदार्थ के आधार पर समझना है। डार्ट का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। • डार्ट प्रभाव से लगभग 50 मिनट पहले तक डिडिमोस को लक्षित करेगा। भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ड्रैको कैमरा और रोल-आउट सोलर ऐरेज़ (आरओएसए) जैसी अन्य तकनीकों का भी परीक्षण किया जाएगा। • **डिमोर्फोस:** यह 160 मीटर चौड़ा है और बहुत बड़े क्षुद्रग्रह डिडिमोस (लगभग 780 मीटर चौड़ा) की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है। • **उपयोग में टेलीस्कोप:** वेब टेलीस्कोप, हबल और एक क्यूबसैट जिसे एलआईसीआईएक्यूब

	(LICIACube) कहा जाता है, जो सिस्टम में बदलावों का मापन करता है और छवियों को वापस प्रसारित करता है। • ऑप्टिकल नेविगेशन के लिए DRACO, या डिडिमोस टोही और क्षुद्रग्रह कैमरा एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा है जो DART के स्वायत्त मार्गदर्शन प्रणाली का समर्थन करते हुए डिडिमोस और डिमोर्फोस की छवियों को कैप्चर करता है। टीटी को वन-वे (one-way) कम्युनिकेशन में 38 सेकंड का समय लगता है। • क्यूबसैट, एलआईसीआईएक्यूब (LICIACube) इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया है, इसमें 2 कैमरे हैं और यह स्वायत्त रूप से संचालित होता है।
एथेरियम (Ethereum)	**ख़बरों में क्यों :** एथेरियम का तकनीकी अपग्रेड हुआ है और इस अपग्रेड को 'एथेरियम मर्ज' कहा जाता है। • इथेरियम ने अपने एल्गोरिथम को प्रूफ-ऑफ-वर्क (पीओडब्ल्यू) सर्वसम्मति पद्धति से लेन-देन को प्रूफ-ऑफ-स्टेक (पीओएस) में सेट करने के तरीके से परिवर्तित कर दिया है। **इसके बारे में:** अधिकांश ब्लॉकचेन में प्रूफ-ऑफ वर्क (PoW) एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। प्रूफ-ऑफ वर्क (PoW) वितरित सर्वसम्मति की एक प्रणाली है जो यह साबित करने के लिए कंप्यूटिंग शक्ति पर निर्भर करती है कि किसी ने नेटवर्क पर उनके प्रभाव के आनुपातिक वैध ब्लॉक बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में काम किया है। ये एल्गोरिदम एक विश्वास रहित प्रणाली बनाते हैं जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं न कि एक व्यक्ति या एक संगठन। • 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' (PoS) एक प्रकार का सर्वसम्मति तंत्र है जिसका उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को यादृच्छिक रूप से चयनित सत्यापनकर्ताओं के माध्यम से मान्य करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली के साथ, क्रिप्टोक्यूरेंसी के मालिक अपने सिक्कों को दांव पर लगा सकते हैं, जो उन्हें लेनदेन के नए ब्लॉक की जांच करने और उन्हें ब्लॉकचेन में जोड़ने का अधिकार देता है। इसे स्टेकिंग की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। **अपग्रेड का महत्व:** • **बढ़ी हुई मापनीयता:** ब्लॉकों के आकार में कमी से डेटा की मात्रा कम हो जाएगी जो नोड्स को नेटवर्क को अधिक स्केलेबल बनाने और सुरक्षा के समान स्तर को बनाए रखते हुए प्रति सेकंड अधिक लेनदेन को संसाधित करने में आसान बनाने की आवश्यकता होती है। • **स्टोर करने में सरलता :** नोड्स चलाने वाले लोगों के लिए कम खर्चीले हार्डवेयर पर ब्लॉकचेन को स्टोर करना आसान होता है। यह नेटवर्क को स्पैम हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। • नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करने से यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा और अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करेगा। • **स्टेकिंग की अवधारणा:** जिसका अर्थ है अपने टोकन को लॉक करना जैसे कि बचत खाते में पैसा जमा करना। आप जितने अधिक टोकन दांव पर लगाते हैं, नेटवर्क पर आपका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। • ब्लॉकों के बीच कम अंतर के कारण तेजी से लेन-देन का समय • लेन-देन 'में कम विलंबता • **हार्डवेयर माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता न होना :** विश्वास कम होने के कारण, वितरित सर्वसम्मति एल्गोरिथ्म जिसके लिए महंगे हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। **इथेरियम के बारे में:** • वर्ष 2014 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी शुरू की गई। • इथेरियम एक विकेन्द्रीकृत, खुला स्रोत ब्लॉकचेन है। यह ईथर मंच की मूल क्रिप्टोक्यूरेंसी है। • इथेरियम की कल्पना वर्ष 2013 में प्रोग्रामर विटालिक ब्यूटिरिन द्वारा की गई थी। • आज इथेरियम को डेवलपर्स के बीच सबसे अधिक अपनाया गया है और यह वेब3 की प्राथमिक अवसंरचना परत है।
मलेरिया का टीका	**खबरों में क्यों :** मलेरिया बूस्टर वैक्सीन 80 प्रतिशत तक प्रभावकारिता है: द लैंसेट इंफेक्शियस डिसीज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधार्थियों ने यह दावा किया है। • R21/Matrix-M मलेरिया के टीके का लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। • वर्ष 2021 में, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय ने निष्कर्षों की सूचना दी - 12-महीने के अनुवर्ती टीके ने 77% की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया।

	• यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के मलेरिया वैक्सीन प्रौद्योगिकी रोडमैप लक्ष्य को कम से कम 75% प्रभावकारिता के साथ पूरा करने वाला पहला है। • अध्ययन में 5 से 17 महीने की आयु के 450 प्रतिभागियों को शामिल किया गया और हाल ही में 80% से अधिक की प्रभावकारिता की सूचना दी गई। **मलेरिया के बारे में:** मच्छर जनित संक्रामक रोग जो मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करता है। • यह प्लास्मोडियम समूह के एकल-कोशिका वाले सूक्ष्मजीवों के कारण होता है और विशेष रूप से संक्रमित एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से मच्छर की लार से परजीवी व्यक्ति के रक्त में मिल जाते हैं। • लक्षणों में बुखार, थकान, उल्टी और सिरदर्द शामिल हैं। गंभीर मामलों में, यह पीलिया, दौरे, कोमा या मृत्यु का कारण बन सकता है। • रोग उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक है जो भूमध्य रेखा के चारों ओर एक विस्तृत बैंड में मौजूद हैं।

पारिस्थितिक निके मॉडलिंग	**खबरों में क्यों :** हिमालय बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मसाले , केसर की जांच के लिए मॉडलिंग रणनीतियों का इस्तेमाल किया।
	केसर के बारे में: क्रोकस सैटिवस , केसर का पौधा, कॉर्म नामक भूमिगत तनों के माध्यम से फैलता है।
	• यह भूमध्यसागरीय जलवायु में सबसे अच्छा बढ़ता है।
	• नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, ईरान दुनिया के केसर का लगभग 90% उत्पादन करता है।
	• **उपयोग:** खाने में स्वाद बढ़ाने, तंत्रिका तंत्र के विकारों को ठीक करने में, एक अवसाद रोधी के रूप में कार्य करता है, इसके कुछ रासायनिक घटकों में कैंसर रोधी गुण पाए गए हैं ।
	• भारत दुनिया के 5% केसर का उत्पादन करता है। ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के कुछ सबसे बेशकीमती केसर कश्मीर की पुरानी झीलों में उगाए गए हैं।
	• **कृषि-जलवायु स्थितियां:** उच्च पीएच मान (6.3 से 8.3), अच्छी जल निकासी वाली मृदा, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के गर्मियों के तापमान (जब फूल विकसित होते हैं) और पोषक तत्वों वाली मृदा केसर की कृषि के लिए अनुकूल है।
	• औसत राष्ट्रीय उपज = 2.6 किलो प्रति हेक्टेयर
	पारिस्थितिक निके के बारे में:
	• एक पारिस्थितिक निके पर्यावरणीय परिस्थितियों का सही सेट है जिसके तहत एक जानवर या पौधे की प्रजाति पनपेगी। पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कई प्रकार के पारिस्थितिक निशान हो सकते हैं। जैव विविधता इन प्रजातियों के कब्जे में होने का परिणाम है जो उनके लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल हैं ।
	• उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय पौधे शुष्क, शुष्क पारिस्थितिक निचे के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि उनमें अपनी पत्तियों में पानी जमा करने की क्षमता होती है।तापमान, उपलब्ध प्रकाश की मात्रा, मिट्टी की नमी जैसे निर्जीव, या अजैविक कारक भी पारिस्थितिक निचे को प्रभावित करते हैं।
	• जलवायु परिवर्तन के कारण, मौजूदा प्रजातियों की अपनी जैव-भौगोलिक विशेषताओं को बनाए रखने की क्षमता में परिवर्तन हो सकता है।
	• **कृषि पर प्रभाव:** सदियों से अच्छी तरह से काम करने वाली प्रथाएं और फसल विकल्प अब आदर्श नहीं हो सकते हैं जिससे भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता, शिकारियों और प्रतिस्पर्धी प्रजातियों की घटना प्रभावित हो सकती है।
	पारिस्थितिक निके मॉडलिंग के बारे में:
	• पारिस्थितिक निके मॉडलिंग नई संभावनाओं की पहचान के लिए भविष्य का एक उपकरण है ।
	  ○ मौजूदा आवास के लिए नए निवासी ।
	  ○ नए भौगोलिक स्थान जहां एक वांछनीय पौधा अच्छी तरह से विकसित हो सकता है।
	• मॉडलिंग में पर्यावरण के बारे में डेटा की तुलना करने और किसी दिए गए पारिस्थितिक स्थान के लिए आदर्श क्या होगा, इसके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग शामिल है।

उलझी हुई परमाणु घड़ियाँ	**संदर्भ:** ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक प्रयोग में दो अद्वितीय और यहां तक कि दिमागी दबदबे वाली खोजों को भी कहा जा सकता है, अर्थात् उच्च-सटीक परमाणु घड़ियां और क्वांटम उलझाव, दो परमाणु घड़ियों को प्राप्त करने के लिए जो "उलझी हुई" हैं। इसका मतलब है कि उनकी आवृत्तियों को एक साथ मापने में अंतर्निहित अनिश्चितता अत्यधिक कम हो जाती है। **उलझाव (एंटेंगलमेंट) की स्थिति:** • क्वांटम भौतिकी में, उलझाव एक अजीब घटना है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा "दूरी पर डरावनी क्रिया" के रूप में वर्णित किया गया है। • यह कहने का एक तरीका है कि उनके भौतिक गुण, जैसे कि स्पिन, या इस मामले में, आवृत्ति, अलग-अलग होती हैं। • उन विशेषताओं के अलग-अलग माप करने के बजाय, जिनमें माप में सटीकता की एक मौलिक सीमा शामिल है, आप दोनों की एक साथ तुलना कर सकते हैं - एक प्रणाली पर विशेषता को मापना, आपको क्वांटम उलझाव (एंटेंगलमेंट) में दूसरी प्रणाली के बारे में बताता है। यह बदले में क्वांटम सिद्धांत द्वारा अनुमत अंतिम सीमा तक माप की सटीकता में सुधार करता है। **परमाणु घड़ियां:** • परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो परमाणुओं की अनुनाद आवृत्तियों की निगरानी करके समय को मापती है। यह विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले परमाणुओं पर आधारित है। यह घटना लगभग 20 मिलियन वर्षों में केवल एक बार प्राप्त करने या खोने की सटीकता के साथ एक सीज़ियम परमाणु के 9,19,26,31,770 दोलनों द्वारा ली गई दूसरी बार की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स (एसआई) परिभाषा के आधार के रूप में कार्य करती है। • "ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक्स (Optical lattice clocks)" स्ट्रोंटियम परमाणुओं का उपयोग करती हैं और अधिक सटीक होती हैं क्योंकि वे 15 अरब वर्षों में केवल एक बार सेकंड खोती हैं। **अवधारणा का प्रमाण:** • इस तरह के क्वांटम नेटवर्क का प्रदर्शन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन यह ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों के क्वांटम उलझाव का पहला प्रदर्शन है। • यहां मुख्य विकास यह है कि हम इस दूरस्थ उलझाव की निष्ठा और दर को उस बिंदु तक सुधार सकते हैं जहां यह वास्तव में अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है, जैसे कि इस घड़ी प्रयोग में। • अपने प्रदर्शन के लिए, शोधकर्ताओं ने दूरस्थ उलझाव उत्पन्न करने में आसानी के लिए स्ट्रोंटियम परमाणुओं का उपयोग किया। वे इसे बेहतर घड़ियों के साथ आजमाने की योजना बना रहे हैं जैसे कि वे जो कैल्शियम का उपयोग करती हैं। • अब हम व्यावहारिक तरीके से दूरस्थ उलझाव उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ बिंदु पर, यह अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए उपयोगी हो सकता है। **अनुप्रयोग:** • मौलिक स्थिरांकों के स्थान-समय भिन्नता का अध्ययन करना, डार्क मैटर की जांच करना, सटीक भूगणित, जीपीएस में सटीक समय रखना, या मंगल ग्रह पर दूर से सामान की निगरानी करना आदि।
फ्लेक्स ईंधन प्रौद्योगिकी	**खबरों में क्यों :** भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान को एक नए पायलट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वैकल्पिक ईंधन को अपनाने और ब्राजील, कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य बाजारों में इस विशेष तकनीक की व्यावसायिक तैनाती को दोहराने के लिए कार निर्माताओं को सरकार के नेतृत्व वाले पुश के हिस्से के रूप में राष्ट्रव्यापी पायलट शुरू किया गया है। • संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 मिलियन से अधिक फ्लेक्स ईंधन वाहन हैं। • ब्राजील इस सेगमेंट में अग्रणी है। **फ्लेक्स ईंधन प्रौद्योगिकी के यांत्रिकी के बारे में :** • एक फ्लेक्स ईंधन, या लचीले ईंधन, वाहन में एक आंतरिक दहन इंजन (ICE) होता है, लेकिन एक नियमित पेट्रोल या डीजल वाहन के विपरीत, यह एक से अधिक प्रकार के ईंधन, या यहां तक कि ईंधन के मिश्रण पर भी चल सकता है। • आंतरिक दहन इंजन पेट्रोल और इथेनॉल या मेथनॉल के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकता है और 100 प्रतिशत

	पेट्रोल या इथेनॉल पर भी चल सकता है। • यह इंजन को एक ईंधन मिश्रण सेंसर और एक इंजन नियंत्रण मॉड्यूल (ईसीएम) प्रोग्रामिंग से लैस करके संभव बनाया गया है जो निर्दिष्ट ईंधन के किसी भी अनुपात के लिए सेंसेस (senses) और स्वचालित रूप से समायोजित करता है। • फ्लेक्स ईंधन वाहनों में एक ईंधन प्रणाली होती है, और अधिकांश घटक वही होते हैं जो एक पारंपरिक पेट्रोल कार में मिलते हैं। • इथेनॉल या मेथनॉल में विभिन्न रासायनिक गुणों और ऊर्जा सामग्री को समायोजित करने के लिए विशेष इथेनॉल-संगत घटकों जैसे संशोधनों की आवश्यकता होती है। इथेनॉल की उच्च ऑक्सीजन सामग्री को समायोजित करने के लिए ईसीएम को भी कैलिब्रेट किया जाता है। **महत्व:** • एथेनॉल सम्मिश्रण का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, और कार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को तेजी से कम करता है। • यह परिवहन के लिए तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करेगा। • उच्च इथेनॉल मिश्रणों पर परिचालन करते समय कई फ्लेक्स ईंधन वाहनों ने त्वरण प्रदर्शन में सुधार किया है। **भारत में इथेनॉल उत्पादन के बारे में:** • वर्तमान में, पेट्रोल के साथ लगभग 9.5% इथेनॉल सम्मिश्रण अधिकांश महानगरों में पंपों में वितरित ईंधन में प्राप्त किया गया है और यह संभावना है कि नवंबर 2022 तक लक्षित 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त किया जाएगा। • लेकिन यह एक बड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है, सरकार के वर्ष 2025 के लक्ष्य के साथ पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण की परिकल्पना राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति वर्ष 2018 में की गई है।
भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली/NavIC	**संदर्भ:** भारत सरकार अगले साल से देश में बेचे जाने वाले नए उपकरणों में अपने NavIC नेविगेशन सिस्टम के लिए समर्थन सक्षम करने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं पर जोर दे रही है। **वैश्विक मानक निकाय 3GPP ने भारत के क्षेत्रीय NavIC को मंजूरी दी है:** • इससे पहले, वैश्विक मानक निकाय 3GPP, जो मोबाइल टेलीफोनी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम NavIC को मंजूरी देता है। • विनिर्देश अनुमोदन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मोबाइल डिवाइस निर्माताओं द्वारा NaVIC (भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन) के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देगा, जिसका अर्थ है कि ऐसे निर्माता अब NaVIC के साथ संगत नेविगेशन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं ताकि इन उपकरणों के उपयोगकर्ता आसानी से देसी GPS (desi GPS) या NaVIC सिग्नल्स का उपयोग कर सकें। • 3GPP द्वारा NavIC की स्वीकृति के निहितार्थ वाणिज्यिक बाजार में एनएवीआईसी प्रौद्योगिकी को 4G, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में उपयोग के लिए लाएंगे। • भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के पास NavIC पर आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) और उत्पादों को डिजाइन करने का अवसर होगा। **3GPP क्या है:** • इसमें दुनिया भर से सात दूरसंचार मानक विकास संगठन (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC) शामिल हैं और अपने सदस्यों को 3GPP प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करने वाले विनिर्देशों का उत्पादन करने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। • वर्तमान में 3GPP के पास सेलुलर पोजिशनिंग सिस्टम के लिए BDS (चाइनीज), गैलीलियो (यूरोपीय), GLONASS (रूसी) और GPS (US) से वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का समर्थन है। **NavIC के बारे में:** • भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, जिसका संचालनात्मक नाम NavIC है, एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो सटीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करती है। इसमें भारत और इसके चारों ओर 1,500 किमी का क्षेत्र शामिल है, जिसमें आगे विस्तार की योजना है।

- NavIC, या भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड-अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
- यह वर्ष 018 में शुरू किया गया।
- आईआरएनएसएस दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, अर्थात् मानक पोजिशनिंग सर्विस (SPS) जो सभी उपयोगकर्ताओं और प्रतिबंधित सेवा को प्रदान की जाती है और प्रतिबंधित सेवा (RS), जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक एन्क्रिप्टेड सेवा है।
- आईआरएनएसएस प्रणाली से प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता प्रदान करने की उम्मीद है।

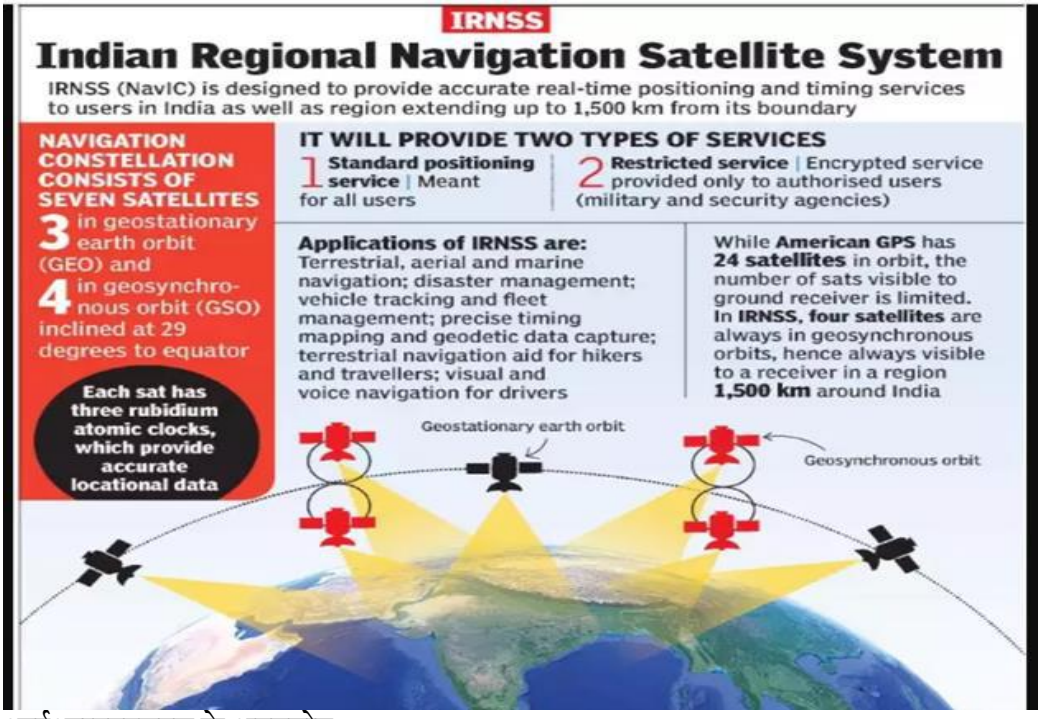

आईआरएनएसएस के अनुप्रयोग:

- स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन
- आपदा प्रबंधन
- वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन
- मोबाइल फोन के साथ एकीकरण
- सटीक समय
- मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर
- हाइकर्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता
- ड्राइवरों के लिए दृश्य और साउंड नेविगेशन

रोहिणी आरएच-200 साउंडिंग रॉकेट

खबरों में क्यों : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) रोहिणी आरएच -200 साउंडिंग रॉकेट के लगातार 200वें सफल प्रक्षेपण में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद कर रहा है।

रॉकेट के बारे में: साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जाँच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये किया जाता है।

- आरएच -200 एक दो-चरणीय रॉकेट है जो वैज्ञानिक पेलोड के साथ 70 किमी की ऊँचाई तक जाने में सक्षम है।
- आरएच-200 के पहले और दूसरे चरण ठोस मोटर्स द्वारा संचालित होते हैं।
- इसके नाम में '200' रॉकेट के व्यास को मिमी में दर्शाता है।
- अन्य परिचालनात्मक रोहिणी संस्करण RH-300 Mk-II और RH-560 Mk-III हैं।
- हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (HTPB) पर आधारित एक नए प्रणोदक का उपयोग करने वाला

पहला RH-200 सितंबर 2020 में TERLS से सफलतापूर्वक उड़ाया गया था, जबकि पिछले संस्करणों में पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC)-आधारित प्रणोदक का उपयोग किया गया था।

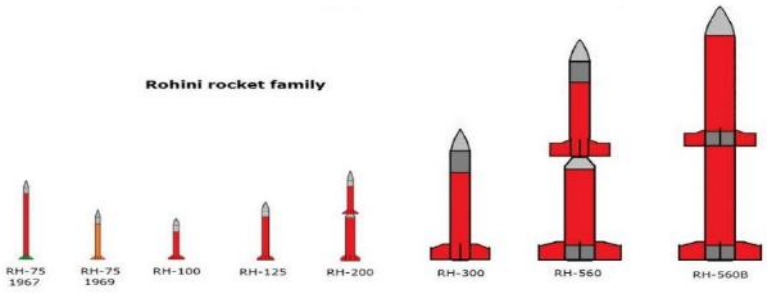

साउंडिंग रॉकेट के बारे में:

- इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए भी किया जाता है, जिनमें ग्रहण से संबंधित परिघटनाएं भी शामिल हैं।
- पहला साउंडिंग रॉकेट अमेरिकन नाइके-अपाचे था - जो वर्ष 1963 में लॉन्च किया गया।
- इसरो ने वर्ष 1967 में अपना स्वयं का संस्करण - रोहिणी RH-75 - लॉन्च किया।
- अंतरिक्ष एजेंसी ने नोट किया है कि साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम "वास्तव में वह आधारशिला था जिस पर प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का भवन बनाया गया था।
- आज, ये छोटे रॉकेट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा दोनों से लॉन्च किए गए हैं।

विविध

भारतीय नौसेना ध्वज (झंडा)

खबरों में क्यों : भारत के प्रधानमंत्री ने कोच्चि में नए नौसेना पताका (ध्वज) का अनावरण किया, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर है, जिन्होंने एक आधुनिक नौसेना की नींव रखी।

भारतीय नौसेना शिवाजी (शासनकाल 1674-80) और महान मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे (1669-1729) के साथ कैसे पहचान करती है, और उन्होंने समुद्र पर मराठा वर्चस्व कैसे सुनिश्चित किया?

- छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में समुद्र-यात्रा कौशल पर बहुत जोर दिया और एक आधुनिक नौसैनिक फ़ोर्स की नींव रखी।
- भारतीय नौसेना ने लोनावाला में आईएनएस शिवाजी के रूप में एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और प्रशंसित मराठा नौसैनिक कमांडर कान्होजी आंग्रे के नाम पर पश्चिमी नौसेना कमान के तट आधारित रसद और प्रशासनिक केंद्र का नाम आईएनएस आंग्रे रखा है।
- नौसेना की नई पताका पर शिवाजी की मुहर के अष्टकोणीय डिजाइन का उपयोग मराठा साम्राज्य की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के गर्भनाल संबंधों पर एक औपचारिक मुहर है।

नौसैनिक कौशल की सीमा

- शिवाजी के रणनीतिक विचार ने यह सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति स्थापित की गई।
- शिवाजी के अधीन नौसेना इतनी मजबूत थी कि मराठा अंग्रेजों, पुर्तगाली और डचों के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते थे।
- शिवाजी नेकल्यान, भिवंडी और गोवा जैसे शहरों में व्यापार के लिए और एक लड़ाकू नौसेना स्थापित करने के लिए जहाजों का निर्माण किया।
- उन्होंने मरम्मत, भंडारण और आश्रय के लिए कई समुद्री किलों और ठिकानों का भी निर्माण किया। शिवाजी ने समुद्र तट पर जंजीरा के सिद्दियों के साथ कई लंबी लड़ाइयाँ लड़ी।
- उन्होंने दक्कन में आठ या नौ बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद अपने दम पर विदेशियों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया।

कनोहजी आंग्रे (Kanhoji Angre)

- कनोहजी आंग्रे मराठा नौसेना के कमांडर थे, और उन्हें एक मजबूत नौसैनिक नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि मराठों को समुद्र में आगे बढ़ने की शक्ति मिली।
- कान्होजी को अंग्रेजी, पुर्तगाली और डच नौसैनिक बलों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने का श्रेय दिया जाता है।
- उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य के लिए अपना व्यापार करने वाले व्यापारियों को समुद्र पर संरक्षित किया जाए।
- उन्होंने रत्नागिरी के निकट सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग में अधिक ठिकानों के साथ कोलाबा में एक आधार स्थापित किया।

	जंजीरा के सिद्दी (Siddis of Janjira): • जंजीरा राज्य ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एक रियासत थी। • इसके शासक हबेश वंश के सिद्दी वंश के थे और राज्य बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन था। • जंजीरा राज्य महाराष्ट्र के वर्तमान रायगढ़ जिले में कोंकण तट पर स्थित था।
नैनो-यूरिया (Nano-Urea)	**ख़बरों में क्यों :** व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए तेजी से ट्रैक किए जाने के बावजूद, नैनो-यूरिया का अभी पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया है। नैनो-यूरिया की मंजूरी फरवरी 2021 में दी गई थी। • नैनो-यूरिया को भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी (इफको) एक बहु-राज्य सहकारी समिति (नई दिल्ली में स्थित) द्वारा विकसित किया गया है और सरकार द्वारा पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए रामबाण के रूप में प्रचारित किया गया है। **पारंपरिक यूरिया पर लाभ:** • फील्ड परीक्षणों में, यह दावा किया गया था कि तरल की एक आधा लीटर की बोतल (~ 240 रुपये और एक एकड़ फसल के लिए अच्छी है) यूरिया ग्रेन्युल के 45 किलो बोरी की भरपाई कर सकती है (लागत लगभग ₹3,000 हालांकि यह है किसान को ₹242 पर उपलब्ध कराया गया। • इनपुट और भंडारण लागत को कम करके किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के अलावा, नैनो यूरिया तरल कृषि उपज और उत्पादकता को बढ़ाने का वचन देता है। • नैनो यूरिया तरल मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करते हुए फसल पोषक तत्वों की दक्षता को बढ़ाकर पौधों के पोषण के लिए दीर्घकालिक समाधान देने का भी वचन देता है। • नैनो यूरिया के प्रयोग में कोई अपव्यय न होने के कारण इसका उपयोग करना बहुत ही कुशल है। इसलिए, इसकी प्रभावकारिता 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पारंपरिक यूरिया प्रभावकारिता केवल 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत है। • केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025 तक, भारत के घरेलू यूरिया उत्पादन (पारंपरिक + नैनो-यूरिया) का मतलब होगा कि भारत यूरिया के निर्माण में आत्मनिर्भर होगा। इसका मतलब है कि भारत को अब हर साल आयात किए जाने वाले 90 लाख टन की आवश्यकता नहीं होगी और इससे देश को लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
डार्क स्काई रिजर्व	**ख़बरों में क्यों :** हाल ही में अपनी तरह की विशिष्ट एवं भारत के पहले डार्क स्काई रिज़र्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा हानले, लद्दाख में स्थापना की घोषणा की है। • हानले, जो समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर ऊपर है, दूरबीनों को होस्ट करता है और इसे खगोलीय प्रेक्षणों के लिए दुनिया के सबसे इष्टतम स्थलों में से एक माना जाता है। • लोगों को न केवल खगोल विज्ञान के बारे में बल्कि आसपास के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में वन्य जीवन और पौधों के जीवन के बारे में सूचित करने के लिए एक आगंतुक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। **डार्क स्काई रिजर्व के बारे में :** • यह एक ऐसे स्थान को दिया गया नाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ हैं कि किसी भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधाएँ होती है। • इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अमेरिका आधारित गैर-लाभकारी संस्था है जो स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस पार्क, रिज़र्व और संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करती है, जो उनके द्वारा दिये गए मानदंडों पर निर्भर करती है। **महत्व:** • विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता

	करता है। • **एस्ट्रो-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए -** **हानले:** हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (HCT), उच्च ऊर्जा गामा रे टेलीस्कोप (HAGAR), मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप (MACE) और ग्रोथ-इंडिया हानले वेधशाला में स्थित प्रमुख दूरबीन हैं।
आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2022	**खबरों में क्यों :** हाल ही में, कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाओं रैनिटिडिन (gastrointestinal medicines ranitidine) और सुक्रालफेट (sucralfate) सहित 26 दवाओं को आवश्यक दवाओं की संशोधित राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2022 से हटा दिया गया है। **महत्वपूर्ण तथ्य :** • आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची पहली बार वर्ष 1996 में संकलित की गई थी और इसे पहले वर्ष 2003, 2011 और 2015 में तीन बार संशोधित किया गया था। • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछली सूची की 26 दवाओं को हटा दिया था। इससे एनएलईएम-2022 में दवाओं की कुल संख्या 384 हो गई। **NLEM क्या है?** • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आवश्यक दवाएं वे हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996 में भारत की आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची तैयार की और जारी की जिसमें 279 दवाएँ शामिल थीं। • यह सूची रोग की व्यापकता, प्रभावकारिता, सुरक्षा और दवाओं की तुलनात्मक लागत-प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। • ऐसी दवाएं पर्याप्त मात्रा में, उचित खुराक रूपों में और सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के लिए अभिप्रेत हैं। • उन्हें इस तरह से उपलब्ध होना चाहिए कि एक व्यक्ति या समुदाय वहन कर सके। **भारत में NLEM:** • एनएलईएम के तहत सूचीबद्ध दवाएं - जिन्हें अनुसूचित दवाओं के रूप में भी जाना जाता है - सस्ती होंगी क्योंकि राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं की कीमतों को सीमित करता है और केवल थोक मूल्य सूचकांक-आधारित मुद्रास्फीति के आधार पर परिवर्तन करता है। • सूची में मधुमेह के इलाज के लिए संक्रमण-रोधी दवाएं जैसे इंसुलिन - एचआईवी, तपेदिक, कैंसर, गर्भनिरोधक, हार्मोनल दवाएं और एनेस्थेटिक्स शामिल हैं। • गैर-अनुसूचित दवाएं बेचने वाली कंपनियां हर साल कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। • आमतौर पर, एनएलईएम जारी होने के बाद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग उन्हें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में जोड़ता है, जिसके बाद एनपीपीए कीमत तय करता है।

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

Gurukul Advanced

A Rigorous & Intensive Test & Mentorship based Program

2ND Batch

ADMISSIONS OPEN

Scan Here
To Register

IASbaba's HQ: 2nd floor, Ganapathi Circle, 80 Feet Rd, Chandra Layout, Bengaluru 560040

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888/90192 76822

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता

संदर्भ:

तेलंगाना की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने सुश्री बानो (बिलकिस बानो मामले) के समर्थन में अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया और गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, इसने इस बारे में चर्चा को प्रेरित किया कि क्या अधिकारी ने सिविल सेवा (आचरण), 1964 के नियमों का उल्लंघन किया साथ ही कानून तथा शासन के मामलों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिये सिविल सेवकों के अधिकार के बारे में बहस को संज्ञान में लाया।

सिविल सेवक कौन हैं और उनकी अपेक्षित भूमिका क्या है?

- आधुनिक लोकतंत्र में, सिविल सेवकों से तात्पर्य है - 'अधिकारियों का वह समूह जो सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं'। इनका चयन योग्यता के आधार पर होता है।
- वे सरकार द्वारा उन्हें दिए गए संसाधनों के प्रबंधन और उनका कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- सरकार की एक सुदृढ़ संसदीय प्रणाली के लिए सिविल सेवकों को अपनी सत्यनिष्ठा, निडरता और स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि कनाडाई लोक सेवा के प्रमुख ने कहा है, सिविल सेवा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, "सत्ता से सच बोलना।"
- सिविल सेवकों में नैतिकता और जवाबदेही का संकट आचार संहिता की संरचना, संवैधानिक संरक्षण, राजनेता-नौकरशाही गठबंधन और उनके राजनीतिक उत्पीड़न से संबंधित कई मुद्दों को उजागर करता है।

इन मुद्दों को संबोधित करने और सिविल सेवकों के बीच अखंडता और अनुशासन बनाए रखने के लिए, विभिन्न सुधार समितियों जैसे संथानम समिति (1964), होता समिति (2004) (Hota Committee (2004) और सबसे हालिया दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट (2005) का गठन किया गया है।

सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता

- कानूनी रूप से लागू करने योग्य आचार संहिता सार्वजनिक सेवा में काम करने वालों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों को निर्धारित करती है।
- सिविल सेवा संहिता सिविल सेवा के मूल मूल्यों और इन मूल्यों को बनाए रखने में सभी सिविल सेवकों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों की रूपरेखा तैयार करती है।
- भारत में, नैतिक मानदंडों का वर्तमान सेट केंद्रीय सेवा (आचरण) नियम, 1964 में निहित आचरण नियम और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू समान नियम हैं।
- आचरण नियमों में प्रतिपादित व्यवहार संहिता में 'अखंडता बनाए रखना और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण' जैसे सामान्य मानदंड शामिल हैं।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

- अनुच्छेद 19 को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को कानूनी मंजूरी या प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचारों और राय को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में कहा गया है कि "सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"।
- इस अधिकार का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए जा रहे "उचित प्रतिबंध" के अधीन है।
- अनुच्छेद 19 (2) में वे आधार शामिल हैं जिन पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है: राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना।

सेवा आचरण नियम सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस हद तक प्रतिबंध लगाते हैं?

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, हालांकि, यह प्रकृति में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारतीय नौकरशाही, जिसे एक गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में माना जाता है, तटस्थता बनाए रखे।

- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं कि स्वस्थ आलोचना के लिए स्थान हो। हालाँकि, भावनात्मक प्रकोप, जो आलोचना में बदल सकते हैं, नियंत्रित होते हैं, क्योंकि इससे जनता का सरकार पर से विश्वास उठ सकता है।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के हालिया फैसलों ने इस बहस को एक अलग दिशा दी

- अपने फैसले में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1988 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, अपनी राजनीतिक मान्यताओं को धारण करने और व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं।
- केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया है, किसी को केवल एक कर्मचारी होने के कारण किसी को अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है। एक लोकतांत्रिक समाज में, प्रत्येक संस्था लोकतांत्रिक मानदंडों द्वारा शासित होती है ।
- स्वस्थ आलोचना किसी सार्वजनिक संस्थान को संचालित करने का एक बेहतर तरीका है।

सेवा नियम के माध्यम से लागू प्रतिबंध, जो अनुच्छेद 19 (1) (ए) के विरोध में आते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि विचाराधीन नियम अनुच्छेद 19 (2) के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, वह ढांचा जो उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है।

आगे की राह :

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों पर जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कामकाज के लिए सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए, एक निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना एक स्वागत योग्य कदम है, भले ही वह सिविल सेवक की ओर से ही क्यों न आए। लेकिन आलोचना भारत के संविधान में निहित सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

संदर्भ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विवाद को फिर से सामने ला दिया है।

पृष्ठभूमि – ज्ञानवापी मस्जिद पंक्ति:

1991: 1991 में वाराणसी में पुजारियों के एक समूह ने अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी।

2019: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

2022 (वर्तमान): पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे) के भीतर श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण 2022

- **हिंदू पक्ष:** मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में एक जलाशय के अंदर एक 'शिवलिंग' पाया गया था।
- **मुस्लिम पक्ष:** हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि यह केवल एक फव्वारा है।
- मस्जिद समिति की दलील में तर्क दिया गया कि "पूजा के अधिकार" का हवाला देते हुए 2021 में दायर किए गए नए मुकदमों को "पूजा के स्थान अधिनियम, 1991 द्वारा रोक दिया गया" और इस कानून द्वारा समाप्त किए गए विवाद को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास था।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991

15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और उसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करता है।

- **लागू:** 11 जुलाई 1991 से
- यदि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी पूजा स्थल के धार्मिक लक्षणों के रूपांतरण से संबंधित कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, तो वह समाप्त हो जाएगी। यह आगे निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों पर कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
- यह अधिनियम किसी धार्मिक स्थान के धर्मांतरण को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करता है, यहां तक कि धर्म के एक विशेष वर्ग को पूरा करने के लिए भी।
- अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को छूट देता है, जो "एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल है या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) या किसी अन्य कानून द्वारा कवर किया गया हो। "
- दंडात्मक प्रावधान: पूजा स्थल की स्थिति को परिवर्तित करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस अपराध को करने के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश में शामिल होने वालों को भी यही सजा मिलेगी।

पूजा स्थलों को चुनौती अधिनियम

द्वारा दी गई चुनौती: भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिछले साल पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

दी थी।

तर्क: कानून भारत के संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन था।

- केंद्र ने पूजा स्थलों और तीर्थों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उपायों पर रोक लगा दी है और अब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अनुच्छेद 226 के तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं।
- इसलिए, वे अनुच्छेद 25-26 की भावना में मंदिर के दान सहित अपने पूजा स्थलों और तीर्थयात्रा को बहाल करने में सक्षम नहीं होंगे और आक्रमणकारियों के अवैध बर्बर कार्य हमेशा के लिए जारी रहेंगे।

संबंधित: "मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को पुनः प्राप्त करने" पर एक निचली अदालत के समक्ष एक कानूनी लड़ाई, जो 1991 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधों से सीधे प्रभावित थी।

अधिनियम के तहत क्या अपवाद हैं?

- बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को उसके दायरे से बाहर रखने के लिए एक अपवाद बनाया गया था क्योंकि उस समय संरचना मुकदमे का विषय थी।
- 1991 का अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होगा जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा कवर किए गए हैं।
- यह किसी भी ऐसे मुकदमे पर भी लागू नहीं होगा जिसे अंततः सुलझा लिया गया है या निपटा दिया गया है, किसी भी विवाद को जो 1991 के अधिनियम के लागू होने से पहले पार्टियों द्वारा सुलझाया गया है, या किसी भी स्थान के रूपांतरण के लिए जो सहमति से हुआ है।

चुनौती के आधार क्या हैं?

- **न्यायिक उपाय को रोकना :** यह अधिनियम अदालतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने और न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लोगों के अधिकार को अधिग्रहण (taking away) करने के बराबर है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम कानूनी कार्यवाही के माध्यम से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जैसे समुदायों के पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के अधिकारों को ले लेता (takes away) है।
- **कट-ऑफ तिथि पर तर्क:** याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तिथि मनमाना और तर्कहीन है।
- **छूट का मुद्दा:** याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून अतीत में आक्रमणकारियों के कार्यों को वैध बनाता है जिन्होंने पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया था। यह आश्चर्य की बात है कि कानून राम के जन्मस्थान को कैसे छूट दे सकता है, लेकिन कृष्ण को नहीं।
- **धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध:** याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकार के साथ-साथ पूजा स्थलों के प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- **धर्मनिरपेक्षता की भावना में न होना :** इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और रक्षा करने के राज्य के कर्तव्य के खिलाफ है।

स्टेटस फ्रीज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

- अयोध्या विवाद पर अपने अंतिम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम "धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक गैर-अपमानजनक दायित्व लगाता है"।
- अदालत ने आगे कहा: गैर- प्रतिगमन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य घटक है।"
- अदालत ने कानून को एक ऐसा कानून बताया जिसने स्वतंत्रता के बाद पूजा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति न देकर धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित किया।
- पूजा स्थल के चरित्र को बदलने के आगे के प्रयासों के खिलाफ सावधानी के शब्दों में, पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने कहा, "ऐतिहासिक गलतियों को लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं सुधारा जा सकता है। सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करते हुए, संसद ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह आदेश दिया है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। "

यूरोप का ऊर्जा संकट

संदर्भ: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 200 दिनों के निशान को पार करने के साथ, यूरोप एक पूर्ण विकसित, अभूतपूर्व ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, और सर्दियों का मौसम बहुत दूर नहीं है।

यूरोप में ऊर्जा की स्थिति क्या है?

- यूरोपीय संघ (और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम) के देश "अब घरों और कंपनियों के लिए खगोलीय बिजली की कीमतों और बाजार में भारी अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।"
- 1 अक्टूबर से (गर्मियों में £1,971 से) एक नियमित परिवार का ऊर्जा बिल प्रति वर्ष £2,500 से अधिक नहीं हो सकता। इस हस्तक्षेप से

पहले, एक नियमित परिवार को 80 प्रतिशत स्पाइक के कारण प्रति वर्ष £3,549 का भुगतान करना पड़ता।

- दूसरी ओर, जर्मनी, जिसने आक्रमण से पहले, लगभग 55 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और अपने कच्चे तेल की आपूर्ति का 30 प्रतिशत से अधिक रूस से आयात किया था, ने अब देश में बढ़ती ऊर्जा लागत के संबंध में €65 बिलियन (£56.2 बिलियन) के राहत पैकेज की घोषणा की है।
    - इसमें कमजोर व्यवसायों के लिए एकमुश्त भुगतान और अधिकतर ऊर्जा से संबंधित व्यवसायों को कर में छूट शामिल है।

आक्रमण से पहले यूरोप ऊर्जा के लिए रूस पर कितना निर्भर था, और वह निर्भरता अब कैसी दिखती है?

- यूरोप की ऊर्जा जरूरतों का 90 प्रतिशत आयात किया जाता है। यह लगभग 40 प्रतिशत गैस के लिए किसी भी अन्य देश की तुलना में रूस पर निर्भर था। यूरोपीय संघ की घोषणा के अनुसार अब यह घटकर केवल नौ प्रतिशत रह गया है।
- पूर्व-आक्रमण संख्या के आधार पर, निरपेक्ष रूप से, जर्मनी और इटली ने रूस से क्रमशः 46 bcm और 29 bcm पर सबसे बड़ी मात्रा में गैस का आयात किया।
- इस गैस का अधिकांश भाग दो पाइपलाइनों के माध्यम से पहुँचाया जाता है:
    - यमल-यूरोप पाइपलाइन, जो बेलारूस के माध्यम से पोलैंड और जर्मनी को गैस की आपूर्ति करती है।
    - नॉर्ड स्ट्रीम, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का पूर्ववर्ती, जो यूक्रेन के माध्यम से जर्मनी को गैस की आपूर्ति करता है (NS2 यूक्रेन को बायपास करता है)। इस पाइपलाइन से गैस सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है।

रूस द्वारा अपनी गैस आपूर्ति में कटौती करने पर यूरोप की क्या प्रतिक्रिया है?

- इसलिए, रूसी गैस के खतरे ने यूरोपीय संघ को नवंबर 2022 तक अपने भंडारण स्थलों को 80% लक्ष्य तक भरने के लिए मजबूर किया, जो कि यूरोपीय हीटिंग सीजन शुरू होने पर होता है। वे समय से पहले इस समय सीमा पर पहुंच गए। 2022 के बाद के वर्षों में लक्ष्य को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना होगा।
- जर्मनी, जो अक्टूबर तक 85 प्रतिशत स्टोरेज हासिल करना चाहता था, इस समय 88 प्रतिशत स्टोरेज के साथ समय से पहले चल रहा है। फ्रांस 94 प्रतिशत पर है, और ऐसा ही डेनमार्क है।
- यूक्रेन की सर्दी से बचने की क्षमता उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की आवश्यक वित्तीय सहायता पर भी निर्भर करेगी ताकि वह जितनी गैस की जरूरत हो, आयात कर सके।
- हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि रूस देश में गैस के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का विकल्प चुनता है या नहीं। सितंबर के पहले सप्ताह में, रूसी सेना ने यूक्रेन में जवाबी हमले शुरू किए (बाद में फिर से हासिल किए गए क्षेत्र के बाद) जिसने पावर ग्रिड और हीट पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिससे खार्किव और अन्य क्षेत्रों में बिजली बंद हो गई।

यूरोप के अन्य विकल्प क्या हैं?

- जर्मनी रूसी गैस के विकल्प की तलाश तब से कर रहा है जब से उसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के प्रमाणीकरण को रोक दिया है। यह ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड की ओर मुड़ सकता है।
- नॉर्वे यूरोपीय संघ के देशों को वर्ष 2027 तक रूसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि कर रहा है।
- दूसरा विकल्प अल्जीरिया और अजरबैजान से अधिक गैस प्राप्त करना है, जो वर्तमान में यूरोप की गैस का लगभग 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आपूर्ति करता है।
- फिर तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वह इस साल यूरोपीय संघ को 15 bcm LNG प्रदान कर सकता है। यह अभी भी पिछले साल रूस की 155 bcm आपूर्ति से बहुत कम है (वास्तव में इसके 10 प्रतिशत से भी कम)।
- यहां समस्या यह है कि यूरोप को LNG की आपूर्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ने तक अन्यत्र LNG आपूर्ति में कमी आएगी (LNG के लिए एक नई उत्पादन सुविधा के निर्माण में दो साल से अधिक समय लगता है)।
- खपत कम करना एक ऐसी चीज है जिस पर यूरोप को भरोसा करना है। यूरोपीय संघ गैस की खपत में 15 प्रतिशत की कटौती करने पर सहमत हो गया है। साथ ही कीमतों को भी मैनेज करना होता है।

भारत के महान एनीमिया रहस्य

एनीमिया क्या है?

- डब्ल्यूएचओ एनीमिया को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है। यह प्रतिरक्षा से समझौता करता है और संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है।
- भारत में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, और यह संख्या पिछले तीन वर्षों में बढ़ी है। वर्ष 2005 और 2015 के बीच, भारत में एनीमिया में मामूली कमी आई।

- लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के हालिया आंकड़े उन लाभों को विपरीत हैं: वर्ष 2019-21 में महिलाओं में एनीमिया की दर 53% से बढ़कर 57% और बच्चों में 58% से बढ़कर 67% हो गई।

इस भयानक परिणाम का कारण क्या हो सकता है?

- NFHS सर्वेक्षण की व्यापकता हमें उन कारकों की जांच करने की अनुमति देती है जो पारंपरिक रूप से एनीमिया जैसे सूक्ष्म पोषक परिणामों की व्यापकता की व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- मांस, मछली, अंडे और डार्क हरे पत्तेदार सब्जियों (DGLF) जैसे लौह युक्त खाद्य समूहों की अपेक्षाकृत कम खपत के साथ अनाज केंद्रित आहार, एनीमिया के उच्च स्तर से जुड़ा हो सकता है।
- हालांकि, आयरन युक्त खाद्य समूहों का सेवन करने वाले बच्चों और महिलाओं का प्रतिशत NFHS-4 से बढ़कर NFHS-5 हो गया है।
- रक्ताल्पता के उच्च स्तर को अक्सर पानी की खराब गुणवत्ता और स्वच्छता की स्थिति जैसे अंतर्निहित कारकों से भी जोड़ा जाता है जो शरीर में लोहे के अवशोषण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
    - हालांकि, दोनों कारकों में NFHS-4 से NFHS-5 में सुधार हुआ। बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत 48.5% से बढ़कर 70.2% हो गया, जबकि पीने के पानी के बेहतर स्रोतों तक पहुंच वाले परिवारों का प्रतिशत 94.4% से बढ़कर 95, 9% हो गया।
- महिला सशक्तिकरण एक अन्य कारक है जो घर के भीतर भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - संपत्ति (जैसे भूमि या घर) पर महिलाओं का स्वामित्व, आय के उपयोग के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, बचत या ऋण जैसे संसाधनों तक पहुंच, और प्रमुख घरेलू निर्णयों में भागीदारी विविध, पौष्टिक आहारों के बारे में जागरूकता और पहुंच में वृद्धि कर सकती है।
    - लेकिन ऐसे क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण भी NFHS-4 से NFHS-5 में सुधार हुआ है, यह सुझाव देता है कि अकेले महिलाओं के निर्णय लेने से एनीमिया में वृद्धि की व्याख्या नहीं की जा सकती है।
- अंत में, रक्ताल्पता की व्यापकता में स्वास्थ्य और पोषण हस्तक्षेप का प्रावधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - लेकिन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के फोलिक एसिड सेवन और प्रसव पूर्व देखभाल तक पहुंच में पिछले पांच वर्षों में सुधार हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि न केवल माताओं में बल्कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में भी एनीमिया की दर कैसे बढ़ी है।

निष्कर्ष:

- एनीमिया की बढ़ती संख्या ने एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करना लगभग असंभव बना दिया है: वर्ष 2015-16 से 2022 तक सभी आयु समूहों में प्रति वर्ष 3% की कमी।
- रिप्रोडक्टिव ऐज ऑफ़ वीमेन (women of reproductive age) में एनीमिया के लिए वैश्विक पोषण लक्ष्य प्राप्त करने में भी भारत पीछे है: वर्ष 2012 की आधार रेखा से 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी।
- इस प्रकार, कठिन शोध और सूचित नीति निर्माण की समय की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं, नीति निर्माताओं और अन्य विशेषज्ञों जैसे विविध हितधारकों को शामिल करता है। एनीमिया के आंकड़े हमें बताते हैं कि कुछ गलत हो गया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम पता करें कि क्या बदल गया है और इसे संबोधित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ें।

फेडरल फैब्रिक अंडर थ्रेट

संदर्भ: महाराष्ट्र की बार-बार गुजरात को परियोजनाओं का नुकसान केंद्र की प्राथमिकता, हाल ही में समाप्त हुई वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना सहित संघीय ढांचे को नुकसान का संकेत देता है।

- इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), नानार तेल रिफाइनरी, भारत के राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों और सऊदी अरब के अरामको और तटीय पुलिस की राष्ट्रीय अकादमी के बीच एक संयुक्त उद्यम जैसी परियोजनाओं को महाराष्ट्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है, लेकिन बाद में इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया।

फ्लेमिंग के प्रसिद्ध नोटों के रूप में यह एक ऐसी प्रवृत्ति को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है जो हमारे संघीय ढांचे को गंभीर रूप से कमजोर करती है। राज्यों को निवेश के लिए होड़ करते देखना हमेशा खुशी की बात होती है, लेकिन शक्तिशाली केंद्र को एक राज्य को दूसरे राज्य के पक्ष में देखना भी उतना ही हानिकारक है।

यह न केवल लड़ाई को अनुचित बनाता है, बल्कि राष्ट्र के संघीय ताने-बाने के लिए भी खतरा है। हालांकि, एनरॉन की महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना के साथ शुरू होने वाली मेगा परियोजनाओं पर उनके लगातार फ्लिप-फ्लॉप (flip-flop) के लिए महाराष्ट्र के राजनेता निस्संदेह स्पष्टीकरण देते हैं।

इस संदर्भ में आइए हम भारत के संघीय ढांचे को समझें:

भारत की संघीय संरचना:

- **भारतीय संघवाद की प्रकृति:** एक संघीय सिद्धांतकार के.सी. व्हेयर ने तर्क दिया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध-संघीय प्रकृति की है।
    - सत पाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1969) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत का संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में अधिक अर्ध-संघीय है।
- संघवाद सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान: राज्यों और केंद्र की संबंधित विधायी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक उपलब्ध हैं।
    - संविधान की 7वीं अनुसूची की सूचियां - संघ, राज्य और समवर्ती भी शक्तियों के समान हिस्से का उदाहरण देती हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना क्षेत्र होता है, जो संदर्भ-संवेदनशील निर्णय लेने को सक्षम बनाता है।
    - अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार के सुचारू रूप से संक्रमण और विवादों के समाधान के लिए एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है।
    - संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों और शर्तों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग के गठन के लिए अनुच्छेद 280 प्रदान किया गया।
    - इसके अलावा, 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को जोड़ा गया, ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
- **संघवाद के लिए संस्थान:** योजना आयोग के पास हमेशा राज्य की संघीय प्रकृति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए जगह थी और वह राज्यों की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील था।
    - अंतर-राज्यीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय विकास परिषद और अन्य अनौपचारिक निकायों ने संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच परामर्श के माध्यम के रूप में कार्य किया है।
    - इन निकायों ने संघ और राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कायम रखते हुए विचार-विमर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से कठिन मुद्दों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत की संघीय भावना को बनाए रखने में चुनौतियां

गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उपर्युक्त संघर्ष के अलावा, भारत में सहकारी संघवाद के लिए प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं।

- **कई निकायों का अप्रभावी कामकाज:** योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है; अंतर्राज्यीय परिषद की पिछले सात वर्षों में केवल एक बार बैठक हुई है जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई है।
- **कर व्यवस्था पर मुद्दा (Issues in Tax Regime) :** गलत अवधारणा वाले वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) ने राज्यों को पहले से ही उपलब्ध अधिकांश स्वायत्तता को ले लिया है और देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकात्मक बना दिया है।
- महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने जीएसटी शासन के तहत राज्यों को मुआवजे की गारंटी का बार-बार उल्लंघन किया। राज्यों को उनके बकाया का भुगतान करने में देरी से आर्थिक मंदी का प्रभाव और खराब हो गया।
- **राज्य के विषयों में राज्यों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण:** पिछले कुछ वर्षों में संबंधित राज्यों के संदर्भ और परामर्श के बिना कई महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्णय लिए गए हैं जैसे:
- संसद ने राज्य सूची में "कृषि" पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को अधिनियमित करने, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकलने और राज्यों पर एक कानून लागू करने के लिए कानून बनाया।
- नई शिक्षा नीति 2020 को राज्य की संघीय प्रकृति के अतिक्रमण के रूप में भी चिह्नित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, बीएसएफ के (BSF's) अधिकार क्षेत्र को असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बिना संबंधित राज्यों के परामर्श के विस्तारित किया गया था।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** राज्यों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित पहलुओं जैसे परीक्षण किटों की खरीद, टीकाकरण, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपयोग और अनियोजित राष्ट्रीय लॉकडाउन में कटौती की गई थी।

आगे की राह

- **संघवाद की मान्यता:** यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि "इंडिया जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है", और ऐसी स्थिति में शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है।
    - भारत के राष्ट्रीय चरित्र (national character) की रक्षा के लिए भारत की राजव्यवस्था के संघीय चरित्र की एक जाग्रत मान्यता आवश्यक है।

- **अंतर-राज्यीय संबंधों को मजबूत बनाना:** राज्य सरकारें संघ द्वारा शुरू किए गए परामर्शों के जवाब तैयार करने में उनका समर्थन करने के लिए मानव संसाधनों को तैनात करने पर विचार करेंगी, विशेष रूप से संघवाद के कोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- **संघवाद को संतुलित करते हुए सुधार लाना:** एक विविध देश भारत को संघवाद के स्तंभों (राज्यों की स्वायत्तता, केंद्रीकरण, क्षेत्रीयकरण आदि) के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता है।
    - अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीकरण या अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण से बचा जाना चाहिए क्योंकि दोनों ही भारतीय संघवाद को कमजोर करते हैं।

अवश्य पढ़ें: असहयोगी संघवाद

अवश्य पढ़ें: विषम संघवाद

सीबीआई और उसकी परेशानियाँ (CBI and its Troubles)

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई की पक्षपातपूर्ण प्रकृति की निंदा की है। सीबीआई को "पिंजरे का तोता (caged parrot)" कहा गया है, जो एजेंसी को कार्यपालिका के अधीन करने और न्याय के लिए इसके संकटपूर्णपरिणामों की ओर इशारा करता है।

क्या है सीबीआई की स्थिति?

- द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान, युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) का गठन किया गया था।
- बाद में, भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की। नतीजतन, इसे वर्ष 1963 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था।
    - वर्ष 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (जो सतर्कता मामलों को देखता था) का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया था
- बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा मिल गया है।
- सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है।
- सीबीआई भ्रष्टाचार के अपराध, आर्थिक अपराध और आतंकवाद के अलावा अन्य गंभीर और संगठित अपराध की जांच करती है।

सीबीआई के कार्य क्या हैं?

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना।
- राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना।
- पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले।
- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय।
- राज्य सरकार के अनुरोध पर, सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को जांच के लिए लेना।
- यह राज्य सरकारों के संदर्भ में या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के निर्देश पर पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की जांच करता है।
- अपराध के आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी का विस्तार करना।
- सीबीआई भारत में इंटरपोल के "राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो" के रूप में कार्य करती है।
- केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में ऐसे अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।

सीबीआई किस तरह के मामलों को देखती है?

1. **विशेष अपराध -** राज्य सरकारों के अनुरोध पर या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत गंभीर और संगठित अपराध की जांच के लिए - जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण के मामले और माफिया/अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध।
2. **आर्थिक अपराध -** नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन, बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं, सांस्कृतिक संपत्ति और तस्करी से संबंधित अपराधों सहित प्रमुख वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी की जांच के लिए अन्य प्रतिबंधित सामान आदि।
3. **भ्रष्टाचार विरोधी अपराध -** भारत सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या निकायों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच के लिए।
4. सुओ मोटो केस (Suo Moto Cases) - सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच स्वयं कर सकती है।

- केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हालांकि, राज्य की सहमति के बिना सीबीआई को देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।

सीबीआई के साथ क्या मुद्दे हैं?

संरचनात्मक रूप से विवश (Structurally constrained): सीबीआई जिस कानूनी ढांचे के भीतर काम करती है, और सरकारों द्वारा इसे नियंत्रित करने वाले नियमों में किए गए परिवर्तनों से दोनों को बाधित किया गया है। इन वर्षों में, यह उत्तरोत्तर एजेंसी को केंद्र सरकार के अधीनस्थ बना दिया है।

- किसी भी विधायक, राज्य मंत्री या सांसद पर मुकदमा चलाने के लिए, सीबीआई को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष (विधायकों के मामले में) या राज्यपाल (राज्य के मंत्रियों के लिए) से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- सांसद के मामले में, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के उपाध्यक्ष से मंजूरी मांगी जाती है।
- चूंकि इन सभी मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों का संबंध सत्तारूढ़ दल से है, इसलिए विपक्षी दलों को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
- यह समझा जाता है कि एजेंसी को स्वयं किसी की भी जांच करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह सरकार है, संघ में या राज्यों में, या अदालत, जो तय करेगी कि किसकी जांच की जाएगी।

संघीय राजनीति के कारण सहमति वापस लेना

- 9 राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। इनमें से ज्यादातर विपक्ष शासित राज्य हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- चूंकि सीबीआई को राज्य के अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, इसलिए एजेंसी को एक सामान्य सहमति दी जाती है ताकि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए सहमति की आवश्यकता न हो।
- सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी की भी जांच नहीं कर सकती है।
- हालांकि, यह एनडीए शासन के लिए अद्वितीय नहीं है। एजेंसी के इतिहास के दौरान, सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है।

सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों पर कोई प्रतिबंध न होना

- आलोचकों ने यह भी बताया है कि किस तरह से लगातार सरकारों ने सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों के लालच का इस्तेमाल सीबीआई निदेशकों को अपनी लाइन में करने के लिए किया है।
- पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार को वर्ष 2013 में यूपीए द्वारा नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अन्य पूर्व सीबीआई प्रमुखों को यूपीए के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी मिली।
- एनडीए सरकार ने वर्ष 2021 में सीबीआई निदेशक को पांच साल का कार्यकाल देने के लिए डीएसपीई अधिनियम में संशोधन किया, लेकिन एक चेतावनी जोड़ा कि SC-जनादेश दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, निदेशक को सरकार की इच्छा पर प्रत्येक वर्ष कार्यकाल का विस्तार होगा। कई लोगों ने इसे निदेशक को सरकार की लाइन बनाने के प्रयास के रूप में देखा ।

अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता

- एजेंसी स्टाफिंग के लिए गृह मंत्रालय पर निर्भर है क्योंकि इसके कई जांचकर्ता भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। सीबीआई वकीलों के लिए कानून मंत्रालय पर भी निर्भर है और उसके पास कुछ हद तक कार्यात्मक स्वायत्तता भी नहीं है।
- प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों द्वारा संचालित सीबीआई, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हेर-फेर करने की सरकार की क्षमता के लिए भी कमजोर है क्योंकि वे भविष्य की पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं।

सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर

- सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची, धारा 24 में रखा गया है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों से जानकारी प्राप्त करने या सरकार को उनके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक अपवाद प्रदान करता है।

संस्था पर जनता का घट रहा विश्वास

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने अफसोस जताया कि एजेंसी लोगों की सबसे भरोसेमंद से गहरी सार्वजनिक जांच के विषय में चली गई है।

- इससे पहले 2019 में, तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने "राजनीतिक रूप से संवेदनशील" मामलों में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया था, और कहा था कि यह "संस्थागत आकांक्षाओं के बीच एक गहरा बेमेल" और "शासन की राजनीति" को दर्शाता है।

सीबीआई में सुधार करने में न्यायपालिका ने अपनी भूमिका कैसे निभाई है?

- सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के ऐतिहासिक विनीत नारायण निर्णय (विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो साल तय किया।
- राजीव गांधी सरकार, जिसे "एकल निर्देश" के रूप में जाना जाता है, ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 (जिससे सीबीआई अपनी शक्तियां प्राप्त करती है) में एक प्रावधान प्रस्तुत किया, जिसने सीबीआई को सरकार की अनुमति के बिना संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच करने से रोक दिया।
- इसे विनीत नारायण मामले से खारिज कर दिया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया था।
- वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे फिर से रद्द करने के बाद, मोदी सरकार ने एक संशोधन के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17A को पेश किया।
- उच्च न्यायपालिका ने अक्सर जांचकर्ताओं को उनकी ढिलाई और नैतिकता से विचलन के लिए फटकार लगाई है। इससे जांचकर्ताओं में एक तरह का डर पैदा हो गया है और एजेंसी को जनता का विश्वास खोने से मना किया गया है।
- कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण से जांच की ईमानदारी पर प्रभाव पड़ा है।
- सीबीआई अधिकारियों के बीच यह स्पष्ट डर है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है यदि एक पीड़ित व्यक्ति यह साबित करने के लिए कि एक अन्वेषक मनमाना और बेईमान था।

आगे का राह क्या है?

- जांचकर्ताओं को अनैतिक दबावों का डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि जनता द्वारा उन पर किए गए विश्वास के साथ विश्वासघात न किया जा सके।
- न्यायालयों को अनुशासन और कानून के पालन को लागू करने की आवश्यकता है। यदि जांचकर्ता निष्पक्षता और तटस्थता के रास्ते से भटकते हैं, तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी।
- अगर सीबीआई को सद्गुणों के रास्ते पर चलना है, तो उसके पास कानून और नैतिकता में एक विशिष्ट विश्वास के साथ सबसे मजबूत नेता होना चाहिए।
- एक मजबूत और नेक नेता होने की जरूरत है जो न केवल ईमानदार होगा बल्कि बेईमान राजनीतिक दिग्गजों के सामने आने पर अपने ईमानदार जनप्रतिनिधियों की रक्षा भी करेगा।
- नेतृत्व को अधिकारियों के बीच बेईमानों को बाहर निकालने पर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए जिन्होंने स्वयं को ईमानदार और पेशेवर रूप से अभिनव दिखाया और साबित किया है।

स्कैंडिनेवियाई सामाजिक लोकतंत्र

संदर्भ: हाल ही में स्वीडन के चुनावों में, सोशल डेमोक्रेट्स, जो नव-नाजी आंदोलन (neo-Nazi movement) से जुड़ी एक पार्टी है, ने हार मान ली, जबकि नरमपंथियों से अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन की पेशकश के साथ सरकार बनाने की उम्मीद की जाती है।

- यह नॉर्डिक देशों में नॉर्डिक मॉडल, या "लोकतांत्रिक समाजवाद" की घटती लोकप्रियता को दर्शाता है, जैसा कि नए हरित आंदोलन और यू.एस. सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने स्वयं नॉर्डिक देशों में सिफारिश की थी।

स्कैंडिनेवियाई में समाजवाद और सामाजिक लोकतंत्र:

- स्कैंडिनेवियाई देशों में राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था को उसके मजबूत कल्याणवादी आधार और सामूहिक सौदेबाजी पर जोर देने के बावजूद "समाजवादी" कहना गलत होगा।

- एक के लिए, शब्द "समाजवाद" तत्कालीन कम्युनिस्ट ब्लॉक के शासन से जुड़ा हुआ है, जिसका न केवल उत्पादन के प्रमुख साधनों के स्वामित्व में, बल्कि राजनीतिक जीवन में भी एक दलीय प्रणाली के साथ राज्य का भारी प्रभुत्व था। मजदूर वर्ग की ओर से शासन के लिए अपना वैचारिक आधार तैयार करना।

- सोवियत संघ के पतन के बाद, हाल के वर्षों में नए समाजवादी शासन ने बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तथाकथित "दूसरी दुनिया" में एक-पक्षीय मॉडल से स्वयं को दूर करने की मांग की है। इस प्रक्रिया में राज्य के लिए धन के पुनर्वितरण और अधिक महत्व पर जोर देते हुए।
- वेनेजुएला, बोलीविया और हाल ही में चिली में सत्तारूढ़ दलों के नेतृत्व में लैटिन अमेरिका के शासन को "लोकतांत्रिक समाजवादी" कहा जा सकता है - जो कि अत्यधिक असमान और कुलीन संचालित प्रणालियों में औपचारिक लोकतांत्रिक और उदार संस्थानों के पुनर्वितरण और पुनर्गठन के समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
- राजनीतिक सर्कल्स ने 20वीं सदी के अंत में सामाजिक लोकतंत्र को कीनेसियनवाद, नॉर्डिक मॉडल, सामाजिक-उदारवादी प्रतिमान के साथ-साथ कल्याणकारी राज्यों के साथ जोड़ना शुरू किया।

परिभाषित विशेषताएं:

- समाजवाद के भीतर, सामाजिक लोकतंत्र एक वामपंथी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। इसे एक नीति शासन के रूप में परिभाषित किया गया है जो उदार-लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और पूंजीवादी-उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे के भीतर सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप का समर्थन करता है।
  - प्रतिनिधि और सहभागी लोकतंत्र के प्रति समर्पण
  - आय पुनर्वितरण के लिए तंत्र
  - जनहित में अर्थव्यवस्था का प्रबंधन
  - समाज कल्याण नीतियां

'असाधारण' स्कैंडिनेवियाई मॉडल

- दूसरी ओर, स्कैंडिनेवियाई देशों में, व्यवस्थाएं विशिष्ट "सामाजिक लोकतंत्रों" के समान हैं -
  - प्रतिनिधि और सहभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्भरता जहां शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है;
  - सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा, और अनुसंधान में निवेश पर जोर देने के साथ एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना, जो प्रगतिशील कराधान द्वारा वित्त पोषित हैं;
  - सक्रिय श्रमिक संघों और नियोक्ता संघों के साथ मजबूत श्रम बाजार संस्थानों की उपस्थिति जो शासन और नीति में सक्रिय भूमिका के अलावा महत्वपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी, मजदूरी वार्ता और समन्वय की अनुमति देते हैं।
  - ये सभी देश विकास के पूंजीवादी मॉडल का भी पालन करते हैं, जो कॉर्पोरेट करों के संबंध में बड़े पैमाने पर मजदूरी कराधान के माध्यम से उद्यमिता और कल्याणकारी नीतियों के वित्तपोषण की अनुमति देता है।

नॉर्डिक देशों की सफलता:

- स्कैंडिनेवियाई देशों में समानताएं - नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड - इनमें से कई मामलों में मापने योग्य हैं।
  - उदाहरण के लिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) (दुनिया में सबसे अधिक आय वाले देशों की विशेषता) के देशों में, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे में ट्रेड यूनियनों से संबंधित कार्यबल का उच्चतम अनुपात है।
- सभी नॉर्डिक राज्यों में शिक्षा निःशुल्क है; डेनमार्क और फ़िनलैंड में स्वास्थ्य देखभाल मुफ़्त है और नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड में आंशिक रूप से मुफ़्त है;
- श्रमिकों को कई लाभ मिलना - बेरोजगारी बीमा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक, प्रभावी बाल देखभाल के अलावा। इसलिए, इन देशों में श्रम भागीदारी दर दुनिया में सबसे ज्यादा है (यहां तक कि महिलाओं में भी)।
- अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गणना की जाए तो पांच नॉर्डिक राष्ट्र स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी खर्च में ओईसीडी देशों में शीर्ष 10 में हैं।
- भारत नॉर्डिक मॉडल से सीख ले सकता है क्योंकि राज्य को अपने युवाओं के लिए रोजगार खोजने के साथ-साथ कमजोर आबादी के अपने विशाल वर्ग को कल्याणकारी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

आगे की राह :

- नॉर्डिक देशों में फलते-फूलते सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडल का एक प्रमुख कारण उनकी अपेक्षाकृत छोटी और अधिक समरूप आबादी रही है जो केंद्रित शासन को सक्षम बनाती है।

- सरकार द्वारा कई स्तरों पर मध्यस्थता करने वाले पूंजी और श्रम दोनों के हितों को शामिल करने के "निगमवादी" मॉडल ने इन देशों को कृषि से औद्योगिक से उत्तर-औद्योगिक (कुछ मामलों में) और ज्ञान / सेवा अर्थव्यवस्थाओं को अपेक्षाकृत सुचारू रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी है।
- कई मायनों में, सामाजिक लोकतंत्र का नॉर्डिक मॉडल विकासशील दुनिया को सबक प्रदान करता है, जिसमें विविधता, अंतर आंतरिक विकास और इतिहास की असंख्य जटिलताओं के बावजूद भारत जैसे देश शामिल हैं।

कर्नाटक हिजाब केस

संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की सही तर्क (correctness) पर बहस सुन रही है, जिसने कर्नाटक में छात्रों द्वारा हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

कर्नाटक हिजाब पंक्ति:

- कर्नाटक में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर विवाद तब भड़क उठा जब एक कॉलेज के कुछ मुस्लिम छात्र जो क्लासों में हिजाब पहनना चाहते थे, उन्हें इस आधार पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया कि यह कॉलेज की यूनिफार्म नीति का उल्लंघन है।
- कई शैक्षणिक संस्थानों ने कर्नाटक सरकार के अनिवार्य यूनिफार्म आदेश और हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियों को प्रवेश से वंचित कर दिया। इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय (एचसी) में चुनौती दी गई थी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, जबकि उसने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, अपने फैसले में तीन प्राथमिक निष्कर्ष दिए:

- सबसे पहले, यह माना गया कि हिजाब का उपयोग इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था।
- दूसरा, इसने फैसला सुनाया कि क्लास के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या निजता का कोई वास्तविक अधिकार मौजूद नहीं है और इसलिए, ये अधिकार यहां दांव पर नहीं थे। इसने क्लासों को "योग्य सार्वजनिक स्थान" के रूप में रखा, जहां व्यक्तिगत अधिकारों को "सामान्य अनुशासन और मर्यादा" के हितों के लिए मार्ग
- तीसरा, यह माना गया कि प्रतिबंध सीधे तौर पर सरकार के उस आदेश से नहीं निकला है, जिसमें केवल राज्य या स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा एक समान ड्रेस कोड निर्धारित करने का आह्वान किया गया था, और इसलिए, कानून ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया।

इस फैसले की सत्यता पर निर्णय लेने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष रखे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा किए गए तीन निष्कर्षों में से किसी एक को उलटने के परिणामस्वरूप प्रतिबंध को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

कानून और धर्म:

- सैद्धांतिक रूप से, इन सबमिशन से निकलने वाले मुद्दों को संवैधानिक कानून के सामान्य सिद्धांतों के आवेदन के माध्यम से आसान समाधान में सक्षम होना चाहिए।
- लेकिन, जैसा कि सुनवाई के प्रतिलेखों ने हमें दिखाया है, जब भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई तर्क दिया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत (ईआरपी) में फंस जाता है।

आवश्यक धार्मिक अभ्यास (ईआरपी) परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत केवल ऐसी धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए विकसित एक सिद्धांत है, जो धर्म के लिए आवश्यक और अभिन्न हैं। "अनिवार्यता" के सिद्धांत का आविष्कार एससी द्वारा 1954 में शिरूर मठ मामले में किया गया था।

संविधान सभा बहस::

आवश्यक अभ्यास सिद्धांत अपने अस्तित्व का श्रेय बी.आर. संविधान सभा में अम्बेडकर: "अम्बेडकर धार्मिक को धर्मनिरपेक्ष से अलग करने का प्रयास कर रहे थे, यह तर्क देकर कि राज्य को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो धर्म से जुड़े हैं लेकिन आंतरिक रूप से धार्मिक नहीं हैं"।

शिरूर मठ मामले में न्यायिक फैसला:

- सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने शिरूर मठ मामले (1954) में कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि धर्म का एक 'आवश्यक' पहलू क्या है, न्यायालय को संबंधित धर्म की ओर देखना चाहिए, और उसके अनुयायियों का मानना है कि उनके विश्वास की मांग की गई थी।

ईआरपी पर सबरीमाला फैसला:

- आवश्यक अभ्यास परीक्षण विकल्पों के बिना नहीं है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के मामले में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तावित किया: बहिष्करण विरोधी सिद्धांत।

- बहिष्करण विरोधी सिद्धांत यह मानता है कि जहां एक धार्मिक प्रथा व्यक्तियों के बहिष्कार का कारण बनती है जो उनकी गरिमा को कम करती है या बुनियादी वस्तुओं तक उनकी पहुंच को बाधित करती है, धर्म की स्वतंत्रता को उदार संविधान के अति-उत्कृष्ट मूल्यों को रास्ता देना चाहिए।

आगे की राह :

लेकिन जब तक सात से अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत को खारिज नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए बाध्य है। शायद वह पुनर्मूल्यांकन तब होगा जब सबरीमाला मामले में फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं में गठित नौ-न्यायाधीशों की पीठ फैसला सुनाएगी।

अभी के लिए, हिजाब पहनने सहित आस्था के मामले को छूने वाले मामले की सुनवाई करने वाले किसी भी न्यायालय के पास न केवल कानून के विशेषज्ञ के रूप में बल्कि धर्म के विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करने का अविश्वसनीय कार्य है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम

संदर्भ: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने केंद्र शासित प्रदेश में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन में खेदजनक स्थिति की ओर इशारा करते हुए शहर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी।

कानून:

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में पारित किया गया था।
- यह यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है, शिकायत और जांच के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, और की जाने वाली कार्रवाई करता है।
- इसने विशाखा दिशानिर्देशों को विस्तृत किया, जो पहले से ही लागू थे।
- 1997 में एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे।

विशाखा दिशानिर्देशों की उत्पत्ति:

- यह महिला अधिकार समूहों द्वारा दायर एक मामले में था, जिसमें से एक विशाखा थी।
- उन्होंने राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी।
- वर्ष 1992 में, उसने एक साल की लड़की की शादी को रोक दिया था, जिससे बदला लेने के लिए कथित सामूहिक बलात्कार हुआ।

दिशानिर्देश और कानून

- **विशाखा दिशा निर्देश:** ये दिशा निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हैं एवं संस्थानों पर तीन प्रमुख दायित्व- निषेध, रोकथाम, निवारण आरोपित किए हैं
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें एक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करेगी।
- 2013 के अधिनियम ने इन दिशानिर्देशों को विस्तृत किया।
- इस कानून में, यह अनिवार्य है कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना चाहिए।
- यह प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है और यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है, जिनमें शामिल हैं:
    - जो "किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो अथवा न हो", जो "यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है"।
- इसका मतलब था कि किसी भी क्षमता में काम करने वाली या किसी भी कार्यस्थल पर जाने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों को अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया था।

यौन उत्पीड़न की परिभाषा:

- यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल हैं जो सीधे या निहितार्थ से किए गए हैं:

- शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव
- यौन अनुग्रह के लिए एक मांग या अनुरोध
- यौन आधारित टिप्पणी
- अश्लील सामग्री को दिखाना
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

- इसके अतिरिक्त, अधिनियम में पांच परिस्थितियों का उल्लेख है जिन्हें यौन उत्पीड़न कहा जाता है -
  - उसके रोजगार में तरजीही व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा;
  - हानिकारक उपचार का निहित या स्पष्ट खतरा;
  - उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा;
  - उसके काम में हस्तक्षेप या एक आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना;
  - अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

शिकायत के लिए प्रक्रिया:

- तकनीकी रूप से, पीड़ित के लिए आईसीसी को कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करना अनिवार्य नहीं है।
- अधिनियम कहता है कि यदि वह शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है, तो आईसीसी का कोई भी सदस्य लिखित रूप में शिकायत करने के लिए उसे सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।
- यदि महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत नहीं कर सकती है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है।
- अधिनियम के तहत, शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए।
- हालांकि, ICC समय सीमा बढ़ा सकती है यदि वह संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जो महिला को उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से रोकती थीं।
- ICC पूछताक्ष से पहले, और पीड़ित महिला के अनुरोध पर, उसके और प्रतिवादी के बीच सुलह के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है, बशर्ते कि "सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा"।
- ICC या तो पीड़ित की शिकायत पुलिस को भेज सकती है, या वह एक जांच शुरू कर सकती है जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करना होता है।
- किसी भी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए बुलाने और जांच करने, और दस्तावेजों की खोज और प्राप्त करने की आवश्यकता के संबंध में आईसीसी के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार हैं।
- अधिनियम में कहा गया है कि महिला की पहचान, प्रतिवादी, गवाह, जांच, सिफारिश और की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
- यदि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो जाते हैं, तो आईसीसी अनुशंसा करता है कि नियोक्ता कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।
- सिफारिशों के बाद, पीड़ित महिला या प्रतिवादी 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं।
- अधिनियम की धारा 14 झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत और झूठे साक्ष्य के लिए सजा से संबंधित है।

भारत में मौत की सजा

संदर्भ: मौत की सजा देने में ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान मानदंड बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है। यह एक ऐसा मामला है जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने लिया था और अब इसे पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया है।

भारत में अपराधों के लिए किस प्रकार की सजा दी जाती है?

- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार की सजा का प्रावधान है जो अपराधियों को दी जा सकती है। यह भी शामिल है:
- **मृत्युदंड (Death Penalty):** इस सजा के तहत व्यक्ति को तब तक फांसी दी जाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने (धारा 121), हत्या (धारा 302) आदि जैसे कुछ आईपीसी अपराधों में मृत्युदंड निर्धारित है।

- सेना अधिनियम (1950), BSF अधिनियम (1968), भारत रक्षा अधिनियम (1971), NDPS अधिनियम (1985), POCSO अधिनियम (2012, 2019 में संशोधित) आदि जैसे कुछ अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले कुछ अपराधों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान है। इसे 'दुर्लभ से दुर्लभ मामलों' में सम्मानित किया जाता है।

- **आजीवन कारावास:** आजीवन कारावास का तात्पर्य दोषी ठहराए गए अपराधी के शेष जीवन के लिए कारावास से है।
- **कारावास (साधारण या कठोर):** साधारण कारावास एक ऐसी सजा है जिसमें अपराधी को केवल जेल तक ही सीमित रखा जाता है। वह किसी कठिन परिश्रम के अधीन नहीं है। कठोर कारावास में व्यक्ति को कठिन परिश्रम जैसे खुदाई, लकड़ी काटने आदि में लगाया जाता है।
- **संपत्ति की जब्ती:** राज्य एक अपराधी की संपत्ति को जब्त करता है। जब्त की गई संपत्ति चल या अचल हो सकती है।
- **जुर्माना:** राज्य एक अपराधी पर आर्थिक दंड भी लगा सकता है।

भारत में दी जाने वाली मृत्युदंड की वर्तमान स्थिति क्या है?

- भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 के अंत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 488 थी, जो 17 वर्षों में सबसे अधिक है।
    - रिपोर्ट के अनुसार, जहां ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2021 में कुल 144 मौत की सजा सुनाई, वहीं उच्च न्यायालयों ने इसी अवधि में केवल 39 मामलों का फैसला किया।
    - सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में मौत की सजा के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने के बावजूद, वर्ष 2021 में केवल 6 मामलों का फैसला किया, जबकि वर्ष 2020 में 11 और वर्ष 2019 में 28 मामलों का फैसला किया।

मृत्युदंड पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या है?

एडिगा अनाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1974): सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास नियम है और कुछ मामलों में मृत्युदंड अपवाद है।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा केवल 'दुर्लभ से दुर्लभ' मामलों में ही दी जानी चाहिए। एक मामला दुर्लभतम से दुर्लभ हो जाता है जब अपराधी की हत्या के अपराध को करने में अत्यधिक दोषी होता है; और हत्या का अपराध करने में अपराधी का एक चरम कारण होता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तभी जारी किया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प 'निस्संदेह रूप से बंद' हो। बढ़ते और कम करने वाले कारकों और उसी के संतुलन को देखने के बाद मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

मृत्युदंड के पक्ष में क्या तर्क हैं?

प्रतिरोध बनाए रखना: समर्थन में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण तर्क मृत्युदंड देकर समाज में बनाए रखा प्रतिरोध का स्तर है। बहुत से लोग मानते हैं कि यदि व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए तो वह हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने से स्वयं को रोक सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: कुछ कार्य जैसे राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, आतंकवाद आदि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की निर्मलता को नष्ट करते हैं। इस तरह के कृत्यों से देश और उसके लोगों के अस्तित्व को ही खतरा है। उदाहरण के लिए, अजमल कसाब को 26/11 के मुंबई हमलों को अंजाम देने के लिए मौत की सजा दी गई थी।

सामूहिक अंत:करण को झकझोरने वाले कार्य: मृत्युदंड के समर्थकों का कहना है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और मृत्युदंड के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए।

- उदाहरण के लिए, विनय शर्मा बनाम भारत संघ (2020) मामले, जिसे निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के नाम से भी जाना जाता है, ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। एक आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर ली और एक आरोपी किशोर था इसलिए उसे मौत की सजा नहीं सुनाई गई।
- लेकिन अन्य चार आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें भी साल 2020 में फांसी दे दी गई।

नागरिकों की सुरक्षा: मृत्युदंड के समर्थकों का तर्क है कि कुछ अपराधी सबसे भयानक अपराध करते हैं और छुटकारे से परे होते हैं (उदाहरण के लिए, कई बलात्कार के मामलों के कुछ आरोपी)। वे कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखाते हैं। इनके सुधार में कोई बदलाव नहीं होते है ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए।

मृत्युदंड को समाप्त करने के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **विषयपरकता की उच्च डिग्री:** मौत की सजा देने में उच्च स्तर की विषयपरकता होती है क्योंकि न्यायाधीशों को कम करने और उत्तेजित करने वाले कारकों को संतुलित करना मुश्किल लगता है।
    - डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 (DPIR) के अनुसार, भारत में मौत की सजा पाने वाले सभी दोषियों में से लगभग 75% सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित श्रेणियों, जैसे दलित, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों से हैं।

- **मानसिक तनाव:** कई मामलों में दोषियों को अंतिम रूप से फांसी दिए जाने से पहले भारी कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है।
    - प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट 'डेथवर्थी' के निष्कर्षों से पता चलता है कि लंबे समय तक मौत की पंकित में रहने के अलग-अलग, अलग-थलग और कलंकित अनुभवों के परिणामस्वरूप मानसिक बीमारी होती है।
- **प्रकृति में अपरिवर्तनीय:** अदालतें अक्सर ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा देती हैं जिन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है और राज्य द्वारा एक त्रुटि के कारण जेल में काफी समय बीतता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फांसी दी जाती है, तो मुआवजे की कोई भी राशि व्यक्ति को वापस नहीं ला सकती है और त्रुटि को कम कर सकती है।
- **अमानवीय:** मानवाधिकार और गरिमा मृत्युदंड के साथ असंगत हैं। मौत की सजा जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जो सभी मानवाधिकारों में सबसे मौलिक है।

वैश्विक मिसाल - कम अपराध दर के साथ कोई संबंध न होना :

- नॉर्वे, स्वीडन और फ़िनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में मृत्युदंड के बिना दुनिया में सबसे कम अपराध दर है। वे अपराधी को कठोर और कठोर दंड देने के बजाय उसे सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - 100 से अधिक देशों ने पहले ही सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। इसमें अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शामिल हैं।

आगे क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने वाली दया याचिका के निपटान में अनुचित देरी के कारण बलवंत सिंह की मौत की सजा में कदम रख सकता है और उसे कम कर सकता है।
- मामलों में बढ़ते और कम करने वाले कारकों को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अद्यतन दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
- मृत्युदंड के स्थान पर कठोर सजा देने के लिए न्यायालय नए तरीके विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूनतम 25-30 वर्ष का कठोर कारावास जिसे कम या समीक्षा नहीं किया जा सकता है।
- सजा की मात्रा के बजाय सजा की निश्चितता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो अपराधियों के लिए बेहतर निवारक के रूप में कार्य करेगा।
- केंद्र सरकार को भी दया याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए न कि राजनीतिक लाभ/नुकसान के आधार पर जो उसे याचिका से मिल सकती है।

निष्कर्ष:

विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों और युद्ध को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। स्कैंडिनेवियाई देशों का अनुभव भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। हालाँकि, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारतीय न्यायालयों द्वारा बचन सिंह के फैसले का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए।

अपराधियों की पहचान के लिए नियम

संदर्भ: हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया। यह कानून पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने में सक्षम करेगा।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के बारे में:

- यह अधिनियम कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है।
    - पुराने अधिनियम का दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और कैदियों और कुछ श्रेणी के गिरफ्तार और गैर-दोषी व्यक्तियों की तस्वीरें लेने तक सीमित था।
- जब विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया तो उसके उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया था कि उन्नत देशों में इस्तेमाल की जा रही नई 'माप' तकनीक विश्वसनीय और विश्वसनीय परिणाम दे रही है और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।
- इसने कहा कि 1920 का अधिनियम शरीर के इन मापों को लेने का प्रावधान नहीं करता है क्योंकि तब कई तकनीकों और तकनीकों का विकास नहीं किया गया था।
    - यह अधिनियम मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को माप देने का निर्देश देने का अधिकार देता है, जो अब तक दोषियों और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के लिए आरक्षित था।
    - यह पुलिस को हेड कांस्टेबल के पद तक के किसी भी व्यक्ति द्वारा माप लेने में सक्षम बनाता है जो व्यक्ति माप देने का विरोध करता है अथवा मना करता है।

नियमों के अनुसार, "माप" में शामिल हैं: CrPC, 1973 की धारा 53 या 53ए में संदर्भित उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पदचिह्न,

फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, हस्ताक्षर, लिखावट या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं।

अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में चिंता:

- जब इस साल मार्च में संसद में विधेयक पर बहस हुई, तो विपक्षी सदस्यों ने इसे "असंवैधानिक" और गोपनीयता पर हमला करार दिया क्योंकि इसने राजनीतिक बंदियों के नमूनों के रिकॉर्ड की भी अनुमति दी थी।
- हालांकि, सितंबर में अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि CrPC की 107, 108, 109, 110, 144, 145 और 151 जैसी निवारक धाराओं के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के नमूने तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी मामले में आरोपित या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी अन्य अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है।
- यह तब भी लिया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को उक्त धारा के तहत कार्यवाही के लिए उक्त संहिता की धारा 117 के तहत शांति बनाए रखने के लिए उसके अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया हो।
- नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

माप डेटा का भंडार:

- गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा को संग्रहीत और संरक्षित करने के लिए एकमात्र एजेंसी होगी।
- राज्य सरकारें डेटा को स्टोर भी कर सकती हैं, लेकिन यह एनसीआरबी के साथ माप या रिकॉर्ड को साझा करने के लिए संगत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करेगी।
- नियम बताते हैं कि एनसीआरबी माप के संग्रह के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा जिसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या उपकरणों के विनिर्देश, विनिर्देश और माप के डिजिटल और भौतिक प्रारूप आदि शामिल होंगे।
- नियमों में कहा गया है कि यदि कोई माप भौतिक रूप में या गैर-मानक डिजिटल प्रारूप में एकत्र किया जाता है, तो उसे मानक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद एसओपी के अनुसार डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा।
- केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही माप को एन्क्रिप्टेड प्रारूप में केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड कर सकते हैं।

एक संदिग्ध के बरी होने की स्थिति में अभिलेखों को नष्ट करने के प्रावधान:

- यह अभी तक एनसीआरबी द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। नियमों में कहा गया है कि अभिलेखों को नष्ट करने का कोई भी अनुरोध संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी से किया जाएगा।
- नोडल अधिकारी यह सत्यापित करने के बाद नष्ट करने की सिफारिश करेगा कि माप का ऐसा रिकॉर्ड किसी अन्य आपराधिक मामले से जुड़ा नहीं है।

चेहरे की पहचान तकनीक (FRT):

- यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है।
- ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (AFRS) में, बड़े डेटाबेस (जिसमें लोगों के चेहरों की तस्वीरें और वीडियो होते हैं) का इस्तेमाल व्यक्ति से मिलान करने और उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है।
- सीसीटीवी फुटेज से ली गई एक अज्ञात व्यक्ति की छवि की तुलना पैटर्न-खोज और मिलान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग करने वाले मौजूदा डेटाबेस से की जाती है।
- हालांकि आपराधिक प्रक्रिया पहचान नियम (सीपीआईआर), 2022 में स्पष्ट रूप से एफआरटी या एएफआरएस का उल्लेख नहीं है, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा इसके संभावित उपयोग पर कुछ चिंताएं उठाई गई हैं। दिल्ली पुलिस पहले से ही एफआरटी का इस्तेमाल कर रही है।

निष्कर्ष: अपराधियों की बेहतर पहचान और रिकॉर्ड रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए, जिसे अब भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

अर्थव्यवस्था

लोगों को खाना खिलाना, ग्रह को बचाना

संदर्भ: इस बात की जागरूकता बढ़ रही है कि मनुष्य इस ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। इससे मानवता के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम:

- भूमि का क्षरण, विशेष रूप से ऊपरी मिट्टी जो हमें भोजन, पशु चारा और फाइबर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- भूजल कम हो रहा है और रासायनिक उर्वरकों और अन्य औद्योगिक कचरे के बढ़ते उपयोग से इसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है।
- दुनिया के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से भारत में, वायु प्रदूषण खतरनाक दर पर है, जहां कभी-कभी दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना भी मुश्किल होता है, जब पंजाब और हरियाणा में किसानों के खेतों में पराली जलती है।

प्रकृति की संपत्ति में इतनी तेजी से गिरावट के पीछे सही कारण क्या है:

- लोगों, हमारे ग्रह और नीतियों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बीच असंतुलन है।
- हम जो जानते हैं वह यह है कि होमो सेपियन्स को मानव जाति के वर्तमान स्वरूप में विकसित होने में मोटे तौर पर 2,00,000 से अधिक वर्षों का समय लगा। वर्ष 1804 में इतिहास में पहली बार मानव आबादी एक अरब तक पहुंची थी।
- अगले अरब में 123 वर्षों में 1927 तक दो अरब को छूने के साथ जोड़ा गया था। चिकित्सा विज्ञान में कई प्रमुख सफलताओं ने सुनिश्चित किया कि अगला अरब 1960 तक सिर्फ 33 वर्षों में जोड़ा गया।
- अगला अरब केवल 14 वर्षों में जोड़ा गया, जिसकी जनसंख्या 1974 में चार अरब तक पहुंच गई। अगले अरब में केवल 13 वर्ष (1987 में पांच अरब), उसके बाद 11 वर्ष (1998 में छह अरब), उसके बाद 12 वर्ष (2010 सात अरब वर्ष) और 2022 में आठ अरब को छूने के लिए एक और 12 साल लगे।

उच्च और उच्च आकांक्षाओं के साथ जनसंख्या की इस विस्फोटक वृद्धि ने लोगों की मांगों और इस ग्रह की स्थायी तरीके से आपूर्ति करने की क्षमता के बीच एक बड़ा असंतुलन पैदा कर दिया है।

क्या यह ग्रह बिना किसी रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक उच्च उपज देने वाले बीजों आदि के उपयोग के बिना प्राकृतिक खेती के माध्यम से सभी को भोजन प्रदान कर सकता है?

- कई सरकारें, धार्मिक संगठन और कुछ गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति मानते हैं कि प्रकृति की ओर वापस जाने और जैविक/प्राकृतिक खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- उदाहरण के लिए, श्रीलंका रासायनिक उर्वरकों से छुटकारा पाना चाहता था।
- भारत में भी, कुछ राज्यों (जैसे सिक्किम) को जैविक राज्य घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी प्राकृतिक खेती को बढ़ा रहे हैं और कई अन्य राज्य ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **मिट्टी बचाओ:** एक आंदोलन जो 24 साल पहले शुरू हुआ था: अब तीन दशकों से, ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु लगातार मिट्टी के महत्व को ला रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कह चुके हैं: "मिट्टी हमारा जीवन है, हमारा शरीर है। और अगर हम मिट्टी को छोड़ देते हैं, तो कई तरह से हम ग्रह को छोड़ देते हैं।"
- ये चलन इस उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं कि वे समाज के लिए सुरक्षित हैं, अपनी आय में वृद्धि करते हैं और सस्ती कीमतों पर भोजन की पर्याप्त उपलब्धता के माध्यम से जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- हालाँकि, कुछ किए गए अध्ययन जो इसके कुछ नकारात्मक पहलू को दर्शाते हैं जैसे
- भारत में ICAR द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से गेहूं और चावल जैसी प्रमुख मुख्य फसलों की पैदावार 30 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है।
- यह देखते हुए कि भारत वर्ष 2023 में ग्रह पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने जा रहा है, हमें बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है यदि हम श्रीलंका जैसी गड़बड़ी से बचना चाहते हैं।

फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक-तकनीकी उपकरणों का उपयोग:

- AIML (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग), GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली), जो कृषि में सटीकता लाने के लिए भारी डेटा का उपयोग कर सकता है।

- सेंसर, ड्रोन, डोवस (doves), और LEOs (निम्न पृथ्वी की कक्षा), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी का उपयोग क्रांतिकारी युग के लिए आधार प्रदान करने के लिए फट रहा (bursting) है।
- ड्रिप, हाइड्रोपोनिक्स, और एरोपोनिक्स, ऊर्ध्वाधर खेती, सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध हैं ताकि ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों के बहुत कम दोहन के साथ और अधिक प्राप्त किया जा सके।

सतत कृषि के लिए सरकार की पहल:

- **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER):**
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के तहत एक उप-मिशन है।
  - जिसका उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है और संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए इनपुट, बीज और ब्रांड निर्माण पहल प्रमाणीकरण से शुरू होकर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) :**
  - यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (PKVY) के तहत प्रमुख परियोजना के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक विस्तृत घटक है जो क्लस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण द्वारा आर्गेनिक विलेज (organic village) को अपनाने के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:**
  - यह योजना वर्ष 2007 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुकी है और इसे दो योजना अवधियों (11वीं और 12वीं) में लागू किया गया है। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इसलिए, टिकाऊ खेती के लिए चिंता के कुछ क्षेत्रों को संबोधित करने की आवश्यकता है-

- **सब्सिडी का सटीक और कुशल उपयोग:** विशेष रूप से भारत में, हमारे पास मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, यूरिया पर लगभग 80 से 90 प्रतिशत सब्सिडी आदि की संस्कृति है। ये सब्सिडी नीतियां 1960 या 1970 के दशक में अच्छी रही होंगी, जब देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी। लेकिन वे जारी हैं और बढ़ भी रहे हैं। इसलिए, 'सूर्यास्त (sunset)' समय के साथ प्रभावी और लक्षित सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।

इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होने पर विचार करते हुए प्राकृतिक संसाधनों के कम दोहन के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सटीक कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह स्थायी खाद्यान्न उत्पादन में मदद करेगा जो ग्रह को खिला सकता है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

संदर्भ: यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) उधारकर्ताओं के लिए COVID-19 महामारी के कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी।

- इस योजना की शुरुआत में मई 2020 में घोषणा की गई थी और फिर समय के साथ, वित्त मंत्रालय ने ECLGS के दायरे का विस्तार किया है।
- हाल ही में (मई 2021), ईसीएलजीएस 4.0 शुरू किया गया है जो अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवर प्रदान करता है, ब्याज दर 7.5 % तक सीमित है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना – प्रमुख बिंदु

- इस योजना ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और MUDRA उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण की अनुमति दी।
- ईसीएलजीएस के तहत, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा के तहत स्वीकृत सभी ऋणों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। हालांकि, दो विनिर्देश हैं:
  - यह योजना घोषणा की तारीख से 31 अक्टूबर, 2020, [अब 3 सितंबर, 2021] तक स्वीकृत ऋणों के लिए लागू होगी या
  - इसमें 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की जाती है (जो भी पहले हो) 31 दिसंबर, 2021 तक संवितरण की अनुमति है।

ECLGS के प्रमुख उद्देश्य:

- इस योजना के अनुसार, सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाना है।

- इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करके आर्थिक संकट को कम करना है।
- यह इस क्षेत्र को कम लागत पर ऋण भी प्रदान करेगा, जिससे छोटे क्षेत्र के व्यवसायों को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने निर्माण तथा काम को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

ECLG योजना के तहत कौन पात्र है?

विस्तारित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के शुभारंभ के साथ नवीनतम पात्रता मानदंड के अनुसार, योजना के तहत ऋण हेतु लागू होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना था:

- 250 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20) तक के टर्नओवर वाले उद्यम, 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण के साथ।
- प्रदान किया गया जीईसीएल क्रेडिट 29 फरवरी, 2020 तक उधारकर्ता के कुल बकाया क्रेडिट का 20% तक होगा।
- इस योजना के तहत प्राप्त किए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि 5 करोड़ रुपए होगी।

ईसीएलजीएस के तहत कार्यकाल और ब्याज दरें

- ऋण अवधि 4 वर्ष के लिए है और मूल राशि पर 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि भी लागू होती है [अब ऋण अवधि 5 वर्ष है]
- ईसीएलजीएस के तहत ब्याज दरों को भी सीमित कर दिया गया है:
    - बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 25%
    - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 14%
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को इस योजना के तहत शामिल सदस्य ऋण संस्थानों से कोई गारंटी शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।

ECLGS 4.0 - योजना का विस्तार

31 मई 2021 को, भारत सरकार ने ECLGS के विस्तार को अधिसूचित किया।

ईसीएलजीएस 4.0 के संस्करण के तहत:

- अस्पतालों/नर्सिंग होम/क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 100 प्रतिशत गारंटी कवर प्रदान किया जा रहा है। यह साइट पर ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिया जाता है।
- इसके पात्र उधारकर्ता जिनकी पहले चार वर्ष की ऋण अवधि थी, अब वे पांच वर्ष की ऋण अवधि का लाभ उठा सकते हैं।
- ECLGS 1 के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को 29 फरवरी, 2020 तक बकाया राशि के 10% तक की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता।
- ECLGS 3.0 के तहत 500 करोड़ की ऋण सीमा को समाप्त किया जा रहा है।
- प्रत्येक उधारकर्ता को अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40% या 200 करोड़ रुपए , जो भी कम हो, तक सीमित की जा रही है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र ईसीएलजीएस 3.0 के तहत एक पात्र उधारकर्ता है।

ECLGS 2.0 के बारे में

- इस योजना की घोषणा नवंबर 2020 में आत्म निर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक भाग के रूप में की गई थी।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का स्वास्थ्य क्षेत्र सहित 27 नए क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।
- कामथ कमेटी (Kamath Committee) ने इन 27 सेक्टरों को एकमुश्त कर्ज पुनर्गठन के लिए चिन्हित किया है। पहचान किए गए कई क्षेत्रों में बिजली, निर्माण, कपड़ा, रियल एस्टेट, पर्यटन कुछ ही हैं।
- इस योजना में पेशेवर और स्वरोजगार दोनों के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
- मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1 वर्ष के स्थगन के साथ अवधि को 5 वर्ष में अपग्रेड कर दिया गया है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बारे में

- NCGTC या नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 2014 में पंजीकृत किया गया था।
- यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- संगठन की मुख्य भूमिका ऋण गारंटी कार्यक्रमों को डिजाइन करना, उधारदाताओं के बीच ऋण देने के जोखिम को साझा करना और संभावित उधारकर्ता को वित्तीय पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

निर्णायक रूप से, देश की अर्थव्यवस्था को संशोधित करने के लिए, जिसे COVID लॉकडाउन के कारण बड़ी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा,

भारत सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यभार संभालने का फैसला किया। और, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना उन पहलों में से एक है।

विंडफॉल टैक्स

खबरों में क्यों : केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर प्रस्तुत किया, जिसकी दरों में उतार-चढ़ाव शामिल है।

- वित्त मंत्री ने विंडफॉल टैक्स का बचाव करते हुए कहा कि यह उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद किया गया था और कुछ तेल रिफाइनरों द्वारा किए गए "अभूतपूर्व लाभ" पर लगाम लगाने के तरीके के रूप में विंडफॉल टैक्स की शुरूआत की व्याख्या की, जिन्होंने घरेलू आपूर्ति को प्रभावित करते हुए वैश्विक कीमतों में आसमान छूते लाभों को प्राप्त करने के लिए ईंधन का निर्यात करना चुना।
- इसने डीजल, पेट्रोल और वायु टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया।

भारत रियायती रूसी तेल का आयात कर रहा है - विंडफॉल टैक्स मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रूसी तेल प्रमुख रोसनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी पर लक्षित था।

विंडफॉल टैक्स के बारे में:

- यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) एक अप्रत्याशित लाभ को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" के रूप में परिभाषित करता है।
- विंडफॉल करों को एक बाहरी, कभी-कभी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है – उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य-वृद्धि।
- सरकारें आम तौर पर इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों से ऊपर और ऊपर एकमुश्त कर लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।
- तेल बाजारों में, कीमतों में उतार-चढ़ाव से उद्योग के लिए अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है। इसलिए, अप्रत्याशित लाभ को पुनर्वितरित करने के लिए कर लगाया जाता है जब उच्च कीमतों से उपभोक्ताओं की कीमत पर उत्पादकों को लाभ होता है।
- इसका उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और सरकार के लिए एक पूरक राजस्व धारा के रूप में किया जा सकता है।

विंडफॉल टैक्स की आवश्यकता

- तेल, गैस और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण देश के व्यापक व्यापार घाटे को कम करने के लिए।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप महामारी से उबरने और आपूर्ति के मुद्दों के कारण कीमतों में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग में वृद्धि।
- बढ़ती कीमतों का अर्थ है ऊर्जा कंपनियों के लिए भारी मुनाफा जबकि घरों के लिए भारी गैस और बिजली बिल - आय असमानता को बढ़ाना।
- बड़ी तेल और गैस कंपनियों के "विचित्र लालच (grotesque greed)" जैसे कि वर्ष की पहली तिमाही में सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने लगभग 100 बिलियन डॉलर का संयुक्त लाभ कमाया।

चुनौतियाँ

- **निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव:** एक अस्थायी अप्रत्याशित लाभ कर की शुरूआत भविष्य के निवेश को कम करती है क्योंकि संभावित निवेशक निवेश के निर्णय लेते समय संभावित करों की संभावना को आंतरिक कर देंगे और कर की पूर्वव्यापी प्रकृति और अप्रत्याशित घटनाओं और आश्चर्यों के प्रभाव के कारण अनिश्चितता से बचेंगे।
- ऐसे कर अल्पावधि में लोकलुभावन और राजनीतिक रूप से उपयुक्त होते हैं।
- आईएमएफ ने कहा कि मूल्य वृद्धि के जवाब में कर उनके उपाय और राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए डिजाइन की समस्या से प्रभावित हो सकते हैं।
- वास्तविक अप्रत्याशित लाभ के गठन में कठिनाई; उनका निर्धारण और लाभ के सामान्यीकरण का स्तर है। उदाहरण के लिए, एक सीआरएस रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि यदि कीमतों में तेजी से वृद्धि से अधिक लाभ होता है, तो एक अर्थ में इसे वास्तविक अप्रत्याशित कहा जा सकता है क्योंकि वे अप्रत्याशित हैं लेकिन दूसरी ओर, कंपनियां यह तर्क दे सकती हैं कि यह वह लाभ है जो उन्होंने जोखिम लेने के लिए पुरस्कार के रूप में अर्जित किया है ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान किया जा सके।
- यह निर्धारित करने का मुद्दा कि किस पर कर लगाया जाना चाहिए - केवल उच्च कीमत वाली बिक्री या छोटी कंपनियों के थोक के लिए जिम्मेदार बड़ी कंपनियां या एक निश्चित सीमा से नीचे राजस्व या लाभ वाले उत्पादकों को छूट दी जानी चाहिए।

मामले पर IMF दिशानिर्देश

- जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण से होने वाले अप्रत्याशित लाभ पर स्थायी कर लागू करना।

- अप्रत्याशित लाभ पर अस्थायी करों में सावधानी बरतें क्योंकि ये निवेशक जोखिम को बढ़ाते हैं, अधिक विकृत हो सकते हैं (विशेषकर यदि खराब तरीके से या समयबद्ध तरीके से तैयार किए गए हों), और इकनोमिक रेंट पर स्थायी कर से अधिक राजस्व लाभ प्रदान नहीं करते हैं।
- कर इकनोमिक रेंट के हिस्से (अर्थात् अतिरिक्त लाभ) पर लगाया जाना चाहिए।

इकनोमिक रेंट आम तौर पर निश्चित आपूर्ति और विविध के परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण से उत्पन्न होते हैं। किराया-लक्षित कर निवेश को कम किए बिना या मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना राजस्व बढ़ाते हैं।

- ऊर्जा उत्पादन में डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता को देखते हुए अक्षय ऊर्जा पर स्विच को प्रोत्साहित करें। अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है।
- **डिजाइन सिद्धांत (Design principles):** अतिरिक्त लाभ के स्पष्ट उपाय पर कर लागू होना चाहिए; कर राजस्व पर लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है और निवेश को कम कर सकता है। कर को सममित उपचार सुनिश्चित करने के लिए नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति देनी चाहिए

पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

खबरों में क्यों : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की हालिया रिपोर्ट, 'भारत को अपने पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में तत्काल निवेश करने की आवश्यकता क्यों है?', ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालती है।

पेटेंट अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान:

- धारा 9(1) - पेटेंट अधिनियम की धारा 9 (1) में प्रावधान है कि अनंतिम विनिर्देशों के साथ उन आवेदनों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण विनिर्देशों द्वारा समर्थित किया जाए।
- धारा 21(1) - धारा 21 (1) पेटेंट आवेदकों को दस्तावेजों को फिर से फाइल करने की आवश्यकता होती है यदि पेटेंट परीक्षक उन्हें आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। एक प्रशंसनीय कारण यह हो सकता है कि आवेदक अपने आवेदनों की जांच में उत्तीर्ण होने के बारे में आश्वस्त नहीं हैं और इसलिए, अपने आवेदनों को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ

- पेटेंट आवेदनों को संसाधित करने की लंबी अवधि आवेदकों को उनके आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने से हतोत्साहित करती है।
- पेटेंट अधिनियम की धारा 9(1) और 21(1) के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के कारण छोड़े गए पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि करती है।
- लगभग 350% की वृद्धि हुई।
- विकृत प्रोत्साहन जो पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तब भी जब प्रवर्तक यह जानता है कि उनके दावों की जांच नहीं होगी।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में उद्योग-अकादमिक सहयोग संकेतक के लिए भारत का गिरता स्कोर वर्ष 2015 में 47.8 से वर्ष 2021 में 42.7 हो गया, परिणामस्वरूप, जीआईआई में इस सूचक में भारत की रैंकिंग 48 से घटकर 65 हो गई।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग उन विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों तक सीमित रहा है, जिनका वाणिज्यिक महत्व कम है।
- भारत से नवप्रवर्तन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्रचलित एक दुर्लभ घटना रही है।

समाधान

- पेटेंट आवेदनों को संसाधित करने की दक्षता बढ़ाने से निश्चित रूप से देश में पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा।
- डॉट्स को जोड़ने के लिए पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र की अधिक नजदीकी से जांच करें ताकि राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उचित उपाय अपनाए जा सकें।
- विकृत प्रोत्साहनों को समाप्त करना।

आगे बढ़ने की राह

- पेटेंट प्रणाली राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है और पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश से भारत की नवाचार क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- अनुसंधान एवं विकास खर्च और पेटेंटिंग परिदृश्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र प्रमुखता से बढ़ रहा है। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, R&D (GERD) पर सकल घरेलू व्यय में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2013 में 5% से बढ़कर वर्ष 2018 में 7% हो गई है।

- उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम):

- यह भारत सरकार को विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी निकाय है।
- **संरचना:** डॉ. बिबेक देबरॉय (अध्यक्ष) और 6 अंशकालिक सदस्य है।
- **उद्देश्य:** प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी मुद्दे, आर्थिक या अन्यथा का विश्लेषण करना और उस पर सलाह देना, व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधान मंत्री को विचार प्रस्तुत करना। ये या तो स्वप्रेरणा से या प्रधान मंत्री या किसी अन्य के संदर्भ में हो सकते हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII)

- यह INSEAD, WIPO और कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया।
- **लक्ष्य:** मैट्रिक्स और विधियों को खोजने और निर्धारित करने के लिए जो समाज में नवाचार की एक तस्वीर को कैप्चर कर सके जो यथासंभव पूर्ण हो।
- वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग - 130 देशों में 46वीं रही।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016

- राष्ट्रीय आईपीआर नीति एक दृष्टि दस्तावेज है जिसमें सभी आईपीआर को एक अद्वितीय मंच पर शामिल किया गया है और लाया गया है।
- यह सभी अंतर्संबंधों पर विचार करते हुए आईपीआर को समग्र रूप से देखता है और इस प्रकार इसका उद्देश्य सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा (आईपी), संबंधित विधियों और एजेंसियों के बीच तालमेल बनाना और उसका दोहन करना है।
- यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य में शामिल करना और अनुकूलित करना है।

रुपया मूल्यह्रास (Rupee Depreciation)

संदर्भ: पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी डॉलर ($) के संबंध में भारतीय रुपये (INR) की विनिमय दर में लगातार गिरावट आई है। इसने मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण विनिमय दर स्तर का उल्लंघन किया। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से रुपये में गिरावट जारी है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं।

मूल्यह्रास क्या है?

- मुद्रा मूल्यह्रास एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है।
- उदाहरण के लिए: USD 1 पहले 70 रुपये के बराबर होता था, अब USD 1 77 रुपये के बराबर है, जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्यह्रास हुआ है, यानी एक डॉलर खरीदने में अधिक रुपये लगते हैं।

भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव: रुपये में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दोधारी तलवार है।

सकारात्मक प्रभाव:

- सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो सकती है।

नकारात्मक प्रभाव:

- यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिये ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है।
- भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकताओं का दो-तिहाई से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है।
- भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के दो-तिहाई से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है।

रुपये का मूल्य क्या निर्धारित करता है?

- किसी भी मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग के साथ-साथ उसकी आपूर्ति से निर्धारित होता है।
- जब किसी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, तो उसका मूल्य गिर जाता है।
- व्यापक अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय बैंक मुद्राओं की आपूर्ति का निर्धारण करते हैं, जबकि मुद्राओं की मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है।
- विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपये की आपूर्ति आयात और विभिन्न विदेशी संपत्तियों की मांग से निर्धारित होती है। इसलिए, यदि तेल आयात करने की उच्च मांग है, तो इससे विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है और रुपये के मूल्य में गिरावट आ सकती है।

- दूसरी ओर विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की मांग भारतीय निर्यात और अन्य घरेलू परिसंपत्तियों की विदेशी मांग पर निर्भर करती है।
- उदाहरण के लिए जब विदेशी निवेशकों में भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्साह होता है तो इससे विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है जिससे डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य बढ़ जाता है।

डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट का क्या कारण है?

- इस साल मार्च के बाद से यूएस फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क ब्याज दर बढ़ा रहा है जिससे निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजारों और संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस पूंजी खींचने के लिए उच्च रिटर्न की तलाश है।
- इसने बदले में उभरती बाजार मुद्राओं पर दबाव डाला है जो इस वर्ष अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी मूल्यह्रास कर चुकी हैं।
- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मई में दरें बढ़ाने का आरबीआई का आश्चर्यजनक निर्णय भारत से पूंजी के किसी भी तेजी से बहिर्वाह को रोककर रुपये की रक्षा करने के लिए हो सकता है।
- इसके अलावा भारत का चालू खाता घाटा जो अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को मापता है चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 3-3% के 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।
- जब यू.एस. में निवेश प्रतिफल बढ़ रहा हो तो विदेशी निवेशकों के भारत में पूंजी लगाने की संभावना नहीं है।

आगे क्या है?

- रुपये को अनिश्चित काल तक गिरने से रोकना आरबीआई के लिए न तो समझदारी है और न ही संभव है। रुपये की रक्षा करने से भारत समय के साथ अपने विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर देगा क्योंकि वैश्विक निवेशकों का वित्तीय दबदबा बहुत बड़ा है।
    - अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि बेहतर रणनीति यह है कि रुपये को मूल्यह्रास होने दिया जाए और व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के लिए एक प्राकृतिक सदमे अवशोषक के रूप में कार्य किया जाए। इस प्रकार, आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए जो कि इसका कानूनी जनादेश है।
- सरकार को अपनी अपनी उधारी रोकनी चाहिए। सरकार द्वारा अधिक उधारी (राजकोषीय घाटा) घरेलू बचत का उपभोग करती है। इसलिए, औद्योगिक और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को विदेशों से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- भारत और यू.एस. के बीच लंबे समय तक चलने वाली मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, लंबे समय में, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी रहने की संभावना है।
- यू.एस. फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों में वृद्धि की है जो 41 साल के उच्च स्तर 8.6% पर पहुंच गई है।
- यह अन्य देशों और उभरते बाजारों को विशेष रूप से अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा ताकि विघटनकारी पूंजी बहिर्वाह से बचा जा सके और उनकी मुद्राओं की रक्षा की जा सके।
- जैसे-जैसे दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ती हैं, वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सख्त मौद्रिक स्थितियों के अनुकूल हो जाती हैं।

निष्कर्ष:

- विश्लेषकों का मानना है कि भारत और यू.एस. के बीच लंबी अवधि की मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए, लंबे समय में, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी रहने की संभावना है।
- विनिमय दर गिरकर 80 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है, हालांकि भारतीय रुपये ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- यू.एस. और भारत के बीच मुद्रास्फीति विभाजन रुपये में और गिरावट जारी रखेगा। बहरहाल, सक्रिय राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ, भारत अपने मुद्रा मूल्य को स्थिर कर सकता है।

धर्मशाला घोषणा

संदर्भ: हाल ही में भारत में पर्यटन को विकसित करने के तरीकों और तंत्रों पर चर्चा करने के लिए राज्य के पर्यटन मंत्रियों की एक सभा, 'धर्मशाला घोषणा' (2022) के साथ आई।

यह केंद्र सरकार के 'पूरी सरकार' दृष्टिकोण से प्रेरणा लेता है, जो विभिन्न सरकारी गलियारों में साइलो (silos) को तोड़ने और तालमेल को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाता है।

- विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के अवसर पर, धर्मशाला घोषणा का उद्देश्य वैश्विक पर्यटन में योगदान के साथ-साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देकर रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने में भारत की भूमिका को पहचानना है, जिसे लंबे समय से अनदेखा किया गया है।
- घोषणा में, पर्यटन मंत्रालय एक रणनीति और कार्य योजना के साथ आया है ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को घरेलू यात्रा करने और भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का पता लगाने के साथ-साथ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के लक्ष्य तक पहुँचने के

लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

- हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करते हुए भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का सेलिब्रेट करने के लिए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना शुरू की गई थी।

- इसके समानांतर में, मंत्रालय भारत में सबसे अधिक पर्यटक आने वाले 20 भारतीय मिशनों की पहचान करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश-विशिष्ट रणनीतियों का निर्माण करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ भी काम कर रहा है।

पर्यटन पर पुनर्विचार और पुनर्कल्पना: पर्यटन उन क्षेत्रों में से एक रहा है जो COVID-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को हाल ही में होटल और रेस्तरां, मैरिज हॉल, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर और हेरिटेज सुविधाओं जैसे आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों को लाभान्वित करने के लिए ₹5 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया था।

- पर्यटन मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के लिए ढांचे की स्थिति में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों का समर्थन करना, पर्यटन सहायता कार्यों को मजबूत करना और पर्यटन उप-क्षेत्रों का विकास करना है।
- मार्गदर्शक सिद्धांतों में हमारे सभ्यतागत लोकाचार के अनुरूप टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
  - गौतम से लेकर गांधी तक, भारत ने हमेशा प्रकृति के साथ और हमारे साधनों के भीतर सामंजस्य स्थापित करने की अंतर्निहित आवश्यकता के बारे में बात की है।
- राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन का उद्देश्य इस दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना है।
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के माध्यम से डिजिटलीकरण, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कौशल मिशन के माध्यम से कौशल प्रदान करना है।
- नीति सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी विशेष प्रोत्साहन देती है।
  - पीपीपी मोड के विकास से जुड़ी कई अन्य योजनाएं भी राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जैसे पर्यटन क्षेत्र की प्रशंसा करेंगी।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 के मसौदे की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी ढांचे का दर्जा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है।
- यह अगले 10 वर्षों में हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गंतव्य प्रबंधन, आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाने और एमएसएमई से संबंधित पर्यटन का समर्थन करने वाले 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है।
- संपर्क-संवेदनशील उद्योग के लिए राहत के उपाय और कराधान में छूट, जो पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक पीड़ित रहा है।
- विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर इस क्षेत्र की मदद करने के लिए अन्य ढांचागत शर्तें। विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समग्र मिशन और विजन तैयार किया जा रहा है।

G20 की अध्यक्षता के दौरान संभावित:

- भारत के G20 (2023) की अध्यक्षता के दौरान देश के पास स्वयं को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का अवसर है।
  - भारत 20 देशों/यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत करता है, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी और कृषि से लेकर स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यटन और विदेश मंत्रियों और अन्य मंत्रिस्तरीय बैठकों के केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों के कर्मचारी शामिल हैं।
- यहां तक कि सम्मेलन के बुनियादी ढांचे, आवास की उपलब्धता, स्वच्छ भारत में रैंकिंग और अन्य मापदंडों जैसे पारदर्शी मानदंडों के आधार पर शहरों की अंतिम सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस क्षमता वाले करीब 35 शहरों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।
- इस दौरान, भारत में दुनिया का स्वागत करते हुए उचित कठोरता, समर्पण और देश की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने की योजना है।
  - पर्यटन मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ काम करने की भी योजना बना रहा है ताकि वीजा सुधार, यात्रा में आसानी, यात्रियों के अनुकूल और हवाई अड्डों पर बेहतर आव्रजन सुविधाओं जैसे आवश्यक हस्तक्षेप किए जा सकें।

आगे बढ़ने की राह :

- पिछले कुछ महीनों में, सभी प्रमुख पर्यटन सूचकांकों जैसे घरेलू हवाई यात्री यातायात, होटल में लोगों की संख्या और पर्यटकों की संख्या में सुधार के संकेत मिले हैं और ये महामारी से पहले के स्तर पर आ रहे हैं।
  - वर्ष 2024 के मध्य तक, हम पूर्व-महामारी के स्तर पर होंगे, जिसमें भारत पर्यटन से जीडीपी योगदान के रूप में $150 बिलियन और विदेशी मुद्रा आय में $30 बिलियन प्राप्त करेगा, जिसमें 15 मिलियन विदेशी पर्यटक आएंगे।

- वर्ष 2030 तक, भारत के 7%-9% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ने का अनुमान है और हम उम्मीद करते हैं कि सक्षम नीतिगत ढांचा पर्यटन से जीडीपी योगदान में 250 अरब डॉलर, पर्यटन क्षेत्र में 140 मिलियन नौकरियों में लाएगा।
- भारत की सदियों पुरानी कहावत 'अतिथि देवो भव' सामने आएगी क्योंकि यह एक नए युग की पर्यटन नीति के तहत दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करती है।

खाद्य सुरक्षा

संदर्भ: अनिश्चितता के इस युग में खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बढ़ते जलवायु-संबंधी जोखिम, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापक आर्थिक झटके के कारण आयात (दोनों मूर्त और अमूर्त रूप में) पहले से कहीं अधिक महंगा हो गया हैI

- विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण , यह अनुमान है कि 2050 तक 9.5 बिलियन से अधिक लोगों को खिलाने के लिए वैश्विक खाद्य उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी ।
- भारत के कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 262 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो आयात पर कम निर्भरता को प्रदर्शित करता है। कृषि में आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करने से महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुआ है।

खाद्य सुरक्षा के बारे में :

- खाद्य सुरक्षा को एक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोगों की आहार संबंधी मांगों और वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच दोनों पर विचार करती है।
- खाद्य सुरक्षा को "यह सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित किया गया है कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो ।"
- खाद्य सुरक्षा चार स्तंभों पर टिकी हुयी है:
    - उपलब्धता
    - पहुँच
    - उपयोग
    - स्थिरता
- उभरते हुए राष्ट्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राथमिक समस्या खाद्य स्थिरता और उपलब्धता है।

खाद्य सुरक्षा के साथ चुनौतियां:

- **जलवायु संबंधी जोखिम:** लंबे समय तक गर्मी की लहरें (हीटवेव्स) और बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के परिणामस्वरूप कृषि इनपुट संबंधित खर्च में वृद्धि हुई है।
- **अपव्यय और हानि:** भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 5-7 प्रतिशत प्रक्रियात्मक अक्षमताओं के कारण बर्बाद हो जाता हैI
- **अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं :** अनाज के लिए अपर्याप्त और अनुचित भंडारण सुविधाएं , जिन्हें अक्सर बाहर तिरपाल के नीचे रखा जाता है जो नमी और कीटों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं।
    - भारत में गर्म और आर्द्र स्थितियां भी शीत भंडारण सुविधाओं के रखरखाव की लागत को बढ़ा देती हैं ।
- **जागरूकता की कमी:** नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और कृषि उत्पादों पर शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। पारंपरिक खेती के तरीके तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेने वाले होते हैं और खाद्यान्न के उत्पादन आदि में देरी करते हैं।
- **मृदा की घटती गुणवत्ता:** खाद्य उत्पादन का एक प्रमुख तत्व स्वस्थ मृदा है क्योंकि वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 95% हिस्सा मृदा पर निर्भर करता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधार:

जल संरक्षण सिंचाई: बाढ़ सिंचाई की प्रथा आज भी काफी हद तक प्रचलित है और इसका भूजल के घटते स्तर पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है , जो बदले में सूखे की स्थिति को बढ़ाता है।

- किसानों के लिए दीर्घावधि में पानी और बिजली की लागत का अनुकूलन होगा , फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को मुक्त किया जाएगा।
- **भंडारण अवसंरचना:** कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति श्रृंखला मूलभूत हस्तक्षेप का एक उदाहरण है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित कर सकता है, साथ ही साथ फसलों के विविधीकरण को बढ़ाता है जिससे किसान ताजा उपज के शेल्फ जीवन को लंबा करने में सक्षम होते हैं।
- **वित्त तक पहुंच का विस्तार:** वैश्विक वित्त प्रतिज्ञाओं और वित्तीय प्रवाह की संरचना को वैश्विक दक्षिण में धन के प्रवाह में वृद्धि की अनुमति देने के लिए बदला जाना चाहिए।

- घरेलू स्तर पर, इस दिशा में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए नए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसे फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए।
- **फसल विविधीकरण:** खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। भारत कमोबेश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है लेकिन दालों और तिलहनों में कमी है।
- खपत पैटर्न में बदलाव के कारण फलों, सब्जियों , डेयरी, मांस, मुर्गी पालन और मत्स्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है।
- ऐसी फसलों और उत्पादों का उत्पादन करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ाने और संबद्ध गतिविधियों में सुधार करने की आवश्यकता है जिनमें हम कमी कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन से निपटना: भारत में खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देकर प्राप्त की जा सकती है , जिसमें जलवायु-स्मार्ट कृषि उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग नीतियां शामिल हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम:

- **मेगा फूड पार्क:** 2008 में सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना, मेगा फूड पार्क नामक खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **पीएम किसान संपदा योजना:** यह एक व्यापक पैकेज है जिसका लक्ष्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे को खाना बनाना है।
    - देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है और किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने में भी मदद करती है।
- **कृषि अवसंरचना कोष:** यह वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
    - इसका उद्देश्य फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है।
    - योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2032 तक होगी।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: पीएमकेएसवाई 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (कोर योजना) है। इसके उद्देश्य:
- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण ,
- सिंचाई (हर खेत को पानी) की सुविधा का विस्तार कर, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ,
- जल की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए,
- सटीक-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए।

आगे बढ़ने की राह :

- भारत को भंडारण सुविधाओं (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) के व्यापक उन्नयन की आवश्यकता है , जो जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए वित्त तक पहुंच का विस्तार करके बिजली, पानी और कटाई के बाद के नुकसान को कम कर सके।
- हमें निजी क्षेत्र के नवाचारों के लिए पहुंच बिंदुओं को सुगम बनाने की आवश्यकता है जो कृषि लचीलापन में सुधार के बोझ को साझा कर सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की कार्रवाइयों को पूरक कर सकते हैं।
- समय आ गया है कि हम खाद्य असुरक्षा पर काबू पाने, पोषण तक पहुंच बढ़ाने और दीर्घकालिक खाद्य क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में आधुनिक समाधानों की भूमिका को स्वीकार करें।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-सऊदी अरब संबंध

खबरों में क्यों : भारतीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में है, और वार्ता भारत और सऊदी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

- केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति (पीएसएससी) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- मंत्री ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने भारत और छह देशों के क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच परामर्श के तंत्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

नव गतिविधि (Recent Developments):

- नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण सऊदी अरब ने इसकी निंदा करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया।
- **कोविड-19 महामारी:** भारत ने किंगडम को 45 लाख COVISHIELD टीके प्रदान किए, जबकि दूसरी लहर के दौरान, बाद वाले ने भारत को COVID-राहत सामग्री, विशेष रूप से तरल ऑक्सीजन प्रदान किया। महामारी के कारण समुदाय का बड़े पैमाने पर प्रत्यावर्तन अभ्यास (repatriation exercise), जिसके कारण वंदे भारत मिशन के माध्यम से 8,00,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश भेजा गया है।
- राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति (पीएसएससी): भारत-सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद के ढांचे के तहत स्थापित।
- भारत-सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद - का गठन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय के लिए किया गया था। परिषद का नेतृत्व प्रधान मंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद करेंगे और यह हर दो साल में बैठक होगी।
- इसकी दो उप-समितियां हैं -
  1. राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी समिति; तथा
  2. अर्थव्यवस्था और निवेश संबंधी समिति।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- भारत और सऊदी अरब के सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हुए सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
- वर्ष 2021-22 भारत की आजादी के 75 साल को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाता है। यह उत्सव भारत और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्षों के साथ भी मेल खाता है।
- वर्ष 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय दौरे हुए।

द्विपक्षीय व्यापार:

- सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत सऊदी निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है।
- वित्त वर्ष 22 में द्विपक्षीय व्यापार 29.28 अरब डॉलर था। इस समय के दौरान, सऊदी अरब से भारत का आयात 22.65 अरब डॉलर और सऊदी को निर्यात 6.63 अरब डॉलर था।
- भारत का 18% से अधिक कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से होता है।
- भारत भी सऊदी अरब से एलपीजी आवश्यकताओं का लगभग 32% आयात करता है।

आर्थिक सहयोग:

निवेश:

- लगभग 745 भारतीय कंपनियां संयुक्त उद्यम/100% स्वामित्व वाली संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनका राज्य में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है।
- ये कंपनियां प्रबंधन और परामर्श सेवाओं, निर्माण परियोजनाओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास, फार्मास्यूटिकल्स आदि जैसे विविध क्षेत्रों में काम करती हैं।
- मार्च 2021 तक भारत में सऊदी निवेश 3.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- प्रमुख सऊदी निवेश समूहों में ARAMCO, SABIC, ZAMIL, E-Holidays, और Al Batterjee Group शामिल हैं।
- अन्य प्रस्तावित प्रमुख निवेशों में महाराष्ट्र में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 'वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट' शामिल है, जिसे सऊदी और भारत के निगमों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है।

प्रवासी:

- 2 मिलियन मजबूत भारतीय समुदाय देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और उनकी विशेषज्ञता, अनुशासन, कानून का पालन करने वाली भावना और शांतिप्रिय प्रकृति के कारण 'सबसे पसंदीदा' है।
- विदेशों में नौकरी चाहने वाले भारतीयों के लिए सऊदी अरब सबसे पसंदीदा गंतव्यों में से एक बना हुआ है। इसलिए, देश से बड़ी संख्या में प्रेषित धन (remittances) प्राप्त हुए हैं, जो 2020 में 34.5 बिलियन डॉलर के बराबर है।
- वर्ष 2019 में, दोनों पक्षों ने घोषणा की कि श्रमिकों के लिए प्रवासन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए भारत की ई-माइग्रेट प्रणाली को किंगडम की ई-तौथीक प्रणाली (Kingdom's e-Tawtheeq system) के साथ एकीकृत किया जाएगा।

सांस्कृतिक संबंध:

- भारत ने 07 से 28 फरवरी, 2018 तक प्रतिष्ठित सऊदी नेशनल फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर-जनाद्रिया के 32वें संस्करण में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में भाग लिया।
- वार्षिक हज यात्रा भारत-सऊदी द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है।
- योग सऊदी अरब में भी एक बहुत लोकप्रिय गतिविधि बन गया है, खासकर नवंबर 2017 में इसे 'खेल गतिविधि' के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद।
- IDY 2021 पर, सऊदी खेल मंत्रालय और भारत के आयुष मंत्रालय के बीच योग सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने किंगडम में औपचारिक योग मानकों और पाठ्यक्रमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, खाड़ी क्षेत्र के किसी भी देश द्वारा इस तरह के मानकों को पहली बार लागू किया जा रहा था।
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को कई कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसका समापन 02 अक्टूबर, 2019 को दूतावास में गांधी प्रतिमा के अनावरण के साथ हुआ।

आगे बढ़ने की राह

- सामरिक, रक्षा और आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में एक संतुलन नीति की आवश्यकता।
- कच्चे तेल और एलपीजी से परे व्यापार संबंधों का विविधीकरण।
- सैन्य अंतर्दृष्टि साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के माध्यम से आतंकवाद से निपटने पर सहयोग।

गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल (Gulf Cooperation Council)

- यह अपने चार्टर के अनुसार एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है।
- GCC की स्थापना वर्ष 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उनके विशेष संबंधों, भौगोलिक निकटता, इस्लामी मान्यताओं पर आधारित समान राजनीतिक व्यवस्था, संयुक्त नियति और सामान्य उद्देश्यों के मद्देनजर संपन्न एक समझौते द्वारा की गई थी।
- GCC की संरचना में सर्वोच्च परिषद (उच्चतम प्राधिकारी), मंत्रिस्तरीय परिषद और सचिवालय जनरल शामिल हैं।
- सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है।

भारत-मिस्र संबंध

खबरों में क्यों : केंद्रीय रक्षा मंत्री काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। भारत और मिस्र सैन्य सहयोग को और विकसित करने और संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा सह-उत्पादन और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए।

ऐतिहासिक संबंध:

- विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से दो भारत और मिस्र ने प्राचीन काल से घनिष्ठ संपर्क के इतिहास का आनंद लिया है। सामान्य युग से पहले भी, अशोक के शिलालेख टॉलेमी II के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख करते हैं।
- आधुनिक समय में, महात्मा गांधी और साद ज़गलौल ने अपने देशों की स्वतंत्रता पर साझा लक्ष्य साझा किए
- जमाल अब्देल नासिर और जवाहरलाल नेहरू के बीच असाधारण रूप से घनिष्ठ मित्रता, जिसके कारण 1955 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई।

राजनीतिक संबंध:

- भारत और मिस्र द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संपर्कों और सहयोग के लंबे इतिहास पर आधारित घनिष्ठ राजनीतिक समझ को साझा करते हैं।
- दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग किया है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे।
- वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

आर्थिक संबंध:

- भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से संचालन में है और यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पर आधारित है और पिछले दस

वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार पांच गुना से अधिक बढ़ा है।

- वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 4.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- महामारी के बावजूद, व्यापार की मात्रा केवल मामूली घटकर 2019-20 में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020-21 में 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। (भारत को मिस्र का निर्यात 1.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत से 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात था, जिसमें भारत का 372 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुकूल व्यापार संतुलन था।)
- वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से विस्तार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 75% की वृद्धि दर्ज करते हुए 26 बिलियन है।
- इस अवधि के दौरान मिस्र को भारत का निर्यात 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में 65% की वृद्धि दर्ज करता है। इसी समय, भारत को मिस्र का निर्यात 86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 3.52 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

विकास सहायता:

- सहायता अनुदान परियोजनाओं में शामिल होना : अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में पैन अफ्रीका टेली-मेडिसिन और टेली-शिक्षा परियोजना, अगावीन विलेज में सौर विद्युतीकरण परियोजना और शोबरा, काहिरा में कपड़ा प्रौद्योगिकी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जो पूरे हो चुके हैं।
- तकनीकी सहयोग और सहायता हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। वर्ष 2000 के बाद से, 1250 से अधिक मिस्र के अधिकारी ITEC और अन्य कार्यक्रमों जैसे ICCR और IAFS छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए हैं।
- वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में आईसीएआर और मिस्र के कृषि अनुसंधान केंद्र कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
- सीएसआईआर (भारत) और एनआरसी (मिस्र) के बीच द्विवार्षिक कार्यकारी कार्यक्रमों और वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी' सहयोग लागू किया गया है।
- अंतरिक्ष सहयोग भारत और मिस्र के बीच सहयोग का एक उभरता हुआ कार्यक्षेत्र है। इसरो और एनएआरएसएस (नेशनल अथॉरिटी फॉर रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंसेज) के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठकें और चर्चाएं हुई हैं, जब से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

रक्षा संबंध:

- वर्ष 1960 के दशक में संयुक्त रूप से एक लड़ाकू विमान विकसित करने के प्रयासों के साथ, वायु सेना के बीच घनिष्ठ सहयोग था।
- IAF पायलटों ने वर्ष 1960 से 1984 तक मिस्र के पायलटों को भी प्रशिक्षित किया था।
- वर्तमान रक्षा सहयोग का अधिकांश भाग संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की गतिविधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- मिस्र ने वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित मित्र अफ्रीकी देशों के लिए बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2021 में पहली बार IAF-EAF संयुक्त सामरिक वायु अभ्यास, डेज़र्ट वॉरियर आयोजित किया गया था।
- भारत और मिस्र के बीच 8 से 22 जनवरी 2022 तक जोधपुर में नियोजित पहला विशेष बल अभ्यास "चक्रवात 1" स्थगित कर दिया गया है।

सांस्कृतिक संबंध:

- मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र (एमएसीआईसी) हिंदी, उर्दू और योग कक्षाओं, सेमिनार; फिल्म शो; प्रदर्शनियों और स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी जैसी नियमित गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता रहा है।
- पिछले छह दशकों से दूतावास की प्रमुख अरबी पत्रिका 'सौत-उल-हिंद (Sawt-ul-Hind)' जुलाई 2017 में अपने 500वें संस्करण के प्रकाशन के साथ एक मील के पत्थर तक पहुंच गई, जिसमें दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन और जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाया गया है।

भारतीय समुदाय: वर्तमान में, मिस्र में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 3200 है, जिनमें से अधिकांश काहिरा में केंद्रित हैं।

आगे की राह :

- वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक रहा है और इस दोस्ती को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा।

G4 देश और UNSC सुधार

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र में सुधार विदेश मंत्री की संयुक्त राष्ट्र यात्रा का एक केंद्रीय विषय रहा है और उन्होंने द ग्रुप ऑफ फोर (G4) के तहत जर्मनी,

ब्राजील और जापान के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की। यह समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार, और G4 सदस्यों के लिए निकाय की स्थायी सदस्यता पर केंद्रित है।

G4 देशों के बारे में:

- ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान से युक्त G4 राष्ट्र चार देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं।

कॉफी क्लब/सहमति के लिए एकजुट होने के बारे में:

- एक अनौपचारिक "कॉफी क्लब", जिसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को रोकने में सहायक रहा है।
- इस क्लब के अधिकांश सदस्य मध्यम आकार के देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों को हथियाने वाली बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों का विरोध कर रहे हैं।
- क्लब के प्रमुख मूवर्स में इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान शामिल हैं।
- जहां इटली और स्पेन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी की बोली का विरोध कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भारत की बोली (bid) का विरोध कर रहा है।
- इसी तरह, अर्जेंटीना ब्राजील की बोली के खिलाफ है और ऑस्ट्रेलिया जापान की बोली का विरोध करता है।
- कनाडा और दक्षिण कोरिया विकासशील देशों के विरोधी हैं, जो अक्सर उनकी सहायता पर निर्भर होते हैं, संयुक्त राष्ट्र में उनसे अधिक शक्ति रखते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता:

- समतामूलक विश्व व्यवस्था - वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।
- समावेशिता - अफ्रीकी देशों जैसे विकासशील देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में हितधारक बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।
- नए खतरों का शमन - कोरोना महामारी, बढ़ते संरक्षणवाद, आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के खतरे के युग में, बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनना चाहिए।
- निराशा भरे समय (Desperate times) में हताशापूर्ण उपायों की आवश्यकता होती है - 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति में जी-20 के विस्तार की एक मिसाल पहले से ही है।
- महासभा की प्रक्रिया के नियम - उदाहरण के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत का प्रकार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता आदि।

संयुक्त राष्ट्र में किन सुधारों की आवश्यकता है:

- महासभा के कार्य करने का नियम - उदाहरण के लिए, किसी दस्तावेज़ को अपनाने से पहले, प्रत्येक दस्तावेज़ का छह भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। उसके बाद कई बार चर्चा 6 भाषाओं की एक्यूरेसी की ओर हो जाती है। इस प्रक्रिया ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में ग्रंथों को अपनाने में देरी की है।
- स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की सदस्यता - अपनी स्थापना के बाद से, यूएनएससी को केवल एक बार बढ़ाया गया है। उसके बाद भी, UNSC के स्थायी सदस्य स्थिर बने हुए हैं। यह समस्याग्रस्त है क्योंकि इसके गठन के बाद से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लगभग चार गुना बढ़ गई है।
- वीटो पावर - वीटो पावर P5 सदस्यों का अनन्य डोमेन रहा है। कई देशों ने वीटो के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। अन्य लोगों ने वीटो की विशिष्टता पर सवाल उठाया है, जो कि P5 राष्ट्रों तक सीमित है, जैसा कि पहले कहा गया है।

सुधारों की चुनौतियां और G4 मांग:

- संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन करना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है क्योंकि प्रक्रिया के नियम कठोरता की ओर झुकते हैं।
- सहमति का अभाव - हालांकि व्यवस्था में बदलाव के लिए एक सामान्य सहमति है, लेकिन अलग-अलग देशों में बदलाव की आवश्यकता के बारे में अलग-अलग धारणाएं हैं।
    - उदाहरण के लिए - G4 राष्ट्र स्थायी सदस्य के रूप में प्रत्येक सीट की मांग करते हैं, यूएफसी गैर-स्थायी सीटों के विस्तार के लिए कहता है, अफ्रीकी संघ किसी भी कीमत पर अपना प्रतिनिधित्व चाहता है।
- संकीर्ण राजनीतिक विचार - देश व्यापक विश्व दृष्टिकोण के बजाय अपने स्वयं के हित में परिवर्तन को देखते हैं।
    - G4 उदाहरण के लिए - कई देश अस्थायी स्थान में विस्तार चाहते हैं, ताकि उनके पास संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए चुने

जाने की संभावना बढ़ जाए।

- पीजीए (इनसेट देखें) भारत की मांग का विरोध - विशेष रूप से, भारत की मान्यता के लिए एक और चुनौती और G4, सामान्य रूप से, यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान पीजीए है।
    - वर्तमान पीजीए तुर्की का है और भारत की मांग के अनुकूल नहीं है। वास्तव में, वह पाकिस्तान के नेतृत्व वाले कॉफी क्लब के प्रति पक्षपाती है, जो यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के विस्तार को सीमित करना चाहता है।
- P5 की वीटो शक्ति - यूएनएससी के विस्तार के लिए सभी पांच स्थायी, वीटो-धारक सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत को सावधान रहना चाहिए कि वह सभी P5 सदस्यों, विशेष रूप से चीन से समर्थन प्राप्त करता रहे, जो अब तक UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के प्रति अस्पष्ट रहा है।
- अफ्रीकी स्थिति - आमतौर पर भारत अफ्रीकी स्थिति का समर्थन करता रहा है जहां उसने अपने उम्मीदवार के लिए एक सीट की मांग की है।
    - समस्या यह है कि अफ्रीका देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए छोड़ने के बजाय अपने आप नामित करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। यह कई सदस्यों को स्वीकार्य नहीं है।

आगे की राह :

- **डिप्लोमैटिक आउटरीच -** G4 के साथ-साथ भारत को अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले प्रमुख राष्ट्रों के लिए एक राजनयिक आउटरीच के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है।
    - उदाहरण के लिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के लिए उम्मीदवारी का किसी भी वीटो-पालन करने वाले राष्ट्र द्वारा विरोध नहीं किया गया है। यहां तक कि चीन, जिसके साथ भारत सीमा गतिरोध में लगा हुआ है, ने कभी भी भारत के रुख का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया।
- **भारत की सॉफ्ट पावर -** भारत ने अफ्रीका के अल्प विकासशील देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीपीय देशों को उनके विकासात्मक प्रयासों में लगातार समर्थन दिया है।
- इससे भारत की छवि एक परोपकारी और मैत्रीपूर्ण देश के रूप में विकसित हुई है।
- **संयुक्त राष्ट्र में योगदान -** भारत को चीन पर नजर रखने की जरूरत है, जो अब संयुक्त राष्ट्र में फंड का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।
    - इसके अलावा, चीन ने अब अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण के एजेंडे के साथ, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेना भेजना शुरू कर दिया है।
- **विविधीकरण -** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा, भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अन्य एजेंसियों की ओर अपनी ऊर्जा में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि एक ऐसी धारणा बनाई जा सके जहां इसे एक प्राकृतिक नेता के रूप में माना जाता है।
    - उदाहरण के लिए - भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में संस्था को महत्व देने के लिए आर्थिक परिषद (ईसीओएसओसी) में चर्चा की।
- **भारत की रणनीति पर बहस -** कुछ संस्थानों में सुधार के लिए भारत की ओर से बलिदान की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए हमारे पास स्पष्ट रूप से उल्लिखित रणनीति होनी चाहिए।
    - उदाहरण के लिए - भारत विश्व बैंक के ऋणों का प्रमुख लाभार्थी रहा है। यदि हमें नेतृत्व की स्थिति की आवश्यकता है, तो हमें इन ऋणों को छोड़ना पड़ सकता है।

भारत-रूस संबंध

संदर्भ: शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर, भारत के प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति ने रूस में चल रहे यूक्रेन युद्ध के बीच रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा की।

ऐतिहासिक संबंध:

- उस दौरान, रूस ने कश्मीर के विवादित क्षेत्रों और गोवा जैसे पुर्तगाली तटीय परिक्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता के लिए सोवियत संघ के समर्थन का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी रूस अभी भी कश्मीर पर भारत के दावे का समर्थन करता है।
- USSR वर्ष 1962 में भारत में मिकोयान-गुरेविच मिग-21 जेट फाइटर के सह-उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहमत हुआ। लेकिन USSR ने चीन के समान कदम को खारिज कर दिया।
- भारत ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए।

राजनीतिक संबंध:

- वर्ष 2019 में, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम को रूस के सर्वोच्च राज्य अलंकरण द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल (St Andrew the Apostle) से सम्मानित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
- दो अंतर-सरकारी आयोग - व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर और दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी-एमटीसी) पर सालाना मिलते हैं।

रक्षा और सुरक्षा संबंध

- भारत-रूस सैन्य-तकनीकी सहयोग एक क्रेता-विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल हैं।
- भारत और रूस के बीच संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास 'INDRA 2019' 2019 में बबीना, पुणे और गोवा में एक साथ किया गया था।

भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम
- 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम
- सुखोई Su-30MKI कार्यक्रम
- इल्यूशिन/एचएएल सामरिक परिवहन विमान
- KA-226T ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर

भारत द्वारा रूस से खरीदे/लीज पर लिए गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:

- S-400 ट्रायम्फ (S-400 TRIUMF)
- मेक इन इंडिया पहल के तहत कामोव का-226 200 को भारत में बनाया जाएगा
- T-90S भीष्म (T-90S Bhishma)
- INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम
- S-400 वायु रक्षा प्रणाली

भारत - रूस व्यापार संबंध:

- दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं।
- वर्ष 2019 में, जनवरी-सितंबर, 2019 से दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 7.55 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- वर्ष 2013-2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में भारी गिरावट आई। हालाँकि, यह वर्ष 2017 के बाद से बढ़ा और वर्ष 2018- 2019 में भी लगातार वृद्धि देखी गई।

सांस्कृतिक संबंध:

- लगभग 20 रूसी संस्थान, जिनमें प्रमुख विश्वविद्यालय और स्कूल शामिल हैं, नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं।
- हिंदी के अलावा, रूसी संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं को पढ़ाया जाता है।
- भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में से हैं जिनका रूस के लोग आनंद लेते हैं।

रूस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की स्थिति:** रूस बना हुआ है, और एक प्रमुख परमाणु और ऊर्जा शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना रहेगा।
- **बहुध्रुवीय विश्व राजनीति:** चूंकि दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है, इसलिए भारत के लिए रूस और अमेरिका के साथ घनिष्ठ और रणनीतिक संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। रूस के साथ मजबूत साझेदारी भारत को अन्य देशों से निपटने के लिए लाभ प्रदान करती है।
- **UNSC सीट के लिए समर्थन:** रूस ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने का समर्थन करता है।
- **चीन की आक्रामकता का प्रतिसंतुलन:** भारत के पास अमेरिका और रूस दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और चीन के साथ अपने कठिन संबंधों को प्रबंधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक रूस के पश्चिम के साथ संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, रूस का चीन की ओर झुकाव रहेगा। जब तक भारत-चीन संबंध खराब रहेंगे, रूस का चीनी प्रभाव क्षेत्र में जाना भारत के अनुकूल नहीं होगा।
- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा:** रूस के पास तेल का विशाल भंडार है। भारत ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में रूस की ओर देख रहा है क्योंकि मध्य पूर्व की स्थिति आवश्यक तेल व्यापार मार्गों के लिए खतरों से बढ़ रही है।

भारत-रूस संबंधों में चुनौतियां:

- **भारत-अमेरिका संबंधों का तेजी से विस्तार:** यह भारत-रूस संबंधों में तनाव के सबसे अधिक उद्धृत कारणों में से एक है। वर्ष 2008 के बाद से भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग का विकास तेजी से हुआ है।
- वर्ष 2014 में अमेरिका रूस को पछाड़कर भारत के लिए शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।
- इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के साथ सभी मूलभूत समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। जैसे लेमोआ, कॉमकासा, बीईसीए।
- इन विकासों के कारण, रूस ने अपनी दशकों पुरानी नीति को बदल दिया और चीन को सुखोई-35 और एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे हथियार प्रणालियों की आपूर्ति शुरू कर दी।
- **चीन के प्रति रूस की निकटता:**
    - रूस ने पहले ही विदेश मंत्रियों के रूस-भारत-चीन (आरआईसी) मंच का प्रस्ताव रखा है। लेकिन चीन के साथ भारत के अनसुलझे मुद्दों के कारण RIC को कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं मिली है।
- अमेरिका का विरोध करने में उनकी साझा रुचि के कारण चीन-रूसी संबंध बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच तीव्र भू-रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता। अमेरिका का विरोध करने वाले रूस ने चीन से हाथ मिला लिया। यह स्पष्ट है क्योंकि रूस चीनी वन बेल्ट वन रोड पहल में शामिल हुआ था।

निष्कर्ष: भारत और रूस अपने संबंधों के लिए एक साझा रणनीतिक तर्क साझा करना जारी रखते हैं: द्विपक्षीय तालमेल के अलावा, दोनों BRICS, RIC, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एससीओ सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं जहां पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर सहयोग के अवसर मौजूद हैं।

कुल मिलाकर, भारत और रूस दोनों को न केवल द्विपक्षीय कारकों से बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों से भी उभरती चुनौतियों के बीच अपने संबंधों को नेविगेट करके सीखना होगा, क्योंकि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उतार-चढ़ाव के समय अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।

इतिहास, कला और संस्कृति

सुभाष चंद्र बोस

खबरों में क्यों : हाल ही में प्रधानमंत्री ने ' कर्त्तव्य पथ' का उद्घाटन और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कर्त्तव्य पथ को पहले राजपथ के रूप में जाना जाता था।

सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन

- कटक में वर्ष 1897 में एक उच्च वर्गीय बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ और प्रभावती बोस की नौवीं संतान थे।
- वर्ष 1909 में, एस सी बोस रेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की।
- उन्होंने जीवन भर अपनी यूरोपीय शिक्षा जारी रखी, जबकि वे अपने परिवार की तुलना में अंग्रेजी तरीकों के प्रति कम आकर्षित हुए।
- रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ-साथ बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के विषयों से प्रभावित होकर, सुभाष ने वह पाया जिसकी उन्हें तलाश थी: "उनकी मातृभूमि की स्वतंत्रता और पुनरुद्धार"।
- उन्होंने साल 1913 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया, और जिसके बाद में उन्हें प्रेसीडेंसी कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने एक छोटी अवधि के लिए अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से दर्शनशास्त्र में बीए पास किया।
- ब्रिटिश सत्ता के साथ उनकी सबसे पहली लड़ाई तब हुई जब वे एक छात्र थे, इतिहास के प्रोफेसर ई एफ ओटन के खिलाफ, जिन्होंने कक्षा में एक बार भारत में इंग्लैंड के सभ्यता मिशन के बारे में बात की थी।
- बाद में, बोस 1920 में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) परीक्षा की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।
- लेकिन बाद में, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा (ICS) से इस्तीफा दे दिया।

गांधी के साथ बोस की असहमति

- वर्ष 1921 में बंबई, अब मुंबई पहुंचने के बाद, गांधी की कार्ययोजना को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने गांधी से मिले।
- जहां गांधी स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार थे, दूसरी ओर बोस तत्काल परिणाम नहीं मिले तो तत्काल कार्रवाई चाहते थे।
- गांधी भौतिकवादी विरोधी और आधुनिक तकनीक के विरोधी थे, वहीं बोस ने प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन को अस्तित्व और गरिमा के लिए आवश्यक माना।
- गांधीजी एक विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे और आधुनिक राज्य को नापसंद करते थे; बोस एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे और उन्होंने आधुनिक राज्य को भारत की समस्याओं के एकमात्र समाधान मानते थे ।
- और अंत में, बोस ने अहिंसा के प्रति गांधी के समर्पण से इत्तेफाक नहीं रखते थे ।
- दोनों के बीच तनाव के बावजूद, बोस गांधी जैसे नेता के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ थे। जुलाई 1944 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो के एक संबोधन के दौरान बोस ने सबसे पहले उन्हें "राष्ट्रपिता" कहकर संभोधित किया था ।

कांग्रेस के अंदर मतभेद

- बोस ने अपना जीवन राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, काफी राजनीतिक प्रभाव मिला और कांग्रेस पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गए।
- वर्ष 1938 में, उन्हें हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, जहाँ उन्होंने "राष्ट्रीय माँग" के रूप में स्वराज को आगे बढ़ाने की कोशिश की और ब्रिटिश शासन के तहत एक भारतीय संघ के विचार का विरोध किया।
- वह वर्ष 1939 में फिर से चुनाव के लिए खड़े हुए और गांधीजी समर्थित उम्मीदवार डॉ. पट्टाभि सीतारमैय्या को हराया।
- कार्यसमिति के 15 में से 12 सदस्यों ने अपनी भूमिकाओं से इस्तीफा दे दिया।
- बोस ने एक और कार्यसमिति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने के बाद, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी जगह प्रसाद ने ले ली।
- एक सप्ताह के भीतर, उन्होंने पार्टी के कट्टरपंथी-वामपंथी तत्वों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर "फॉरवर्ड ब्लॉक" के निर्माण का प्रस्ताव रखा ।

एक नाटकीय पलायन

- कलकत्ता के ब्लैक होल के पीड़ितों को समर्पित स्मारक को हटाने के लिए एक अभियान शुरू करने से पहले बोस को 1940 में गिरफ्तार

किया गया था, ब्लैक होल घटना के तहत 1756 में कई यूरोपीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी।

- भूख हड़ताल पर जाने के बाद, दिसंबर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
- उन्होंने जल्द ही भारत से भागना शुरू कर दिया, ब्रिटिश निगरानी से बचने के लिए विभिन्न भेष में सड़क, रेल, वायु और पैदल यात्रा की।
- उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सोवियत-नियंत्रित काबुल में प्रवेश किया और अंत में नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां वे दो साल तक रहे।
- अंग्रेजों से लड़ाई के लिए उन्हें सहायता प्रदान की गई, और बोस को आज़ाद हिंद रेडियो शुरू करने की अनुमति दी गई और जर्मनी द्वारा पकड़े गए युद्ध के कुछ हज़ार भारतीय कैदियों को प्रदान किया गया।
- बोस ने जल्द ही अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से सिंगापुर पर केंद्रित किया, जो एक ब्रिटिश गढ़ था जिसे जापान ने अपने कब्जे में ले लिया था।

INA और द्वितीय विश्व युद्ध

- भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में किया गया था, जिसमें जापानियों द्वारा पकड़े गए और जापानी सैनिकों द्वारा समर्थित हजारों भारतीय युद्धबंदी शामिल थे।
- सिंगापुर पहुंचने के बाद, बोस ने वहां से अपना प्रसिद्ध आह्वान 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।
- इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय जनवरी 1944 में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था, और अराकान मोर्चे पर लड़ने के बाद, आईएनए ने भारत-बर्मा सीमा पार की और मार्च में इंफाल और कोहिमा की ओर कूच (marched) किया।
- दिल्ली चलो अभियान इंफाल में समाप्त हो गया, हालांकि, ब्रिटिश और ब्रिटिश भारतीय सेनाएं जापानी सेना और आईएनए को हराने और उन्हें कोहिमा से बाहर निकालने में सक्षम थीं।
- 16 अगस्त को जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद, बोस एक जापानी विमान पर दक्षिण पूर्व एशिया छोड़ कर चीन की ओर रवाना हुए। हालाँकि, विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई।

भूगोल

शहरी बाढ़ (Urban Flooding)

संदर्भ: भारत की आईटी और स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में अभूतपूर्व बाढ़ (unprecedented floods) का सामना करना पड़ रहा है। भारत में शहरी बाढ़ का यह पहला मामला नहीं है। वास्तव में, देश के कई हिस्सों में शहरी बाढ़ आम होती जा रही है, इस मानसून के मौसम में ही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं।

शहरी बाढ़ के क्या कारण हैं?

- शहरी बाढ़ एक निर्मित वातावरण में भूमि का जलभराव है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, वर्षा के कारण जल निकासी प्रणालियों की क्षमता अत्यधिक हो जाती है।

प्राकृतिक कारण

- **अधिक वर्षा:** आईएमडी के अनुसार, मानसून लगातार और अप्रत्याशित हो गया है।
- तूफान की लहरें (तटीय शहरों के लिए): वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान ने कोलकाता की सड़कों पर पानी भर दिया। पूर्वी भारत में, तूफान ने 98 लोगों की जान ले ली और $ 13.8 बिलियन (2020 USD) का कारण बना।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण और भीषण घटनाएँ हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कम अवधि की भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है जिसके कारण उच्च जल अपवाह हुआ है।

मानवशास्त्रीय कारण (Anthropological Reasons):

- **जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण:** भारतीय शहरों और कस्बों में, भूमि की कीमतों में वृद्धि और शहर के केंद्र में भूमि की कम उपलब्धता के कारण निचले इलाकों में बस्तियां आ रही हैं, आमतौर पर झीलों, आर्द्रभूमि और नदी के किनारों पर अतिक्रमण के रूप में। इसके विपरीत प्राकृतिक नालों को चौड़े किए बिना बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। नतीजतन, प्राकृतिक नालों की क्षमता कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ गई है।
- **शहर की जल निकासी व्यवस्था का प्रबंधन करने में असमर्थता:** अक्टूबर 2020 की हैदराबाद बाढ़ इसलिए आई क्योंकि पानी का निर्वहन समय पर नहीं हुआ। और जब पानी छोड़ा गया तो वह अचानक, अनियंत्रित तरीके से था।

- बांधों और झीलों से अनियोजित और अचानक पानी छोड़ने से शहरी क्षेत्र में बाढ़ आती है, जनता को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उदाहरण: चेंबरमबक्कम झील से पानी छोड़े जाने के कारण चेन्नई में 2015 की बाढ़ आई।

- **पुरानी जल निकासी अवसंरचना:** अधिकांश शहरों में, सदियों पुरानी जल निकासी प्रणाली (औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित) मौजूद है, जो मुख्य शहर के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर करती है। पिछले 20 वर्षों में, इन शहरों ने अपने मूल निर्मित क्षेत्र में कम से कम चार गुना वृद्धि की है और पर्याप्त जल निकासी प्रणालियों के अभाव को दूर करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है।
- **आर्द्रभूमि का नष्ट होना :** वृद्धिशील भूमि उपयोग परिवर्तन के मुद्दों की उपेक्षा करना, विशेष रूप से उन कॉमन के जो हमें आवश्यक पारिस्थितिक सहायता आर्द्रभूमि प्रदान करते हैं। इससे शहरी इलाके का निर्माण हुआ है जो पानी को अवशोषित करने, धारण करने और निर्वहन करने में असमर्थ है।
- शहरी ताप द्वीप प्रभाव के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है।
- **सतत विकास:** बेंगलुरू में हाल ही में आई बाढ़ जैसी कई शहरी बाढ़ आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों जैसे क्षेत्रों में अनियमित निर्माण का परिणाम है।
- **खराब शासन:** शहरी विस्तार, जो अक्सर शहरी अधिकारियों की मिलीभगत से पानी की प्राकृतिक निकासी की कीमत पर किया जाता है। कैग की रिपोर्ट (पिछले साल) ने इस खराब प्रबंधन के लिए बेंगलुरु नगरपालिका की खिंचाई की।
  - वर्ष 2019 में, पटना शहर सितंबर के अंत में बड़े पैमाने पर शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ा। नगरपालिका अधिकारी समस्या से निपटने में असमर्थ होने के कारणों में से एक यह था कि वे शहर के जल निकासी मानचित्र का पता नहीं लगा सके, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5.8 मिलियन है।
- **विकास बनाम पर्यावरण के बीच नैतिक दुविधा:** कोई भी नीति जो निर्माण पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देती है, उसे भारत में, विशेष रूप से शहरों में बहुत सारी निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति से इनकार करना होगा।
- **अवैध खनन गतिविधियां:** भवन निर्माण में उपयोग के लिए नदी की रेत और क्वार्टजाइट का अवैध खनन नदियों और झीलों के प्राकृतिक तल को समाप्त कर देता है। यह मिट्टी के कटाव का कारण बनता है और जल प्रवाह की गति और पैमाने को बढ़ाकर जलाशय की जल धारण क्षमता को कम करता है। उदाहरण: जयसमंद झील- जोधपुर, कावेरी नदी- तमिलनाडु।

शहरी बाढ़ के प्रभाव क्या हैं?

- **जीवन और संपत्ति का नुकसान:** शहरी बाढ़ अक्सर जीवन के नुकसान और मानव क्षति से जुड़ी होती है या तो सीधे बाढ़ के प्रभाव के कारण या परोक्ष रूप से जल जनित रोगों के संक्रमण के कारण बाढ़ की अवधि के दौरान फैलती है।
- **नागरिक सुविधाओं में व्यवधान:** शहरी बाढ़ के स्थानीय प्रभाव हैं जैसे इमारतों, संपत्ति, फसलों को संरचनात्मक क्षति। इसके अलावा, यह जल आपूर्ति, सीवरेज, बिजली और पारेषण लाइनों, संचार, यातायात-सड़क और रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में व्यवधान का कारण बनता है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** आश्रय और रिश्तेदारों की हानि फंसे हुए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक उथल-पुथल पैदा करती है। ऐसी घटनाओं के मामले में पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया एक थकाऊ प्रक्रिया और समय लेने वाली होती है जो अक्सर लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक आघात की ओर ले जाती है।
- **पारिस्थितिक प्रभाव:** अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के दौरान पेड़ और पौधे बह जाते हैं और नदी के किनारे का कटाव उच्च गति वाले बाढ़ के पानी के कारण होता है।

शहरी बाढ़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

- **स्पंज सिटीज मिशन:** स्पंज सिटी वो होती है जहां सड़कों-फुटपाथों जैसी कठोर सतहों को पारगम्य सतहों (Permeable Surfaces) में बदल दिया जाता है, जिससे वो पानी को सोख लें। इससे पानी को शुद्ध और जमा किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **नियोजित विकास:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करना।
  - बृहन्मुंबई (Brihanmumbai) स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम या BRIMSTOWAD, मुंबई शहर की पुरानी तूफानी जल निकासी प्रणाली की मरम्मत के लिए परियोजना 2005 की बाढ़ के बाद शुरू की गई थी।
- **नीतिगत मानसिकता में बदलाव:** जल-संवेदनशील शहरी डिजाइन (ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूएसयूडी) शहरी तूफानी जल अपवाह, और अपशिष्ट जल को उपद्रव या दायित्व के बजाय एक संसाधन के रूप में मानता है।
- **पारिस्थितिक समाधान:** बायोस्वालेस या 'रेन गार्डन' (न्यूयॉर्क) परिदृश्य की विशेषताएं हैं जो प्रदूषित तूफानी जल अपवाह को इकट्ठा करती हैं, इसे जमीन में भिगोती हैं, और प्रदूषण को फ़िल्टर करती हैं।
- **वर्षा जल संचयन:**

- लोगों को वर्षा जल संचयन में भारी निवेश करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जितना संभव हो वर्षा जल का संग्रह, उसका उपयोग हमारे जलभृतों को भरने के लिए करें और हमारे भूखंडों और अपार्टमेंटों और गेटेड समुदायों को शून्य वर्षा निर्वहन क्षेत्रों के रूप में डिजाइन करने का प्रयास करें।

- **वाटरशेड के आधार पर डिजाइन:**
  - प्रत्येक झील एक सूक्ष्म या लघु जलसंभर है। अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि वाटरशेड एक हाइड्रोलॉजिकल इकाई है, यह समझें कि पानी कैसे बहता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे चैनलों में बहने देना चाहिए और झील में प्रवाहित किया जाना चाहिए।
  - जब झील ओवरफ्लो होती है, तो यह अगली डाउनस्ट्रीम झील से जुड़ जाती है, जिसके लिए उन्हें स्लुइस गेट की आवश्यकता होगी जो वे संचालित कर सकें।

स्पंज सिटीज क्या है?

- स्पंज शहरों का विचार शहरों को और अधिक पारगम्य बनाना है ताकि उस पर गिरने वाले पानी को धारण किया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके।
- स्पंज शहर बारिश के पानी को अवशोषित करते हैं, जिसे बाद में मिट्टी द्वारा प्राकृतिक रूप से फ़िल्टर किया जाता है और शहरी जलभृतों तक पहुंचने दिया जाता है। यह शहरी या पेरी-शहरी कुओं के माध्यम से जमीन से पानी निकालने की अनुमति देता है।
- निर्मित रूप में, इसका तात्पर्य निकटवर्ती खुले हरे भरे स्थानों, परस्पर जुड़े जलमार्गों और आस-पड़ोस के चैनलों और तालाबों से है जो प्राकृतिक रूप से पानी को रोक सकते हैं और फ़िल्टर कर सकते हैं।
- इन सभी को कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT), राष्ट्रीय विरासत विकास और वृद्धि संवर्धन योजना (HRIDAY) और स्मार्ट सिटीज मिशन की तर्ज पर एक शहरी मिशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकता है।

स्पंज सिटीज मिशन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?

- **आर्द्रभूमि नीति:**
  - हमारी अधिकांश झीलों में, उथले किनारे, जो अक्सर पूर्ण टैंक स्तर से परे होते हैं, गायब हो गए हैं।
  - इन उथले किनारों को आर्द्रभूमि के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है; कभी-कभी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में, अन्य समय में पारिस्थितिक सामान्य रूप में मौजूद होते हैं।
  - स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना, इस छोटे पैमाने पर भी भूमि उपयोग को विकास नियंत्रण द्वारा विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।
- **वाटरशेड प्रबंधन और आपातकालीन जल निकासी योजना**
  - इसे नीति और कानून में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए।
  - शहरी जलसंभर सूक्ष्म पारिस्थितिक जल निकासी प्रणालियाँ हैं, जो भू-भाग की आकृति द्वारा आकारित होती हैं।
  - इन शहरी वाटरशेडों का विस्तृत दस्तावेजीकरण उन एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए जहां शासन की सीमाओं (जैसे वार्ड) के बजाय प्राकृतिक सीमाओं का उपयोग जल निकासी योजना के लिए किया जाता है।
  - महानगर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य के राजस्व और सिंचाई विभागों के साथ-साथ नगर निगमों को मिलकर इस तरह के काम में शामिल होना चाहिए।
- **इलाके में बदलाव के विरुद्ध प्रतिबंध**
  - बिल्डरों, संपत्ति के मालिकों, और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इलाके को समतल करके और जल निकासी मार्गों को बदलकर शहर को स्थायी अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई गई है।
  - क्षेत्र में बदलाव को सख्ती से विनियमित करने की जरूरत है और इलाके में किसी और बदलाव पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

- **सामग्री के उपयोग में परिवर्तन**
  - पानी को अवशोषित करने की शहर की क्षमता में सुधार करने के लिए, नई छिद्रपूर्ण सामग्री (new porous materials) और प्रौद्योगिकियों को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित या अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  - इन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण बायोस्वेल्स और प्रतिधारण प्रणालियां, सड़कों और फुटपाथ के लिए पारगम्य सामग्री, जल निकासी प्रणाली जो तूफान के पानी को जमीन में गिरने देती हैं, ग्रीन रूफ्स (green roofs) और इमारतों में संचयन प्रणालियां

हैं।
    - ये न केवल रन-ऑफ और बुनियादी ढांचे पर भार को कम करते हैं, बल्कि बाद में उपयोग के लिए शहर में पानी रखने में भी मदद करते हैं।

- **अन्य हितधारकों की साझेदारी**
    - इस पैमाने की शहरी बाढ़ को केवल नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। न ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा निपटाया जा सकता है।
    - इसे ऊर्जा और संसाधनों के ठोस और केंद्रित निवेश के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।
    - इस तरह के निवेश केवल महानगरीय स्तर पर नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक मिशन मोड संगठन में किए जा सकते हैं।

बंगाल की खाड़ी

संदर्भ: बंगाल की खाड़ी भू-आर्थिक, भू-राजनीतिक और भू-सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव कर रही है । इसलिए, चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज (CBS) खोलने की घोषणा की।

खाड़ी पर पुनर्विचार:

- खाड़ी में एक समर्पित संस्थान की स्थापना ने एक बार फिर खाड़ी में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए कनेक्शन और मंच स्थापित करके रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।
- CBS खाड़ी क्षेत्र के लिए अवसर पैदा करने के लिए भू-अर्थशास्त्र और भू-राजनीति, पारिस्थितिकी, व्यापार और कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, समुद्री कानून, सांस्कृतिक विरासत और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश करेगा।
    - यह समुद्री जुड़ाव के लिए भारत के समग्र ढांचे को मजबूत करेगा, जिसका उद्देश्य निकट समुद्री संबंधों को बढ़ावा देकर सभी के लिए सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।

खाड़ी का महत्व:

- विश्व का लगभग आधा कंटेनर यातायात इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और इसके बंदरगाह विश्व व्यापार का लगभग एक तिहाई संभालते हैं, इस प्रकार यह "दुनिया का आर्थिक राजमार्ग" बनाता है।
- इसने व्यापार और संस्कृति के संदर्भ में पूर्व और पश्चिम के बीच एक मार्ग का निर्माण करता है। एक इंडो-पैसिफिक ओरिएंटेशन और एशिया की ओर वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के पुनर्गठन का खाड़ी क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है।
- इस क्षेत्र में संचार की प्रमुख समुद्री गलियां वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए जीवन रेखाएं हैं और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं जो इस क्षेत्र के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति प्रदान करती हैं।
- आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन सहित गैर-पारंपरिक खतरे अधिक प्रचलित हो गए हैं।
- खाड़ी समुद्री और ऊर्जा संसाधनों के पर्यावरण के अनुकूल अन्वेषण में अधिक क्षेत्रीय सहयोग का अवसर भी प्रदान करती है।
- खाड़ी में जैवविविध समुद्री पर्यावरण है और कई दुर्लभ और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों और मैंग्रोव का घर है, जो पारिस्थितिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।

खाड़ी में विकार:

- प्रमुख शक्तियों द्वारा अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के परिणामस्वरूप क्षेत्र का समुद्री वातावरण बदल गया है।
    - आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव ने नए आयाम ले लिए हैं।
- जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तित भूमि उपयोग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, लवणता, समुद्र स्तर में वृद्धि, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खाड़ी के पर्यावरण पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रही हैं।
- छोटे और मध्यम फीडर जहाजों से परिचालन निर्वहन, शिपिंग टकराव, अनजाने में तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट , प्रदूषण, और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कूड़े का संचय, सभी खाड़ी की गिरावट में योगदान दे रहे हैं।
    - परिणामस्वरूप एक मृत क्षेत्र बन गया है, और तट को प्रकृति के प्रकोप से बचाने वाले मैंग्रोव पेड़ पहले से कहीं अधिक खतरे में हैं।

आगे बढ़ने की राह :

- चुनौतियों के बेहतर ज्ञान और क्षेत्र के सतत विकास के लिए उन पर काबू पाने की रणनीतियों के लिए, इन मुद्दों पर अधिक केंद्रित और अंत:विषय अध्ययन की आवश्यकता है।
- सीबीएस की स्थापना करके, नालंदा विश्वविद्यालय ने पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी है और देश को बे-केंद्रित शिक्षण (Bay-

focused teaching), अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एक अद्वितीय अंतःविषय अनुसंधान केंद्र दिया है। इसके अतिरिक्त, कई देशों और शैक्षणिक धाराओं के विद्वान पहले से ही खाड़ी में सीबीएस के फर्स्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम (first certificate programme) में भाग ले रहे हैं।

- यह आवश्यक है कि समुद्री पड़ोसी एक साझेदारी विकसित करें और समुद्री डोमेन के परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित प्रकृति के कारण सहयोग करें। कुछ चिंताएँ जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री संपर्क और समुद्री पारगमन में आसानी में सहयोग का विस्तार शामिल है।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए सूचना संलयन केंद्र (IFC) के बारे में:

- IFC की स्थापना गुरुग्राम, हरियाणा में भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) में की गई है।
- IFC लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की एक सहज वास्तविक समय की तस्वीर उत्पन्न करने के लिए सभी तटीय रडार श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल बिंदु केंद्र है।
- ये सभी देश जिन्होंने भारत के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, अब IFC में संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। यूएसए, यूके जैसे देशों ने आईएफसी-आईओआर में अपने अधिकारियों को तैनात किया है।

पर्यावरण

कार्बन ट्रेडिंग नीति

भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 क्या है?

अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की उपलब्धि की सुविधा के लिए और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में तेजी से संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार 20 साल के कानून को मजबूत करने की मांग कर रही है, जिसे 2001 का ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, जिसने भारत के पहले चरण को अधिक ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर अग्रसर किया है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने वाला विधेयक -

- सबसे पहले, यह औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपभोक्ताओं के चुनिंदा समूह के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य बनाने का प्रयास करता है। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का एक निर्धारित न्यूनतम अनुपात नवीकरणीय या गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आना चाहिए।
- दूसरा, यह एक घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करना चाहता है और कार्बन क्रेडिट में व्यापार को सुविधाजनक बनाना चाहता है।

महत्वपूर्ण रूप से, संशोधन विधेयक बड़े आवासीय भवनों को भी शामिल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास करता है। अब तक, ऊर्जा संरक्षण नियम मुख्य रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसरों पर लागू होते थे।

नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) शिखर सम्मेलन में, भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने और अगले 10 वर्षों में अपने उत्सर्जन को एक मिलियन टन कम करने का वादा किया था। कार्बन क्रेडिट बाजार की स्थापना इस लक्ष्य की ओर पहला कदम है।

कार्बन उत्सर्जन (CE)

- कार्बनयुक्त जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान, या सीमेंट, स्टील, रसायन आदि की औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं में होता है।
- थर्मल पावर के लिए ऊर्जा स्रोत/ईंधन-नवीकरणीय सौर/पवन ऊर्जा, पेट्रोल/डीजल वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन; और मिट्टी के तेल/गैस के बजाय घरेलू बिजली के उपकरण को प्रतिस्थापित करके सीई को समाप्त किया जा सकता है।

कार्बन बाज़ार (Carbon Market) क्या है?

- सरल शब्दों में, कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करता है।
- इन प्रतिबद्धताओं से भारत में स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट की मांग बढ़ेगी।
- भारत में स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट की वार्षिक मांग वर्ष 2030 तक 500+ मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है।

क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, पेरिस समझौते के पूर्ववर्ती, कार्बन बाजारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है।

- क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों के एक समूह के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित किए थे।
- अन्य देशों के पास ऐसे लक्ष्य नहीं थे, लेकिन यदि उन्होंने अपने उत्सर्जन को कम किया, तो वे कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते थे।

- ये कार्बन क्रेडिट तब उन विकसित देशों को बेचे जा सकते थे जिन पर उत्सर्जन कम करने का दायित्व था लेकिन वे असमर्थ थे।
- यह प्रणाली कुछ वर्षों तक अच्छी तरह से काम करती रही। लेकिन कार्बन क्रेडिट की मांग में कमी के कारण बाजार ढह गया।

कार्बन की कीमत कैसे तय होती है?

वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि कार्बन मूल्य निर्धारण शुरू में बिजली जैसे उच्च कार्बन-गहन क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया था, और फिर कुछ समय के बाद इसका दायरा सीमेंट और धातु जैसे अन्य कार्बन-गहन क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

- वर्तमान में, भारत की कोई सीमा और व्यापार नीति या स्पष्ट कार्बन मूल्य नहीं है। देश में आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण (ICP) द्वारा परिभाषित एक अंतर्निहित मूल्य संरचना है।
- कार्बन प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी) के अनुसार, आईसीपी एक स्वैच्छिक रूप से निर्धारित मूल्य है जिसका उपयोग संगठन के भीतर CO2 उत्सर्जन की एक इकाई की लागत के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। यह उस क्षेत्र में कार्बन बाजार मूल्य को दर्शाता है जहां कंपनी संचालित होती है।

कार्बन क्रेडिट के विकास/परामर्श/व्यापार में लगी कंपनियों के लिए कार्बन बाजार भी नए क्षितिज खोलेगा। दूसरी ओर, यह कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता और कोल इंडिया की विकास महत्वाकांक्षाओं की संभावनाओं के लिए हानिकारक होगा।

कार्बन व्यापार नीति अपनाने से क्या लाभ हैं?

ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए किसी भी उत्सर्जन में कमी एक कदम है और कार्बन ट्रेडिंग योजना उसी में मदद करती है।

- यह उत्सर्जन में उच्चतम सीमा, व्यापार और जुर्माने के रूप में प्रतिबंधों के साथ कम लागत पर GHG उत्सर्जन में कमी के उद्देश्य को प्राप्त करता है जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में देखा गया है।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके से मदद करता है। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा भूटान जैसे देशों में जलविद्युत परियोजना निवेश।
- उत्सर्जन व्यापार अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी जलवायु नीति के लिए आवश्यक उत्सर्जन निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के आसपास कठोरता (rigour) स्थापित करने का एक तरीका प्रदान करता है।
- उत्सर्जन व्यापार का परिणाम एकीकरण और सहयोग के माध्यम से और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास के माध्यम से एक सहक्रियात्मक प्रभाव में होता है। उदाहरण के लिए, तीसरे स्तर के शहर में एक औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग नहीं करने पर जलवायु परिवर्तन में योगदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जो उत्सर्जन व्यापार द्वारा सुगम है।

कार्बन व्यापार नीति से क्या सरोकार हैं?

- यह अप्रभावी हो जाता है यदि कंपनियों के पास अपने द्वारा भुगतान की जाने वाली कार्बन कीमत की भरपाई करने के लिए भारी निवेश करने का साधन है।
- बिना किसी लचीलेपन के कंपनियों द्वारा की जाने वाली भौतिक कार्रवाइयों का निर्धारण, आवश्यक कटौती प्राप्त करने की गारंटी नहीं होती है।
- जैसा कि सटीक उत्सर्जन का लेखा-जोखा कठिन है, विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत उत्सर्जन गणना में मुद्दों के परिणामस्वरूप उत्सर्जन में वास्तविक कमी के बजाय केवल संख्या मैजिक है।
- बिना किसी आंतरिक मूल्य वाली वस्तु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बाजार बनाना बहुत मुश्किल है।
- राजनीति के साथ मिश्रित कम कार्बन मूल्य निर्धारण ने योजना को अप्रभावी बना दिया है जहां समग्र उत्सर्जन में कमी के बजाय वृद्धि हुई है।

भारत के लिए कार्बन बाजार महत्वपूर्ण क्यों है?

भारतीय कंपनियां पहले से ही वैश्विक कार्बन बाजार में भाग ले रही हैं। यह तीन तरीकों में से एक कार्बन तटस्थता, अक्षय (RE 100), और विज्ञान आधारित लक्ष्य (एसबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

- RE 100 और SBT में भाग लेने वाली कंपनियां हानिकारक गतिविधियों पर अपनी निर्भरता को कम करके सीधे अपने उत्सर्जन को कम करने का काम करती हैं।
- कार्बन तटस्थता का अभ्यास करने वाले व्यवसाय समान कमी प्राप्त करने के लिए कार्बन ऑफ़सेट में निवेश करते हैं।
- इन ऑफसेट्स के अधिग्रहण के लिए घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों का स्रोत है।
- हालांकि बाजार शुरू में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक होगा, एक बार जब यह एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो जाता है, तो यह योजना भारतीय स्वैच्छिक बाजार खरीदार के लिए खुली रहेगी जैसा कि विधेयक में उल्लेख किया गया है। यह नए रास्ते के लिए बाजार खोलेगा, भले ही देश में स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट की मांग तेजी से बढ़ रही हो।

क्योटो प्रोटोकॉल का स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)

- विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के तहत कार्बन बाजार से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया।
- भारत ने सीडीएम के तहत 1,703 परियोजनाएं पंजीकृत कीं जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। इन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन (CER) के रूप में ज्ञात कुल कार्बन क्रेडिट लगभग 255 मिलियन है जो S. $ 2.55 बिलियन की राशि है।
- इसलिए, तार्किक रूप से, भारत को एक संपन्न कार्बन बाजार से बहुत कुछ हासिल करना है। हालाँकि, पेरिस समझौते के अनुसमर्थन के साथ, खेल के नियम बदल गए हैं।

आगे की राह क्या है?

भारत कार्बन क्रेडिट के लिए कोई अजनबी नहीं है, जिसे उसने स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजनाओं में भागीदारी के माध्यम से जमा किया है। सीडीएम परियोजनाओं में मजबूत अनुभव ने भारत को ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने में मदद की है जो स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट के लिए योग्य हैं। हालांकि, अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की तुलना में, भारत में स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट बाजार अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

- नियामक ढांचे और नीति दिशानिर्देशों की आवश्यकता है जो उत्सर्जन में कमी पर स्पष्ट आदेश प्रदान करते हैं।
- एक नई कार्बन व्यापार प्रणाली के साथ क्रेडिट का उचित मूल्य निर्धारण होना चाहिए ताकि यह हार्डकोर प्रदूषकों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य कर सके।
- केंद्र और राज्य दोनों को बड़े भवनों को कानून के दायरे में लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है - क्योंकि सत्ता एक ऐसा विषय है जिस पर राज्यों और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है। परिवर्तन वास्तव में प्रभावी होने के लिए, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

जलवायु सुधार

संदर्भ: अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रहे पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अमीर देशों से क्षतिपूर्ति या मुआवजे की मांग शुरू कर दी है।

जलवायु सुधार क्या हैं?

- जलवायु सुधार, ग्लोबल नॉर्थ द्वारा ग्लोबल साउथ को भुगतान किए जाने वाले पैसे के लिए एक कॉल को संदर्भित करता है, जो कि ग्लोबल नॉर्थ द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए गए (और जारी है) ऐतिहासिक योगदान को संबोधित करने के साधन के रूप में है।
- वैश्विक उत्तर में देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 92% अतिरिक्त के लिए जिम्मेदार हैं।
- इसके बावजूद, अनगिनत अध्ययनों से पता चला है कि वैश्विक दक्षिण के देशों को भारत में भीषण गर्मी की लहरों से लेकर केन्या में बाढ़ और निकारागुआ में तूफान तक जलवायु परिवर्तन के सबसे तेज परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।
- बार-बार सार्वजनिक बयानों में, पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री कहती रही हैं कि उनका देश ग्लोबल वार्मिंग में नगण्य योगदान देता है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक रहा है।
- वर्तमान बाढ़ ने पहले ही 1,300 से अधिक लोगों की जान ले ली है, और अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है।
- क्षतिपूर्ति के लिए पाकिस्तान की मांग एक लंबा शॉट प्रतीत होता है, लेकिन लागू किए जा रहे सिद्धांत पर्यावरण न्यायशास्त्र में काफी अच्छी तरह से स्थापित हैं।
- लगभग सभी विकासशील देश , विशेष रूप से छोटे द्वीपीय राज्य, वर्षों से जलवायु आपदाओं के कारण हुए नुकसान और क्षति के लिए वित्तीय मुआवजे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं।

ऐतिहासिक उत्सर्जन तर्क

- जलवायु आपदाओं से नुकसान और क्षति के लिए मुआवजे की मांग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत का विस्तार है।
- जलवायु परिवर्तन ढांचे में, जिम्मेदारी का बोझ उन अमीर देशों पर पड़ता है जिन्होंने 1850 के बाद से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है, जिसे आमतौर पर औद्योगिक युग की शुरुआत माना जाता है।
- युनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूके भी शामिल है, इस दौरान सभी उत्सर्जन का 50% से अधिक का योगदान करते हैं।
- यदि रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है, तो संयुक्त योगदान 65% या सभी उत्सर्जन के लगभग दो-तिहाई से अधिक हो जाता है।
- **ऐतिहासिक जिम्मेदारी का महत्व:**
    - कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बनी रहती है, और यह इस कार्बन डाइऑक्साइड का संचयी संचय (cumulative accumulation) है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है।

- भारत जैसा देश, जो वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ऐतिहासिक उत्सर्जन का केवल 3% है।
- चीन, जो पिछले 15 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ने 1850 के बाद से कुल उत्सर्जन में लगभग 11% का योगदान दिया है।

आशय:

- जबकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक है, यह गरीब देशों पर उनकी भौगोलिक स्थिति और सामना करने की कमजोर क्षमता के कारण कहीं अधिक गंभीर है। इससे नुकसान और क्षति के मुआवजे की मांग उठ रही है।
- जिन देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन में नगण्य योगदान रहा है और जिनके पास संसाधनों की गंभीर सीमाएं हैं, वे जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

स्वीकृति की जिम्मेदारी

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), 1994 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों के व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की इस विभेदित जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।

- यह वह जनादेश है जो बाद में 100 अरब डॉलर की राशि में विकसित हुआ जिसे अमीर देश हर साल विकासशील देशों को प्रदान करने के लिए सहमत हुए।
- वर्ष 2013 में स्थापित क्षति और नुकसान के लिए वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM), जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता की पहली औपचारिक स्वीकृति थी। इसने अब तक मुख्य रूप से जानकारी बढ़ाने और संवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- हाल ही में ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन में, एक तीन वर्षीय टास्क फोर्स का गठन एक वित्त पोषण व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए तैयार मानवीय प्रयासों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओसीएचए) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 और 2021 के बीच तीन साल की अवधि में जलवायु से जुड़ी आपदाओं से संबंधित वार्षिक वित्त पोषण अनुरोधों का औसत $ 15.5 बिलियन था।
- वर्ष 2020 में भारत और बांग्लादेश में चक्रवात अम्फान से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन 15 अरब डॉलर आंका गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उत्सर्जन के कारण अन्य देशों को 1.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। फिर गैर-आर्थिक नुकसान भी होते हैं, जिनमें जीवन की हानि, विस्थापन प्रवास, स्वास्थ्य प्रभाव, सांस्कृतिक विरासत को नुकसान शामिल है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन से अपरिहार्य वार्षिक आर्थिक नुकसान 290 अरब डॉलर से 580 अरब डॉलर के बीच पहुंचने का अनुमान है।

'मियावाकी पद्धति' के तहत मेरा गांव, मेरा जंगल'

संदर्भ : पंजाब के फाजिल्का जिले का एक गांव कुहारियांवाली वन क्षेत्र के विस्तार में एक ट्रेंडसेटर बन गया है। वन अनुसंधान संस्थान' के आंकड़ों के अनुसार, 2021 तक जिले में केवल 1.34 प्रतिशत वन क्षेत्र था, जोकि राज्य में सबसे कम था।

जिला प्रशासन को पता था कि उसे तस्वीर बदलने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए, उन्होंने 'मियावाकी पद्धति' मेरा गांव, मेरा जंगल, नामक एक पायलट परियोजना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप जंगल अब आत्मनिर्भर हो गया है क्योंकि पौधों ने पर्याप्त ताकत हासिल कर ली है।

यह मियावाकी पद्धति क्या है?

- मियावाकी जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा अग्रणी तकनीक है, जो थोड़े समय में घने, देशी जंगलों (native forests) के निर्माण में मदद करती है।
- इस प्रणाली में घरों के आगे तथा पीछे खाली स्थानों को छोटे बगानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है।
- इस विधि में एक ही क्षेत्र में जितना संभव हो सके पेड़ लगाना (केवल देशी प्रजाति) शामिल है जो न केवल जगह बचाता है, बल्कि लगाए गए पौधे भी विकास में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सूर्य की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे खरपतवार की वृद्धि को रोका जा सकता है।

- पौधे पहले तीन वर्षों के बाद रखरखाव-मुक्त (स्व-टिकाऊ) हो जाते हैं।

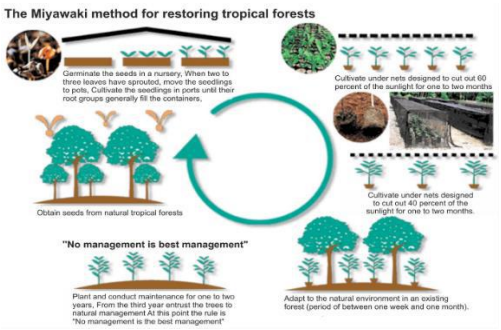

मियावाकी प्रक्रिया:

- क्षेत्र के देशी पेड़ों की पहचान की जाती है और उन्हें चार परतों झाड़ी, उप-वृक्ष, पेड़ और छत्र में विभाजित किया जाता है।
- मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है और बायोमास जो वेध क्षमता, जल धारण क्षमता और उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, को इसके साथ मिलाया जाता है।
- मिट्टी से एक टीला बनाया जाता है और बीज बहुत अधिक घनत्व पर तीन से पांच पौधे प्रति वर्ग मीटर में लगाए जाते हैं।
- जमीन गीली घास की मोटी परत से ढकी होती है।

मियावाकी विधि के लाभ:

- **तेज़ प्रक्रिया और घने जंगल:** इस विधि से छोटे वन बनते हैं। वे पारंपरिक तरीकों से लगाए गए पौधों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुना सघन और 100 गुना अधिक जैव विविधता वाले हो जाते हैं।
- **भूमि का तेजी से पुनर्जनन:** मियावाकी जंगलों को बहुत कम समय में भूमि को पुन: उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक जंगल को अपने आप ठीक होने में 70 साल से अधिक का समय लगता है।
- **आत्मनिर्भर:** पौधे पहले तीन वर्षों के बाद आत्मनिर्भर हो जाते हैं।
- **पर्यावरणीय लाभ:** ये छोटे वन ठोस ताप द्वीपों में तापमान कम करने, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, स्थानीय पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करने और कार्बन सिंक बनाने में मदद करते हैं।
- मियावाकी पद्धति से केवल 20 से 30 वर्षों में जंगल बनाने में मदद मिलती है, जबकि पारंपरिक तरीकों से इसमें 200 से 300 वर्ष लग जाते हैं।

संधारणीय ऊर्जा (Sustainable energy)

खबरों में क्यों : टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड (टीपीआरएमजी) ने पूरे देश में 1,000 हरित ऊर्जा उद्यम प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ हाथ मिलाया है।

- टाटा पावर दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोग्रिड सिस्टम में से एक का प्रबंधन करती है और देश के दूरदराज के हिस्सों में बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण के साथ सौर ऑफ-ग्रिड संयंत्र पर काम करती है।

इसके बारे में:

- माइक्रोग्रिड ऊर्जा वितरण प्रणाली है जिसमें एक जनरेटर और भंडारण प्रणाली शामिल होती है जिसे ऑन-ग्रिड या ऑफ-ग्रिड नियंत्रित किया जा सकता है।
- माइक्रोग्रिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसंरचना है जो ग्रामीण/दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां मुख्य ग्रिड की सीमित या पहुंच नहीं है, स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने में मदद करता है।
- माइक्रोग्रिड के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक संचालन और रखरखाव है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) के पास संचालन और रखरखाव के लिए एक समर्पित सेल है।
- मिनी-ग्रिड के प्रत्येक गांव में एक ऑपरेटर होता है। क्रेडा द्वारा प्रत्येक 15-20 गांवों के लिए एक क्लस्टर तकनीशियन प्रदान किया गया है। ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी का रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
- संयंत्र की संग्रहण दक्षता वित्तीय स्थिरता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

- माइक्रोग्रिड के संचालन में शामिल तकनीशियनों, ग्रामीणों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- TPRMG तकनीक में एक मीटर का बॉक्स है जो लगभग छह ग्राहकों को रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग फीचर्स के साथ लोड लिमिटिंग, दिन के समय और इसके साथ उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के साथ आपूर्ति प्रदान कर सकता है।

माइक्रोग्रिड का महत्व:

- गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा उत्पादक ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी हो सकते हैं, जो अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक डीजल जनरेटर पर निर्भर करता है।
- वे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने में योगदान और ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के निर्माण में मदद करते हैं।
- TPRMG ग्रामीण क्षेत्रों को विश्वसनीय, गुणवत्ता, सस्ती, स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सौर, पवन और बायोगैस की आपूर्ति करेगा।
- सिडबी अपनी प्रयास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकासशील व्यवसायों के लिए वित्त विकल्पों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा।
- इससे संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी मदद मिलेगी।
- लागत अर्थव्यवस्था: भारत में मिनी-ग्रिड का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है और टीपीआरएमजी ग्राहकों के लिए समूह स्मार्ट मीटर (टीपीआरएमजी की पेटेंट तकनीक) जैसी नवीन तकनीकों के साथ इस मुद्दे को हल करता है।
- चूंकि अधिकांश ग्राहक अपने स्वयं के उपभोग के लिए बिजली की आपूर्ति का उपयोग नहीं करते हैं; माइक्रोग्रिड का उपयोग पड़ोसी भूमि पर भी खेती के लिए किया जाता है। इससे उनकी आय में मदद मिलती है और लाभ अन्य किसानों तक भी पहुंचता है।
- टाटा पावर माइक्रोग्रिड अब तक दुकानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आटा मिलों, बल्क मिल्क चिलर, आरओ कोल्ड वाटर सिस्टम, स्कूलों, कॉलेजों और बैंकों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- टीपीआरएमजी ने माइक्रोफाइनेंसिंग उपायों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए COVID-19 महामारी के कारण रिवर्स माइग्रेशन में शामिल परिवारों के लिए एक अच्छा अवसर दिया और सभी के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया।

बायो-मीथेन जनरेटर के बारे में:

- बायोगैस का उत्पादन तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ अवायवीय वातावरण (anaerobic environment) में टूट जाते हैं। बायो-मीथेन जनरेटर बिजली पैदा करने के लिए चीनी मिलों के अपशिष्ट का उपयोग करते हैं।
- **लाभ:** ऊर्जा लागत में कमी, अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल उपयोग, कम स्थापित लागत, कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की कम मात्रा और प्राकृतिक उर्वरक का उत्पादन।
- **अर्थव्यवस्था:** जैव ईंधन आधारित जनरेटर डीजल जनरेटर की तुलना में सस्ते होते हैं। हालांकि, वे सौर माइक्रोग्रिड की तुलना में अधिक महंगे हैं। यह संयंत्र की रखरखाव लागत के साथ-साथ संयंत्र के लिए कच्चे माल की सोर्सिंग के कारण है।
- सौर-आधारित उत्पादन का एकमात्र नुकसान यह है कि इसे केवल दिन के समय ही टैप किया जा सकता है, जिससे भंडारण प्रणाली की आवश्यकता होती है।

सिडबी की प्रयास योजना:

- यह एक ऐप-आधारित, एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है।
- **उद्देश्य:** पिरामिड के नीचे से इच्छुक उद्यमियों और आजीविका उद्यमियों को ऋण और कम लागत वाली पूंजी की सुविधा प्रदान करना, जिससे उनकी व्यवहार्यता में सुधार हो।
- इसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में साझेदारी मॉडल में लागू किया जा रहा है जैसे कि इसने ऋण देने के लिए BigBasket को ऑनबोर्ड किया है।
- 31 मार्च 2020 तक, इसने 161 करोड़ रुपये की कुल मंजूरी के साथ 14000 सूक्ष्म उधारकर्ताओं की सहायता की है।
- कुल लाभार्थियों में महिला और ग्रामीण लाभार्थी क्रमश: 74 प्रतिशत और 88 प्रतिशत हैं।

सामाजिक मुद्दे

गर्भपात का अधिकार

संदर्भ: प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित और सिंगल महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार देते हुए कहा कि यह "राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन विकल्प बनाने का हर महिला का अधिकार है। "

- पीठ एक अविवाहित गर्भवती महिला की याचिका पर फैसला सुना रही थी, जो सहमति से रिश्ते में थी, लेकिन उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह 20 सप्ताह की सीमा पार कर चुकी थी।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट 1971 का संबंध काफी हद तक 'विवाहित महिलाओं' से था।
- हालांकि, 2021 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता है। एमटीपी अधिनियम 1971 के प्रावधानों की व्याख्या 20 सप्ताह के गर्भ से परे सिंगल महिला के अधिकार से इनकार करने के लिए नहीं की जा सकती है।
- विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच यह कृत्रिम भेद संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। कानून में लाभ सिंगल और विवाहित महिलाओं दोनों को समान रूप से मिलते हैं।

बेंच का तर्क:

- बेंच ने फैसला सुनाया कि गर्भावस्था एक महिला का एकमात्र विशेषाधिकार है और परिस्थितियाँ अद्वितीय हैं और आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कारकों के संबंध में प्रत्येक के लिए अलग हो सकती हैं।
- यदि लाभ केवल विवाहित महिलाओं को दिया जाता है, तो यह रूढ़िवादिता और सामाजिक रूप से प्रचलित धारणा को कायम रखेगा कि केवल विवाहित महिलाएं ही इंटरकोर्स (intercourse) करती हैं, और इसके परिणामस्वरूप, कानून का लाभ केवल उन्हें ही मिलना चाहिए।
- निर्णयात्मक स्वायत्तता के अधिकार का अर्थ है कि महिलाएं अपने जीवन का मार्ग चुनती हैं। अनचाहा गर्भधारण इनकी शिक्षा, उनके करियर को बाधित करके या उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करके उनके बचे जीवन को व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
- प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को किसी तीसरे पक्ष की सहमति या प्राधिकरण के बिना गर्भपात कराने या न करने का चयन करने का आंतरिक अधिकार हो।
- गर्भवती महिला की शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।
- जटिल जीवन परिस्थितियाँ गर्भपात के निर्णय में एक भूमिका निभाती हैं जिसे केवल महिला ही बाहरी हस्तक्षेप या प्रभाव के बिना अपनी शर्तों पर चुन सकती है।

संवैधानिकता:

- संविधान का अनुच्छेद 21 "यदि किसी महिला का मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य दांव पर है तो गर्भपात कराने के उसके अधिकार को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है।
- अनुच्छेद 51ए महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए कहता है। महिलाओं को न केवल अपने शरीर पर बल्कि अपने जीवन पर भी स्वायत्तता से वंचित करना उनकी गरिमा का हनन होगा।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971

- पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा कुछ गर्भधारण की समाप्ति और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है ।
- इसने गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात की अनुमति दी जिसमें एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है और 12 से 20 सप्ताह के बीच दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
- यह बिल राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है जो यह तय करता है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
- मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट 2021 के अनुसार, गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव (विधवा और तलाक), शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को गर्भपात की अनुमति है।

दुनिया भर में गर्भपात कानून:

- गर्भपात उन 24 देशों में अवैध है जहां लगभग 90 मिलियन या प्रजनन आयु की 5 प्रतिशत महिलाएं निवास करती हैं।

- इनमें अफ्रीका में सेनेगल, मॉरिटानिया और मिस्र, एशिया में लाओस और फिलीपींस, मध्य अमेरिका में अल सल्वाडोर और होंडुरास और यूरोप में पोलैंड और माल्टा शामिल हैं।
- इनमें से कुछ देशों में कठोर कानूनों के अनुसार, गर्भपात कराने के लिए महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अल सल्वाडोर में, गर्भपात कराने वाली कई महिलाओं को गर्भपात के मामलों सहित "गंभीर हत्या" का दोषी पाया गया है।
- **अमेरिका:** यूएस सुप्रीम कोर्ट के साथ 1973 के रो वी वेड के ऐतिहासिक फैसले को पलटना जिसने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार की स्थापना की, संयुक्त राज्य अमेरिका अब उन कुछ दर्जन देशों में शामिल है, जिन्होंने इस प्रक्रिया तक पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
- **कनाडा:** अदालत ने फैसला सुनाया कि गर्भपात कानून पर प्रतिबंध एक महिला के "जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा" के अधिकार का उल्लंघन करता है जो कनाडा के अधिकारों और स्वतंत्रता के चार्टर में निहित था।
- अधिकांश यूरोपीय देश गर्भकालीन समय सीमा के भीतर गर्भपात की अनुमति देते हैं, जो आमतौर पर लगभग 12-14 सप्ताह का होता है। लेकिन कई देशों में ऐसे कई अपवाद हैं जो बाद में भी गर्भपात की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, यूके में, भ्रूण की विकलांगता के मामलों में गर्भावस्था को जन्म तक तुरंत समाप्त किया जा सकता है।
- न्यूज़ीलैंड ने वर्ष 2020 में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, कानूनी अवधि को गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक बढ़ा दिया है।
- वर्ष 2021 में, कोलम्बिया में, संवैधानिक अदालत ने मानवाधिकारों और नागरिक समाज समूहों के प्रयासों के परिणामस्वरूप गर्भावस्था के 24 सप्ताह से पहले गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतदान किया।

आगे की राह

- कानून स्थिर नहीं रहना चाहिए और इसकी व्याख्या को बदलते सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहिए। एमटीपी अधिनियम और नियमों की व्याख्या विकसित होनी चाहिए और आज की सामाजिक वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए।
- परिवर्तनकारी संविधानवाद यह सुनिश्चित करके सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है और उत्पन्न करता है कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम है।
- कानून को इस तथ्य से अवगत रहना चाहिए कि समाज में परिवर्तन ने पारिवारिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

भारत में एलजीबीटी अधिकारों और कानूनों का एक संक्षिप्त इतिहास

संदर्भ: एक अलग यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के लोग प्रायः भेदभाव, सामाजिक कलंक और बहिष्कार का सामना करते रहे हैं। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सभी राज्य चिकित्सा परिषदों को हालिया निर्देश, धर्मांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध लगाना और इसे "पेशेवर कदाचार" कहना एक स्वागत योग्य कदम है।

कन्वर्ज़न थेरेपी क्या है?

- इसे रिपेरेटिव थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को बदलना है।
- समलैंगिक (पुरुष), समलैंगिक (महिला), उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर (विचित्र), इंटरसेक्स, अलैंगिक या किसी अन्य अभिविन्यास के सदस्यों को खासकर जब वे युवा होते हैं तो अक्सर बल द्वारा उनके यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को बदलने के लिए उनकी रूपांतरण या 'रिपेरेटिव' थेरेपी की जाती है।

यह दिशानिर्देश भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के तहत एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जारी किये गए है, जिसमें रूपांतरण चिकित्सा को गलत बताया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो प्रतिबंध की ओर ले जाती हैं?

7 जून, 2021 को, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक ऐसे मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें वह अपने माता-पिता से पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक समान-लिंग वाले जोड़े की पीड़ा के बारे में सुन रहे थे।

- **प्रतिबंध आदेश:** इस फैसले ने LGBTQIA+ लोगों के चिकित्सकीय रूप से "इलाज" या यौन अभिविन्यास को बदलने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित कर दिया। इसने अधिकारियों से "किसी भी रूप या रूपांतरण चिकित्सा के तरीके में स्वयं को शामिल करने वाले पेशेवरों" के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें दवा का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस की वापसी शामिल हो सकती है।
- **जीवन का अधिकार:** न्यायमूर्ति वेंकटेश ने पुलिस, कार्यकर्ताओं, संघ और राज्य समाज कल्याण मंत्रालयों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लिए "उनके द्वारा चुने गए जीवन जीने के लिए उनकी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने" के लिए कई अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए।
- **लंबित मामले बंद करना :** उदाहरण के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच में पता चलता है कि पक्ष

LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित वयस्कों की सहमति दे रहे हैं, तो गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों की शिकायतों को "उत्पीड़न के अधीन किए बिना" बंद कर दें।

- **गैर सरकारी संगठनों की सूची:** अदालत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा जो समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को संभाल सकते हैं।
- **कानूनी सहायता:** अदालत ने कहा कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से समुदाय को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **संवेदीकरण:** एजेंसियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का अक्षरश: पालन करने के लिये कहते हुए न्यायालय ने कहा कि समुदाय एवं उसकी ज़रूरतों को समझने के लिये हर संभव प्रयास हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।

अगर सुप्रीम कोर्ट का 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म करके समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना पहला कदम था, तो एनएमसी का नोटिस भी समावेशिता की दिशा में एक छोटा कदम है।

- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को पढ़ा और एलजीबीटी व्यक्तियों को कारावास के डर के बिना सहमति से इंटरकोर्स (intercourse) करने की अनुमति दी।

प्राचीन और मध्यकालीन भारत में समलैंगिकता की तुलना में क्या स्थिति थी?

- ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक युग के कानूनों को लागू करने से पहले, भारत के अपने ग्रंथ थे, जिसमें समलैंगिकता और समान-लिंग इंटरकोर्स की प्रथा का विवरण दिया गया था।
- 400 ईसा पूर्व, भारतीय दार्शनिक वात्स्यायन द्वारा लिखे गए कामसूत्र में समलैंगिक कृत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें इस तरह के कृत्यों को करने के बारे में स्पष्ट निर्देश शामिल हैं।
- इस बीच, दक्षिण भारत में, तमिल ग्रंथों में सबसे पुराना, 3 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक के तमिल संगम साहित्य में पुरुष-पर-पुरुष संबंधों और ट्रांसजेंडर लोगों के बीच संबंधों का विवरण शामिल था।
- अर्थशास्त्र, नारदस्मृति और सुश्रुत संहिता जैसे अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के समलैंगिक संबंधों का उल्लेख है।
- लेकिन कुछ मिथकों और प्राचीन ग्रंथों में एलजीबीटी संबंधों पर जितना विस्तृत और यहां तक कि निर्देश दिया गया है, मनुस्मृति जैसे अन्य ग्रंथों ने उसी का उपहास किया।
    - उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में समलैंगिक इंटरकोर्स (intercourse) में शामिल होने की सजा के रूप में एक महिला का सिर मुंडवाने या उसकी उंगलियां काटने जैसे विस्तृत दंड दिए गए हैं।
- ग्रंथों के अलावा प्राचीन वास्तुकला की दीवारें कामुकता पर प्राचीन भारत के विचारों के बारे में जानकारी का दूसरा स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, खजुराहो के मंदिर, समलैंगिक संबंधों और उभयलिंगी संबंधों के साथ-साथ कुछ समय पहले तक "अप्राकृतिक इंटरकोर्स (unnatural intercourse) " कहे जाने वाले अन्य कृत्यों को दर्शाते हैं।
- हालांकि, भारत में मुगल शासन के दौरान, "अप्राकृतिक इंटरकोर्स (unnatural intercourse)" को फतवा 'आलमगिरी' के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो शरिया कानून पर आधारित एक एकीकृत मार्गदर्शन संहिता है। इसमें समलैंगिक इंटरकोर्स में शामिल होने के लिए दंड जैसे सजा शामिल है।

स्वतंत्रता पूर्व युग में समलैंगिकता और एलजीबीटी अधिकारों का कैसे निपटारा किया गया था?

- भारत में समलैंगिकता पर पहला संहिताबद्ध कानून आईपीसी की धारा 377 था। अप्राकृतिक अपराधों से निपटने वाली धारा में कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध रखता है, उसे दस साल तक की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- आईपीसी की धारा 377 का पाठ जानबूझकर अस्पष्ट रहा जिसे मामला-दर-मामला आधार पर किसी भी "प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंधों" पर लागू किया जा सके। यह समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांस संबंधों तक फैला हुआ है, साथ ही साथ पाशविकता और व्यभिचार जैसे कार्य करता है।

आजादी के बाद क्या स्थिति थी?

- स्वतंत्रता और विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान दोनों ने मूल आईपीसी के अपने-अपने संस्करणों को भारतीय दंड संहिता और पाकिस्तान दंड संहिता के रूप में अपनाया।
- धारा 377 प्रभावी बनी रही और एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों को कई रूपों में उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
    - उदाहरण के लिए, वर्ष 1987 में, मध्य प्रदेश के भोपाल के पुलिस अधिकारी लीला और उर्मिला को "विवाहित" होने और एक समलैंगिक जोड़े के रूप में सामने आने के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था।

- वर्ष 2001 में एचआईवी+ रोगियों और सेक्सुअल हेल्थ के साथ काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन नाज़ फाउंडेशन ने भारत के संविधान में निहित भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में इस खंड को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।
- वर्ष 2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, नाज़ फ़ाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, फैसला सुनाया कि धारा 377 असंवैधानिक थी, और कानून को रद्द कर दिया। इस तरह फैसले ने पहली बार भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- वर्ष 2013 में, सुरेश कौशल और एनआर बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य में, SC ने दिल्ली HC के फैसले को यह कहते हुए उलट दिया कि "इस मुद्दे पर कानून बनाना केंद्र पर निर्भर था।" इस प्रकार, धारा 377 समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाली क़ानून की हिस्सों में वापस आ गई।
- इस फैसले से आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा, जिससे 2014 के आम विधानसभा चुनावों में समलैंगिकता को उनके चुनावी घोषणापत्र का एक हिस्सा बना दिया जाएगा।
- वर्ष 2018 में, पांच-न्यायाधीशों वाली एससी बेंच ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया। यह फैसला भारतीय कोरियोग्राफर नवतेज सिंह जौहर और 11 अन्य लोगों द्वारा धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने खंड के प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि वे सहमति से समान-सेक्स संबंधों से संबंधित हैं।
- कानून में बदलाव का एलजीबीटी समुदाय ने स्वागत किया, और एलजीबीटी और मानवाधिकारों की जीत के रूप में स्वागत किया।

रूपांतरण चिकित्सा पर हाल ही में एनएमसी प्रतिबंध को देखते हुए, और क्या करने की आवश्यकता है?

- **दंडात्मक प्रावधान:** कनाडा जैसे देशों से संकेत लेते हुए, जिसने धर्मांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि झोलाछाप डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और उन पर दंड का सामना करने का आरोप लगाया जाएगा।
- **पाठ्यक्रम में बदलाव:** वर्ष 2018 में निर्धारित मेडिकल पाठ्यपुस्तकें अभी भी समलैंगिकता को एक "विकृति" मानती हैं, जो "मानसिक पतन" का कार्य है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में बदलाव की शुरुआत करने की जरूरत है।
- **जेंडर-न्यूट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर:** शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर जेंडर-न्यूट्रल टॉयलेट अनिवार्य होने चाहिए।
- **माता-पिता की संवेदनशीलता:** गलतफहमी और दुर्व्यवहार का पहला बिंदु अक्सर घर से शुरू होता है, जिसमें किशोरों को "रूपांतरण" उपचारों को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, इस प्रकार माता-पिता को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है।
- **सामाजिक परिवर्तन:** भारतीय संस्थानों और समाज को "मनुष्य की परिवर्तनशीलता" को स्वीकार करना होगा और सभी को समान सम्मान देना होगा, चाहे यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान कुछ भी हो।
- **कानूनी संशोधन:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की तुलना में सामाजिक स्तर में बदलाव को विविध समुदाय की जरूरतों के लिए बेहतर कानूनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

संस्कृतिकरण (Sanskritization)

संदर्भ: संस्कृतिकरण एक शब्द था जिसे एम.एन. श्रीनिवास द्वारा गढ़ा और लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीय समाज की पारंपरिक जाति संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करने के लिए , एक प्रसिद्ध सामाजिक मानवविज्ञानी ने अपनी पुस्तक रिलिजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया (1952) में लिखा है।

संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है?

- एम एन श्रीनिवास लिखते हैं, "संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह उच्च जाति की दिशा में अपने रीति-रिवाजों, विचारधारा और जीवन के तरीके को बदल देता है।"
    - उदाहरणों में पवित्र धागा पहनना, मांस और शराब के उपयोग से इनकार करना, अंतर्विवाह का पालन करना, विधवा पुनर्विवाह का निषेध आदि शामिल हैं।
- गतिशीलता की इस प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए श्रीनिवास ने 'ब्राह्मणीकरण' शब्द का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इसे व्यापक अर्थों में 'संस्कृतीकरण' कहा।
- संस्कृतिकरण की अवधारणा ने भी डी-संस्कृतीकरण को जन्म दिया है। आधुनिक समय में कुछ उदाहरण हैं, कुछ उच्च जातियां "निचली" जाति के व्यवहार पैटर्न की नकल कर रही हैं, और उदाहरण के लिए ब्राह्मणों ने मांस और शराब लेना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को डी-संस्कृतीकरण (De-Sanskritization) कहा जाता है।

क्या संस्कृतिकरण ने सामाजिक गतिशीलता को जन्म दिया?

- एम एन श्रीनिवास ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया का परिणाम हमेशा ऐसी जातियों के लिए उच्च सामाजिक स्थिति में नहीं होता

है।

- अन्य कारक जैसे आर्थिक कल्याण, राजनीतिक शक्ति, शिक्षा और साहित्यिक/ऐतिहासिक साक्ष्य की स्थापना के लिए एक विशेष जाति वंश से उनकी संबद्धता / वंश भी उच्च सामाजिक पदों के लिए उनकी आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलितों के लिए, संस्कृतिकरण ने उच्च सामाजिक स्तर की गारंटी नहीं दी और उनके दैनिक जीवन में सुधार नहीं किया। इससे पता चलता है कि कैसे जाति व्यवस्था दलितों के लिए विशेष रूप से बहिष्कृत रही, और उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के प्रयासों का विरोध किया गया और उनके ऊपर की जातियों द्वारा रोक दिया गया।

संस्कृतिकरण में बाधाएँ क्या हैं?

- तथ्य यह कि किसी जाति को अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में दशकों-दशकों का समय लगता है, प्रक्रिया की धीमी गति का संकेत है और धीमापन विपक्ष का संकेत है।
- इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बाधा किसी भी जाति के खिलाफ अन्य जातियों की नाराजगी है जो अपनी स्थिति को बढ़ाने की कोशिश करती है। अक्सर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डाला जाता है। कभी-कभी निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति-रिवाजों और रस्मों (rituals) को अपनाने से रोकने के लिए फिजिकल फ़ोर्स का भी प्रयोग किया जाता है।
- एक अन्य कारक जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालता है, वह है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण को पवित्र से धर्मनिरपेक्ष की ओर एक आंदोलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- चूंकि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों की प्रक्रियाएं एक ही समय पर चल रही हैं, एक विरोधाभासी, या अधिक सही, एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। अधिकांश जातियों को चुनाव करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है।
- एक ओर, निचली जातियां उच्च जातियों के पारंपरिक मूल्यों और रीति-रिवाजों को अपनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनकी स्थिति को ऊंचा किया जा सके। दूसरी ओर सवर्ण जातियाँ इनमें से कुछ रीति-रिवाजों को त्याग रही हैं।
- बढ़ते औद्योगीकरण, अधिक संचार, नए व्यवसायों, अधिक शिक्षा के साथ, ऐसा लगता है कि पश्चिमीकरण अधिक प्रभावी प्रक्रिया होगी।

संस्कृतिकरण सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ क्या हैं?

यह पदानुक्रम को मजबूत करता है; यहां तक कि जब संस्कृतिकरण जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत उच्च स्थान पर उन्नयन के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है, तो यह केवल जाति पदानुक्रम में समुदायों की रैंक/स्थिति को संशोधित करता है और जाति के नाम पर वर्गीकृत असमानताओं और प्रथाओं को मजबूत करता है, जबकि एक मजबूत आलोचना की पेशकश नहीं करता है और समग्र रूप से जाति व्यवस्था की निंदा करता है।

जाति-विरोधी संघर्ष को कुंद करना (Blunts Anti-Caste Struggle) : केवल संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति संबंधों को समझने के लिए जाति-विरोधी संघर्षों की भूमिका की उपेक्षा करना है जो संस्कृतिकरण के सांस्कृतिक-अनुष्ठान प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करते थे। इन जाति-विरोधी संघर्षों का उद्देश्य उच्च जातियों के कथित 'श्रेष्ठ' सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का अनुकरण या अनुकूलन नहीं करना है - वे मूल्य और प्रथाएं जो जातिवादी, भेदभावपूर्ण और शोषक हैं।

इसके बजाय, इन जाति-विरोधी संघर्षों का उद्देश्य जाति के मूल ढांचे को नष्ट करना और जातिविहीन, जाति-मुक्त समाज की स्थापना करना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

केस स्टडी

- लैंगिक मुद्दे, विशेष रूप से लैंगिक असमानता और उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षा जगत में भेदभाव, शायद भारत में पहली बार 1937 में सुर्खियों में आए जब प्रोफेसर डी.एम. बोस, तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर, इस आधार पर बिभा चौधरी को अपने शोध समूह में शामिल करने के लिए अनिच्छुक थे कि उनके पास महिलाओं को देने के लिए उपयुक्त शोध परियोजनाएँ नहीं थीं। चौधरी अचंभित थी और उसने अपना मार्ग बना लिया। वह बोस के शोध समूह में शामिल हो गईं। मेसॉन के द्रव्यमान का निर्धारण करने में ब्रह्मांडीय किरणों पर उनका काम पौराणिक है।

20वीं शताब्दी में महिलाओं के विरुद्ध सामान्य पूर्वाग्रह जो उनकी बुद्धि की संदिग्ध क्षमता और शोध के कठिन कार्य को करने में उनकी क्षमता से

उत्पन्न हुआ था, काफी सामान्य था।

ग्लास की सीलिंग क्या है?

- यह एक अदृश्य बाधा को संदर्भित करता है जो किसी संगठन, राजनीति, या समाज के शीर्ष पदों तक पहुँचने से महिलाओं (या किसी अन्य वंचित/हाशिए पर रहने वाले समूह) के उत्थान को रोकता है।
- कॉर्पोरेट प्रबंधन क्षेत्र में अवधारणा की उत्पत्ति हुई जहां इसे 'व्यवहारिक या संगठनात्मक पूर्वाग्रह पर आधारित कृत्रिम बाधाओं के रूप में परिभाषित किया गया जो योग्य व्यक्तियों को उनके संगठन में प्रबंधन स्तर के पदों पर ऊपर की ओर बढ़ने से रोकता है'।

कॉर्पोरेट जगत में गिलास सीलिंग :

- इसके विपरीत, शिक्षाविदों में वास्तविकता की तुलना में निजी उद्यमों (कॉर्पोरेट क्षेत्र) में नेतृत्व और निर्णय लेने की स्थिति में महिलाओं की भागीदारी चौंकाने वाली है।
- भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर महिलाओं की संख्या 39% है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों में महिला सीईओ की संख्या 15% है, जबकि निजी उद्यमों के प्रबंधन में महिला बोर्ड सदस्य वर्ष 2016 में 15% से बढ़कर वर्ष 2022 में 19.7% हो गई हैं। डेलॉइट द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार, यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो 2045 तक समता के करीब पहुंच जाएगी।
- दूसरा, हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की तुलना में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को अपनाने के साथ निजी क्षेत्र में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना बहुत पहले शुरू हुआ था।

STEM में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:

- **रूढ़िवादिता:** रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाएँ जैसे कि महिलाएँ गृहिणियों के रूप में काम करती हैं।
- **पितृसत्तात्मक और सामाजिक कारण:** प्रथाओं को काम पर रखने या फैलोशिप और अनुदान देने आदि में पक्षपातपूर्ण रवैया।
- शादी और बच्चे के जन्म से संबंधित तनाव, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दबाव और घरेलूता के बंधन - घर चलाने और बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित जिम्मेदारी इन गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को और बाधित करती है।
- **रोल मॉडल की कमी:** लैंगिक समानता को रोकने में संगठनात्मक कारकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। महिला नेताओं और महिला रोल मॉडल की कमी अधिक महिलाओं को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है।
- **सहायक संस्थागत संरचना की अनुपस्थिति:** गर्भावस्था के दौरान सहायक संस्थागत संरचनाओं की अनुपस्थिति, फील्डवर्क और कार्यस्थल में सुरक्षा के मुद्दों के कारण महिलाएं कार्यबल छोड़ देती हैं।

- इन क्षेत्रों में महिलाओं की कम संख्या के लिए खराब शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जिम्मेदार है।

सरकार के प्रोत्साहन:

- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना।
- **नॉलेज इंवॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग (KIRAN):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पुनः विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और महिला वैज्ञानिकों को पारिवारिक कारणों से शोध छोड़ने से रोकने के लिए एक योजना उल्लेखनीय है।
- किरण के तहत 'महिला वैज्ञानिक योजना' नामक कार्यक्रमों में से एक - बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को करियर के अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से उनके करियर में ब्रेक था।
- STEMM (WISTEMM) कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भारत-अमेरिका फैलोशिप- इस द्विपक्षीय समझौते के तहत, भारतीय महिला वैज्ञानिक अब अमेरिका में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम कर सकती हैं।
- यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वूमेन यूनिवर्सिटीज (CURIE) कार्यक्रम का समेकन- इसका उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में S&T में उत्कृष्टता पैदा करने के लिए R&D बुनियादी ढांचे में सुधार करना और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की

स्थापना करना है।

- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम- कक्षा 9-12 की मेधावी छात्राओं को एसटीईएम क्षेत्र में उच्च शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हालाँकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद, अभी भी एक लैंगिक पूर्वाग्रह बना हुआ है और जिसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। हार्डकोर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में विश्व स्तर पर महिलाएं अभी भी एक कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी हैं।

आगे की राह :

- **विज्ञान अकादमियों की भूमिका:** विज्ञान अकादमियों को विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए उनकी भूमिका और योगदान पर विचार करना होगा, जिससे विज्ञान को समावेशी और संवेदनशील बनाया जा सके।
- **व्यवहारिक परिवर्तन लाना:** मंद लैंगिक भागीदारी सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से उत्पन्न होती है, जिसका उपचार व्यवहार परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। इसे बदला जा सकता है अगर अधिक महिलाओं को नेतृत्व के पद दिए जाएं।
- **व्यवस्थित रूप से ग्लास की सीलिंग को तोड़ना:** लिंगवाद और संस्थागत बाधाओं को दूर करना जो अधिक महिलाओं को वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं।
- **सकारात्मक कार्रवाई:** सरकार सभी शोध संस्थानों, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और एसटीईएम संगठनों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की नीति की जांच कर सकती है।

यह आशा की जाती है कि कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम वर्ष 2047 तक लैंगिक समानता की शुरुआत करेंगे, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी को चिह्नित करेगा- एकसच्चा 'आजादी का अमृत महोत्सव'।

PRACTICE QUESTIONS

Q.1) 'द नेशनल पॉलिसी ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है।
2. भारत, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1988 का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
3. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a. केवल 1
b. केवल 1 और 3
c. केवल 3
d. केवल 2 और 3

Q.2) निम्नलिखित जोड़ो पर विचार करें:

समाचारों में स्थान और उनके स्थान

1. सोलोमन द्वीप - उत्तरी प्रशांत महासागर
2. जेपोरीजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र - यूक्रेन
3. अंबरनाया नदी - जापान
4. माउंट न्यारागोंगो - फिलीपींस

ऊपर दिए गए कितने जोड़े/जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक जोड़ा
b. केवल दो जोड़े
c. केवल तीन जोड़े
d. सभी चार जोड़े

Q.3) 'आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक' में निम्नलिखित में से किस एक को सबसे अधिक वेटेज दिया गया है?

a. रिफाइनरी उत्पाद
b. प्राकृतिक गैस
c. कच्चा तेल
d. इस्पात

Q.4) भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें:

1. GATI
2. KIRAN
3. WISTEMM
4. CURIE

उपरोक्त में से कौन महिलाओं के लाभ के लिए शुरू किए गए हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2, 3 और 4
c. केवल 1, 3 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 27°C से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह
2. कोरिओलिस बल की अनुपस्थिति
3. ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव

उपरोक्त में से कौन सी परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.6) भारत में दुर्ग-बस्तर-चंद्रपुर बेल्ट और बल्लारी-चित्रदुर्ग-चिक्कमगलुरु-तुमकुरु बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है?

a. लौह अयस्क भंडार
b. यूरेनियम भंडार
c. सोने का भंडार
d. कोयला भंडार

Q.7) क्रि-मैक पोर्टल (Cri-MAC Portal) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्रि-मैक को वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. यह आवेदन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा चलाया जाता है।
3. इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 अपराध और अपराधियों पर जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है।

सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. 1 और 3
c. 2 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.8) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं।
2. जमानत के प्रावधान के लिए अदालत को यह मानने के लिए "उचित आधार" की आवश्यकता है कि आरोपी दोषी नहीं है।
3. नशीली दवाओं के दोषियों द्वारा समाप्ति, छूट, और पारित वाक्यों को कम करके कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है।

गलत कथन चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 3
c. 1 और 3
d. इनमें से कोई भी नहीं

Q.9) 'सर्वाइकल कैंसर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सर्वाइकल कैंसर के सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कुछ स्ट्रेन से जुड़े होते हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
2. शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर दो साल के भीतर स्वाभाविक रूप से एचपीवी संक्रमण से छुटकारा पाती है।
3. सर्ववैक (Cervavac) सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (क्यूएचपीवी) है।

सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. 1 और 3
c. केवल 3
d. 1, 2 और 3

Q.10) 'नैनो यूरिया' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह नैनोपार्टिकल के रूप में तरल यूरिया है।
2. इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित किया गया है, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है।
3. इसकी प्रभावकारिता 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पारंपरिक यूरिया प्रभावकारिता केवल 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए :

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1,2 और 3

Q.11) निम्नलिखित में से कौन स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है/हैं:

1. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) :
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:
3. MOVCDNER

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.12) हाल ही में खबरों में रहा 'हैनले क्षेत्र' कहाँ स्थित है?

a. सिक्किम
b. जम्मू और कश्मीर
c. लद्दाख
d. अरुणाचल प्रदेश

Q.13) निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों पर विचार करें:

1. तोलकाप्पियम (Tholkappiam)

2. मेयाराम (Meyyaram)
3. मेयारिवु (Meyyarivu)

उपर्युक्त निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं?

a. गज़ुलु लक्ष्मी नरसु चेट्टी
b. तिरुप्पुर कुमारानी
c. धीरन चिन्नामलाई
d. ओ. चिदंबरम पिल्लै

Q.14) 'पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (PM SHRI) का उद्देश्य क्या है?

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.15) भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा करता है?

a. अनुच्छेद 21
b. अनुच्छेद 16
c. अनुच्छेद 22
d. अनुच्छेद 24

Q.16) 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है?

a. मलेशिया
b. थाईलैंड
c. फिलीपींस
d. ताइवान

Q.17) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अधीन है।
2. यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।
3. यह वैक्सीन के लाइसेंस और इसके आपातकालीन उपयोग के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.18) वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इस समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
2. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर दान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.19) 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना है जिसके लिए सरकार द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआईएस) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।
2. सभी अनुसूचियां वाणिज्यिक बैंकों को ऋण वितरण के लिए एमएलआई के रूप में मान्यता दी गई है।
3. यह पूर्व-अनुमोदित ऋण प्रदान करता है जिसके लिए योजना के तहत पात्र उधारकर्ताओं को 'ऑप्ट-आउट (opt-out)' विकल्प प्रदान किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 3
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.20) निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:

1. फसल के खेत में कीटनाशकों का छिड़काव
2. सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटरों का निरीक्षण
3. डीएनए विश्लेषण के लिये टोंटी व्हेल से सांस के नमूने एकत्र करना

प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर, ड्रोन का उपयोग करके उपरोक्त में से कौन सी गतिविधियों को सफलतापूर्वक किया जा सकता है?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. केवल 1, 2 और 3

Q.21) हाल ही में खबरों में रही 'कुशियारा नदी' निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है?

a. गंगा
b. तीस्ता
c. ब्रह्मपुत्र
d. बराक

Q.22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. WEST कार्यक्रम I-STEM की एक पहल है जो महिला शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को एक अलग मंच प्रदान करती है।
2. आई-एसटीईएम, अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है।
सही कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. हॉट स्प्रिंग्स चांग चेन्मो नदी के पूर्व में है।
2. चांग चेन्मो नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है।
3. कोंगका दर्रा अरुणाचल प्रदेश - म्यांमार सीमा में एक पहाड़ी के ऊपर एक निचला पहाड़ी दर्रा है।
गलत कथन चुनें:
a. 1, 2 और 3
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. केवल 1 और 2

Q.24) निम्नलिखित में से कौन दुनिया के देशों को 'मानव विकास सूचकांक' रैंकिंग देता है?
a. विश्व आर्थिक मंच
b. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
c. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
d. विश्व बैंक

Q.25) निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

शहर और नदी

1. हैदराबाद - म्यूसिक
2. दिल्ली - यमुना
3. बेंगलुरु - अर्कावती
4. कोलकाता - हुगली

दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?
a. केवल एक जोड़ा
b. केवल दो जोड़े
c. केवल तीन जोड़े
d. सभी चार जोड़े

Q.26) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए NAAQS मानक।
2. NAAQS में 10 प्रदूषक होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.27) 'दारा शिकोहो' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. उन्हें भारत में अंतरधार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है।
2. उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मजमा-उल-बहरीन और सिर-ए-अकबर शामिल हैं जो हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के कारण हैं।
सही कथन चुनें:
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.28) भारत के संदर्भ में, न्युकमाडोंग, ज्ञानद्रब्रांगसा (Gyandrabrangsa), हाल्टंगमु (Halftangmu) और पेनपेयटंग (Penpeytang) के नाम हैं-
a. जनजातीय बस्तियां
b. ग्लेशियर
c. सामुदायिक आरक्षित वन
d. जनजातीय भाषाएं

Q.29) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. कर से बचाव से तात्पर्य धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरणों और खातों के फर्जीवाड़ा के माध्यम से नेट कर देयता से बचने के अवैध साधनों से है।
2. कर चोरी में भारी जुर्माना और दंड लगता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों
d. न तो 1 न तो 2

Q.30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. कुशियारा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है।
2. यह दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट से होकर बहती है।
3. भारत-बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है जिसके बाद चीन है।
4. तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो असम और बांग्लादेश से होकर बहती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a. केवल 1
b. केवल 1 और 2
c. केवल 3 और 4
d. केवल 2 और 3

Q.31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. होयसल मंदिर पंचायतन शैली के हैं।

2. चेन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक के बेलूर में स्थित है।
3. जगती एक वास्तुशिल्प तत्व है जो ऊंचे टावर का प्रतिनिधित्व करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 3
b. केवल 2
c. केवल 3
d. केवल 2 और 3

Q.32) 'वेम्बनाड झील' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. यह भारत की सबसे लंबी झील है।
2. यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है।
3. 'कुमारकोम पक्षी अभयारण्य' झील के पूर्वी तट पर स्थित है।
सही कथन चुनें:

a. 1 और 2
b. 2 और 3
c. 1, 2 और 3
d. 1 और 3

Q.33) निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने 1940 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था?

a. जवाहर लाल नेहरू
b. सुभाष चंद्र बोस
c. सरोजिनी नायडू
d. विनोबा भावे

Q.34) भारत में "रबर बोर्ड" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रबर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है।
2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है।
3. रबर बोर्ड का मुख्य कार्यालय केरल के अलाप्पुझा में स्थित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 3
c. केवल 3
d. केवल 1 और 2

Q.35) 'नागोर्नो-कराबाख' किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है?

a. सूडान-दक्षिण सूडान
b. सूडान-इथियोपिया
c. अज़रबैजान-आर्मेनिया
d. रूस-यूक्रेन

Q.36) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. नासा का डार्ट मिशन डिडिमोस में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है।
2. एलआईसीआईएक्यूब नासा द्वारा विकसित एक क्यूबसैट है
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.37) भारत के संदर्भ में, 'कुरिविकरण(Kurivikkaran), हट्टी और बिंझिया' शब्द किससे संबंधित हैं?

a. मर्चेंट गिल्ड
b. अनुसूचित जनजाति
c. अनुसूचित जाति
d. इनमे से कोई भी नहीं

Q.38) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है।
2. यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
3. यह बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
4. केवल बीपीएल व्यक्ति ही इसके लिए पात्र हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 3 और 4
d. केवल 1 और 4

Q.39) 'मानसबल झील' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. यह लद्दाख में मीठे पानी की झील है।
2. इस झील का पानी एक विनियमित बहिर्वाह चैनल के माध्यम से झेलम नदी में बहता है।
सही कथन चुनें:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.40) "ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह रूस के साथ G20 द्वारा समर्थित एक पहल है।
2. यह बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निम्न आय पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने की एक पहल है।
3. यह मुख्य रूप से रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2 और 3
c. 1, 2 और 3
d. केवल 3

Q.41) निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं?

1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान
2. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
3. पेंच राष्ट्रीय उद्यान
4. ताडोबा-अंधारी राष्ट्रीय उद्यान

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1, 2 और 3
b. केवल 1 और 3
c. केवल 2 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

Q.42) R21/Matrix-M वैक्सीन, जो हाल ही में चर्चा में है, किससे संबंधित है?

a. डेंगू
b. मलेरिया
c. ट्यूबरक्लोसिस (TB)
d. हेपेटाइटिस बी

Q.43) भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इरोड वेंकट रामास्वामी / पेरियार निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं:

1. स्वाभिमान आंदोलन
2. वैकोम सत्याग्रह:
3. द्रविड़ कड़गम
4. जस्टिस पार्टी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए :

a. केवल 1, 2 और 3
b. केवल 2, 3 और 4
c. केवल 1, 2 और 4
d. 1, 2, 3 और 4

Q.44) विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (WPP) किसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है?

a. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
b. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग
c. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
d. जनसंख्या परिषद (एनजीओ)

Q.45) 'एशियाई शेर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एशियाई शेर को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. पिछले पांच वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3. गुजरात में गिर वन एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 3
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.46) निम्नलिखित में से किस समूह में आसियान के सभी चार देश सदस्य हैं?

a. मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर
b. ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया और भारत
c. सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश और वियतनाम
d. इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी

Q.47) अर्धचालकों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपभोक्ता उत्पाद शामिल है:

1. मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
2. टेलीविजन
3. वाशिंग मशीन
4. डिजिटल कैमरा
5. रेफ्रिजरेटर
6. एलईडी बल्ब

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1, 3, 5, और 6
b. केवल 1, 2, 4, 5 और 6
c. केवल 2, 3, 5, 4, और 5
d. 1, 2, 3, 4, 5, और 6

Q.48) भारत में, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है?

a. उपभोक्ता मामले विभाग
b. व्यय प्रबंधन आयोग
c. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
d. भारतीय रिजर्व बैंक

Q.49) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान में परिभाषित किया गया है।
2. विधायिका के पास व्यक्तियों के सभी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, प्रत्येक संवैधानिक संशोधन को उसके गुण-दोष के आधार पर आंका जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. 1 और केवल
b. केवल 2 और 3
c. केवल 2
d. केवल 3

Q.50) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी घोषणा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी।
2. यह अन्य बातों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर भी प्रदान करेगा।
3. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार प्रदान करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 3
b. केवल 2
c. केवल 1 और 2
d. 1, 2, और 3

Q.51) भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना के लिए सिफारिश की।
2. सीबीआई निदेशक की नियुक्ति गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.52) "शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संरचना पूंजी, लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता जैसे मानकों पर आधारित है।
2. इस संरचना का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना है।
3. यह संरचना केवल भारतीय बैंकों पर लागू होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 2
d. केवल 1

Q.53) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।
2. यह आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.54) 'पूसा बायो-डीकंपोजर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक बैक्टीरिया आधारित सूत्रीकरण है।
2. यह फसल के पराली को जैव खाद में परिवर्तित करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.55) भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, शृंकफ्लेशन को संदर्भित करता है

a. एक अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों का संयोजन।
b. स्थिर विकास और मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था
c. मुद्रास्फीति के स्तर को शृंकफ्लेशन
d. उपभोक्ता की कीमत को समान रखते हुए पैकेज का आकार घटाना

Q.56) आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) नियम, 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. फिंगरप्रिंट जैसे जैविक नमूनों के संग्रह की अनुमति देते हुए नियम स्पष्ट रूप से चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग को रोकते हैं।
2. यह नियम पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.57) एशियाई विकास बैंक (ADB) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एडीबी के 60 से अधिक सदस्य देश हैं।
2. भारत एडीबी में सबसे बड़ा शेयरधारक है।
3. एडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 2
c. केवल 2 और 3
d. केवल 3

Q.58) निम्नलिखित में से कौन सा वह संदर्भ है जिसमें "लोरा (लॉन्ग रेंज रेडियो) तकनीक" शब्द का उल्लेख किया गया है:

a. बैंकिंग सेवाएं
b. वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क
c. जीपीएस नेविगेशन सिस्टम
d. डीएनए बारकोडिंग

Q.59) भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी।
2. यह "टीम भारत" के नाम से खेलता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2

c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और 2

Q.60) 'पीएम केयर फंड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गृह मंत्री निधि के न्यासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
2. इस फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी लेखा-परीक्षा की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

a. 1,2 और 3
b. केवल 2 और 3
c. केवल 2
d. केवल 1 और 2

Q.61) 'रेबीज' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक जूनोटिक वायरल रोग है।
2. रेबीज 100% घातक होता है लेकिन 100% वैक्सीन-रोकथाम योग्य है।
3. विश्व में रेबीज से होने वाली मौतों का एक तिहाई भारत में दर्ज किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए :

a. केवल 1 और 2
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.62) 'कार्बन डेटिंग' शब्द का अक्सर संबंधित समाचारों में उल्लेख किया जाता है:

a. पशुओं में रोगों के उपचार की एक प्रक्रिया।
b. पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारित करने की एक प्रक्रिया।
c. कैंसर के इलाज के लिए एक दवा।
d. एक उल्कापिंड की आयु निर्धारित करने की एक प्रक्रिया।

Q.63) 'ब्रह्मोस मिसाइल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
2. यह मिसाइल उच्च सटीकता के साथ फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.64) निम्नलिखित में से कौन ड्रैगनफ्लाई नहीं है?

a. स्पाइनी हॉर्नटेल
b. गोल्डन डार्टलेट
c. स्पूनबिल (एक प्रकार का पक्षी)
d. डिच ज्वेल

Q.65) फ्लेक्स-ईंधन वाहनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे फ्लेक्स ईंधन के मिश्रण पर काम करते हैं।
2. दहन के लिए ईंधन को मिलाने के लिए उनके पास दो अलग ईंधन प्रणाली है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.66) बैंकिंग प्रणाली की तरलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करता है जिसे बैंकों को दीर्घकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है
2. बैंकिंग प्रणाली में नकदी तीन वर्षों में पहली बार घाटे में बदल गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.67) निम्नलिखित में से कौन समय-समय पर 'ब्रेकथ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022' रिपोर्ट जारी करता है?

a. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
b. विश्व बैंक
c. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
d. प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ

Q.68) एशियन पाम ऑयल एलायंस (APOA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक खाद्य तेल व्यापार संघ है जो ताड़ के तेल आयात करने वाले देशों से बना है।
2. इसका गठन वर्ष 2020 में हुआ था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और 2

Q.69) निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में GPS तकनीक का उपयोग किया जा सकता है?

1. मोबाइल फोन संचालन
2. विश्व के नक्शे बनाना

3. व्यक्तिगत / वस्तु आंदोलन की निगरानी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1 और 3
b. केवल 2 और 3
c. केवल 1 और 2
d. 1 2 और 3

Q.70) निम्नलिखित में से किस राज्य में 'सेसा आर्किड अभयारण्य' स्थित है?

a. असम
b. अरुणाचल प्रदेश
c. मणिपुर
d. सिक्किम

Q.71) फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. एफएफएस फंड का इस्तेमाल योग्य स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक फंड के एक निर्दिष्ट हिस्से से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को लाभ होना चाहिए।
3. योजना के संचालन के लिए नाबार्ड जिम्मेदार है।
4. यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दायरे में आती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1 और 2
b. केवल 3 और 4
c. केवल 1, 2 और 3
d. केवल 1 और 4

Q.72) निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कला रूप की पहचान करें:

1. यह केरल राज्य में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है।
2. इस कला के अभ्यासियों (Practitioners) को मानव शरीर पर दबाव बिंदुओं और उपचार तकनीकों का जटिल ज्ञान होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. चविट्टुनाटकम (Chavittunatakam)
b. कथकली
c. कलारिपयाट्टू
d. मोहिनीअट्टम

Q.73) प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के संदर्भ में, बायो-मीथेन बिजली जनरेटर के क्या/क्या लाभ/लाभ हैं?

1. वे अवायवीय श्वसन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए जैविक अपशिष्ट जैसे खाद्य फसलों का उपयोग करते हैं।
2. माइक्रोग्रिड का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और 2

Q.74) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के संस्थापकों में से एक थे।
2. वह लाहौर साजिश मामले में शामिल था।
3. वह अपने आदर्श को "नए, यानी मार्क्सवादी, आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण" के रूप में घोषित करता है।
4. उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में 'मैं नास्तिक क्यों हूँ', 'मेरे पिता को पत्र' और 'जेल नोटबुक' शामिल हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपरोक्त कथनों में वर्णित व्यक्तित्व की पहचान करें:

a. राजगुरु
b. सुखदेव
c. लाला लाजपत राय
d. भगत सिंह

Q.75) 'नीलकुरिंजी ब्लूम्स' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ढलानों को कवर करते हैं।
2. ये 10 साल में एक बार खिलते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

Q.76) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सीडीएस के लिए पहला प्रस्ताव 2000 कारगिल समीक्षा समिति (KRC) से आया था।
2. यह चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
3. यह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 1 और 2
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

Q.77) मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें,

1. यह असाधारण स्थिति में 22 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है।
2. इस अधिनियम के तहत विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. दोनों 1 और 2
d. न तो 1 और न ही 2

a. आंध्र प्रदेश
b. कर्नाटक
c. तेलंगाना
d. तमिलनाडु

Q.78) 'बथुकम्मा' नामक पुष्प उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?

KEY ANSWERS

1	d	21	d	41	a	61	d
2	b	22	a	42	b	62	b
3	a	23	c	43	d	63	c
4	d	24	c	44	b	64	c
5	c	25	c	45	c	65	a
6	a	26	a	46	a	66	b
7	d	27	c	47	d	67	c
8	d	28	a	48	d	68	a
9	d	29	b	49	d	69	d
10	c	30	d	50	c	70	b
11	d	31	b	51	a	71	d
12	c	32	c	52	c	72	c
13	d	33	d	53	a	73	c
14	B	34	a	54	b	74	d
15	c	35	c	55	d	75	a
16	c	36	d	56	b	76	d
17	d	37	b	57	a	77	b
18	a	38	c	58	a	78	c
19	d	39	b	59	d		
20	d	40	d	60	a		

IAS BABA

UPSC 2023

TLP CONNECT

Integrated Prelims cum Mains Test Series

ONLINE & OFFLINE

Features

- 69 Prelims Tests
- 68 Mains Tests
- 1:1 Mentorship
- Discussion classes after Every Mains Test (Online)
- Babapedia (For Current Affairs)
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

Batch 3

ADMISSIONS OPEN

Scan Here

To Know more

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888